

भारत में शिक्षा

प्रकाशक
जयन्तीलाल छोदालाल शाह
आचार्य बुक डिपो
बडौदा

प्रथम संस्करण
मूल्य ९ रुपये

मुद्रक
श्री कृष्णाजी वामन मराठे, बी. ए.
श्रीरामविजय प्रिंटिंग प्रेस
रावपुरा, बडौदा
१-५-१९६०

प्राक्कथन

अंग्रेजी भाषा में मेरी 'Education in India—Today and Tomorrow' नामक पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उसका चतुर्थ संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है। शिक्षा-जगत् में उस पुस्तक का इस प्रकार समुचित आदर एवं प्रचार उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्रस्तुत पुस्तक मेरी उसी अंग्रेजी पुस्तक पर आधारित है। इसमें कहीं-कहीं तो उस मूल ग्रन्थ का श्रुनुवाद है, और कहीं उसको आधार मान लिया गया है। आशा है कि मेरी उक्त अंग्रेजी पुस्तक का यह हिन्दी रूप भी पाठकों को रुचिकर होगा।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम की ओर दृष्टि रखकर मैंने यह पुस्तक लिखना आरम्भ किया था; किन्तु जिस समय मैं वर्ष्य विषय के विभिन्न अङ्गों पर व्याख्या पूर्वक लिखने बैठा, उस समय मैंने अनुभव किया कि व्यापकता का ध्यान रखते हुए इस पुस्तक को केवल बी० एड० या एम० एड० के पाठ्यक्रम तक ही सीमित न रखा जाये, वरन् इसे इस प्रकार लिखा जाये, जिससे यह साधारण शिक्षित भारत-वासी का भी ध्यान आकृष्ट करे। चूँकि शिक्षा-विषयक जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है, अतएव इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है कि जिससे कठिनाइयों के बिना सर्वसाधारण वाचक इसका समुचित लाभ ले सके।

इस पुस्तक को लिखने का मेरा दूसरा उद्देश्य हिन्दी-भाषा की यथा-रुचि सेवा करना भी है। हिन्दी भाषा में शिक्षा विषयक पुस्तकों की माँग है, और ऐसी शिक्षा साहित्य की पुस्तकों का अभाव भी है। इसीसे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समझी गयी। मैंने इस ग्रन्थ में भाषा को भरसक सरल रखने का प्रयत्न किया है। शिक्षा विषयक पारिभाषिक शब्दों के रूप की अनिश्चितता के कारण कभी कभी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, पर साधारणतया मैंने हिंदी में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया है।

अन्त में उन अनेक विद्वानों तथा ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके विचारों तथा ग्रन्थों से मुझे इस कार्य में सहायता प्राप्त हुई है। इनके नाम ग्रन्थ सूची में दिये गये हैं।

मैं श्री समामोहन अवधिया, 'स्वर्ण-सहोदर' एवम् आदरणीय प० शालग्राम द्विवेदी, एम० ए०, (भूतपूर्व अधीक्षक, प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जमलपुर, का अत्यन्त

प्राक्कथन

अंग्रेजी भाषा में मेरी 'Education in India—Today and Tomorrow' नामक पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उसका चतुर्थ संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है। शिक्षा जगत में उस पुस्तक का इस प्रकार समुचित आदर एवं प्रचार उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्रस्तुत पुस्तक मेरी उसी अंग्रेजी पुस्तक पर आधारित है। इसमें कहीं-कहीं तो उस मूल ग्रन्थ का अनुवाद है, और कहीं उसको आधार मान लिया गया है। आशा है कि मेरी उक्त अंग्रेजी पुस्तक का यह हिन्दी रूप भी पाठकों को रुचिकर होगा।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम की ओर दृष्टि रखकर मैंने यह पुस्तक लिखना आरम्भ किया था; किन्तु जिस समय मैं वर्ष विषय के विभिन्न अङ्गों पर व्याख्या पूर्वक लिखने बैठा, उस समय मैंने अनुभव किया कि व्यापकता का ध्यान रखते हुए इस पुस्तक को नेवल वी० एड० या एम० एड० के पाठ्यक्रम तक ही सीमित न रखा जावे, वरन् इसे इस प्रकार लिखा जावे, जिससे यह साधारण शिक्षित भारतवासी का भी ध्यान आकृष्ट करे। चूंकि शिक्षा विषयक जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है, अतएव इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है कि जिससे कठिनाइयों के बिना सर्वसाधारण वाचक इसका समुचित लाभ ले सके।

इस पुस्तक को लिखने का मेरा दूसरा उद्देश्य हिन्दी-भाषा की यथा रुचि सेवा करना भी है। हिन्दी भाषा में शिक्षा विषयक पुस्तकों की माँग है, और ऐसी शिक्षा साहित्य की पुस्तकों का अभाव भी है। इसीसे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समझी गयी। मैंने इस ग्रन्थ में भाषा को भरसक सरल रखने का प्रयत्न किया है। शिक्षा विषयक पारिभाषिक शब्दों के रूप की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, पर साधारणतया मैंने हिन्दी में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया है।

अन्त में उन अनेक विद्वानों तथा ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके विचारों तथा ग्रन्थों से मुझे इस कार्य में सहायता प्राप्त हुई है। इनके नाम ग्रन्थ सूची में दिये गये हैं।

मैं श्री समामोहन अवधिया, 'स्वर्ण सहोदर' एयम् आदरणीय प० शालग्राम द्विवेदी, एम० ए०, (भूतपूर्व अधीक्षक, प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर, का अत्यन्त

विषय-सूची

प्राक्कथन v
तालिका-सूची xi
चित्र-सूची xii
१. भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूपरेखा			
भूमिका १
वैदिक युग २
बौद्ध युग ७
मुस्लिम युग १२
ब्रिटिश युग १६
स्वातन्त्र्योत्तर काल २२
२. शिक्षा व्यवस्था			
भारत के राज्य २६
शिक्षा प्रशासन २७
शिक्षा सस्थाओं का वर्गीकरण	 ३५
शिक्षा की सीढ़ी ३६
शिक्षा व्यय ३८
३. बुनियादी शिक्षा			
प्रस्तावना ३९
प्रारम्भिक कार्य ४०
नयी तालीम के प्रक्रम ४४
नयी तालीम और भूदान ४७
नयी तालीम और सरकार ४८
समालोचना ५१

ही आभारी हूँ। इन महाभानुवों ने कृपा-पूर्वक पुस्तक की पाण्डु-लिपि संशोधन में मेरी यथेष्ट सहायता की है। मैं अपने मित्र श्री भारतेन्दु सिनहा, प्राध्यापक, हिंदी विभाग बड़ौदा विश्वविद्यालय एवं प्रिय छात्र श्री रामभाई पटेल, शिक्षक, शारदा मन्दिर हाईस्कूल, बड़ौदा का भी अनुग्रहीत हूँ; क्योंकि उनके प्रूफ-संशोधन एवं अनुकूल परामर्श के बिना निश्चय ही यह पुस्तक इतनी अच्छी नहीं निकल सकती थी।

सेवन्ती बाग, बड़ौदा।
शिवरात्रि,
सं० २०१६ वि०।

श्रीधरनाथ मुकर्जी

✓८. प्राविधिक शिक्षा

प्रस्तावना १९४
ब्रिटिश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा १९५
स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा १९८
कतिपय समस्याएँ २०५
उपसंहार २१३

९ शिक्षक प्रशिक्षण

पूर्व-पृष्ठिका २१५
वर्तमान परिस्थिति २२०
अनुसन्धान एवं उत्तर-स्नातक कार्य २२७
मध्य अध्यापन प्रशिक्षण २२९
शिक्षक प्रशिक्षण समस्याएँ २३१
शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ २३९
उपसंहार २४३

१०. विविध विषय

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा २४५
ग्रौढ (समाज) शिक्षा २५०
मजबूतों की शिक्षा २६२
स्वास्थ्य एवं अनुशासन २७१

११. कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना २७९
गुरुकुल, काँगड़ी २७९
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय २८०
विश्व भारती २८१
विद्यापीठ २८४
जामिया मिलिया, दिल्ली २८५
हिन्दुस्थानी तालीमी सध, सेवाग्राम २८७

१४. प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	६२
अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन...	६६
वर्तमान स्थिति	७२
प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	७९
सुधार की ओर	८३
उपसंहार	९६

१५. माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	९७
वर्तमान स्थिति	१०६
माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	११५
उपसंहार	१३५

१६. विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना	१३६
आधुनिक काल में उच्च शिक्षा	१३६
वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ	१४३
कतिपय समस्याएँ	१४८
स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय	१६१
उपसंहार	१७७

१७. स्त्री-शिक्षा

प्रस्तावना	१७८
स्त्री-शिक्षा का विस्तार	१७८
वर्तमान स्थिति	१८१
आलोचना	१८७
उपसंहार	१९२

तालिका-सूची

१. प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का आवण्टन (करोड़ रुपये)	२३
२. प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य	२५
३. भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या	२६
४. अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा, १९२१-३७	७१
५. प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	७२
६. प्राथमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	७३
७. प्राथमिक तथा युनिवर्सिटी शिक्षा, १९५१-५२ से १९५६-५७	७५
८. एक शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल	७६
९. शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय, १९०१-०२ से १९४७-४८	८१
१०. कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति	८८
११. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७	१०६
१२. माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	१०८
१३. माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	११०
१४. मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल	११४
१६. कालिजों की संख्या, सन् १८५७	१३७
१७. अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४७	१४२
१८. प्रबन्धानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६	१४३
१९. उच्च शिक्षा की आय का स्रोतवार बँटवारा, १९५५-५६	१५८
२०. विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग द्वारा अनुदान आवण्टन	.	..	१५९
२१. विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम, १९५५-५६	१६३
२२. स्कूल तथा कालिजों में लड़कियों की संख्या, १९२१-२२ से १९४६-४७	१८०		
२३. कालिका माध्यमिक शिक्षा में प्रगति	१८५
२४. विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या	१८६
२५. कतिपय क्षेत्रों में नारी	१८८
२६. भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७	२४०
२७. समाज शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६	२५६
२८. मजदूरों की शिक्षा सस्थाएँ, १९५५-५६	२६५
२९. राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की प्रगति	२७३
३०. राष्ट्रीय अनुशासन योजना की व्यवस्था, १९५९-६०	२७७

१२. उपसंहार २९०
परिशिष्ट			
१. शिक्षा-संस्थाएँ एवं छात्र-संख्या, भारत (१९५६-५७) ३००
२. भारत के विश्वविद्यालय, १९५८ ३०२
३. पारिभाषिक शब्दावली ३०५
ग्रन्थ-सूची ३१०
अनुक्रमणिका (विषयानुसार) ३२०
अनुक्रमणिका (नामक्रमानुसार) ३२९

पहला अध्याय

भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा

[एक सिंहावलोकन]

भूमिका

आज हमारा देश पिछड़ा गिना जाता है। यदि अर्थाभाव पिछड़ेपन का लक्षण है तो हमें कुछ कहना नहीं है। यदि निरक्षरता के कारण हम पिछड़े गिने जाते हैं, तो भी हमें चुप रह जाना पड़ता है। किन्तु यदि सभ्यता की दृष्टि से देखा जाय तो कुछ इन्ने गिने देश ही हमारी बराबरी कर सकते हैं। जब हमारा देश समार का सिरमौर समझा जाता था, तब पाश्चात्य देश बर्बर गिने जाते थे। यद्यपि आज ८३ प्रति शत भारतवासी निरक्षर हैं, तथापि वे गर्वों नहा कहे जा सकते हैं। चाता ही गतों में उनके मुँहों से कबीर, तुलसी प्रभृति की उपदेश-भरी पक्तियाँ निकल पड़ती हैं। वे आल्हा ऊदल की वीर-रस-पूर्ण वीर-गाथा बजानने लगते हैं, और नरसी मेहता तथा कम्बन के भक्ति मय गीतों को सुनकर विभोर हो उठते हैं।

इसका मुख्य कारण है हमारी सस्कृति। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक हमारी सस्कृति की धारा अटूट बहती आ रही है। निश्चय ही उसे अनेक आँधी तूफानों का सामना करना पड़ा, तो भी हमारी सभ्यता का क्रम अक्षुण्ण रहा। आज भी हमारी प्राचीन कला तथा साहित्य की उत्कृष्टता को समार स्वीकार करता है। अनेक सभ्य देश तो काल के गाल में समा गये, पर भारत आज भी सिर ऊँचा किये खड़ा है। हमारी शिक्षा की सुदृढ़ नींव पर आधारित हमारी सभ्यता आज भी गर्वोन्नत माल खड़ी है।

शिक्षा का आरम्भ ऋग्वेद काल से होता है। इस अवधि अर्थात् २,५०० ई० पू० से वर्तमान सन् १९६० ई० तक के वर्षों को विचार एवं विवेचना की सुविधा के लिए, हम निम्नलिखित पाँच भागों में बाँट सकते हैं :

चित्र-सूची

१. शिष्यग-सहित तक्षशिला के एक आचार्य	...	८
२. बौद्ध विश्वविद्यालय में भिक्षुगण	...	१०
३. केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय	...	३०
४. शिक्षा-सीढ़ी	...	३७
५. बुनियादी शिक्षा में समवाय	...	५५
६. भारत में प्राथमिक शिक्षा	...	७८
७. प्रारम्भिक शिक्षा-की प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य...	...	८४
८. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार	...	१०६
९. माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य बच्चों की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में शिक्षा का प्रबन्ध, १९५५-५६	...	१०६
१०. हाईस्कूल पाठ्य-विषयों के निर्वाचन के लिए निर्देश	...	१२९
११. उच्च शिक्षा की प्रगति, १९५१-१९७७	...	१४९
१२. उत्तीर्ण प्रेजुप्ट-संख्या, १९५१-५२ से १९५५-५६	...	१६४
१३. स्त्री-शिक्षा, १९५५-५६	...	१८२
१४. प्राविधिक शिक्षा की प्रगति, १९४७-५७	...	२०१
१५. प्रमाण कार्य	...	२३०
१६. घेतन बर्गों के अनुगार कालिन्न-अध्यापकों का बर्गीकरण, १९५५-५६	...	२४२
१७. खेल-पद्धति द्वारा शिक्षा	...	२६६
१८. सुवह-कल्याण	...	२७६
१९. गत-भर्ग की छात्रा में गुरुदेव (शान्ति-निकेतन)	...	२८२
२०. सेवामान में गान्धीजी की कुटिया	...	३८८

के लिए जाता था। उपनयन का अर्थ है गुरुकुल में पहुँचाने का संस्कार। प्रथम तीन वर्षों के लिए गुरुकुल में अध्ययन करना अनिवार्य था। शूद्र अपने शिक्षागुरु या पिता से आवश्यक अध्ययन करता था। गुरुकुल में शुल्क नहीं लिया जाता था। बालक से गुरु पूछते थे—‘कस्य ब्रह्मचारी असि?’ (तुम किसके ब्रह्मचारी हो?) बालक उत्तर देता था—‘भवतः’ (आपका)। फिर उसका नाम पूछा जाता था, और वह प्रविष्ट कर लिया जाता था।

गुरुकुल आश्रम, नगर के कोलाहल से दूर, किसी नदी या वृहत् जलाशय के समीप होता था, जिससे शान्त वातावरण में समुचित पढ़ाई हो सके तथा निवास के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु गृह में जितेंद्रिय रहकर ब्रह्मचर्य-जीवन पालन करना पड़ता था। उसका जीवन अति सयमी तथा सात्विक होता था। तामसिक पदार्थों का सेवन, शशी भक्षण, मिठाई आदि का भोजन, तथा तेल, जूता, छतरी और दर्पण का उपयोग करना विद्यार्थी के लिए निषिद्ध था। उसे कठोर शय्या पर सोना होता था और धोये हुए सच्छ वस्त्रों को पहनना पड़ता था। उसे स्त्रियों के बीच बैठने की मनाही थी।

ब्रह्मचारी की दिनचर्या भी बँधी थी। प्रति दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म समाप्त कर, उसे आश्रम के लिए कुश, जल, समिधा आदि लाना होता था। तत्पश्चात् आश्रम को बुहारकर, गायों को दुहकर तथा दुग्ध पानकर वह गुरुजी के पास जाता था। वहाँ वह गुरुजी को प्रणाम कर चुपचाप उनका पढ़ाया हुआ पाठ सुनाता तथा सुनता था। पाठ पूरा होने पर वह गुरुजी की आज्ञा से अपनी शका समाधान करता था। दोपहर के समय, वह निकट जे किसी गाँव या नगर में मिश्रा भोगने जाता था। प्राप्त मिश्रात्र गुरुपत्नी को देता, तथा उसका दिया हुआ भोजन खाकर वह कुछ समय विश्राम करता था। विश्राम के बाद वह प्रातःकाल जे पाठ की चर्चा अन्य सहपाठियों के साथ करता था। सन्ध्या के समय वह व्यायाम करता था। फिर, आश्रम को साफ कर, गौओं को दुहकर तथा निकट के गाँव से मिश्रा लेकर वह गुरु के पास जाता था। गुरु या किसी साधु विद्वान से इतिहास पुराण की कथा-वार्ता सुनकर या किसी वयोवृद्ध का सत्संग कर वह एक पहर रात गये सो जाता था, और पुनः दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाता था।

प्रत्येक बालक को सांस्कारिक, नैतिक, शारीरिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। सांस्कारिक शिक्षा के अन्तर्गत चार वेद, वेदाङ्ग, दर्शन तथा नीतिशास्त्र

१. वैदिक युग	...	२,५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक;
२. बौद्ध युग	...	५०० ई० पू० से १,२०० ई० तक;
३. मुस्लिम युग	...	१,२०० ई० से १,७५७ ई० तक;
४. बृटिश युग	...	१,७५७ ई० से १,९४७ ई० तक; और
५. स्वातन्त्र्योत्तर काल	...	१,९४७ ई० से आगे।

प्रस्तुत पुस्तक में वर्तमान शिक्षा-स्थिति की विस्तार-पूर्वक चर्चा की गयी है तथा शिक्षा के जटिल प्रश्नों की विशद रूप से व्याख्या की गयी है। पर इन्हें समझने के लिए हमें अतीत को समझना आवश्यक है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान सदैव बीती हुई घटनाओं की नींव पर खड़ा होता है। इसी कारण इस अध्याय में भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप रेखा दी गयी है तथा अगले अध्यायों के प्रत्येक शिक्षा-प्रश्न की पूर्व-वृष्टिगत संक्षेप में दी गयी है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय शिक्षा के इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों तथा घटनाओं का ही वर्णन किया है। ये इस प्रकार चुनी गयी हैं, जिनसे वर्तमान स्थिति पर सम्यक् प्रकाश पड़े।

वैदिक युग में आर्यों ने यह सिद्धान्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर पर तीन ऋण लेकर पैदा होता है—देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण। अन्नादि का दान देकर तथा यज्ञ कर के वह देव-ऋण से मुक्त होता है, विवाह कर और पुत्र उत्पन्न कर वह पितृ-ऋण से छूटता है, तथा अध्ययन और अध्यापन कर वह ऋषि-ऋण से उन्मूढ होता है।

वैदिक युग

वैदिक युग में मानव-समाज कर्म-स्वभाव के अनुसार चार वर्णों में बाँट दिया गया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का कर्तव्य था प्रजा तथा धार्मिकों का रक्षण और पालन करना, वैश्य का काम था व्यापार और खेती करना, तथा शूद्र का काम था सेवा करना और सब वर्णों के काम की वस्तुएँ बनाना। समाज को पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए, इस वर्ण-व्यवस्था की सृष्टि की गयी थी, जिससे प्रत्येक मनुष्य वही काम करे, जिसके लिए वह उपयुक्त समझा जावे। जाति-भेद की व्यवस्था उस समय किसीने सोची भी नहीं थी।

अध्ययन के प्रथम ठीक-ठीक बाँट दिये गये—जन्म से सात वर्ष तक घर में, और उसके बाद गुरुकुल में। आठवें वर्ष उपनयन के पश्चात्, बालक गुरुकुल में विद्याध्ययन

ऊँच नीच का भेद भाव न था। इस प्रकार गुरुकुलों का सामाजिक जीवन भ्रातृभाव से परिपूर्ण था। इसी कारण आर्थिक सङ्कट के समय सुदामाजी सहायतार्थ अपने पूरे सहापाठी श्रीकृष्ण भगवान् के निकट दौड़े गये थे, और एक नृपति होकर भी उन्होंने अपने एक भूतपूर्व दीन सहापाठी का समुचित सम्मान किया था।

वैदिक कालीन शिक्षण-पद्धतिम तीन क्रियाओं का समावेश था — श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। अध्यापन के समय विद्यार्थी गुरु न वचन को ध्यान पूर्वक सुनते थे। पाठ समाप्त होने पर विद्यार्थी प्रश्न करते थे और गुरु उनके उत्तर देते थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर-प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थियों न उत्तर की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। अपने अज्ञान के समय वे पठित पाठ का मनन और निदिध्यासन (चिन्तन) करते थे।

गुरुकुलों में आजकल के समान पराक्षा प्रणाली न थी। गुरुजी प्रति दिन जो कुछ पढ़ाते थे, उसे उसके अगले दिन प्रत्येक विद्यार्थी से सुनते थे। जहाँ कमी रह जाती थी, उसे वहाँ विद्यार्थी पूरा कर लेता था। पूर्णतः सन्तुष्ट होने पर ही गुरुजी अगला पाठ पढ़ाते थे। इस प्रकार प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत योग्यता की ओर विशेष लक्ष्य दिया जाता था। बीच बीच में गुरुजी आश्रम के विद्यार्थियों को दो टलों में बाँट देते थे, जिनमें परस्पर शास्त्रार्थ चलता था। कभी कभी दो गुरुकुल के छात्रों में भी परस्पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। प्रत्येक विद्वान् को भी सदैव शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता था। उसे कोई भी शास्त्रार्थ के लिए आह्वान कर सकता था, और उसे स्वार्जित विद्या का परिचय देना पड़ता था। आजकल के विद्यार्थी तो अपनी विद्वत्ता की साक्षी के रूप में विश्वविद्यालय का एक दस्तावेज पेश कर सकते हैं, पर वैदिक काल में प्रत्येक विद्वान् की विद्वत्ता उसकी जीभ पर नाचती थी। वह नहीं कह सकता कि मैंने जो कुछ सीखा था उसे भूल गया हूँ। उसे सदैव विद्या की चर्चा रुकनी पड़ती थी।

इस काल में कन्याओं का यज्ञोपवीत तो अवश्य होता था, पर पालकों के समान उनके लिए गुरुकुल न थे। ऋग्वेद के काल में स्त्रीशिक्षा पूर्णतः प्रचलित थी। सहशिक्षा वर्जित न थी, पर धीरे धीरे यह प्रथा उठ गयी। याज्ञवल्क्य ने बालिकाओं का उपनयन अनावश्यक समझा तथा उनका विवाह ऋतु प्रारम्भ के पूर्व होने लगा। अन्तिमतर कन्याओं के लिए यह नियमान था कि वे अपने माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी, सास तथा पति से विद्या प्राप्त करें। आचार्यों की कन्याएँ स्वयं अपने पिता के साथ रहकर विद्याध्ययन करती थीं, जैसे गार्गी, देवयानी, मैत्रेयी आदि। हमारे धर्म ग्रन्थों में

सभी को पढ़ना पड़ता था। अपने-अपने वर्ण के अनुसार विद्यार्थीगण वेद तथा वेदाङ्ग का अध्ययन करते थे। नैतिक शिक्षा कुछ तो उपदेश से और कुछ आश्रम के वातावरण से मिलती थी। शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम और व्यायाम का विधान था। यों तो दैनिक नियमित कार्यों के सम्पादन में ही पर्याप्त व्यायाम हो जाता था, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को लकड़ी काटना, पानी भरकर ढोना तथा आश्रम की स्वच्छता करना आवश्यक होता था।

व्यावसायिक शिक्षा वर्णों के अनुकूल दी जाती थी। ब्राह्मण पौरोहित्य, दर्शन, कर्मकाण्ड आदि विषय का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय दण्ड-नीति, राज-नीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद आदि सीखते थे तथा वैश्य को पशु-पालन एवं कृषि-विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त करना पड़ती थी। इन विषयों के सिवा आयुर्वेदादि विषय अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी छात्र सीख सकते थे। एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा रहते हुए भी, प्रत्येक छात्र को किसी एक विषय में पारङ्गत होना पड़ता था। साधारणतः पच्चीस वर्ष की आयु में तीनों वर्णों की शिक्षाएँ पूरी हो जाती थीं; पर ब्राह्मण को यह विशेषाधिकार था कि वह आजीवन स्वेच्छापूर्वक विद्यार्जन करे—‘यावज्जीवमधीते विप्रः’। शिक्षा समाप्त होने पर तथा गुरु-दक्षिणा देकर प्रत्येक विद्यार्थी विवाहोपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता था।

आचार्य या गुरु सत्र से ऊपर के वर्गों के छात्रों को पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी अपने से निम्न वर्ग के छात्रों को सिखाते थे, और वे अपने से नीचे वालों को। इस प्रकार सत्र से नीचे वर्ग के छात्रों के सिवा, गुरुकुल में सत्र गुरु-ही-गुरु रहते थे। अध्यापन के समय, प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। कारण, वैदिक काल में गुरु किसी विद्यालय या वर्ग के शिक्षक न थे। गुरु का कर्तव्य केवल पढ़ाना ही न था। उसका धर्म था कि वह प्रत्येक छात्र को सदाचारी बनावे, उसके आचरण की रक्षा करे, उसका चरित्र-गठन करे, उसके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध करे तथा उसके प्रति अपने पुत्र के समान वात्सल्यभाव दिखावे। विद्यार्थी भी गुरु को पिता और देवता समझता था। उसे ‘आचार्यदेवो भव’ की शिक्षा दी जाती थी। यह सत्र कुछ सम्भव था, क्योंकि शिक्षा सावास-प्रणाली के अनुसार दी जाती थी और गुरु तथा शिष्य साथ-साथ रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का शिष्य गुरु का केवल विद्यार्थी ही नहीं होता था, वरन् वह गुरु-परिवार का एक सदस्य भी होता था। इस गुरु-परिवार में गरीब और अमीर साथ-साथ रहते और विद्याध्ययन करते थे। वहाँ

काष्ठ शिल्प, चिकित्सा तथा शल्य शास्त्र, धनुर्विद्या तथा युद्ध विद्या, ज्योतिष (गणित और फलित), भविष्य-कथन, जादू, गारुडी विद्या, गुप्त द्रव्योत्पादन, संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य । †

बौद्ध युग

भूमिका.—प्रसिद्ध दार्शनिक श्रीराधाकृष्णन् का कहना है “ बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं, अपितु हिन्दू धर्म का ही परिवर्तित रूप है । ” ‡ जिस समय भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था (५६३ ई० पू०), उस समय धार्मिक सुधारों की विशेष आवश्यकता थी । वैदिक धर्म में ज्ञान एवं कर्म के समन्वय का सम्पूर्ण ह्रास हो गया था । इसके ब्रह्मे यज्ञ का आडम्बर आ गया था, जिसमें मास की आहुति देना आवश्यक था । ब्राह्मणों की प्रधानता उठ गयी थी और उनके सिवा अन्य जातियों से उपनयन संस्कार उठ गया था । ब्राह्मणों ने तो अपने फुन्दे में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी—को फँस रखा था । जनता उनके बनाये हुए नियमों तथा धार्मिक अन्ध-विश्वासों से तड़क आ गयी थी, और कहीं भी स्वतन्त्रता का मार्ग दिग्गलयी नहीं पड़ता था । ब्राह्मण पुकार पुकार कर कह रहे थे कि नीच जातियों मोक्ष नहीं पा सकतीं, अत एव उनकी आशालता पूर्ण रूप से मुरझा गयी थी और उनकी आन्तरिक भावनाओं में उन्नति की ज्योति प्रज्वलित नहीं रही थी ।

उन्नति की वह ज्योति दिरगयी एक क्षत्रिय राजकुमार—गौतम बुद्ध ने । जाति पौति का भेद-भाव उठाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार जन-भाषाओं द्वारा सभी अश्वत्था, वर्ग, जाति तथा स्त्री पुरुष में किया । जीवन का लक्ष्य ठहराया गया निर्वाण या मोक्ष । इसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय ठहराया गया—अहिंसा तथा पवित्र जीवन । भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को दो भागों में विभाजित किया—भिक्षु अर्थात् पुरुष और भिक्षुणी अर्थात् स्त्री ।

पञ्चउज्जा तथा उपसम्पदा.—वैदिक शिक्षा की मूर्ति बौद्ध शिक्षा का प्रारम्भ संस्कारों से ही होता है । इनमें दो मुख्य थे—पञ्चउज्जा (प्रव्रज्या) और उपसम्पदा । वैदिक धर्म में जो स्थान उपनयन संस्कार का है, बौद्ध धर्म में वही स्थान

† D G Apte *Universities in Ancient India* Baroda, Faculty of Education & Psychology. n d pp 13-14

‡ S Radhakrishnan *Indian Philosophy*, Vol I p 360

विश्ववारा, लोपामुद्रा, आत्रेयी, मैत्रेयी, घोषा, वज्राया इत्यादि अनेक विदुषियों का होना पाया जाता है।

गुरुकुल के परिपोषण के लिए अनेक नृपति गाँव के गाँव लगा देते थे। इसके बदले गुरुकुल को न कुछ अर्थ ही देना पड़ता था और न कर ही भुगतना होता था। ऐसी वस्ती को ब्रह्मपुरी या अग्रहार, तथा इस प्रकार के टान को मह-वृत्ति कहते थे। गुरुकुलों के सिवा अनेक तीर्थ-स्थानों तथा शहरों में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान् आचार्यों ने अपने गृहों में ही विद्या-केन्द्र खोल रखे थे। इन नगरों में काशी, कांची, कनौज, तक्षशिला, तजौर, पाटलीपुत्र, नाशिक, मिथिला प्रधान विद्या-क्षेत्र थे।

वैदिक युग में, विद्या की सबसे महत्व-पूर्ण सस्था परिषद् थी। ये परिषद् विशिष्ट विद्वानों की गोष्ठियाँ थीं। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने के लिए परिषद् की बैठकें समय समय पर होती थीं। इनका निर्णय राज्य एवं प्रजा - दोनों - को मानना पड़ता था। परिषद् के सदस्यों की संख्या १० से २१ तक होती थी। गौतम धर्म-सूत्र के अनुसार इन दस सदस्यों का संयोजन इस प्रकार था: (१) चार वेदों के पूर्ण ज्ञाता, (२) धर्मशास्त्रों के तीन पण्डित तथा (३) ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ - तीनों - के एक एक प्रतिनिधि। धीरे धीरे इन विद्वानों के पास अनेक छात्र विद्याध्ययन के लिए आने लगे तथा परिषदों ने सावास विश्वविद्यालयों का रूप धारण किया। श्री राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं, “परिषद् में आधुनिक विश्व-विद्यालयों के सभी उपकरण वर्तमान थे।” † इन विद्या-केन्द्रों में दो मुख्य थे— एक, ‘काशी’ और दूसरा, गान्धार की राजधानी ‘तक्षशिला’।

७०० ई० पू० से ५०० ई० पू० की अवधि में तक्षशिला शिक्षा का प्रधान केन्द्र रहा। यह स्थान रावलपिंडी से २० मील पश्चिम की ओर था। यहाँ अनेक आचार्यों ने अपने विद्या-केन्द्र खोल रखे थे, और संसार के दूर-दूर के देशों से विद्यार्थिगण अध्ययन के लिए आते थे। एक-एक आचार्य के पास पाँच-पाँच सौ विद्यार्थी पढ़ते थे। यथार्थ में तक्षशिला एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बन गया था, और भारत के अन्य नगरों के अनेक विद्या-केन्द्र इससे सम्बन्धित थे। इस विश्वविद्यालय में केवल उच्च शिक्षा ही दी जाती थी। चारों वेदों के अतिरिक्त यहाँ निम्न लिखित विषय पढ़ाये जाते थे: धर्म, विधि (कानून), गणित, कृषि, वाणिज्य, पशु-विद्या, लौह-शिल्प,

† R. K. Mookerji. *Ancient Indian Education*. Bombay, Macmillan, 1951. pp. 220-22.

प्रव्रज्या (पब्रज्जा) का है। इस संस्कार का शाब्दिक अर्थ 'बाहर जाना' है। इस संस्कार में द्वारा एक अष्टवर्षीय बालक या बालिका अपने गृह से सदा के लिए अलग होकर एक सघ में प्रवेश करता था। पब्रज्जा का द्वार सभी वर्गों के लिए खुला था। अपनी सिर मुड़ाकर तथा पीत वस्त्र पहन कर, विद्यार्थी नत मस्तक होकर भिक्षु को प्रणाम करता था तथा प्रार्थना करता था कि वह उस शिष्यरूप में स्वीकार करें। इसके स्वीकार होने पर, उसे अपने उपाध्याय के सम्मुख 'सगणत्रय' में तीन प्रणामों को तीन बार उच्चारण कर कहना पड़ता था

बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सघं शरणं गच्छामि।

पब्रज्जा प्रविष्ट छात्र समनेर अथवा भ्रमण कहलाता था। लगातार लगभग बारह वर्ष विद्याध्ययन करने में पश्चात्, तीस वर्ष की आयु में भ्रमण उपसम्पदा संस्कार ग्रहण करता था। इस संस्कार में पश्चात् वह भिक्षु कहलाता था। उसे चार व्रत धारण करने का प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी (१) वृक्ष में नीचे बास करना, (२) भिक्षा-पात्र में भिक्षान्न एकत्रित करना भोजन करना, (३) माँग हुए वस्त्रों से शरीर ढँकना और (४) औषधि रूप में गौमूत्र सेवन करना। उपसम्पदा से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक विद्यार्थी पच्चीस वर्ष की आयु में स्नातक होकर गार्हस्थ्य जीवन पालन करते थे, पर बौद्ध विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर सघ के स्थायी संन्यस्त बन जाते थे, और शेष जीवन भिक्षु रूप में बिताते थे।

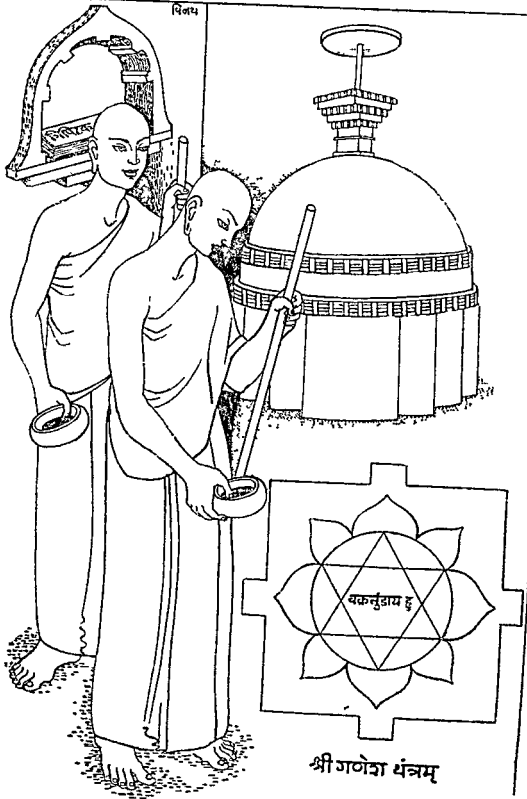
दैनिक जीवन — वैदिक ब्रह्मचारियों की नाई भ्रमणों तथा भिक्षुओं का जीवन शुद्ध एवं सात्त्विक, सरल तथा आदम्बर शून्य होता था। उनका भोजन अति सादा होता था, मस्तक मुँगा हुआ रहता था और शरीर पर चीवर धारण करते थे। उनका जीवन नियमित रहता था, वह विनम्र एवं अनुशासित होते थे तथा उनके अध्ययन, भिक्षाटन और भोजन के लिए समय निर्धारित रहता था। उन्हें अपने आचार्य की विभिन्न सेवाएँ करनी पड़ती थीं, और मठ को साफ सुथरा भी रखना पड़ता था।

विहार — भिक्षु तथा भिक्षुणी विहार या सघाराम में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। विहार शहरों आबादी से दूर स्थापित होते थे। बौद्ध शिक्षा मठ या विद्यालय नहीं से जुड़े हुए रहते थे। वैदिक गुरुकुल की नाई इनकी छोटी-छानी टोलियों नहीं होती थीं। वे प्रशस्त होते थे, तथा प्रत्येक मठ में कम से कम ५००-१,००० विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध रहता था। इसके सिवा, स्त्रियाँ ने मठ एवं विहार प्रत्येक होते थे।



विद्यया

हिन्दुमतसहित मञ्जुनिता के एक भाषादे



श्री गणेश यंत्रम्

बौद्ध शिक्षा-पद्धति की एक और विशेषता थी। वह थी संघीय प्रणाली। इसके अनुसार छोटे-मोटे वैयक्तिक विद्यालय एक बड़े समुदाय से सम्बन्धित रहते थे। इनके छात्रगण अपने उपाध्याय से वैयक्तिक शिक्षा अवश्य ग्रहण करते थे, तिस पर भी वे केन्द्रीय सभा के सदस्य होते थे तथा उसके समस्त सामूहिक व्यापारों में भाग ले सकते थे। इस प्रकार यह संघीय प्रणाली वर्तमान संबंधीय विश्वविद्यालयों से मिलती-जुलती है।

पाठ्यक्रम.—बौद्ध शिक्षा में दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था : (१) लौकिक और (२) धार्मिक। प्रथम पाठ्यक्रम का उद्देश्य था साधारण स्त्री-पुरुषों को उचित नागरिक बनाना तथा उन्हें अपने भावी जीवन के लिए तैयार करना। इस पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के कला-कौशल, शास्त्रार्थ, सारथीविद्या, घनुर्विद्या, मन्त्रविद्या, चित्रकारी, संगीत, चिकित्साशास्त्र प्रभृति होते थे।

धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिए होता था। इसमें इन पाठ्य-विषयों का समावेश था : (१) बौद्ध धार्मिक साहित्य, जो नौ भागों में विभक्त था, (२) मठों तथा विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान और (३) विहारों को दिये गये दान की सम्पत्ति का हिसाब-किताब तथा प्रबन्ध।

इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने जन-शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। बौद्ध उपाध्यायों का यह कर्तव्य था कि वे अपने परिभ्रमण में प्रवचन करें। इसके द्वारा वे गृहस्थों को धर्म की शिक्षा देते थे तथा उनकी शकाओं का समाधान करते थे। उपाध्याय के पीछे-पीछे उनके शिष्यगण प्रवचन सुनते चलते थे।

अध्यापन-विधि.—बौद्ध विहारों में साधारणतः प्रवचन या व्याख्यान-द्वारा शिक्षा दी जाती थी। उपाध्याय एक मंच पर बैठते थे, और भिक्षुगण उनके तीन ओर बैठकर मौनपूर्वक प्रवचन सुनते थे। जहाँ कुछ शक्का होती थी, वहाँ विद्यार्थीगण उपाध्याय की आज्ञा लेकर प्रश्न पूछते थे। प्रवचन प्रणाली के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षाक्रम में व्याख्या-प्रणाली, प्रश्नोत्तर-विधि तथा वाद-विवाद की रीति का प्रमुख स्थान था। इस काल में लिपि का प्रचलन हो गया था। सम्भवतः पुस्तकाधारित अध्यापन-विधि भी चालू थी। इसके अतिरिक्त, भिक्षुगण आपस में पाठ-चर्चा या ज्ञान-विनिमय भी किया करते थे। देशाटन तथा प्रकृति-निरीक्षण को भी मान्यता दी जाती थी।

बौद्ध विश्वविद्यालय.—बौद्ध शिक्षा में सबसे अधिक उद्देश्ययोग्य बौद्ध विश्वविद्यालय : नालन्दा (विहार), यहमी (गुजरात), ज्येन्द्रविहार (काश्मीर), जम्बुधर विहार (पंजाब), विक्रमशिला, ओडन्तपुरी तथा जगदड (बंगाल), इत्यादि। यहाँ विश्व के

महमूद गज़नवी के आक्रमण के बाद से बतने लगे। जहाँ जहाँ यवन सेनाएँ पहुँचीं, वहाँ वहाँ उलेमा तथा इस्लाम के धर्म-प्रचारक पहुँच गये। जहाँ वे बस गये, वहाँ इस्लामी धर्म-शास्त्रों की शिक्षा देने लगे।

ईसा की तेरहवीं शताब्दी में, मङ्गोलों ने मध्य एशिया में लूट-मार मचा दी। इस कारण अनेक उलेमा वहाँ से भाग कर दिल्ली में आये। तथा उन्होंने बलघन के दरबार में शरण ली। ये विद्वान् बल्लु, बुरसाग, समरकन्द, ख्यारीज़म से आये थे, जो मुस्लिम सस्कृति के प्रधान केन्द्र थे। उस समय दिल्ली में इतने विद्वान् इकट्ठे हो गये थे कि बरनी के कथनानुसार वह बगदाद और करतब्या से मुकाबला करती थी। इस प्रकार भारत में जो दिल्ली इस्लामी राज्य की राजधानी थी, वह मुस्लिम सस्कृति और शिक्षा का केन्द्र बन गयी।

भारत में यवन-आधिपत्य प्रायः साढ़े पाँच सौ वर्षों तक रहा, अर्थात् कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण से प्रसी के युद्ध तक (१२०६-१७५७ ई०)। इस दीर्घकालीन आधिपत्य के फल-स्वरूप भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता विशेष रूप से प्रभावित हुई। साहित्य तथा ललित कलाओं का विकास हुआ, भारतीय भाषाओं को नया रूप मिला तथा नवीन 'भक्ति-मार्ग' का जन्म हुआ। मुस्लिम शासन का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। प्रथमतः, एक नयी शिक्षा-प्रणाली की नींव इस देश में पड़ी। हम इसे मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली कह सकते हैं। यह उन भारतीयों के लिये निर्मित हुई थी, जिन्होंने इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी। द्वितीयतः, यवन सत्ता का प्रभाव पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणालियों पर पड़ा। इन दोनों विषयों की चर्चा अगले शीर्षकों में की जावेगी।

मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली.—भारत में मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली का यही स्वरूप था, जो अन्य इस्लामी देशों में प्रचलित था। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। साधारणतः मकतब प्रत्येक मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे। कहीं कहीं मकतब मौलवियों के घर अथवा अन्य स्थानों में लगते थे। मकतबों का पाठ्य-क्रम कुरान पर ही केन्द्रीभूत होता था। कुरान के साथ-साथ बालकों को घुजू करना, नमाज़ पढ़ना, अज्ञान के समय पढ़ी जानेवाली दुआएँ इत्यादि भी सिखायी जाती थी। उन्हें मकतब में ही सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था।

मकतब में कुरान "नाज़िरा" रीति से पढ़ाया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अरबी वर्णमाला का ज्ञान होने के पश्चात् विद्यार्थी अर्थ-ग्रहण किये बिना ही कुरान का पाठ करते थे। सबसे पहले बालकों को तख्ती पर अक्षर लिखकर उनके नाम बता दिये

कोने-कोने से विद्यार्थीगण विद्याभ्यास के लिए आते थे और उन्हें यहाँ प्रविष्ट होने के लिए वर्षों ठहरना पड़ता था। प्रवेश पाने के लिए परीक्षा का विधान कठोर था। इन विद्यालयों के अन्तर्गत पुस्तकालय, छात्रावास तथा अतिथि-शाला के लिए अनेक सुन्दर भवन थे। विद्यालय के व्यय की समस्या राजा-महाराजाओं ने अनेक गाँव अधयनीवी (स्थिर पोषण) में देकर सुलझा दी थी। नालन्दा में प्राप्त यशोवर्मा के शिला-लेख में लिखा है :

अपने शुभ्र ऊँचे चैत्यों के किरण-समूहों से नालन्दा नगरी बड़े-बड़े राजाओं की नगरियों की मानों हँसी उड़ाती है और इसके जिन ऊँचे प्रासादों एवं विहारों की पंक्तियों में प्रसिद्ध धुरन्धर विद्वान् वास करते हैं, वे उस सुमेरु पर्वत-सी शोभावाली लगती हैं, जिनमें विद्याघर वास करते हैं।

इन विश्वविद्यालयों का पाठ्य-क्रम सर्वाङ्गपूर्ण था तथा उसमें बौद्धीय या अबौद्धीय महायान तथा हीनयान विषयों का समावेश था। कुछ विषय तो अनिवार्य थे, और कुछ ऐच्छिक। प्रत्येक भिक्षु को महायान तथा अठारह सम्प्रदायों के ग्रन्थ का अध्ययन करना पड़ता था। व्यायाम तथा दैनिक चंक्रमण अर्थात् टहलना भी सबके लिए अनिवार्य था। इनके अतिरिक्त दर्शन, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, तान्त्रिक दर्शन, वेद तथा वेदाङ्ग, आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र, व्याकरण, विधि (कानून), भाषा शास्त्र, इत्यादि भी पाठ्यक्रम में रखे गये थे। बौद्ध संस्थाएँ होते हुए भी, इन विश्वविद्यालयों में साम्प्रदायिकता की बू न थी।

अन्त.—मुसलमानों के आक्रमण के कारण भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ। बहुत से भिक्षु तो तलवार के घाट उतार दिये गये, और अनेक भारत के बाहर भाग गये। यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है। सन् १२३० ई० में अख्तियार खिलजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहुँचा। उसने उसे भूल से एक गढ़ समझ लिया, और उसके भिक्षुओं को सिपाही। कारण, विश्वविद्यालय के भवन के चारों ओर एक दीवार थी, और सब भिक्षुओं के शरीर पर पीत वस्त्र थे। बस, क्या था, भवन ध्वस्त कर दिया गया और सिरमुँड़े भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। कहा जाता है कि विश्व-विद्यालय का विशाल पुस्तकालय छः महीने निरन्तर जलता रहा।

मुस्लिम युग

भूमिका.—भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन प्रथम हिजरी शताब्दी के अन्त में अर्थात् आठवीं शताब्दी ईस्वी के आरम्भ में हुआ था। पर वे इस देश में

थी, इस कारण शिक्षा-केन्द्रों के सत्यानाश के साथ-साथ इस देश से बौद्ध शिक्षा-प्रणाली का भी लोप हो गया। इसके विपरीत वैदिक शिक्षा इस कारण अमिट रही कि यह शिक्षा गुरु-केन्द्रित थी। इसके विद्यालय छोटे-मोटे थे, जिनकी छात्रसंख्या ३०-४० से अधिक न थी और वे समूचे देश में फैले हुए थे। ये दो प्रकार के थे : (१) संस्कृत विद्यालय — इन्हें बङ्गाल में 'टोल' तथा पश्चिम भारत में 'पाठशाला' कहते थे। इनकी पढ़ाई बहुत ही ऊँचे दर्जे की थी इन विद्यालयों में पाँच विषयोंका अध्यापन होता था — तर्क, कानून, साहित्य, उद्योग तथा व्याकरण। प्रत्येक विद्यालय अपना एक ही विषय पढ़ाता था। (२) प्रायमरी स्कूल — जो गाँव-गाँव में फैले हुए थे। ये दोनों प्रकार के विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मौजूद थे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह प्रणाली 'देशी शिक्षा' के नाम से प्रसिद्ध है। †

शिक्षा और राज्य.—वैदिक तथा बौद्ध युग में, शिक्षा का राज्य से कोई सम्बन्ध न था, तथापि हिन्दू नृपतिगण शिक्षा-केन्द्रों तथा विद्वानों को यथेष्ट दान देते थे। मुसलमान-सुल्तानों तथा बादशाहों ने अनेक मकतब, मदरसे तथा पुस्तकालय खुलवाये, तथा उलेमा और मोअहिमों को सरकारी खजाने से बजीफ़े दिये। पर पठानों के काल में शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था न थी। वस्तुतः शिक्षा शासक की रुचि पर निर्भर रहती थी। इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन तथा फ़ीरोजशाह शिश्वा में अभिरुचि रखते थे। पर अलाउद्दीन, इब्राहीम लोदी आदि बादशाहों का विद्या से कोई प्रेम न था। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण बाबर ने अपनी आत्म-कथा में लिखा है कि 'भारतीय शिक्षा गिरती हुई अवस्था में है।'

मुगलवंश के सभी बादशाह विद्या-प्रेमी थे। बादशाह अकबर ने मुस्लिम शिक्षा को एक नयी दिशा देने की कोशिश की। सरकारी नौकरों के लिए राजभाषा फ़ारसी के ज्ञान की ज़रूरत थी, पर अनेक हिन्दू मकतब तथा मदरसे में अध्ययन करने में हिचकते थे। अकबर ने पाठ्य-क्रम में सुधार किया तथा मकतबों और मदरसों में हिन्दुओं के पढ़ने-लिखने की उचित व्यवस्था की, ताकि पढ़ने की हिचकिचाहट दूर हो और उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान मिले।

इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुआ। इसी समय एक नवीन भाषा — उर्दू — की सृष्टि हुई। हिन्दू तथा मुस्लिम ग्रन्थों के अनुवाद होने से नवीन विचारों के स्रोतों का उद्गम हुआ, तथा सूफ़ी मत का उदय हुआ। इस प्रकार शनैः शनैः भारतीय तथा आर्यनी संस्कृतियों एवं प्रणालियों का समन्वय हो चला।

† देखिए चौथा अध्याय।

जाते थे। जब बालक वर्णमाला के सभी अक्षरों से परिचित हो जाते, तब उन्हें संयुक्ताक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। अक्षर-ज्ञान का सम्यक् अभ्यास हो जाने के बाद कुरान का तीसवाँ पारा पढ़ाया जाता था, जिसमें छोटी-छोटी सूत्रें हैं। कुरान को यथावत् पढ़ लेने के बाद, विद्यार्थियों को फ़ारसी का साधारण ज्ञान करा दिया जाता था। किसी-किसी महत्त्व में हदीस, कविता तथा नीतिशास्त्र भी पढ़ाया जाता था।

उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में मदरसे थे। इनकी स्थापना बादशाहों, नवाबों तथा धनी अमीरों ने की थी। बड़े-बड़े मदरसों के साथ पुस्तकालय सलग रहते थे। कई एक संस्थान तो खासे सावास विश्व-विद्यालय थे, जहाँ कि छात्रगण दूर-दूर से विद्याध्ययन के लिए आते थे। मदरसों का शिक्षा-काल १० से १२ वर्ष का रहता था। शिक्षा का माध्यम अरबी थी। वर्तमान शिक्षा-काल के समान मदरसों में कक्षा-प्रणाली नहीं होती थी। कक्षाओं का विभाजन पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होता था। पाठ्यपुस्तकें तीन प्रकार की होती थीं। पहली सक्षिप्त पाठ्य पुस्तकें “मुखतसरत” (ए० व० मुखतसर) कहलाती थीं। दूसरी पाठ्य पुस्तकें मध्यम विस्तार वाली होती थीं। उन्हें “मुतवस्सतत” (ए० व० मुतवस्सत-मध्यम) कहते थे। तीसरी पाठ्यपुस्तकें “मुतव्वलात” (ए० व० मुतव्वल) नामक विस्तृत होती थीं। इस प्रकार सारा पाठ्यक्रम संकेन्द्रीय होता था।

पाठ्य-क्रम दो प्रकार के थे : (१) धार्मिक—इस्लामी धर्मग्रन्थ, इस्लामी इतिहास तथा कानून, और (२) सांसारिक—अरबी, व्याकरण, साहित्य, गणित, विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, यूनानी चिकित्सा, कृषि, कानून, हिसाब, इत्यादि। यह आवश्यक न था कि प्रत्येक मदरसा सब विषय पढ़ावे। कुछ मदरसे किसी विशेष विषय या विषयों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ केन्द्रों की ख्याति देश भर में थी, जैसे: लाहौर और सियालकोट (गणित तथा ज्योतिष), रामपूर (तर्क एवं ज्योतिष), दिल्ली (कविता और संगीत) तथा लखनऊ (शिया-शिक्षा)। किसी-किसी मदरसे में हिन्दू विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबन्ध रहता था, जहाँ कुरान के बदले वेदान्त तथा पातञ्जलि के योग-भाष्य का अध्ययन कराया जाता था। कई एक मदरसे तो केवल उत्तर-स्नातक शिक्षा ही देते थे। उदाहरण के लिए बादशाह अकबर की धाय मौं—माहम अंगा द्वारा स्थापित मदरसा (१५६१ ई०) है। इस संस्था में केवल संगीत, चित्रकला, दर्शन तथा गणित की शिक्षा उत्तर-स्नातक स्तर पर दी जाती थी।

पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणालियों का नया रूप.—मुस्लिम शासन काल का प्रभाव बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा-प्रणालियों पर भी पड़ा। चूँकि बौद्ध शिक्षा संस्था केन्द्रित

कई अफसरों ने शिक्षा के प्रति दिलचस्पी दिखलायी, और उन्होंने अपने व्यय से दो-एक विद्यालय स्थापित भी किये, जिन्हें बाद में कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया। पहली संस्था 'कलकत्ता मदरसा' सन् १७८१ में स्थापित हुई थी। उसके स्थापक भारत के सर्व प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य कम्पनी की नौकरी के लिए मुसलमान नवयुवकों को उचित शिक्षा देना था। दूसरा विद्यालय था बनारस संस्कृत कालेज (सन् १७९१ ई०)। इसके प्रतिष्ठाता थे बनारस के तत्कालीन रेसीडेन्ट जनाथान डन्कन। यह संस्था हिन्दुओं के लिए खोली गयी थी। कम्पनी के राज्य का विस्तार हो रहा था, पर अग्रेज अफसर इस देश के कानून कायदों से नितान्त अपरिचित थे। उनकी सहायता के लिए, भारतीय नायबों की विशेष आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से ऐसे विद्यालय खोले गये।

यद्यपि कम्पनी स्वतः चुप रही, तथापि उसने भारत में ईसाई मण्डलों तथा धर्म-प्रचारकों को स्कूल तथा कालेज खोलने दिये। यद्यपि उन शिक्षा-संस्था संचालकों का उद्देश ईसाई धर्म का प्रचार ही प्रधान था, तो भी उन लोगों ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ क्रिया और शिक्षा-पद्धति में एक जान फूँक दी। उन्होंने इस देश में छापेखाने भी खोले, जिससे छपी हुई पुस्तकों का प्रचार बढ़ा।

अन्ततः कम्पनी तटस्थता की नीति अधिक समय तक स्थिर न रख सकी। इंग्लैंड में पार्लियामेण्ट के कई सदस्य प्रयत्न कर रहे थे कि कम्पनी भारत में शिक्षा विस्तार के लिए कुछ न-कुछ करे। उन्हींके प्रयत्नों के फल स्वरूप सन् १८१३ ई० के नवीन आशा-पत्र में एक धारा बढ़ा दी गयी थी कि "ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों का यह भी कर्तव्य होगा कि वे भारत में कम-से-कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय करें।" पाठक समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए शिक्षार्थ व्यय की यह अल्प राशि 'ऊँट के मुँह में जीरा' की भाँति थी। कुछ भी हो, संख्या की दृष्टि से भले ही यह राशि महत्व-हीन थी, तथापि इस कार्यवाही का मूल्यांकन वहीं और ही है। सन् १८१३ ई० के आदेश ने ब्रिटिश पार्लियामेण्ट को यह मानने के लिए बाध्य किया कि "शिक्षा का सरकारी राजस्व पर अधिकार है"। यह बात कम्पनी अभी तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किन्तु उसे इस आदेश से हार माननी पड़ी और उसे झुकना ही पड़ा।

द्वितीय काल (प्रयोगात्मक रीति).—इस अरसे में कम्पनी ने प्रयोगात्मक रीति अपनायी। पैसे की कमी के कारण वह यह स्थिर न कर सकी कि शिक्षा के लिए क्या किया जावे। उसके सामने ये समस्याएँ थीं : (१) आम जनता में प्राथमिक शिक्षा

ब्रिटिश युग

भूमिका.—इस युग के इतिहास को हम निश्चित कालों में बाँट सकते हैं :

- (१) प्रथम काल (सन् १७५७-१८१३ ई०)—इस अवधि में ईस्ट इंडिया कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही। उसने तटस्थता की नीति अपनायी। (२) द्वितीय काल (सन् १८१३-१८५७ ई०)—इस समय कम्पनी शिक्षा-समस्या पर विचार करती रही। उसने प्रयोगात्मक रीति अपनायी। (३) तृतीय काल (सन् १८५७-१९१९ ई०)—इस अवधि में केन्द्रीय सरकार पूरे देश की शिक्षा-नीति निर्धारित करती रही। (४) चतुर्थ काल (सन् १९१९-१९४७ ई०)—इस काल में प्रादेशिक स्वशासन शुरु हुआ। कारण, शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी प्रान्तीय सरकार के हाथ में आ गयी।

प्रथम काल (तटस्थ नीति).—प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के गले में विजय-माला पहना दी, जिससे वे धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे। देश विजय करने पर भी गौरांग प्रभुओं ने आरम्भ में विद्या के लिए कुछ न किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास न पैसा था और न अवकाश। भारत में अपना पाया मजबूती से जमाने के लिए उसे दिन-रात युद्ध करना पड़ा। इस अवधि में कम्पनी ने शिक्षा के प्रति तटस्थ नीति अपनायी, और वह शिक्षा के लिए शासक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। डाइरेक्टरों का कहना था कि शिक्षा-विस्तार के लिए शासक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसे किसी देश की प्रचलित शिक्षा विधि में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। इस नीति के लिए हम उन डाइरेक्टरों को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनके देश की यही राजनीति थी।

जिस समय गौराङ्ग महाप्रभुओं ने इस देश पर अपना अधिकार जमाया, उस समय हमारी देशी शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ अस्तित्व में थी। यह अवश्य है कि अठारवीं सदी में सम्पूर्ण भारत में गड़बड़ी रहने के कारण देशी शिक्षा-पद्धति को गहरा धक्का पहुँचा था। इस शिक्षा की जाँच भारत के विभिन्न प्रदेशों में सन् १८२० से सन् १८३८ के बीच हुई थी। तदुक्तियों से पता चला कि भारत के गाँव-गाँव में प्राथमिक स्कूल तथा मस्जिदों से संलग्न मानव अवस्थित थे। उच्च शिक्षा के लिए बड़े-बड़े नगरों में 'टोल' या 'पाठशालाएँ' (हिंदुओं के लिए) और मदरसे (मुसलमानों के लिए) मौजूद थे।

यद्यपि कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही, तथापि उसे अपने व्यावसायिक केन्द्रों के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोलने ही पड़े। कम्पनी के देगिए चाँधा अध्याय।

इस विवाद ने उग्र रूप धारण किया, और सन् १८३४ ई० में दोनों दलों ने सरकार के सम्मुख अपना अपना अभिमत व्यक्त करते हुए वक्तव्य भेजे। इसी साल प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान् लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होकर यहाँ आये। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उन्हें अधिकार दिया कि आप इस विषय की जाँच करके अपना मत व्यक्त करें। फलतः २ फरवरी, सन १८३५ का एक लेख पत्र द्वारा मैकाले ने अपना मत दिया।

इस लेख पत्र द्वारा मैकाले ने यह प्रतिपादित किया था कि सरकार बिना रोक टोक चाहे जिस प्रकार शिक्षा की रकम खर्च कर सकती है, पर हम इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह सब कैसे हो सकता है? इस छोटी सी रकम के द्वारा जन शिक्षा असम्भव है, इसलिए हमें कुछ इने गिने मनुष्यों में उच्च विद्या का प्रचार करना पड़ेगा, जो भारतीय लोक भाषा, संस्कृत या फारसी से सभ्य नहीं है। कारण, इन भाषाओं में कोई टम नहीं है और न इनका साहित्य भण्डार युरोपीय चुनी हुई पुस्तकों की एक आलमारा के मुकाबिले ठहर ही सकता है। इस कारण हमें पाश्चात्य विद्या का प्रचार अंग्रेजी भाषा द्वारा करना पड़ेगा। यह भाषा सारे सभ्यता में प्रचलित है, इसका ज्ञान का खज़ाना असीम है और भारतवासी इसे सीखने के लिए उत्सुक हैं। मैकाले ने पुनः घोषित किया कि “हमें निर्माण करना है इस देश में ऐसे वर्ग का, जो रङ्ग और रक्त में भले ही भारतीय हो, परन्तु ज्ञान, पान, रहन सहन, आचार विचार तथा बुद्धि में पूरे अंग्रेज रहे।” †

यह प्रसिद्ध लेख पत्र ब्रिटिश के सामने पेश किया गया। वे तो इसी की ताक में बैठे थे। उनकी इच्छा इस देश में अंग्रेजी भाषा के प्रचार की थी ही, क्योंकि राज कार्य के लिए उन्हें अल्प बतनभोगी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय नौकरों की ज़रूरत थी। बस, मैकाले के लेख पत्र के मिलते ही, उन्होंने झट उस पर लिख दिया, “मैं सम्पूर्ण रूप से सहमत हूँ।”

७ मार्च, सन् १८३५ ई० को एक सरकारी सूचना निकली, जिसका सार अथ यह था कि भारत में पाश्चात्य विद्या का प्रचार अंग्रेजी भाषा द्वारा किया जावे। प्रधान शिक्षा समिति को हुक्म दिया गया, “प्राच्य शिक्षा के लिए जो कुछ किया जा चुका है, वह जैसे का तैसा बना रहेगा, परन्तु भविष्य में सम्पूर्ण अनुदान अंग्रेजी माध्यम द्वारा दी जानेवाली अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जायगा।”

फैलायी जावे या उच्च शिक्षा का प्रचार उच्च श्रेणी में किया जावे। (२) प्राच्य या पाश्चात्य विद्या का प्रचार किया जावे। (३) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होवे या संस्कृत और फारसी। (४) शिक्षा का प्रचार देशी विद्यालयों या नये स्कूलों और कालेजों द्वारा किया जावे।

इन समस्याओं के रहते हुए भी सन् १८१३ ई० के आदेशान्तर्गत धारा को क्रियान्वित करने के लिए कम्पनी दस वर्ष मौन रही। उसे इस समय इस दिशा में सक्रियता दिखाने के लिए अवकाश भी तो नहीं था। सन् १८१३ से १८२३ ई० तक कम्पनी को गुरुखों, पिण्डारियों तथा मराठों का सामना करना पड़ा। लड़ाई से फुरसत मिलने पर कम्पनी ने सन् १८२३ में शिक्षा के लिए प्रधान शिक्षा-समिति (जनरल कमिटी ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) मुकर्रर की। इस समिति को इस देश के अनुकूल शिक्षा-प्रबंध निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया, और खर्च के लिए तथाकथित आदेशानुसार एक लाख रुपया वार्षिक दिया जाने लगा।

प्रधान समिति में दस सदस्य थे। शुरू-शुरू में सब-के-सब अंग्रेज थे, जो प्राच्यवादी थे। इस कारण पहिले पहल इस समिति ने प्राच्य विद्या फैलाने का प्रयत्न किया, लेकिन धीरे-धीरे पौसा पलट गया। शिक्षा-समिति के कुछ सदस्य बदल गये। सन् १८३१ ई० में इसके आधे मेम्बर प्राच्यवादी थे और आधे आंग्लवादी। दोनों दलों में झगड़ा खड़ा हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि कुछ भी कामकाज होना कठिन हो गया। दोनों दलों ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण जन-शिक्षा की ओर ध्यान देना असम्भव है। इसलिए दोनों दल सहमत हुए कि इस थोड़ीसी रकम के द्वारा पहले उन्नत समाज में उच्च शिक्षा का प्रचार किया जावे। उन्होंने सोचा कि ये लोग धीरे-धीरे अपनी मातृभाषा में उपयोगी पुस्तकें लिखेंगे और जनता में शिक्षा का प्रचार करेंगे। इस प्रकार शिक्षा छनते हुए विशिष्ट समाज से आरम्भ होकर जनता की ओर फैलेगी। यह सिद्धान्त भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा छनने के सिद्धान्त (फिल्ट्रेशन थ्योरी) के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में दोनों दलों में यह विवाद खड़ा हुआ कि यह उच्च शिक्षा किस देश की विद्या हो (भारत या युरोप की), तथा शिक्षा का माध्यम क्या हो—अंग्रेजी या संस्कृत और फारसी? प्राच्यवादियों का मत था कि यह विद्या इस देश की हो तथा शिक्षा का माध्यम इस देश की सांस्कृतिक भाषा हो; पर आंग्लवादियों का कथन था कि प्राच्यविद्या सड़ गयी है, अतएव इस देश में पाश्चात्य विद्या का प्रचार अंग्रेजी के द्वारा किया जाय।

इस घोषणा-पत्र के फल स्वरूप प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा विभाग संगठित हुए। लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, राजकीय प्रशासन-विभाग तथा प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये, प्राथमिक एवं स्त्रीशिक्षा पर जोर दिया गया तथा जनता-द्वारा चलाये हुए विद्यालयों की सहायता के लिए आर्थिक अनुदान-पद्धति (ग्रण्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रावधान प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार वर्तमान शिक्षाप्रणाली को इस आज्ञा-पत्र ने ही सघटित किया। इसी कारण यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा का महा विधान (मैग्ना-कार्टा) गिना जाता है।

तृतीय काल (केन्द्रीय निर्धारित नीति).—सन् १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य-युद्ध के फल स्वरूप, भारत के शासन की ब्रागडोर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से निकलकर अंग्रेज नरेशों के हाथ में आ गयी। इस दीर्घ काल में, अर्थात् सन् १९१९ तक, भारत सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति नियन्त्रित करती रही। केन्द्रीय सरकार ने तीन महत्व-पूर्ण आयोग या कमीशन (इटर, १९०२ की विश्वविद्यालय समिति तथा सैडलर) नियुक्त किये। दो शिक्षा-नीति (१९०४ और १९१३) घोषित की, प्रान्तीय सरकारों को अनेक प्रसिद्धि-पत्र भेजे, तथा शिक्षा सम्बन्धी कई सम्मेलन बुलवाये। इन सबका जिक्र अगले अध्यायों में यथा स्थान किया जावेगा। इस प्रकार भारत सरकार देश की शिक्षा नीति संचालित करती रही।

इस समय का विशेष उल्लेखयोग्य विषय है राष्ट्रीय जागृति। इसी काल में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बंग भंग का आन्दोलन खड़ा हुआ। इन सब घटनाओं का आँच शिक्षा पर भी लगी। लाई कर्जन की विश्वविद्यालय नीति का तीव्र प्रतिवाद हुआ, बँग-भंग आन्दोलन ने विद्यार्थियों को राजनैतिक क्षेत्र में लीँचा तथा प्राविधिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य करने की चेष्टा की। इस प्रयत्न में वे असफल हुए, किन्तु उनकी चेष्टा व्यर्थ न हुई। देश में स्वाधीनता का आन्दोलन बढ़ा और इसीके फल-स्वरूप भारत सरकार का सन् १९१९ का नियम निकला।

चतुर्थ काल (प्रान्तीय स्वशासन).—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के समय, अगस्त १९१७ ई० में, इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट में तत्कालीन भारत-सचिव माण्टेग्यू ने घोषणा की, “शासन के हर एक क्षेत्र में भारतवासियों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय।” इस घोषणा के पश्चात् माण्टेग्यू साहब इस देश में आये। उन्होंने और तत्कालीन वाइसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर भारत में लागू करने के लिए राजनीतिक सुधारों की एक योजना तैयार की। इस योजना के आधार पर सन् १९१९ में इंग्लैण्ड

इस ऐलान का असर आज भी हमारी शिक्षा पर है। अंग्रेजी शिक्षा कैन्टी, और खूब कैन्टी। पर शिक्षा उच्च श्रेणी में ही सीमित रही, जनता में न कैन्टी। फल-स्वरूप आज ८० प्रति शत भारतवासी अपढ़ हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति और सांस्कृतिक भाषाएँ भूल बैठे। हम अंग्रेजी के रङ्ग में रँग गये। हमें पाश्चात्य कला और विज्ञान का लाभ अवश्य मिला और यहाँ पाश्चात्य दृष्टि के स्कूल तथा कालेज भी खोले गये, पर पर्याप्त रूप में नहीं। हमारे देश की परम्परागत शिक्षा-पद्धति नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। हमारे देशी स्कूल, टोल, पाठशालाएँ, मकतब तथा मदरसे कुचल दिये गये। माना कि वे पुराने ढाँचे में ढले हुए थे, तथापि उनमें सजोधन या सुधार किया जा सकता था।

आज मैकाले साहब के लेख-पत्र की नुस्खाचीनी करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी एक ऐसा युग था, जिसके लिए हम मैकाले साहब को विशेष टोपी नहीं ठहरा सकते। अठारहवीं शताब्दी की व्यावसायिक क्रान्ति और साम्राज्यवृद्धि ने प्रत्येक अंग्रेज का सिर फेर दिया था। वह यही सोचता था कि न अंग्रेजी भाषा के समान कोई दूसरी भाषा है और न किसी राष्ट्र की उन्नति अंग्रेजी के बिना हो ही सकती है। मैकाले इस युग का एक चिन्तनगारी मात्र था। पर हमें यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान से हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। आधुनिक काल में, ज्ञान का विकास सांस्कृतिक भाषाओं-द्वारा असम्भव है।

सन् १८३५ ई० के बाद दूसरी मञ्जिल आती है सन् १८५४ ई० में। इस वर्ष कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक सरकारी पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम 'वुड का घोषणापत्र' (वुड्स डिस्पैच) पड़ गया है। प्रथमतः इस चिट्ठे ने शिक्षा के ये सिद्धान्त इस देश के लिए घोषित किये:

यह सत्य है कि भारत की जनता अपनी सांस्कृतिक भाषाओं के बिना काम नहीं चला सकती है, तिस पर भी इस देश में शिक्षाप्रसार के विषय युरोप के समुन्नत कला-कौशल, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य—संक्षेप में युरोपीय ज्ञान—हों।†

इस घोषणा ने जन-शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के माध्यम पर, इस दस्तावेज़ ने गौर किया, "भारत की शिक्षा-प्रणाली में अंग्रेजी और मातृ-भाषा—दोनों का विशेष स्थान है; अंग्रेजी, उच्च शिक्षा के लिए और मातृभाषा, जन-शिक्षा के लिए।"‡

† Wood's Despatch, para 7

‡ Ibid., para 14

लिए समितियाँ गठित हुई, जैसे : प्राविधिक शिक्षा, समाज शिक्षा, उच्च ग्राम शिक्षा, भाषा, इत्यादि। इन आयोगों एवं समितियों के अभिस्तावों के अनुसार बहुत कुछ काम भी हुआ।

पञ्चवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति स्वाधीन भारत का सर्वाधिक उल्लेखनीय कदम है। इनका प्रधान उद्देश्य देश में विकास कार्य आरम्भ करना है, जिससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें। इन योजनाओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के लिए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (१९५१-५६ ई०) में १६९ करोड़ रुपये खर्च हुए, और द्वितीय योजना (१९५६-६१ ई०) में ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हैं। दोनों योजनाओं के विभिन्न अंशों पर होनेवाले व्यय का आवण्टन नीचे दिया गया है :

तालिका १

✓ प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का आवण्टन (करोड़ रुपये)

विवरण	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
प्राथमिक शिक्षा	९३	८९
माध्यमिक शिक्षा	२२	५१
विश्वविद्यालयीय शिक्षा	१५	५७
प्राविधिक शिक्षा	२३	४८
समाज शिक्षा	५	५
प्रशासन तथा विविध	११	५७
योग.....	१६९	३०७

सन् १९५५ ई० में द्वितीय योजना की प्राथमिक रूपरेखा की आलोचना के समय, शिक्षा के निमित्त १०८ अरब रुपयों की माँग थी। सशोषित रकम घटते घटते ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हुई। इस व्यय में से ९५ करोड़ रुपये केन्द्र तथा २१२ करोड़ रुपये राज्य वहन करेंगे। अगले पन्ने की तालिका में प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य दिखाये गये हैं।

की सरकार ने 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ इंडिया एक्ट' के द्वारा भारतवासियों को माण्टेग्मू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रदान किये। इस कानून की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है शिक्षाक्षेत्र में प्रांतीय स्वशासन। इस कायदे के अनुसार शिक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के हाथ से निकल कर प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायित्व में आ गयी। प्रत्येक प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया कि अपने प्रान्त की शिक्षा-नीति का नियन्त्रण वही करे। इस विषय में केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों पर कोई दबाव नहीं डाल सकती।

प्रांतीय स्वशासन का एक और भी विशेष रूप है। सन् १९१९ के कायदे के अनुसार शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबन्ध एक निर्वाचित भारतीय मन्त्री के हाथ सौंप दिया गया। इस प्रकार प्रांतीय विधान-सभा शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने लगी और जनता शिक्षा की उन्नति के कार्य में काफी दिलचस्पी लेने लगी। प्राथमिक शिक्षा लाजमी (अनिवार्य) करने के लिए कानून निकले, स्त्री-शिक्षा की उन्नति हुई तथा प्रौढ़ शिक्षा का श्रीगणेश हुआ।

यह सब कुछ होते हुए, शिक्षा की सन्तोषप्रद प्रगति न हुई। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् सम्पूर्ण संसार में आर्थिक मन्दी आयी, और फिर आरम्भ हुआ द्वितीय विश्व-युद्ध। इसके साथ-साथ देश में स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा। यह सत्य है कि शिक्षा का विस्तार भारत में ठीक-ठीक न हुआ, पर शिक्षा-क्षेत्र में नयी धाराएँ अवश्य ही बढ़ निकलीं; यथा : बुनियादी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मातृभाषा पर जोर, पाठ्य-क्रम का विस्तार, प्राविधिक शिक्षा पर ध्यान, आदि। इस प्रकार अन्त में १५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश पराधीनता की शृंखला से मुक्त हुआ।

स्वातन्त्र्योत्तर काल

स्वाधीन होने पर हमारे देश के सामने सब से बड़ा सवाल था, पूर्व स्वाधीन-युगीन शिक्षा की कमियों को हटाना। ८० प्रति शत भारतवासी अपढ़ थे, ६-११ बयोवर्ग के केवल ३० फी सदी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ थीं, और इनसे बहुत ही कम प्रतिशत या माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए। वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा पिछड़ी हुई थी, तथा शोध का तो श्रीगणेश ही हुआ था। इन कमजोरियों को दूर करने के सिवा हमारे सामने प्रश्न था—देश की संस्कृति का पुनरुद्धार करना और पूर्व तथा पश्चिम के पड़ोसी देशों के साथ मर्द-चारे का भाव बढ़ाना।

इन बहुमुष्गी समस्याओं का सामना करना कुछ कम साहस का काम नहीं था, तो भी स्वाधीन भारत इन सबके लिए कटिबद्ध हुआ। विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए दो स्वतन्त्र आयोग नियुक्त हुए, और अन्य सभी महत्व-पूर्ण विषयों के

अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा-योजना के अन्तर्गत आ जावें तथा लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जावे। इस रूप-रेखा में यह भी सिफारिश की गयी है कि कम-से-कम ५० प्रति शत वर्तमान हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलने की व्यवस्था की जाय तथा राज्य सरकारों द्वारा वयस्क स्कूलों की स्थापना का अलग कार्यक्रम शामिल किया जाय।

भारत को स्वाधीन हुए बारह वर्ष हुए। इस अरसे में शिक्षा काफी बढ़ी। आज (१९५७) हमारे देश में २,८७,३१८ प्राथमिक शालाएँ, ३५,८३८ माध्यमिक स्कूल, ७७१ आर्ट्स तथा साइन्स कालेज, ४०४ व्यवसाय-सम्बन्धी कालेज तथा ३,२८३ व्यावसायिक स्कूल हैं।† सन् १९४८ के वर्ष में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः १,४०,७९४ (प्राथमिक), १२,८९९ (माध्यमिक), २९५ (आर्ट्स तथा साइन्स कालेज), १३१ (व्यावसायिक कालेज) और १,३९१ (व्यावसायिक स्कूल) थी।‡ इसी अरसे में छात्र-संख्या भी प्रायः तिगुनी हो गयी।

यह शिक्षा-विस्तार कुछ कम नहीं है, पर यदि हम सब कन्वे से कन्धा लगाकर काम करते तो सम्भवतः प्रगति और भी अधिक होती। हाल ही में चीन देश से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है 'China's Big Leap Forward'। इससे पता चलता है कि चीन में ८ वर्ष के अरसे में शिक्षा-संस्थाओं की छात्र-संख्या कितनी बढ़ी। प्राथमिक शालाएँ २,४०,००० से ६,४०,०००, माध्यमिक शालाएँ १० लाख से ६० लाख, व्यवसाय सम्बन्धी स्कूल साढ़े तीन लाख से ७,८०,००० तथा विश्वविद्यालय और कालेज १,५५,००० से ४,४५,००० की संख्या में बढ़े। इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की संख्या तो पंचगुनी होकर १,६३,००० तक जा पहुँची। सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग के कारण ही यह विस्तार वहाँ हो सका।

आज भारत सचेत हो उठा है। चारों ओर से शिक्षा-सुधार की पुकार मची हुई है। लोग अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा के अङ्ग प्रत्यङ्ग में एक नवीन जीवन के प्रादुर्भाव की आवश्यकता है। प्रशासन-पद्धति, शैक्षणिक रूप-रेखा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा स्त्री शिक्षा पर नये नये विचार हो रहे हैं। भाषा तथा शिक्षा के माध्यम की नयी समस्याएँ देश के सामने उपस्थित हैं। इसीके फल स्वरूप हमारे शिक्षा क्षेत्र में नयी-नयी विचार धाराएँ बहने लगी हैं, जैसे : बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय प्रयोग शालाएँ तथा विज्ञान मन्दिर, राष्ट्रीय तथा सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल, इत्यादि। इन गहन प्रश्नों पर इस पुस्तक के अगले अध्यायों में विचार किया जायगा।

† भारत, १९५९, पृष्ठ ७९।

‡ Seven Years of Freedom. pp 31-47.

तालिका २ †

प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य

कार्य	१९५५-५६	१९६०-६१
६-११ वयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस वयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती	५१.०	६२.७
११-१४ वयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस वयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती	१८.२	२२.५
१४-१७ वयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस वयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती	८.४	११.७
प्रारम्भिक तथा अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	२,७८,७६८	३,२६,८००
अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	४२,९४१	६४,९१०
मिडिल तथा प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या...	२१,७३०	२२,७२५
प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या	४,८४२	४,५७१
हाई तथा उच्च हाईस्कूलों की संख्या	१०,७३८	१२,१२५
हाईस्कूल से परिवर्तित उच्च हाईस्कूलों की संख्या... ..	४७	१,१९७
बहुदेशीय स्कूलों की संख्या	३६७	१,१८७
विश्वविद्यालयों की संख्या	३२	३८
इजीनियरिंग डिप्री-संस्थानों की संख्या	४७	५४
” डिप्लोमा ” ” ” संख्या	८८	१०४
” डिप्रीप्राप्त छात्रों की संख्या	३,३९५	५,४८०
” डिप्लोमाप्राप्त ” ” ” संख्या	३,८११	८,०००
” डिप्री संस्थानों की संख्या ”	२५	२८
” डिप्लोमा ” ” ” संख्या	३६	३७
” डिप्री प्राप्त छात्रों की संख्या ”	७००	८००
” डिप्लोमा प्राप्त ” ” ” संख्या	४३०	५८०

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना (१९६१-६६) की प्राथमिक रूप-रेखा की आलोचना की गयी रही है। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य यह है कि तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के

इन राज्यों के सिवा भारत में छः सघीय क्षेत्र हैं, अर्थात् (१) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, (२) दिल्ली, (३) हिमाचल प्रदेश, (४) लक्षा द्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह, (५) मणिपूर और (६) त्रिपुरा।

भारत पृथ्वी का एक छोटा-सा स्वरूप है, जिसका क्षेत्रफल १२,५९,७६५ वर्ग मील है। ससार के सबसे अधिक जन-संख्यावाले देशों में इस देश का स्थान दूसरा है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार, इस देश की कुल जन संख्या ३५,६८,७९,३४९ थी, जिसमें १८,३३,०८,७३३ पुरुष तथा १७,३५,२२,८३१ स्त्रियाँ हैं। औसतन १,००० पुरुष पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि देश की एकत्रित जन संख्या में से १७.३ प्रतिशत लोग शहरों में तथा शेष गाँवों में रहते हैं। इस जन-गणना के अनुसार भारत में ५,९१,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थी; अर्थात् सम्पूर्ण देश की साक्षरता थी : १६.६१ प्रतिशत — २४.८७ (पुरुष) तथा ७.८७ (स्त्रियाँ)।

भारत में विभिन्न रूप रङ्गोवाले तथा अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं। १९५१ की मर्दुमशुमारो के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें ७०२ भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक के भाषियों की संख्या एक लाख से कम है, तथा ६३ गैर भारतीय भाषाएँ हैं। ९१ प्रतिशत जनता सविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी न-किसी एक भाषा को बोलती है।

शिक्षा-प्रशासन

पूर्व-शृष्टिका

सन् १८५५ ई० तक इस देश में शिक्षा प्रशासन सुव्यवस्थित न था। ^①बुद्ध के घोषणा-पत्र की सिफारिशों के कारण, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग कायम हुए। इसके साथ-साथ समूचे देश की शिक्षा नीति भारत सरकार निरूपित करने लगी।† पर केन्द्र में शिक्षा शासन के लिए कोई राजकीय विभाग स्थापित न हुआ। कुछ काल तक शिक्षा की व्यवस्था गृह विभाग की शिक्षा-शाखा करती रही, पर भारत सरकार अनुभव कर रही थी कि पूरे देश की शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक अफसर की आवश्यकता है। इस अभाव की पूर्ति लार्ड कर्जन ने की। सन् १९०१ ई० में उन्होंने पूरे देश के लिए प्रधान शिक्षा-सचालक (डाइरेक्टर जनरल ऑफ़ एजुकेशन) पद की सृष्टि गृह-विभाग के मातहत की।

† देविप्र चौधा अध्याय।

दूसरा अध्याय

शिक्षा-व्यवस्था

भारत के राज्य

जब १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वाधीन हुआ तब भारत में नौ प्रान्तों के अतिरिक्त ५४८ रियासतें थीं। भारत के उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्ष के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया, जिससे ये बहुसंख्यक देशी राज्य भारत के आन्तरिक भाग बन गये, जिस तरह कि अन्य राज्य इसके अङ्ग हैं। परिणामतः सारे भारत में प्रजातन्त्र राज्य प्रस्थापित हुआ। १ नवम्बर, १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें देशी राज्यों का षट्क राज्यों के रूप में नवनिर्मित राज्यों में विलयन हो गया। आज भारत इन चौदह नवीन राज्यों का संघटित रूप — राष्ट्र-संघ — है। इन चौदह राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधोलिखित तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका ३

भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जन-संख्या†

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन-संख्या
असम	८५,०६२	९०,४३,७०७
आन्ध्रप्रदेश	१,०५,६७७	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५,९४६
उत्तरप्रदेश	१,१३,४२२	६,३२,१५,७४२
केरल	१५,००६	१,३५,४९,११८
जम्मू और कश्मीर	८५,८६१	४०,१०,०००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४,८९०
पश्चिम बङ्गाल	३३,९२७	२,६३,०२,३८६
बम्बई	१,९०,६६८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,०७१	३,८७,८३,७७८
मद्रास	५०,१३८	२,९९,७४,९३६
मध्यप्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७१,६३७
मैसूर	७४,८६१	१,९०,०१,१९३
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५९,७०,७७४

† भारत, १९५९, पृष्ठ ८-९।

वैज्ञानिक शोध का कार्य सौंपा गया और इसका नाम पड़ा ' शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय'। लेकिन एक वर्ष बाद, यह मन्त्रालय दो भागों में विभक्त हुआ (१) शिक्षा और (२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और स्रष्टृति।

यह हमारे देश के शिक्षा शासन के विकास की रूप रेखा हुई। इस शासन की चांगडोर तीन स्वतन्त्र अधिकारियों के अधीन है (१) केन्द्रीय सरकार, (२) राज्य सरकार और (३) स्वायत्त शासन। इनके कार्यकलाप का सक्षित विवरण नीचे दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार

शिक्षा मन्त्रालय.—शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री की अधीनता में है। सन् १९५८ तक शिक्षा मन्त्री मन्त्री मण्डल के सदस्य रहे, पर अब वे केवल राज्य-मन्त्री ही हैं। मन्त्रालय के मुख्य दो कर्तव्य हैं (१) देश की शिक्षा नीति संयोजित करना और (२) यथा सम्भव भिन्न भिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता रखना।

मन्त्रालय के सब से प्रधान कर्मचारी शिक्षा परामर्श दाता (एज्युकेशन एडवाइजर) होते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के सचिव का काम करते हैं, तथापि इनकी सबसे बड़ी जवाबदारी यह है कि ये शिक्षा मन्त्री को पूरे देश की शिक्षा नीति तथा शासन के विषय में उचित परामर्श दें। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय निम्नलिखित आठ सविभागों में विभक्त है

- (१) प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षण,
- (२) माध्यमिक शिक्षा,
- (३) उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को,
- (४) हिन्दी,
- (५) सामाजिक शिक्षा तथा समाज-कल्याण,
- (६) व्यायाम तथा मनोरंजन,
- (७) छात्र-वृत्ति तथा
- (८) प्रशासन।†

नौ वर्षों तक इसी प्रकार ही काम चलता रहा। सन् १९१० ई० में वाइसराय की कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ा दी गयी। इस सदस्य को शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गयी, पर प्रधान शिक्षा-संचालक का पद उठा दिया गया। पाँच वर्ष बाद 'एज्यूकेशन कमिश्नर' नामक एक नये अफसर की नियुक्ति हुई। उसका काम वही रहा जो प्रधान शिक्षा-संचालक का था। इसी साल शिक्षा-सूचना-कार्यालय (ब्यूरो ऑफ़ एज्यूकेशन) भी खोला गया। भारत सरकार की वार्षिक तथा पंचवार्षिक रिपोर्टों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त, यह दफ्तर शिक्षा-सम्बन्धी अनेक साहित्य निकालता रहता था। सन् १९०२-१८ की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा प्रान्तीय सरकारों को काफी रुपये अनुदान में दिये।

(३) भारत सरकार के सन् १९१९ के कायदे के अनुसार, शिक्षा की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार के हाथ से निकल कर प्रान्तीय सरकार के हाथ आ गयी। पर इस प्रान्तीय स्वशासन के कारण प्रान्तीय सरकारों का भारत सरकार से एकलन होने के सिवा, आपसी पृथक्करण भी हुआ। इस पृथक्वादी नीति के फल-स्वरूप पैसा तथा परिश्रम बहुत कुछ व्यर्थ जाने लगा। कारण, न प्रान्तीय सरकारें आपस के कार्य-कलापों का लाभ उठा सकती थीं और न केन्द्रीय सरकार पूरे देश के लिए कोई शिक्षा-नीति निर्धारित कर सकती थी। इस प्रकार सभी अनुभव करने लगे कि सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति में एकसूत्रता लाने के लिए एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान बन्द हो गया। फल-स्वरूप, शिक्षा की नवीन योजनाएँ शिथिल पड़ने लगीं।

इस कारण सन् १९२१ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मण्डल (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ़ एज्यूकेशन) की स्थापना हुई। पर केवल दो वर्ष बाद, इस मण्डल का खाल्ता हुआ। कारण, सरकार के पास पैसा न था। इस मितव्ययता के फल-स्वरूप शिक्षा-सूचना-कार्यालय भी उठा दिया गया, तथा शिक्षा विभाग अन्य सरकारी सुदकर्मों अर्थात् स्वास्थ्य, राज्य-कर और कृषि के साथ जोड़ दिया गया। आर्थिक स्थिति सुधरने पर तथा हार्टग समिति की सिफ़ारिशों के कारण, सन् १९२५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मण्डल तथा इसके दो साल बाद शिक्षा-सूचना-कार्यालय पुनः स्थापित हुए।

सन् १९४५ ई० में, भारत सरकार ने अपना एक स्वतंत्र शिक्षा-विभाग खोला। दो वर्ष बाद यह विभाग मन्त्रालय में बढ़ा दिया गया। सन् १९५७ में इस मन्त्रालय को

✓ शिक्षा मन्त्रालय को कई सलाहकारों या परिनियत परिषद सहायता पहुँचाती है। मुख्य परिषद ये हैं : (१) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (केशिसम), (२) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन), (३) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ सेकण्डरी एज्युकेशन), (४) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ एलीमेंटरी एज्युकेशन), (५) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ रूरल हायर एज्युकेशन), (६) राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ वुमेन्स एज्युकेशन), (७) केन्द्रीय समाज-सेवा मण्डल (सेन्ट्रल सोशियल वेलफेयर बोर्ड), इत्यादि। इस अध्याय में केवल 'केशिसम' की आलोचना की जायेगी। अन्य परिषदों के विषय में अगले अध्यायों में यथायोग्य अंशों में लिखा जायगा।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यों का प्रधान साधन 'केशिसम' है। इसकी स्थापना सन् १९२१ ई० में हुई थी। इसका संविधान इस प्रकार है। 17 25 के टिप्पणीकर्ता 19 16

- (१) भारत-सरकार के शिक्षा मन्त्री (सभापति),
- (२) भारत-सरकार के शिक्षा परामर्श दाता (सदस्य),
- (३) भारत सरकार द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्य, जिनमें से पाँच सदस्य महिला हों,
- (४) संसद द्वारा निर्वाचित पाँच सदस्य — दो राज्य सभा द्वारा तथा तीन लोक सभा द्वारा,
- (५) अन्तर्विद्यालय मण्डल (इण्टर युनिवर्सिटी बोर्ड) द्वारा निर्वाचित दो सदस्य,
- (६) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ टेकनिश एज्युकेशन) द्वारा मनोनीत दो सदस्य,
- (७) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, जो कि शिक्षा मन्त्री हो। उसकी अनुपस्थिति में, उसका मनोनीत व्यक्ति किसी भी बैठक में भाग ले सकता है और
- (८) मण्डल का सचिव — (जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है)।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य काल तीन वर्ष रहता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है, जिसमें सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय



विभाग

प्रारम्भिक तथा
बुनियादी शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

उच्च शिक्षा
तथा युनेस्को

हिन्दी

सामाजिक शिक्षा
तथा समाज-कल्याण

व्यायाम तथा
मनोरंजन

छात्र-वृत्ति

प्रशासन

शिक्षामन्त्री

शिक्षा
परामर्शदाता

सलाहकारी परिषद

केन्द्रीय शिक्षा
सलाहकार मण्डल

विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग

अखिल भारतीय
माध्यमिक
शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय
प्रारम्भिक
शिक्षा परिषद

ग्रामीण उच्चतर
शिक्षा समिति

राष्ट्रीय
स्त्री-शिक्षा
परिषद

आधिकार क्षेत्र

अन्तर्राष्ट्रीय
सम्पर्क

संघीय क्षेत्र

शिक्षा-सूचना
कार्यालय

विदेशी दफ्तरें

केन्द्रीय
विश्वविद्यालय

पब्लिक स्कूल

अखिल भारतीय
शिक्षा-संस्थाएँ

वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय.—इस मन्त्रालय के सबसे प्रमुख व्यक्ति एक राज मन्त्री हैं, जिनकी सहायता एक उप मन्त्री करते हैं। इस मन्त्रालय की स्थापना हाल ही में हुई है। इस मन्त्रालय के मुख्य कार्य ये हैं : (१) वैज्ञानिक शोध तथा भूमीक्षण, (२) सांस्कृतिक कार्यकलाप तथा (३) प्राविधिक शिक्षा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में इस मन्त्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेओडोटिक सर्वे ऑफ इंडिया—इसीके प्रशासन में हैं। यह मन्त्रालय अनेक शिक्षा-संस्थाएँ भी चलाता है, जैसे : दिल्ली पोलिटेक्निक, राइगपुर स्थित प्रौद्योगिकी संस्था, धानवाड़ स्थित इंडियन स्कूल ऑफ़ माईन्स एण्ड एप्लाइड ज्योलोजी, इत्यादि। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक गवेषणा के प्रोत्साहन के लिए, मन्त्रालय अनेक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता भी देता है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद मन्त्रालय को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देता है।†

राज्य सरकार

यह पहले ही बताया जा चुका है कि, शिक्षा एक राज्यीय विषय है। केन्द्रीय सरकार राज्यीय शिक्षा नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केवल दो विषयों की शक्ति, केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। ये हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विभिन्न उच्च शिक्षा निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना। ये जटिल तथा व्यय साध्य विषय पूरे देश से सम्बन्धित हैं, इसलिए हमारे विधान ने इनकी जिम्मेवारी राज्यों पर लाटना हितकारी नहीं समझा। और यह ठीक भी है। इनके सिवा, राज्य सरकारों पर एक और प्रतिबन्ध है। जिन-जिन योजनाओं के लिए, राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना पड़ता है। इन रुकावटों के सिवा, राज्यों को शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण स्वायत्तता है।

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की दृष्टि से मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि परिषद की व्यवस्था की गयी है। मन्त्रियों को अलग-अलग शासन विभाग सौंप दिये जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी पूरे मन्त्रि परिषद पर होती है। यह सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा मन्त्री के

† देखिए आठवाँ अध्याय।

किया जाता है। मण्डल की कई स्थायी समितियों भी हैं, और समय समय पर मण्डल शिक्षा के विशिष्ट विषयों पर रिपोर्टें प्रकाशित करता रहता है। हर्ष की बात है कि आरम्भ से ही मण्डल का कार्य प्रशासनाय रहा है। मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। कारण, शिक्षा एक राज्याय विषय है। राज्य सरकारें मण्डल की सिफारिशों को ठुकरा सकती हैं, बदल सकती हैं या अपना सकती हैं। इस कारण, मण्डल की चेष्टाएँ कभी-कभी व्यर्थ भी जाती हैं।

मण्डल से संलग्न शिक्षा-सूचना कार्यालय तथा एक सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तकालय है। शिक्षा-सूचना-कार्यालय का काम है देश-विदेश के शिक्षा-विषयक समाचारों का संग्रह करना तथा शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित करना। पुस्तकालय तो देश-विदेश के शिक्षा-साहित्य का भण्डार ही है।

यद्यपि शिक्षा के सम्बन्ध में भारत-सरकार राज्यों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तथापि उसका स्थान शिक्षा-क्षेत्र में महत्व-पूर्ण है। प्रथमतः, पूरे देश की शिक्षा-नीति में समानता लाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है। 'केशिसम' तथा राज्य के शिक्षा-मन्त्रियों की बैठकों में, पूरे देश के शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ करता है। शिक्षा के पंचीदे प्रश्नों को सुलझाने के लिए भारत-सरकार समितियों तथा आयोग नियुक्त करती है, रिपोर्टें प्रकाशित करती है तथा वित्तीय मामलों पर सोच-विचार करती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विशेषतः तथा प्रकाशक का कार्य करती है। द्वितीयतः, यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा संयुक्त राष्ट्र सघीय शिक्षा, 'विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन' (यूनेस्को) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करती है। इसके सिवा, केन्द्रीय सरकार का काम है इस देश के छात्रों को विदेश की शिक्षा-संस्थाओं में प्रविष्ट कराना तथा उनकी देख-भाल करना। इस कार्य के लिए भारत-सरकार के लंडन, वाशिंगटन, वान तथा नैरोबी में दफ्तर हैं। तृतीयतः, सघीय क्षेत्र की शिक्षा की जिम्मेवारी भारतीय सरकार पर है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्व-भारती) का देख-रेख इसे ही करनी पड़ती है। चतुर्थतः, भारत के अठारह पब्लिक स्कूल शिक्षा-मन्त्रालय के प्रशासन में हैं। पञ्चमतः, अनेक अखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाएँ स्वयं भारत-सरकार-द्वारा सञ्चालित हैं, जैसे : दिल्ली सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एज्युकेशन, देहरादून सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस, दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ वेसिक एज्युकेशन, इत्यादि। षष्ठतः, केन्द्रीय सरकार अनेक शिक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है, बशर्ते कि ये योजनाएँ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हों।

प्रकार के हैं • शहरा तथा ग्रामीण । बड़े बड़े नगरों के निकायों को 'निकाय' और मध्यम तथा छोटे नगरों के निकायों को 'नगरपालिका समिति' कहा जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों की देल माल जिला मण्डल अथवा तालुका मण्डल (जनपद सभा) तथा ग्राम पंचायतें करती हैं ।

सरकार ने कई कायदे कानूनों तथा प्रस्तावों द्वारा स्थानीय निकायों को शिक्षा विषयक अनेक अधिकार दिये हैं । माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने स्पष्ट घोषणा की कि "शासन की ओर से जिलों, शहरों एव कस्बों का शासन उनक निवासियों को मिल जाय और वे उनका प्रबन्ध सभाए बनाकर इच्छानुक्ल कार्य करें ।" इस विषय मे बाहरी हस्तक्षेप वाञ्छनीय नहीं है । इस घोषणा का फल यह हुआ कि प्रान्तीय विधान सभाओं ने धीरे धीरे स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ा दी । आज सभी राज्यों मे प्राथमिक शिक्षा का शासन स्थानीय निकाय ही करते हैं । वे स्वत स्कूल खोलते हैं, गैरसरकारी स्कूलों को मजूर करते हैं तथा उन्हें प्राण्ट देते हैं । शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए वे अपने स्कूल बोर्ड स्थापित करते हैं तथा स्कूलों की देखरेख के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं । प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, वे अपनी योजनाएँ भी चला सकते हैं ।

शिक्षा-संस्थाओं का वर्गीकरण

भारत की शिक्षा संस्थाएँ दो श्रेणियों मे विभाजित की जा सकती हैं • (१) स्वीकृत तथा (२) अस्वीकृत । पहले वर्ग की संस्थाएँ किसी शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय या हाईस्कूल बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृत होते हैं । इनक द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को पाठ्य क्रम तथा पाठ्य पुस्तकों को चलाना पड़ता है, और उन्हें अपने विद्यार्थियों को सरकारी या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं मे बिठाने का हक रहता है । समय समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण भी होता है । इस कारण, इन्हें सदैव चौकचा रहना पड़ता है । ऐसे स्कूल और कालेजों को छोड़कर शेष संस्थाएँ अस्वीकृत होती हैं । बहुधा ये देशी विद्यालय होते हैं, जिनमे संस्कृत, फारसी, कुरान, आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता है । हमारे देश मे कुछ ऐसे स्कूल भी खुल गये हैं, जो परीक्षाओं में असफल छात्रों को फिर से परीक्षाओं में प्राइवेट बिठाने के लिए तैयार करते हैं । परमेश्वर देश को ऐसी अनथकारी संस्थाओं से बचावें ।

स्वीकृत संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं—सरकारी तथा स्वसंचालित । पहले वर्ग की संस्थाएँ राजकीय या स्थानीय निकायों द्वारा परिचालित होती हैं । स्वसंचालित संस्थाओं को या तो कोई व्यक्ति अथवा ही चलाता है या कोई शिक्षा-मण्डल चलाता है । इन

मातहत शिक्षा-विभाग रहता है। पूरे राज्य की शिक्षा-नीति का निर्देशन वे ही करते हैं। उनकी सहायता के लिए दो प्रधान अफसर रहते हैं : शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन)। सचिव शिक्षा-विभाग के सारे कागजात शिक्षा-मन्त्री के सामने पेश करते हैं तथा सरकार की ओर से हुक्म निकालते हैं। बहुधा सचिव शासकीय अफसर ही होता है, और उसे शिक्षा-विभाग का अधिक अनुभव नहीं रहता है।

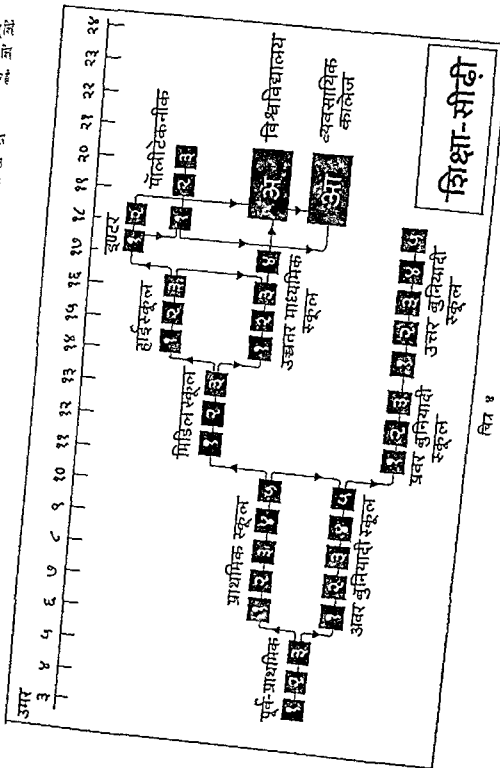
शिक्षा-विभाग का अमली काम डाइरेक्टर चलाते हैं, जो सदा इस विभाग के एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी पेचीदे प्रश्नों पर ये ही शिक्षा-मन्त्री को सलाह देते हैं। डाइरेक्टर की सहायता के लिए, सद्र दफ्तर में कई उपसंचालक (डिप्टी या असिस्टेंट डाइरेक्टर) रहते हैं। राज्य विभागों में बाँट दिया जाता है, और विभाग जिलों में। प्रत्येक विभाग एक क्षेत्रीय डिप्टी डाइरेक्टर या सुपरिण्टेण्डेण्ट अथवा इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल के प्रशासन में रहता है; यह प्रबंध प्रत्येक राज्य की शासन-पद्धति पर निर्भर होता है। कई राज्यों में मध्यवर्ती शासक रखने की प्रथा उठा दी गयी है। इन राज्यों में डाइरेक्टर से परवर्ती अफसर जिला शाला निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन इन्स्पेक्टर) होता है। प्रत्येक राज्य तालुका या तहसीलों में बाँट दिया जाता है जो कि एक डिप्टी इन्स्पेक्टर के मातहत रहता है। इन सब अफसरों के काम की निगरानी शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर करते हैं।

यों तो पूरे राज्य की शिक्षा की जिम्मेवारी शिक्षा-मन्त्री पर रहती है, पर कुछ विशेष शिक्षा-संस्थाएँ अन्य मंत्रियों के प्रशासन में रहती हैं, जैसे : कृषि-विद्यालय, टैकनीकी स्कूल तथा कालेज, समाज-शिक्षा-केन्द्र, आदि। हमें यह न सोचना चाहिए कि शिक्षा-विभाग अपना पूरा कार्य स्वयं चलाता है। उसे अन्य व्यवस्थापकों की सहकारिता की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे : उच्च शिक्षा-विश्वविद्यालयों के जरिये, प्राथमिक शिक्षा-स्थानीय बोर्डों से मिलजुल कर, माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-मण्डलों के सहयोग से। इस पृथकीकरण नीति के कारण, कभी-कभी शिक्षा को क्षति पहुँचती है। शिक्षा-प्रशासन के समग्र यह एक गुरुत्व-पूर्ण प्रश्न है।

स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन की नींव सन् १८६१ ई० में पड़ी। इस वर्ष कलकत्ता, मद्रास और बम्बई शहरों का इन्तजाम करने के लिए प्रजा-द्वारा निर्वाचित सभाओं की स्थापना हुई। इसके बाद सन् १८८२ ई० में लार्ड रिपन ने एक नियम बनवाया, जिसके अनुसार भारतवर्ष के शहरों, कस्बों और जिलों का प्रबंध करने के लिए नगरपालिका समितियाँ तथा जिला-मण्डल स्थापित हुए। आज स्थानीय निःशुल्क मोटे तौर पर दो

व मं वि
 वं लि
 वि
 वं



शिक्षा-सीढ़ी

प्रवर बुनियादी स्कूल (1-2-3-4-5)
 उत्तर बुनियादी स्कूल (1-2-3-4-5)
 प्रवर बुनियादी स्कूल (1-2-3-4-5)

संस्थाओं को भी हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (१) सहायता-प्राप्त अर्थात् जिन्हें सरकार या और स्थानीय निकायों से ग्राण्ट मिलती है, और (२) स्वाश्रित, जिन्हें अनुदान प्राप्त नहीं होता। ऐसी संस्थाओं को अधिकतर फीस, चन्दा या दान पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

१९५५-५६ में स्वीकृत संस्थाओं की संख्या ३,६६,६४१ थी : राजकीय ८७,६०१, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १,४२,९८०, म्युनिसिपल बोर्ड १०,४९७, स्वसंचालित १,१४,२०४ (सहायता-प्राप्त) और ११,३५९ (स्वाश्रित)। इसी वर्ष सम्पूर्ण देश में ४,८०६ अस्वीकृत संस्थाएँ थीं।†

शिक्षा की सीढ़ी

शिक्षा की पहली सीढ़ी पर पूर्व-प्राथमिक स्कूल हैं, जहाँ ३ से ६ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या देश में बहुत ही कम है। इनके बाद प्राथमिक स्कूलों और अवर बुनियादी स्कूलों का नम्बर आता है, जहाँ ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बाद के माध्यमिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं— (१) मिडिल-अवर हाई स्कूल या प्रवर बुनियादी स्कूल, जिनमें ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चे विद्याध्ययन करते हैं और (२) हाईस्कूल, जिनमें ११ से १६ वर्ष की आयु के बच्चे शिक्षा पाते हैं। परन्तु कई राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी हैं, जहाँ ११ से १७ या १८ वर्ष की आयु के बालक शिक्षा पाते हैं।

हाईस्कूल के बाद इण्टरमीडिएट कालेजों या डिग्री कालेजों की इण्टरमीडिएट कक्षाओं का नम्बर आता है। यहाँ दो वर्ष शिक्षा मिलती है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में सफलता होने के बाद विद्यार्थी को दो वर्ष का समय प्रथम डिग्री पाने के लिए लगता है। जो विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्कूल से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट नहीं पढ़नी पड़ती है। ये सीधे तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम में भरती होते हैं।

स्नातक होने के बाद, विद्यार्थी को उत्तर-स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए दो वर्ष लगते हैं। आवश्यक विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थाओं तथा कई कालेजों में शोध का विशेष बन्दोबस्त है। यहाँ विद्यार्थीगण उत्तर-स्नातक स्तर के अनुसन्धान कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं।

† Education in India, 1955-56, Vol. I, pp. 18-19

तीसरा अध्याय

✓ बुनियादी शिक्षा

प्रस्तावना

आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में सबसे उल्लेखनीय घटना है 'बुनियादी शिक्षा'। इसने इस देश के शिक्षा क्षेत्र में एक नवीन धारा प्रवाहित कर दी। भारत को श्रद्धेय राष्ट्र की यह अन्तिम, किन्तु सबसे बहुमूल्य देन है। उन्होंने अनुभव किया कि देश में एक नूतन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की सृष्टि की आवश्यकता है, और यह उपयुक्त शिक्षा पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। गान्धीजी ने तो देश का कोना कोना छान डाला था, और उन्हें जन समुदाय की स्थिति का रत्ती रत्ती पता था। उन्होंने अनुभव किया था कि भारतीय जनता को न तो भरपेट भोजन ही नसीब होता है और न तन भर कपड़ा ही प्राप्त होता है।

इस आर्थिक दरिद्रता से भी हीनतर थी आत्मिक दरिद्रता। देश में सदियों से परवशता का शोलबाला था। यहाँ के अधिवासी तन, मन, विचार, आचार, रहन-सहन, खान पान, वेश भूषा आदि के दासत्व के कुचक्र में इस बुरी तरह फँस रहे थे कि उससे उन्हें मुक्ति पाना दुष्कर सा हो रहा था। अधिक क्या, लोग इस मायामयी गुलामी पर मोहित से हुए उसे अधिकाधिक आत्मसात् करते जा रहे थे। पूज्य गान्धीजी के ध्यान में यह बात विशेष रूप से खटकी। देश के शिक्षित वर्ग की आकांक्षाओं तथा गति निधि को देखते हुए उनके हृदय में वर्तमान शिक्षा के प्रति एक वितृष्णा उत्पन्न हुई। जिस जमीन का अन्न पानी इस वर्ग के शरीर में भिदा था उस वातावरण के अनुकूल उसे शिक्षा नहीं मिली थी, जिससे उसे अपनी भारतीय सभ्यता के प्रति घृणा थी। उसके हाव भाव से पादचाल्य बू आ रही थी, वह परिश्रम से दूर भागता था और जनता से अपने को कोठों दूर रखना चाहता था। इस कारण समाज के दो टुकड़े हो गये थे। एक ओर इने गिने बुद्धिजीवी थे और दूसरी ओर करोड़ों श्रमजीवी। दोनों के बीच भेद की गहरी खाई खुद गयी थी। बुद्धिजीवी श्रम से घबराते थे, और श्रमजीवियों को बुद्धि का लाभ नहीं मिलता था। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी जगह

व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा नाना प्रकार की होती है, जैसे : अर्थ-वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विधि (कानून), चिकित्सा, वन-विद्या, नृत्य, चित्रकला, आदि। कालेजों में तो विद्यार्थी इण्टरमीडिएट या पूर्व-व्यावसायिक (प्री-प्रफेशनल) परीक्षा उत्तीर्ण होकर ही प्रविष्ट होते हैं, पर स्कूल तथा पालीटेकनीक में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिक सर्टीफिकेट यथेष्ट होता है। अशक्त एवं अन्य विकलाङ्ग बच्चों के लिए विशेष स्कूल हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ों के लिए भी अलग स्कूल हैं।

यह तो हुआ हमारे देश की शिक्षा-पद्धति का साधारण विवरण। आजकल पद्धति में बहुत कुछ फेरफार हो रहे हैं। इनके सिवा प्रत्येक राज्य की कुछ-न-कुछ अपनी शैक्षणिक विशिष्टताएँ हैं, जिससे समूचे देश की शिक्षा-पद्धति एक समान नहीं है।

शिक्षा-व्यय

शिक्षा-व्यय दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) और परोक्ष (इन्-डाइरेक्ट)। प्रत्यक्ष व्यय में जो खर्च शामिल है, वे ये हैं : अध्यापकों, कर्मचारियों आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंश-दान, साज-सामान और उपयोग में आनेवाली वस्तुएँ, लेखन-सामग्री, इमारतों की मरम्मत, किराया, परीक्षाओं आदि का आवर्ती प्रसार। परोक्ष व्यय में वे खर्च शामिल हैं : छात्रावास और छात्र-वृत्तियों का खर्च, इमारतों और साज-सामान का खर्च, निर्देशन एवं निरीक्षण का खर्च और इस प्रकार के विविध खर्च जो किसी एक संस्था या एक प्रकार की संस्थाओं में नहीं बाँटे जा सकते।

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा-व्यय बढ़ गया है, और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। ३१ मार्च, १९४८ को पूरे देश का कुल शिक्षा-व्यय केवल ५५.१ करोड़ रुपया था। यद खर्च १९५६ ई० में १८९.४ करोड़ रुपया हुआ। अर्थात् शिक्षा-खर्च तीन गुने से अधिक बढ़ गया है। इतना होते हुए भी इस रकम से पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती हैं। एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है :

शिक्षा-व्यय में यह वृद्धि अवश्य सराहनीय है; पर पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ४०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इस रकम से यह भी पता चलता है कि हमें अभी कितना काम करना है।†

† Ministry of Education. *Ten Years of Freedom*. Delhi, Manager of Publications, 1957, p. 65.

रजत-जयन्ती के अवसर पर, गान्धीजी के सभापतित्व में इस देश के शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन आमन्त्रित हुआ। इसमें गान्धीजी ने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा न तो किसी प्रकार की जीवन वृत्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है और न उसमें किसी प्रकार के उत्पादनशील कार्य की क्षमता ही है। उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए :

१. इस सम्मेलन की राय में, देश के सत्र बच्चों के लिए सात वर्ष की मुफ्त और तालीम तालीम होना चाहिए।

२. तालीम का जरिया मातृ-भाषा होना चाहिए।

३. यह सम्मेलन महात्मा गान्धी की इस तजवीज की तार्किकता करता है कि तमाम मुद्दत में शिक्षा का मध्य बिन्दु किसी किसम की दस्तकारी होना चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा हो सके और बच्चों में जो कुछ अच्छे गुण पैदा करने हैं और उनको जो शिक्षा दीक्षा देनी है वह जहाँ तक हो सके किसी केन्द्रीय दस्तकारी से सम्बन्ध रखती हो और जिस दस्तकारी का चुनाव बच्चों के माहौल का लिहाज रखकर किया जाय।

४. सम्मेलन आशा करता है कि इस तरीके से धीरे-धीरे अध्यापकों की तनख्वाह का खर्च निकल आवेगा। †

नयी तालीम की अहिंसक योजना.—सम्मेलन ने फिर दिल्ली के जामिया मिलिया के प्राचार्य डाक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी मुक़रर की। उस समिति की रिपोर्ट २ दिसम्बर, १९३७ में निकली। १९३८ की हरिपुरा कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को मजूर किया और वर्धा के पास सेवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ स्थापित किया। इस सघ का उद्घाटन करते हुए गान्धीजी ने कहा

यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म सेगाँव में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवों में बसता है, जो सेगाँव से भी बहुत हीन दशा में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन गाँवों से निरक्षरता दूर भगा दें, तथा सत्य और अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का सन्देश गाँवों में पहुँचावें। यह जिम्मेवारी आपके

† सदैव, ३०-१०-१९३७।

पगु बनकर बैठे थे। ऊँच-नीच, छोटा बड़ा, मालिक-नौकर और हुजूर-मजूर के विचार ने सबको इस बुरी तरह पछाड़ रखा था कि छुटकारे का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था।

नयी तालीम का जन्म नये समाज और नवीन मानव की रचना के विचार से हुआ था। इस तालीम में गान्धीजी ने शिक्षा के श्रेष्ठ आदर्शों का समावेश करना चाहा था। वे इस शिक्षा के द्वारा अपनी मातृ-भूमि में वास्तविक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे; ऐसी शिक्षा, जो पुस्तकीय न हो, वरन अभिरक्षा तथा सृजनात्मक कार्यों पर निर्भर हो, जो भारतीय संस्कृति के पाये पर खड़ी हो, जिनमें शारीरिक परिश्रम के लिए यथेष्ट स्थान हो, जो अमीर-गरीब का भेद मिटावे और जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देवे। गान्धीजी के सामने एक और प्रश्न था—अर्थ। कारण, शिक्षा-विस्तार के लिए पर्याप्त द्रव्य अपेक्षित होता है। पर हमारी गरीब एवं परार्थीन मातृभूमि के लिए इस महत् कार्य के निमित्त इतना अधिक धन संग्रह करना सम्भव न था। इसलिए गान्धीजी एक ऐसी शिक्षा की कल्पना में थे जो असली अवश्य हो, पर खर्चीली न हो।

गान्धीजी अपनी नवीन शिक्षा विषयक कल्पना में बहुत दिनों से निमग्न थे। उनकी शिक्षा का आरम्भ दक्षिण आफ्रिका के फिनिक्स कालोनी में अपने परिवार में ही और टालस्टाय फार्म में हुआ। दक्षिण आफ्रिका में मानव की आत्मा एवं मानवता का जो नित्य अपमान हो रहा था, और आज भी हो रहा है, उसके विरुद्ध गान्धीजी ने जो अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, वही उनकी शिक्षा के कार्यक्रम का माध्यम रहा। इस माध्यम का प्रथम विकास दक्षिण आफ्रिका में करके बापूजी भारत में आये, और यहाँ साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन् १९१७ ई० के चम्पारण सत्याग्रह से लेकर उनकी जन-शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। यह भारत जैसे एक विराट राष्ट्र की समग्र जनता के लिए अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन की तैयारी थी। आगे जाकर उन्होंने अपनी इस नयी शिक्षा का नाम 'बुनियादी शिक्षा' या 'नयी तालीम' दिया। जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' के अंकों में गान्धीजी ने राष्ट्र के सामने बुनियादी तालीम की मूल कल्पना रखी। †

प्रारम्भिक कार्य

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन, वर्धा.—२२ और २३ अक्टूबर, १९३७ को वर्धा के मारवाड़ी हाईस्कूल (वर्तमान नवभारत विद्यालय) की

† हरिजन सेवक, २-७-१९३७

धुनाई और फताई का साधारण ज्ञान । (३) मातृ भाषा । (४) गणित । (५) समाज शास्त्र (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समन्वय) । (६) साधारण विज्ञान । (७) संगीत और चित्रकला । (८) हिन्दुस्तानी (ऊर्दू और देवनागरी लिपि द्वारा) ।

योजना की प्रगति.—जाकिर हुसैन रिपोर्ट के निकलते ही कांग्रेस प्रदेशों अर्थात् असम, उ्त्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का प्रचार जोरों से आरम्भ हुआ । स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों तथा शासकीय अफसरों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्संजीवन केन्द्र खोले गये तथा बुनियादी शिक्षा की समितियाँ स्थापित हुईं । रक्षित राज्यों में कश्मीर ने अच्छा काम किया । कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानों ने अपनी निजी बुनियादी शालाएँ चलायीं । इनमें उद्देश्ययोग्य हैं : दिल्ली जामिया मिलिया, मुबरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, आन्ध्र ज्ञातीय कलाशाला, इत्यादि । पर द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होते ही, योजना में शिथिलता आ गयी । तो भी देश की आजादी के साथ साथ बुनियादी शिक्षा में फिर से तेजी आ गयी ।

नयी तालीम पर नये विचार.—इस अवधि में गान्धीजी ने नयी तालीम को एक नया रूप दिया । १९४२ में जेल से मुक्त होने के बाद, उन्होंने घोषणा की :

बन्दी अवस्था में नयी तालीम की शक्यता पर सोचते सोचते मेरा दिल अस्थिर हो पड़ा । योजना की कामयाबी देखकर हमें चुप नहीं रहना चाहिए । हमें आगे बढ़ना है । हमें बच्चों के घर सुधारने पड़ेंगे, हमें उनके माँ-बाप को शिक्षा देनी होगी । बुनियादी शिक्षा का ध्येय होना चाहिए—आजीवन शिक्षा ।

इस घोषणा के साथ आरम्भ हुई नयी तालीम की दूसरी मञ्जिल । बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध अब केवल बच्चों की तालीम में मर्यादित न रहा । इस शिक्षा का वृत्त बढ़ाना पड़ा, ताकि इस वृत्त में हर उम्र का हर व्यक्ति शामिल हो सके । जनवरी १९४५ को, सेवामाग में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई । प्रश्न था बुनियादी शिक्षा का सिंहावलोकन तथा भविष्य के लिए एक प्रोग्राम रीचिना । अध्यक्षीय भाषण देते हुए गान्धीजी ने कहा :

हमारी जिम्मेवारी सात से चौदह वर्ष के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाप्त नहीं होती । नयी तालीम के कार्य क्षेत्र के विस्तार की बहुत आवश्यकता है । यह शिक्षा मानव जीवन में गर्भाधान से आरम्भ होती है और मृत्यु पर्यन्त चलती रहती है ।

ऊपर है। यदि यह योजना असफल हुई तो इसके लिए अध्यापक दोपी उठराये जावेंगे। दस्तकारी के जरिये, भूमिति, इतिहास, भूगोल और गणित की शिक्षा दी जायगी और छात्रों के शारीरिक श्रम से स्कूल का खर्च निकालने का प्रयत्न किया जायगा। पाठ्यालय जगत विनाशिनी शिक्षा दे रहा है। हमें अहिंसा के जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है। †

जाकिर हुसैन रिपोर्ट की रूप-रेखा—अब हमें यह देखना है कि जाकिर हुसैन रिपोर्ट की शिक्षा-योजना की रूप-रेखा क्या है। यह निम्न-लिखित रूप में प्रस्तुत की गयी थी : (१) सम्पूर्ण ज्ञान का मध्य-विन्दु एक केन्द्रीय दस्तकारी है। तमान पढ़ाई इस केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा दी जाती है। (२) योजना स्वावलम्बी है। इस स्वावलम्बन के दो रूप हैं। प्रथमतः, योजना विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन में अपने पाँवों पर खड़ा होना सिखाती है। द्वितीयतः, योजना का ध्येय है कि छात्रों के परिश्रमार्जित उत्पादन से कम-से-कम शिक्षकों के घेतन का खर्च निकले। (३) हाथ के काम पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से न डरे। (४) योजना अहिंसात्मक है, क्योंकि बच्चों को मशीन-द्वारा दूसरों की रोटी छीनना इसके द्वारा नहीं सिखाया जाता है। (५) तालीम विद्यार्थी के वातावरण और स्थानीय परिस्थिति की ओर विशेष लक्ष्य रखती है, जैसे : उसका गृह तथा ग्राम, गाँव के धन्धे तथा दस्तकारी। (६) योजना प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य जीवन में उपयुक्त नागरिक बनाने की कोशिश करती है।

रिपोर्ट का मुख्य ध्येय था कि इस देश में ७ से १४ वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चे एवं बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, तथा शिक्षा की अवधि सात वर्ष की रहे। पाठ्यक्रम का स्तर अंग्रेजी को छोड़कर वर्तमान मैट्रिक के समान रहे। इन सब विषयों की शिक्षा एक आधारभूत दस्तकारी के माध्यम से दी जाय। शिक्षण का माध्यम मातृ-भाषा रहे, परन्तु राष्ट्र-भाषा (हिंदुस्तानी) का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रहे।

पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किये गये : (१) केन्द्रीय दस्तकारी—कोई भी एक विषय : (अ) कताई और बुनाई, (आ) बटुईगिरी, (इ) फल और सब्जी की बागवानी, (ई) कृषि, (उ) चमड़े का काम, (ऊ) अन्य कोई उपयुक्त दस्तकारी जो शिक्षा-प्रद हो और जिमके लिए स्थानिक वातावरण अनुकूल हो। (२)

† तद्वत्, २१ अप्रैल, १९३८।

प्रक्रम है 'प्रौढ़शिक्षा'—अर्थात् समूचे समाज की तालीम और साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी शिक्षा, जिससे कि सत्र लोग एक मुसीबत, स्वास्थ्यकर, स्वच्छ तथा स्वावलम्बी जीवन बिता सकें।

पूर्व-बुनियादी—(७ से कम आयुवाले बच्चों की शिक्षा)—ज्योंही बच्चा स्वतः अपने घर से स्कूल पैदल जाने लगता है, त्योही शिक्षा प्रक्रिया गृह से शाला की ओर प्रसारित होती है। पूर्व बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों का पूर्णतया शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। यह तभी सम्भव है जब कि शिक्षक, माता-पिता तथा समाज मिल-जुल कर बच्चों की शिक्षा में हाथ बँटावें तथा घर, स्कूल एवं गाँव एक सूत्र में गुँथ जावें। †

बुनियादी शिक्षा—(सात से चौदह वर्ष वाले बालक-बालिकाओं के लिए)—इस शिक्षा की इमारत प्रौढ़ शिक्षा तथा पूर्व-बुनियादी शिक्षा की नींव पर खड़ी होती है। जाकिर हुसैन रिपोर्ट का पूर्व पाठ्यक्रम दुबारा सशोधित किया गया है। योजना निम्न लिखित कार्य-कलापों से सम्बन्ध रखती है :

१. आवश्यक ज्ञान, अभ्यास, भाव तथा कौशल — जो स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) के लिए आवश्यक हो।

२. नागरिक शिक्षा (व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक)—गृह, स्कूल, ग्राम, स्वदेश तथा विश्व के ज्ञान के द्वारा। यह ज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सरल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र द्वारा दिया जाय।

३. स्वावलम्बी होने की शक्ति—अन्न वस्त्र तथा आश्रय प्राप्ति के लिए।

४. केन्द्रीय दस्तकारी—इनमें से कोई भी एक हस्तकार्य हो : कृषि और बागवानी, कताई और बुनाई, बढईगिरी, गृह निर्माण और मरम्मत का काम, या अन्य कोई दस्तकारी जो शिक्षा प्रद हो और जिसके लिए स्थानिक वातावरण अनुकूल हो।

५. साधारण विज्ञान और गणित।

हाल ही में बुनियादी शिक्षा की अनुमान निर्धारण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) ने सिफारिश की है कि जो विद्यार्थी हाईस्कूल या अन्य उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय की भौति छोटी बक्ष्ता से ले सकने हैं। इसी प्रकार अहिन्दी क्षेत्रों की बुनियादी शालाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय कर दिया जाय।

† देखिए अध्याय दसवाँ।

गान्धीजी के नवीन निर्देशानुसार बुनियादी शिक्षा को आजीवन शिक्षा बनाने की ओर सम्मेलन ने ध्यान दिया। सम्मेलन ने चार समितियाँ गठित की और प्रत्येक को जीवन के एक-एक प्रक्रम के अनुकूल सुप्रयोज्य शिक्षा-योजना निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इन शिक्षा-प्रक्रमों के नाम प्रमशः इस प्रकार हैं : (१) प्रौढ़ शिक्षा, (२) पूर्व बुनियादी अर्थात् सात से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, (३) बुनियादी अर्थात् सात से चौदह वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा और (४) उत्तर बुनियादी शिक्षा, अर्थात् उन विद्यार्थियों की शिक्षा, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा समाप्त कर ली हो।

३० जनवरी, १९४८ को गान्धीजी हम सबको रोता हुआ छोड़ इस संसार से सदा के लिए विदा हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात् नयी तालीम के कार्य-कर्त्ताओं ने यह शपथ ली कि जब तक हमारे टम में दम है तब तक हम नयी तालीम की यात्रा को जारी रखेंगे, तथा अपने जीवन और काम में नीचे लिखे उद्देश्यों को सामने रखकर मजिल की ओर बढ़ते रहेंगे :

१. तालीम में सत्य और अहिंसा की रूढ़ फूँकना।
२. तालीम को हाथ के काम से, कुदरती वातावरण से, और समाजी जिन्दगी से जोड़ना।
३. तालीम के द्वारा सच्ची देश-भक्ति और इन्सानी हमदर्दी सिखाना तथा साम्प्रदायिकता को मिटाना।
- ✓ ४. बचपन से बुढ़ापे तक की उम्र की हर सीढ़ी के लिए नयी तालीम का उचित प्रबन्ध करना।
५. बच्चों और सयानों को ऐसे समाज के लिए तैयार करना, जिसमें मुकाबिले की जगह सहयोग हो, छूट की जगह इन्साफ़ हो, आज्ञादी हो जिम्मेवारी के साथ, और आर्थिक उन्नति हो नैतिक उन्नति के साथ। †

नयी तालीम के प्रक्रम

अब तनिक नयी तालीम के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर विचार किया जाय।

प्रौढ़ शिक्षा.—नयी तालीम की पूरी कामयाबी के लिए आवश्यक है कि यह शिक्षा बच्चों से आरम्भ न की जाय, वरन इसकी शुरुआत बच्चों के माता-पिता, अभिभावक एवं प्रौढ़ समाज से होनी चाहिए। इसलिए नयी तालीम का प्रथम

† नयी तालीम का चौथा सम्मेलन, अप्रैल, १९४८।

उत्तम बुनियादी या विश्वविद्यालयीय शिक्षा:—१९४९ में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट निकली। इस रिपोर्ट में ग्रामीण विश्वविद्यालय की चर्चा विदोष रूप से की गयी है। बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन के सातवें अधिवेशन के समय विश्वविद्यालय (उत्तम बुनियादी) शिक्षा की आलोचना की गयी और सेवाग्राम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना निश्चित हुआ। एक कमिटी ने उत्तम बुनियादी शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम खींचा। ममिति ने अध्ययन के लिए सात कार्य-कलाप ठीक किये: कृषि तथा उद्यान विद्या, पशु पालन तथा दुग्ध-व्यवसाय, ग्रामीण इञ्जीनियरिंग, ग्राम-उद्योग, ग्राम्य स्वास्थ्य तथा आहार, ग्रामीण टेक्नोलॉजी और ग्राम्य शिक्षा।

नवम्बर, १९५२ में विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ हुआ और अठारह विद्यार्थी उसमें प्रविष्ट हुए। अधिक छात्रों ने कृषि या पशु-पालन को चुना और कुछ ने इञ्जीनियरिंग या स्वास्थ्य। इतने में सन्त विनोबा की पुकार आयी। ये विद्यार्थी सेवाग्राम छोड़कर, विनोबाजी के भूदान-यज्ञ में सम्मिलित हुए। यथार्थ में विनोबाजी की भूदान-यात्रा एक परिव्राजकीय ग्राम-विश्वविद्यालय है। प्रतिदिन नये नये ग्रामों में इस जंगम विद्यालय का अध्यापन चलता है, और विद्यार्थियों को नयी तालीम का साक्षात्कार होता है।

नयी तालीम और भूदान

आज भारत में विनोबाजी ने एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न की है। हमारे लिए आशा और उत्साह की बात यह है कि भारत की जनता विनोबाजी की बात सुन रही है और उसका जवाब भी दे रही है। अभी तक ४४ लाख एकड़ भूमि और पॉच हजार के करीब ग्रामों का दान प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नयी तालीम की विचार-धारा देश में प्रवाहित हो रही है। नयी तालीम का क्षेत्र तैयार हो रहा है।

उपर्युक्त प्रयोग के फल-स्वरूप तालीमी संघ ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो यह ग्राम-दान आन्दोलन है, यह नयी तालीम का ही कार्य क्रम है। दिनांक १८ जनवरी, १९५७ की बैठक में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि :

पूज्य विनोबाजी के भूदान-कार्य ने अब जो ग्रामदान का रूप ग्रहण किया है उससे अहिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति का कार्य प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने के दिन आ गये हैं। अहिंसात्मक क्रान्ति राज सत्ता के द्वारा नहीं, किन्तु शिक्षा के द्वारा हो सकती है। इसलिए हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का कर्तव्य होता है कि इस क्रान्ति में यथा सम्भव सहयोग हो।

उत्तर बुनियादी शिक्षा (पन्द्रह से अठारह वर्षवाले विद्यार्थियों के लिए)—
 हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की उत्तर बुनियादी समिति के निर्णय के अनुसार इस शिक्षा के
 ये उद्देश्य हैं : (१) इस शिक्षा की नींव भी बुनियादी शिक्षा की नाई किसी दस्तकारी
 पर आधारित या केन्द्रित होना चाहिए। (२) पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण हो।
 (३) पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों का समावेश रहे, ताकि विद्यार्थियों की
 योग्यता के अनुसार विषयों का चयन हो सके। (४) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय
 भाषा हो। (५) पूरी शिक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार
 भिन्न-भिन्न अवश्य हो, पर तीन से चार वर्ष के भीतर की ही हो। (६) पाठ्यक्रम
 ऐसा हो कि अभ्यास-काल में प्रत्येक विद्यार्थी अपना स्वर्च स्वतः कमा लें। †

समिति ने चौदह प्रकार के कार्य प्रस्तावित किये हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी
 रुचि के अनुकूल कार्य का चयन कर सके। वे कार्य ये हैं : कृषि, चिकित्सा,
 इञ्जीनियरिंग, यन्त्रसम्बन्धी कला, वाणिज्य, इस्तकला, विद्युत, शिक्षा, पत्रकार कला,
 मुद्रण, ललितकला, गृह-विज्ञान, धातु-विज्ञान और उद्योग। ‡

इस शिक्षा की एक और खूबी है; और वह है स्वाश्रितता, जिसकी ओर बुनियादी
 और उत्तर बुनियादी—दोनों—शिक्षाओं का लक्ष्य है। पर बुनियादी शिक्षा का ध्येय है
 कि शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी अपने भविष्य जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सके
 तथा विद्यार्थियों के श्रमार्जित उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का व्यय भी निकले। पर
 उत्तर बुनियादी शिक्षा का आदर्श गूढ़तर है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी कौशल तथा
 स्वार्जित ज्ञान के द्वारा अपने विद्याध्ययन का व्यय स्वतः उठा सके, और उसे इस स्वर्च के
 लिए अपने माता-पिता तथा समाज का मुँह न ताकना पड़े। एक आदर्श बुनियादी
 विद्यालय का विवरण मुनिए :

उत्तर बुनियादी पाठशाला तो एक विद्यालय-ग्राम है, जहाँ विद्यार्थी
 तथा शिक्षक साथ-साथ रहते हैं। वे अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा आय से
 अपने लिए भन्न वस्त्रादि की आवश्यकता को स्वयं ही पूरा करते हैं। इस
 मेहनत का ध्येय अर्थ-समृद्ध नहीं है। *

† Marjorie Sykes, ed. *A Picture and Programme of Post-Basic Education*. Sevagram, Hindustani, Talimi Sangh, 1954, pp. 21-22

‡ *Ibid.*, p. 18.

* Ram Kishore. 'After Fifteen Years,' *Modern Review*, March, 1955, pp. 228-29.

४. सांस्कृतिक विषयों के वे अद्य स्वतन्त्र रूप से सिखाये जावें, जो केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा न सिखाये जा सके।

५. बुनियादी शिक्षा के अन्त में किसी ग्राह्य परीक्षा की जरूरत नहीं है। आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाय।

द्वितीय समिति ने निम्न लिखित रिपोर्ट दी :

१. बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम आठवर्षीय अर्थात् ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा जावे, पर पाठ्यक्रम की एकता को बनाये रखते हुए इस अवधि को दो हिस्सा में बाँट दिया जाय : (१) अवर (जूनियर) बुनियादी, जो ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए हो और (२) प्रार (सीनियर) बुनियादी, जो ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए हो।

२. अवर शिक्षा के समाप्त होने पर ही, विद्यार्थी अन्य उच्चस्तर की संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाने पावें।

सारजेण्ट योजना (सन् १९४४)—‘केसशिम्’ ने खेर समितियों की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसी समय अर्थात् सन् १९४४ के आरम्भ में ‘केसशिम्’ ने अपनी ‘युद्धोत्तर शिक्षा पुनर्निर्माण योजना’ प्रकाशित की। इस योजना का चादू नाम ‘सारजेण्ट योजना’ है, क्योंकि सर जान सारजेण्ट ने, जो कि उस समय भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार थे, इस योजना के तैयार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इस योजना ने खेर समितियों की रिपोर्टों पर पूर्णतः विचार किया और घोषित किया कि इस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नयी तालीम होनी चाहिए। यह शिक्षा आठ वर्ष की अवधि की हो, पर खेर समिति की सिफारिशों के अनुसार दो भागों में हो—अवर और प्रार। पर नयी तालीम के ‘क्रिया के द्वारा ज्ञान’ के सिद्धान्त का सम्पूर्ण समर्थन करते हुए रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया :

उसकी सम्मति में विशेषतः प्राथमिक चरण में शिक्षा कभी भी स्वाश्रयी न हो ही सकती है और न होनी चाहिए। विद्यार्थियों के उत्पादन से, अधिक से अधिक, दस्तकारी व सामान ही खरीदे जा सकते हैं।†

हाल की समितियाँ—‘केसशिम्’ के बाईसवें अधिवेशन की सिफारिशों के कारण, एक केन्द्रीय बुनियादी समिति स्थापित हुई है। इस समिति का मुख्य कार्य है,

† Sargent Report. p 8

ग्राम-दान आन्दोलन आगे बढ़ता हुआ अब शान्ति-सेना के कार्य-क्रम तक आ पहुँचा है। शान्ति-सेना की कल्पना भारत के लिए कोई नयी बात नहीं है। आज से बीस वर्ष पूर्व गांधीजी ने शान्ति-सेना की योजना राष्ट्र और विश्व के सामने उपस्थित की थी, लेकिन उस समय उसकी कल्पना के अनुसार काम करने का नैतिक बल इस देश में जायत न था। अब सन्त विनोबाजी ने भूदान-यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण देश में एक नवीन जीवन फूँक दिया है। ग्राम-दान में मिले हुए गाँवों में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नयी तालीम का एक नया पर्व है। विनोबाजी ने ग्राम-शिक्षा और ग्राम-रक्षा — इन दोनों—को जोड़कर राष्ट्र के समक्ष नयी तालीम का जो समग्र कार्यक्रम रखा है उसके विषय में शिक्षक-समाज को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। सच्चा शिक्षक वही है जो प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-निर्भरता का और समाज की प्रवृत्तियों में अनुशासन-युक्त सहयोग की भावना का विकास करे तथा जो सच्चा सेवक एवं मित्र होवे।

गांधीजी के मन में शान्ति-सेना की जो कल्पना थी, विनोबाजी ने उसकी ओर राष्ट्र का ध्यान पुनः आकर्षित किया है। शान्ति-सैनिक का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है :

शान्ति सेना का सैनिक नित्य जन-सेवा करेगा, और नैतिक तौर पर शान्ति-कार्य करेगा। ऐसे निष्काम, निस्वार्थ, निष्पक्ष एवं निरपेक्ष सेवकों की सेना खड़ी होनी चाहिए।

राष्ट्र के शिक्षक ही इस शान्ति-सेना के सैनिक बन सकते हैं। नयी तालीम का ध्येय है : जब कि सारा संसार भयभीत है तब शिक्षकगण स्वेच्छा से शान्ति-सेना के स्वयंसेवक (सैनिक) बनकर विश्व में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करें।

नयी तालीम और सरकार

खेर समितियाँ.—जाकिर हुसैन रिपोर्ट की जॉच-पड़ताल के लिए 'केसदिम' ने बम्बई के मुख्य तथा शिक्षा मन्त्री श्री खेर की अध्यक्षता में दो वार समितियाँ नियुक्त कीं। प्रथम समिति ने अपनी रिपोर्ट १९३८ में तथा दूसरी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४० में दी। प्रथम रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं :

१. बुनियादी शिक्षा का आरम्भ पहले गाँवों में किया जाय।
२. अनिवार्य शिक्षा की आयु ६ से १४ वर्ष रखी जाय।
३. विद्यार्थियों को बुनियादी स्कूलों से अन्य स्कूलों में जाने की अनुमति कक्षा पाँचवीं अथवा ग्यारह वर्ष की आयु के बाद दी जावे।

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नहीं। फल-स्वरूप उत्तर बुनियादी शिक्षा एक टिमटिमाते हुए दीप के समान है। पूरे देश में सिर्फ २६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं (१९५६-५७)।† हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ग्यारह ग्राम-प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं, जिनका बुनियादी शिक्षा से निकटतम सम्बन्ध है। इस समय पूरे देश में ५,८१ प्रशिक्षण स्कूल तथा ३१ प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं।‡

अनुमान-निर्धारण—समिति की सिफारिश के कारण, राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान की स्थापना हाल में ही हुई है। इस सस्था का उद्देश्य नयी तालीम में रोज या अन्वेषण, तथा बुनियादी शासकों एवं निरीक्षकों को बुनियादी शैली में प्रशिक्षित करना है। प्रतिष्ठान अन्य बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों से मिलकर काम करता है, वह बुनियादी शिक्षा के विविध समाचारों का लेखा रपता है तथा नयी तालीम की समस्याओं को मुलज्ञाने की चेष्टा करता है।

समालोचना

कुछ आक्षेप—इस योजना के प्रस्तुत होने के साथ ही साथ, भारतीय शिक्षा-जगत में इसकी बड़ी आलोचना हुई तथा शिक्षा विगारदों ने इसके विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तुत किये। इनमें से कुछ आक्षेपों को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम आक्षेप शिक्षा की स्वाश्रयता है। बहुतों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा स्कूल शिल्प कुटीर केन्द्र बन जावेंगे, जिनमें बालकों का शोषण होगा। कारण, शिक्षकों का वेतन विद्यार्थियों के परिश्रम पर निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा प्रस्तुत माल सब समय भड़ा रहेगा। वह कुशल कारीगरो द्वारा निर्मित माल के समक्ष न टिक सकने योग्य रहेगा। ऐसे में उसकी खपत भी न होगी। यह प्रायः देखा गया है कि हस्त कौशल शिक्षा सदैव रचौली ही हुआ करती है। इसमें आमदनी की अपेक्षा खर्च सदैव अधिक ही रहता है।

यह आक्षेप बहुत कुछ युक्ति-सगत तथा तथ्यपूर्ण है। बुनियादी तालीम का प्रचार अनेक स्थानों में हुआ है। सबका अनुभव है कि वहाँ स्वाश्रयता नहीं पनप पायी। शायद कहीं वह सध भी सकी होगी। सारजेण्ट रिपोर्ट ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि शिक्षा — विशेषकर प्राथमिक शिक्षा — कभी भी स्वाश्रयी नहीं हो सकती है।*

† *Education in The States, 1956-57, pp. 2-3*

‡ *Loc. cit*

* *Sargent Report p 8*

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के लिए सलाह देना। सन् १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने अनुमान-निर्धारण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) मुकर्रर की। इसे निर्देश दिया गया कि वह चुने हुए स्थानों में स्वतः जाकर बुनियादी शिक्षा की जाँच करे। समिति ने सिफारिश की है :

१. प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत उत्तर-स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किये जावें।
२. बुनियादी शिक्षा पर गवेषणा करने के लिए, एक केन्द्रीय अन्वेषण सस्था की आवश्यकता है।
३. ग्राम-पुनर्गठन से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी समितियों शिक्षा-विभाग से मिलकर बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करें।
४. प्रत्येक राज्य-सरकार अपनी शिक्षा-नीति स्पष्ट घोषित करें कि थोड़े ही अरसे में राज्य के सब प्राथमिक स्कूल तथा प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी रूप में बदल दी जावें।
५. उच्च विद्यालयों में भरती होने के समय बुनियादी तथा माध्यमिक स्कूलों के समान वर्गों को एक-सी मान्यता दी जावे।
६. दस्तकारी सिखाने के लिए, बुनियादी स्कूलों में पुराने कुशल अशिक्षित कारीगर नियुक्त किये जावें, जो बुनियादी शिक्षकों से मिलकर काम करें।

वर्तमान स्थिति—आज हमारे देशमें नयी तालीम का जो भी काम चल रहा है, वह अधिकतर सरकार के शिक्षा-विभाग की ओर से या सरकारी मान्यता और आर्थिक सहायता के बल पर चल रहा है। केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों ने स्वीकार कर लिया है कि पूरे देशमें ६ से १४ वर्षवाले बच्चों की शिक्षा बुनियादी होगी। देश में बुनियादी स्कूल खुलते जा रहे हैं, पुरानी प्राथमिक शालाओं को बुनियादी रूप दिया जा रहा है, प्रशिक्षण स्कूलों के विद्यार्थी-शिष्यरुग्ण इस नयी शिक्षा में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं तथा नयी तालीम के साहित्य की उन्नति होती जा रही है। इतना होते हुए भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति आशानुकूल नहीं हो रही है।

इसी प्रश्न के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा को मान्यता प्रदान की है; पर

पर दृष्टि-निक्षेप कीजिए। इस दृष्टिपात से ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों का यथेष्ट समावेश है, और इसका उद्देश्य एक समन्वित एवं सर्वाङ्गीण शिक्षा देना है। पुस्तकों के पढ़ने के साथ-साथ बच्चों को अपने हाथ तथा अपनी बुद्धि को उपयोगी कामों में लगाने की क्षमता प्राप्त होती है। अपनी मातृभाषा, राष्ट्र भाषा, स्वदेश का इतिहास, साधारण विज्ञान, इत्यादि साहित्यिक विषयों के सीखने के सिवा वह इस देश का एक उपयुक्त नागरिक तैयार होता है। सारांश यह है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की अपेक्षा बुनियादी पाठ्यक्रम कहीं अधिक स्वाभाविक, प्रेरणादायक तथा मनोवैज्ञानिक है।

दूसरी शका के उठने का मुख्य कारण है योजना की भ्रामक समय सारिणी, जिसके ५½ घण्टे के दैनिक कार्यक्रम में ३ घण्टे २० मिनट केन्द्रीय दस्तकारी के लिए और केवल दो घण्टे साहित्यिक विषयों के लिए निर्धारित किये गये हैं। इस भ्रम को मिटाने के लिए जाकर हुसैन समिति की द्वितीय रिपोर्ट का निम्नांकित अंश पढ़ना आवश्यक है :

आधारभूत कौशल के लिए निर्धारित समय की रूब टीका टिप्पणी हुआ करती है और कहा जाता है कि इसके कारण साहित्यिक विषयों की उपेक्षा होती है। इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि केन्द्रीय दस्तकारी के लिए बँधा हुआ पूरा समय केवल शिल्प सम्बन्धी अभ्यास में नहीं व्यय हो जाता, वरन् निर्धारित समय का यथेष्ट भाग दस्तकारी से सम्बन्धित मौखिक कार्य, भाषा अभिव्यञ्जन तथा रेखाचित्र पर खर्च होता है। इसके सिवा, विद्यार्थियों को उद्योग प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप अर्थात् हर क्रिया का क्या और कहाँ का परिज्ञान दिया जाता है। †

यहाँ तक सभी सहमत होते हैं, पर बुनियादी योजना में इस कौशल के साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का अन्तर्योग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है। समवाय सहज तथा स्वाभाविक होना चाहिए। यदि इस पद्धति में अधिक रींचतान की जाय, तो ज्ञान अधूरा तथा खोपला रह जाता है। सब विषयों का प्रत्येक भाग समवाय द्वारा कभी भी नहीं सिखाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के दिग्गजों ने इस कमी को शीघ्र ही समझ लिया और उन्होंने इसे हटाने की कोशिश भी की। सन् १९३९ के अक्टूबर में नयी तालीम के सम्मेलन ने निर्णय किया :

जाकिर हुसैन समिति ने भी वाद को इस प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, “यद्यपि यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं हो सकती है, तथापि इसकी आवश्यकता है। कारण, ऐसी ही शिक्षा से राष्ट्रीय संगठन हो सकता है।”†

स्वावलम्बन की चर्चा करते हुए गान्धीजी ने कहा था कि पहली-दूसरी कक्षाओं में नुरुसान होगा, इसलिए घाटा रहेगा। लेकिन कुल सात कक्षाएँ होंगी; अतएव कुल मिलाकर सब ठीक हो जायगा। बिहार सरकार का कहना है, “यदि आठ कक्षाओंवाले प्रवर वेसिक स्कूल हों — १५० विद्यार्थी प्रथम पाँच वर्गों में तथा १०० विद्यार्थी अन्तिम तीन वर्गों में — तो स्कूल का ६७ प्रतिशत खर्च, विद्यार्थी-निर्मित माल की कीमत से निकल सकता है।”‡ लेकिन आज सभी जगह आठ कक्षाएँ नहीं हैं, और सभी जगह प्रत्येक कक्षा में ३० विद्यार्थी मिलना शक्य नहीं है। उत्तर-बुनियादी भवन सेवाग्राम में देखा गया है कि विद्यार्थीगण अपने परिश्रम-द्वारा अपना ६५ प्रतिशत खर्च निकाल सकते हैं, पूरा नहीं।§ सार अर्थ यह है कि स्वाश्रयता केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाल में ही अखिल भारतीय नयी तालीम के द्वादशवें सम्मेलन के उद्बोधन भाषण में डा० जाकिर हुसैन ने उत्पादक कार्य (प्रोडक्टिव वर्क) का यथार्थ रूप समझाते हुए कहा :

मेरी समझ में एज्यूकेशन प्रोडक्टिव वर्क का नाम ही ‘शिक्षा’ है। यह काम असल में मस्तिष्क का काम है, कमी हाथ के काम के साथ, और कभी हाथ के काम से अलग। यह हाथ का काम भी हो सकता है, और मस्तिष्क का काम भी।§

द्वितीय आक्षेप यह है कि एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा पूर्ण शिक्षा देना। इस विषय में अनेक प्रश्न किये जाते हैं : क्या केन्द्रीय उद्योग-द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है ? और क्या इससे साहित्यिक शिक्षा नीरस नहीं हो जाती है ? क्या इस शिक्षा के द्वारा बौद्धिक एवं व्यावहारिक माध्यम से प्रत्येक विषय का कोना-कोना पढ़ाया जा सकता है ? इत्यादि। अब पहला प्रश्न लीजिए और बुनियादी पाठ्यक्रम

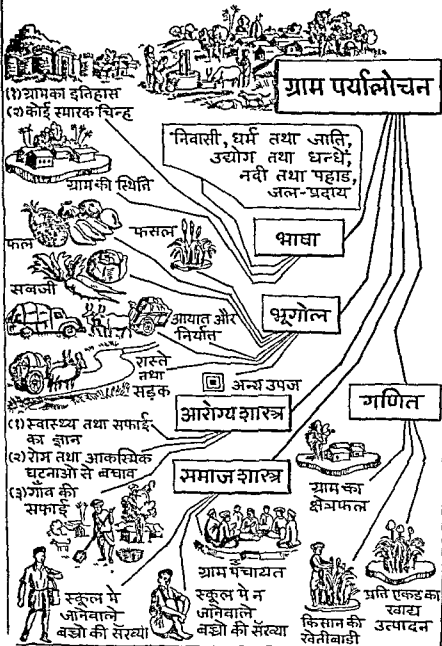
† Hindustani Talimi Sangh, *Educational Reconstruction*, 1950.
p. 96.

‡ *Education in India, 1950-51.*, Vol. I. p. 77.

§ Ram Kishore, *op. cit.*, p. 229.

§ द्वादश बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, नवम्बर, १९५०।

बुनियादी शिक्षा में समवाय कार्यकलाप: ग्राम पर्यालोचन



बुनियादी शिक्षण में समवाय का प्रयोग जबरदस्ती न किया जाय। समवाय की स्थापना केवल केन्द्रस्थ दस्तकारी के साथ ही तक सीमित न रहे। यह समवाय बच्चों के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से भी सम्बद्ध किया जाय।†

असल में इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थीगण जो उद्योग करते हैं, उस उद्योग के आसपास जो ज्ञान सहज-प्राप्य हो, वह उन्हें देना चाहिए।

हाल में ही केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने अंग्रेजी भाषा में 'बुनियादी शिक्षकों की पुस्तिका' (The Hand-book for Teachers of Basic Schools) प्रकाशित की है। इस पुस्तिका ने बुनियादी शिक्षण-पद्धति तथा विशेषतः समवाय के यथार्थ रूप पर नवीन प्रकाश डाला है। पुस्तिका में ठीक ही समझाया गया है कि बुनियादी पाठ्य-क्रम कार्य-कलाप पर निर्भर है। इसका उद्देश्य है विविध विषयों के पृथक्त्व को दूर करना तथा उन अंगों को समन्वित करना जो सहज में ही जोड़े जा सकें। इसके सिवा बुनियादी शिक्षा जोर देती है कि तमाम तालीम जीवन के जीते-जागते साकार तथा जहाँ तक हो सके उत्पादक अनुभवों के मार्फत दी जाय। इसी प्रकार प्रत्येक बुनियादी दस्तकारी शिक्षणीय अवश्य हो; पर इसके साथ-साथ वह स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल हो। चित्र ५ में एक कार्य-कलाप-केन्द्रित कार्यक्रम का रूप समझाना गया है। इस आकृति से यह भी स्पष्ट होगा कि आशय-पूर्ण कार्यों-द्वारा विद्यार्थीगण किम प्रकार अपने स्थानिक वातावरण का अपने अध्ययन में उपयोग कर सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि समवाय केवल केन्द्रीय दस्तकारी तक ही मर्यादित नहीं है। इसकी सीमा और भी विस्तृत है।

इन आशयों के सिवा, बुनियादी शिक्षा की और भी बहुत कुछ नुकताचीनी होनी रहती है, जैसे: इस शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया, विद्यार्थी की रुचि का ध्यान किये बिना ही हम उस पर एक दस्तकारी लवट देते हैं, एक ही प्रकार के या कुछ इने-गिने हस्त-कौशल के साथ माया-पच्ची करते-करते क्रमशः उमसे उपरामता हो जाती है, योजना में केवल गाँवों की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है, अस्पष्टता के व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं रह गया, इत्यादि। जहाँ तक हो सका है, बुनियादी शिक्षा के कार्य-कर्त्ताओं ने इन पुटियों को दूर करने की चेष्टा हाल में ही की है।

† Hindustani Talimi Sangh, One Step Forward, 1910 p 219

इस शिक्षा का 'बुनियादी' नामकरण क्यों हुआ ? इसके मुख्य तीन कारण हैं :

१. यह शिक्षा इस राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्यता, सभ्यता तथा शिक्षा सघटन की नींव पर गड़ी है ।

२. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को वह ज्ञान देती है जो उसके लिए अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने तथा प्रयोग करने के लिए आवश्यक है ।

३. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य जीवन के निर्वाह की क्षमता देती है ।

नयी तालीम ने कट्टर विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि इस शिक्षा ने स्वाधीन भारत के बच्चों के सामने नया आदर्श उपस्थित किया है । प्रत्येक योजना में कुछ-न कुछ जुटियाँ हो ही सकती हैं । समय और अनुभव उन जुटियों को दूर करने का सामर्थ्य देता है ।

उपसंहार — इतना होते हुए भी नयी तालीम की सन्तोषप्रद प्रगति नहीं हुई । सन् १९५६-५७ में, अरब बुनियादी स्कूलों और पुराने प्राथमरी स्कूलों की संख्या क्रमशः ४६,८८१ तथा २,४०,४१७ थी । इसी प्रकार उस वर्ष प्रवर बुनियादी स्कूलों तथा पुराने मिडिल स्कूलों की तादाद क्रमशः ६,८९७ तथा १७,५८९ थी,† अर्थात् पुरानी संस्थाओं की संख्या प्रायः चौगुनी थी । यह स्थिति उस समय की है, जब सरकार ने ६ से १४ वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए नयी तालीम को अपनाया स्वीकार किया । इस मन्थर गति के अनेक कारण हैं । एक सरकारी रिपोर्ट ने स्वीकार भी किया है, "बुनियादी शिक्षा एक नवीन प्रयोग है । इसे पद पद पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है : उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अर्थभाव तथा शिक्षा साधनों की ख़ल्पता ।"‡

असन्तोषप्रद प्रगति के और भी अनेक कारण हैं । नयी तालीम को चले हुए चाईस वर्ष भीत गये, पर लोग इस शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सके । जैसा कि अनुमान निर्धारण समिति ने महसूस किया है कि "बुनियादी शिक्षा के विषय में सही धारणा का अभाव है, और अभी भी अधिकतर लोगों को इस सम्बन्ध में ठीक

† *Education in the States, 1956-57, p. 2*

‡ *Ten Years of Freedom, p. 3.*

कुछ गुण.—यह निर्विवाद है कि इस शिक्षा-योजना ने भारत के शिक्षा-जगत में एक हलचल-सी मचा दी है। इसका जन्म नये ममान और नये मनुष्य की रचना के विचार से हुआ था। देश में मद्रियों से गुलामी की वेड़ियाँ पड़ी थीं। अपनी दूर दृष्टि से गान्धीजी ने यह देख लिया था कि भारत की उन्नति के लिए बिल्कुल नयी वृत्ति, बुद्धि, भावना और शक्तियुक्त समाज की आवश्यकता है। पर देश की शारीरी तथा निरक्षरता इस दिशा में पट-पट पर बाधा डाल रही थी।

यही कारण है कि गान्धीजी ने एक ऐसी योजना हमारे सामने रखी, जिसके द्वारा तमाम लड़के और लड़कियों को सात साल तक मुफ्त और लाजिमी तालीम मिल सके। चूँकि अनिवार्य शिक्षा-योजना बिना पैसे के नहीं चल सकती है, इस कारण उन्होंने एक स्वाश्रयी योजना की परिकल्पना की। पर स्वाश्रयता तो इस शिक्षा की प्रासंगिक बात थी। इस विचार ने देश में एक लहर-सी लहरा दी और प्रत्येक भारतवासी अनुभव करने लगा कि उसकी मातृ-भूमि की उन्नति अनिवार्य शिक्षा पर निर्भर है। इस तरंग के आगे अंग्रेज सरकार न टिक सकी।

गान्धीजी की बनवायी हुई योजना में बहुत महत्व की दूसरी बात यह थी कि बुनियादी शिक्षा केवल शब्दों और किताबों की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की शिक्षा है। आदमी के जीवन के तीन बड़े-बड़े क्षेत्र (मरकज़) हैं: एक, उसका प्राकृतिक वातावरण; दूसरा, उसका सामाजिक वातावरण; और तीसरा, उसका काम। इस योजना में अहिंसा के अनुसार, इन्हीं तीन को शिक्षा का मरकज़ भी माना गया है। जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, "इसमें बच्चों के लिए एक काम होगा। ऐसा काम जिससे कुछ काम की चीज़ बने, जो उसके अपने काम आ सके या उसके साथियों और पड़ोसियों के काम आ सके।" †

पर इस योजना में खाली काम शिक्षा का मरकज़ नहीं है, बच्चे का प्राकृतिक वातावरण भी है। मौखिक रटन्त के बटले यह शिक्षा बच्चों को सृजनात्मक कार्य के लिए तैयार करती है। इसके कारण शिक्षा में एक नयी जान आ गयी है, कक्षाओं की पुरानी नीरमता समाप्त हो गयी है, रटन्त विद्या के बटले विविध प्रकार के रचनात्मक शारीरिक कार्य होने लगे हैं। अब कक्षाएँ मानों हँसने लगी हैं और छात्रों में परिश्रम के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। पर सबसे उल्लेखनीय परिणाम यह है कि हमें हमारे देश के प्रचलित शिक्षा के अंग-प्रत्यंग के दोष दृष्टि में आने लगे। इन अनुभव करने लगे कि देश की शिक्षा-नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

† द्वादश भाषित भारतीय नयी तालीम सम्मेलन — उद्घोषन भाषण।

भी चूक हुई तो शिक्षक समाज तथा निरीक्षकों को हाथ मलना पड़ता है। एक सरकारी प्रस्ताव का यह उद्धरण पढ़िए, जो कि बुनियादी स्कूलों से सम्बन्धित है :

१. निवास की सुविधा . .. दस्तकारी के अभ्यास के लिए, सस्ते बरामदे बँधे जायें तथा शिक्षा साधनों और कच्चे भाल के लिए स्वतन्त्र कमरे हों।

२. खेती के लिए उचित तथा पर्याप्त भूमि हो।

३. शिक्षा साधन ठीक समय में बराबर तैयार रखे जायें। वे छात्रों की सख्या के अनुसार यथेष्ट हों।

४. नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार दस्तकारी की शिक्षा के लिए प्रतिदिन साठ मिनट के दो घण्टे लगाये जावे।†

ऐसे निर्देशों का उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर इसका फल विपरीत होता है। शिक्षकगण अपनी प्रेरणा शक्ति खो बैठते हैं तथा लकीर के पक्की होकर प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। यह स्मरणीय है कि नयी तालीम के साथ ग्राम-पुनर्निर्माण का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। गान्धीजी का उद्देश्य था कि प्रत्येक बुनियादी स्कूल अपने गाँव का समाज-केन्द्र बनकर उसकी हालत सुधारे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि स्कूल का पाठ्यक्रम अपने वातावरण की आवश्यकताओं पर अत्र्यभिन्न हो तथा स्थानीय समाज उसे ठीक करे। सरकारी अधिकारियों की डाँट तथा एक शहरी शक्ति के प्रभाव से यह सम्पादित नहीं हो सकती है। श्री सैयेदीन का कथन है :

ग्राम्य पाठशाला कभी भी लोक प्रिय न हो सकेगी, जब तक कि वह स्थानीय ग्रामवासियों की रुचि, धन्यों एवं आवश्यकताओं का ख्याल नहीं करेगी। प्रत्येक स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे तथा उनके माता पिता अनुमत्त करे कि विद्यालय एक ऐसी, सुव्यवस्थित कार्य शाला तथा यह है जहाँ कि वे अपने घर के कार्य-क्रम को सुचारु रूप से चालू रख सकते हैं।‡

† Government of Bombay. *A Report of the Progress of Basic Education in the State of Bombay, 1938-52*. Bombay, Government Central Press, 1954. pp 29-32

‡ K G Sanyal. 'Educating the Village, *Developing Village India*. Delhi Indian Council of Agricultural Research, 1951

ज्ञान नहीं है। जहाँ भी कहीं समिति के सदस्य गये, वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि बुनियादी शिक्षा की अलग-अलग रीति से व्याख्या की जाती है — ऊँचे पद के लोगों के द्वारा भी।” †

मुख्य प्रश्न यह है कि बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट धारणा क्यों नहीं हो पायी है? इसका एक प्रधान कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप हैं। कहीं प्राथमिक चरण में चार वर्ष की पढ़ाई हो रही है, कहीं पाँच वर्ष की और कहीं छः वर्ष की। कुछ स्कूलों में एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा शिक्षा दी जा रही है और कहीं दूसरे विषयों के साथ एक उद्योग सिखाया जाता है। जब सम्पूर्ण देश के प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा ही अपनायी जायगी तब अत्यावश्यक होगा कि बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा का एक ही स्वरूप सारे देश में चालू किया जावे। राज्य सरकारों से मिलकर, केन्द्रीय सरकार इस नीति को स्पष्ट करे।

बुनियादी शिक्षा के समर्थकों में हम दो मत देखते हैं : कट्टरपन्थी और उदारपन्थी। कट्टरपन्थी गान्धीजी के आदर्श पर चलना चाहते हैं। वे नयी तालीम के मूल रूप में विशेष परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वे समग्र नयी तालीम पर आस्था रखते हैं तथा उसे अशत रूप में रखना चाहते हैं। उदारपन्थी खेर समितियों तथा सारजेण्ट योजना द्वारा निरूपित मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। वे नयी तालीम की महत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं, पर स्वाश्रयता का समर्थन वे नहीं करते हैं।

उदारपन्थी अनुयायियों में भी दो भेद हैं। प्रथम टल बुनियादी शिक्षा की अवधि (६-१४ वर्ष) को दो हिस्सों (अवर और प्रवर) में बाँटने का पक्षपाती है। द्वितीय टल इस बाँट का विरोध करता है। उसका कथन है कि यह बाँट बुनियादी शिक्षा में दोष लायगा। कारण, इस शिक्षा में दस्तकारी का महत्वपूर्ण स्थान है। आठ वर्ष के अविच्छिन्न — सतत — अभ्यास के बिना, उद्योग-द्वारा शिक्षा ठीक ठीक प्रतिफलित नहीं होती है। इन सव मत-भेदों के कारण, नयी तालीम की धारणा स्पष्ट नहीं हो सकती।

इसके सिवा बुनियादी शिक्षा में वैसी ही नियम-निष्ठा आ गयी है, जैसी कि हमारी पूजा-पाठ विधि में वर्तमान है। नयी तालीम की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के लिये नियम निर्धारित किये गये हैं। यदि किसी भी कार्यक्रम के तामील करने में थोड़ीसी

† अनुमान-निर्धारण समिति रिपोर्ट, पृष्ठ ६।

दो विभिन्न धाराएँ निरुद्ध दिशाओं में न जाकर एक साथ मिल जावें। इस सम्मिलित धारा प्रवाह में हमारी शिक्षा में व्याप्त समस्त दोषों का प्रक्षालन हो जायगा।

बुनियादी शिक्षा 'नूतन' शिक्षा है। इसने हमारे सामने नवीन विचार उपस्थित किये हैं — सृजनात्मक शिक्षा, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कृतियाँ, परिश्रम के प्रति आदर एवं विश्वास, मातृ भाषा के प्रति श्रद्धा, ग्राह्य परीक्षाओं की परिचयमाप्ति, भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता का सम्मान, समाजसेवा, शिक्षा का विद्यार्थी के भावी जीवन से सम्बन्ध, देश की आवश्यकताओं का ध्यान, इत्यादि। हमें इस नवीन रस में अपनी पुरानी शिक्षा सस्थाओं को परिप्लावित कर देना चाहिए ताकि वे इस नूतन शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण को आत्मसात कर लें। कुछ लड़खड़ाते हुए उत्तर बुनियादी स्कूलों तथा उच्च शिक्षा ग्राम प्रतिष्ठानों द्वारा ही इस देश का काम नहीं चल सकता है। हमारे देश में एक सुदृढ़ तथा विशाल शिक्षा-अट्टालिका की जरूरत है, न कि दो विभिन्न तथा कमजोर इमारतों की। शिक्षा की उन्नति विकासवाद द्वारा हो सकती है, न कि पूर्ण परिवर्तन के द्वारा।

हर्ष की बात है कि अनुमान निर्धारण-समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि ग्राम-पुनर्रचना तथा बुनियादी शिक्षा साथ-साथ चले समिति ने यह सुझाव दिया है कि ग्राम-पुनर्रचना से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीगण बुनियादी शिक्षा के विकास में सहयोग देंगे।

बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह योजना वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से बिलकुल मेल नहीं खाती। चूँकि सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा को अपना लिया है, इस कारण अवर और प्रवर बुनियादी स्कूल काफी खुल गये हैं और खुलते जा रहे हैं। पर इसके बाद के चरणों का कुछ विशेष पता नहीं चलता। ग्यारह उच्च शिक्षाग्राम-प्रतिष्ठान अवश्य खुल गये हैं, पर उत्तर-बुनियादी स्कूलों की संख्या तीस से भी कम है। इसके विपरीत पूरे देश में शारह हजार से अधिक माध्यमिक स्कूल तथा एक हजार कालेज हैं, और इनकी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर एव उत्तम बुनियादी शिक्षा की स्थिति शोचनीय है और पुराने ढर्रे की शिक्षा-संस्थाओं की माँग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

बिहार के उत्तर-बुनियादी स्कूलों पर विचार करते हुए, एक सरकारी रिपोर्ट ने कहा है, "पुराने माध्यमिक स्कूल अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोगों में मैट्रिक सर्टीफिकेट की चाह अधिक है।"† अनुमान-निर्धारण समिति ने भी बुनियादी शिक्षा की कठिनाइयों को अनुभव किया। इसी कारण समिति ने सुझाव दिया है कि उत्तर-बुनियादी शालाओं की स्थापना और बुनियादी संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के साथ उचित सम्बन्ध स्थिर करना आवश्यक है।‡

यह मानना ही पड़ेगा कि इस देश की शिक्षा-पद्धति में अनेक दोष आ गये थे, और इनके सुधार की जरूरत थी। बुनियादी विचारधारा ने भारतीय शिक्षा-संसार में एक नवीन जीवन का सञ्चार किया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा-क्षेत्र में दो विभिन्न धाराएँ प्रवाहित होने लगीं, और जिनके गन्तव्य मार्ग एक दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल हों। पर खेद की बात है कि आज हमारे देश के शिक्षा-शास्त्रियों में दो दल हैं — बुनियादी और गैरबुनियादी। इन दोनों दलों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। यह होड़ देश के लिए हितावह एवं श्रेयस्कर नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि ये

† *Education in India, 1951-52, Vol. I, p. 75.*

‡ शोषिण, पृष्ठ ५०।

उन्चे पाँच वर्ष की अवस्था से लेकर पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा पाते थे। पाठ्य क्रम बहुत ही साधारण तथा सरल होता था।^(१) विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने तथा हिसाब का साधारण ज्ञान प्राप्त होता था। स्कूल अधिकतर एक शिक्षकीय सस्था के रूप में थे, अनेक शिक्षक अयोग्य थे, शिक्षा पद्धति पुरानी हो चली थी, नियमित कक्षा-प्रथा का अभाव था, शिक्षा-साधनों का प्रचलन न था, पुस्तकें छपी हुई नहीं होती थीं तथा^(२) दण्ड विधान बढोर था। सामान्यतः स्कूलों के लिए स्वतंत्र मकान न होते थे जिसे गॉर्न न मन्दिर, धनी व्यक्तियाँ न बरामतों अथवा शिक्षक के मकान में लगा करते थे। शिक्षकों की आय अधिक न थी, तथापि उनकी स्थिति वर्तमान शिक्षकों से गरीब गुजरी न थी।

ईसाई पादरियों की चेष्टाएँ—भारत में वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ करने का श्रेय ईसाई मण्डलों तथा पादरियों को मिलना चाहिए। यारोपीय जातियों के बसने पर, ईसाई पादरी भारत में आने लग गये, और शिक्षा प्रसार के नाम पर धर्म प्रचार करना चाहत थे। आरम्भ में उद्दोने प्राथमिक शिक्षा को आग बढ़ाया। जहाँ तक धन सका, ईसाई मण्डलों ने अपने प्रत्येक केन्द्र में प्राथमिक स्कूल खोले। ये केन्द्र समूचे देश में फैले हुए थे।

ईसाइयों की शिक्षा नीति की बहुत कुछ सुकताचीनी की गयी है, पर हमारा उससे कुछ सम्बन्ध नहीं है। कुछ भी हो, यह स्वीकार करना ही पडेगा कि ईसाइयों ने भारत की शिक्षा प्रणाली में एक नवीन ज्ञान डाल दी। ईसाई स्कूलों की कुछ विशेषताएँ नीचे दी गयी हैं

१. ईसाई मत के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में धर्म शिक्षा दी जाती थी, और बाइबिल भी वहाँ एक पाठ्यपुस्तक थी।

२. पाठ्य क्रम विस्तृत था। उसमें व्याकरण, भूगोल तथा इतिहास का समावेश था। छपी हुई पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन आरम्भ हुआ था।

३. स्कूल लगने का समय निश्चित था। प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित था। रविवार के दिन छुट्टी मिलती थी।

४. कक्षा प्रथा का प्रचलन आरम्भ हुआ, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक से अधिक शिक्षक नियुक्त थे।

५. शिक्षा मातृ भाषा द्वारा दी जाती थी।

चौथा अध्याय

प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका

देशी शिक्षा.—जिस समय यह देश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिनार में आया, उस समय यहाँ देशी शिक्षा का यथेष्ट विस्तार था। समूचे देश में प्राथमिक स्कूल तथा उच्च विद्यालय पर्याप्त विद्यमान थे। प्राथमिक स्कूलों में जन-साधारण के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के केन्द्र थे: मदरसा, टोल या पाठशाला।[†] देशी शिक्षा की यह प्रथा भारत में परम्परा से चली आ रही थी। यह हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से गुँथ गयी थी। पूर्व-अंग्रेज युग में हमारे गाँव स्वायत्तम्नी थे। लगभग सभी गाँवों में प्राथमिक स्कूल स्थित थे।

इस देशी शिक्षा की तहकीकात उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में की गयी। 'विलियम एडम' नामक एक पादरी की रिपोर्ट के अनुसार बङ्गाल और बिहार में प्राथमिक स्कूलों की संख्या एक लाख थी (सन् १८३८ ई०)। औसत में प्रत्येक ^①तीन गाँव पीछे दो स्कूल थे, और प्रत्येक ४०० जन-संख्या पर एक स्कूल अवस्थित था।[‡] मद्रास के गवर्नर 'मनरो' की जाँच के अनुसार मद्रास में प्राथमिक (बालकों की) शिक्षा लगभग ३३.३ प्रति शत थी (सन् १८२६ ई०)। १६ अक्टूबर, सन् १८२९ ई० की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बम्बई प्रान्त में छात्र और जन-संख्या का पारस्परिक अनुपात का औसत १ : १३३ था। बङ्गाल में साक्षरता का प्रतिशत ६.१ था। सम्भवतः यही स्थिति भारत के अन्य प्रदेशों की भी थी।*

† देखिए पृष्ठ १५।

‡ A. N. Basu. *Adam's Reports*. Calcutta University, 1941. pp 6-7.

* K. G. Saiyidain, et. al. *Compulsory Education in India*. Paris, UNESCO, 1952. pp. 12-13.

एक स्थानिक कर लगाने का अधिकार मिल। सन् १८८४ ई० म मडोच जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स श्री शास्त्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का सुझाव दिया।

वाद विवाद (१८९०-१९१८)

✓ राष्ट्रीय जागृति — उपर्युक्त सुझावों की ओर सरकार ने एकदम ध्यान न दिया। ये प्रस्ताव असामयिक ठहराये गये। पर इतने म समूचे देश में राष्ट्रीय भावना की जागृति का आरम्भ हा गया। अंग्रेजी शासन की बहुत कुछ नुटियाँ थीं, तथापि इस शासन स देश को अनेक लाभ मी हुए। उसने भारत क निचरे भागा को एक म मिला दिया, और एकता की सृष्टि की। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश में पाश्चात्य विचारों का प्रसार होने लगा। सोता हुआ भारत जाग उठा। देश में चारा और सुधार की पुकार मच गयी। इस प्रकार नवीन भारत का प्रादुर्भाव हुआ। पर हमारे नेताओं ने देखा कि शिक्षा की उन्नति क बिना राष्ट्रीय संगठन कठिन है। देखिए, स्वामी विवेकानन्द ने क्या भविष्यद्वाणी की

राष्ट्र अग्रसर क्यों नहीं हा रहा है ? हमारा प्रथम आवश्यकता है शिक्षा का प्रचार। राजाओं की सत्ता कहीं लुप्त हो गयी है ? जनता के पास। इस जनता क सुधार की आवश्यकता है। समाज सुधार का प्रथम सोपान शिक्षा है।

बम्बई में चेष्टाएँ — सन् १८८० ई० से हमार कई जन नायक अनिवार्य शिक्षा क प्रचार के लिए प्रयत्नशील थे। सन् १८८७ ईस्वी में 'इंडियन नेशनल काँग्रेस' का जन्म हुआ, और परिणाम स्वरूप शिक्षा की माँग उठी। अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा क लिए प्रथम सुव्यवस्थित प्रयत्न बम्बई क सर इब्राहीम रेहमतुल्ला तथा सर चिमनलाल सीतलवाड ने किया। इन्हीं क यत्न क कारण, बम्बई सरकार ने एक समिति नियुक्त क (सन् १९०६)। जॉन्स पड़ताल द्वारा इसे यह निर्णय करना था कि बम्बई नगर में अनिवार्य शिक्षा लागू की जा सकती है या नहीं। समिति ने फैसला दिया कि इस त्वचार को कार्यान्वित करने का अनुकूल समय अभी नहीं आया है, अतएव अभी ठहरने की आवश्यकता है।

मार्गदर्शक बडौदा — तत्कालीन ब्रिटिश शासन जो गुफ्तर कार्य न कर सका, उसे एक भारतीय नरेश ने क्रियान्वित किया। ये थे बडौदा नरेश महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड। सन् १८९३ ई० म उन्होंने अनुभव प्राप्त करने क लिए

पर ऐसा न हुआ। सरकार ख्याली पुलाव ही पकार्ती रही। उसने जो कुछ सोचा था, वह मृग-वृष्णा मात्र रहा। शिक्षित समाज ने जनता की ओर अग्रसर होने के बदले, उधर से मुँह मोड़ लिया। जो धारा नदी के रूप में विस्तृत होनेवाली थी, वह एक प्रवाह-विहीन उथली तलैया बनकर रह गयी!!

तृतीयतः, अंग्रेजों ने यह कभी अङ्गीकार नहीं किया कि प्राथमिक शिक्षा दी जावे। हण्टर कमीशन की ६०० पन्नोंवाली रिपोर्ट में, अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अंग्रेजों का हर समय यही कहना रहा कि अनिवार्य शिक्षा भारत के लिए दिवा-स्वप्न है। पर सबसे अचम्भे की बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन विश्व में सबसे पहले इंग्लैण्ड से ही आरम्भ हुआ था।

उपर्युक्त तीन मूल शिक्षा-नीति के सिवा, उन्नीसवीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा के असन्तोषप्रद प्रसार के अन्य कारण भी हैं :

१. केन्द्राकरण राजनीति—जिसके कारण देहाती भारत की उपेक्षा की गयी थी। स्मरण रहे कि ८० प्रति शत भारतवासी देहात में रहते हैं।

२. भारतीय उद्योगों के प्रति उदासीनता—जनता के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कोई भी विशेष चेष्टा नहीं की गयी।

३. शिक्षा का तिरस्कार—सन् १९०१-०२ में समूचे देश का शिक्षा-व्यय सिर्फ १,०२,७८,६५९ रुपये था। यह रकम देश की आय का ०.८८ प्रतिशत भाग था।

अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन

✓ प्रारम्भिक प्रस्ताव—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सब से प्रथम सुझाव एडम साहिव ने सन् १८३८ में दिया था। उनका कहना था कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक गाँव कम-से-कम एक प्राथमिक स्कूल चलावे। सन् १८५३ में, बम्बई प्रान्त के लिए रेवन्सु सर्वे कमिश्नर कप्तान ब्रिन्गेट ने प्रस्ताव किया कि जमीन की आय का पाँच प्रति शत कर शिक्षा के लिए लगाया जाय और इस रकम से किसानों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जावे। इसके छः वर्ष पश्चात् गुजरात के स्कूलों के इन्स्पेक्टर श्री टी. सी. होप ने सिफारिश की कि एक ऐसा कानून अमल में लाया जाय, जिसके अनुसार किसी भी जगह के निवासियों को स्कूल खोलने के लिए

उपसंहार.—पर गोएले के प्रयास सर्वथा निष्फल न हुए। सन् १९१०-१९१७ के बीच, प्राथमिक शिक्षा का गैरसरकारा प्रसार हुआ। तत्र सरकार भी चुप न रह सकी। सन् १९११ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय अण्डर सेक्रेटरी को प्राथमिक शिक्षा के प्रति यथेष्ट ध्यान देने का निर्देश दिया। सन् १९११-१२ में इस देश में सम्राट् पञ्चम जार्ज का शुभागमन हुआ। उन्होंने दिल्ली दरबार में पचास लाख रुपयों का आवर्तक वार्षिक अनुदान प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्वीकृत किया। सन् १९१३ ई० में भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध से यह आदेश प्रचारित किया

१. प्राथमिक शिक्षा में निम्न प्राथमिक विद्यालयों का विकास और निस्तार किया जाय।

२. केन्द्रीय ग्रामों में उच्च प्राथमिक स्कूल अधिक सख्या में खोले जावें।

३. साधारणतः प्राथमिक शिक्षा का प्रसार बोर्ड स्कूलों के द्वारा हो। जहाँ यह न हो सके, वहाँ स्वीकृत स्कूल 'ग्राण्ट इन एड' पद्धति पर चलाये जावें।

इसी अवसर पर प्रथम विश्व युद्ध शुरु हुआ। इस कारण ऊपर के प्रस्ताव कार्यान्वित न किये जा सके। युद्धकाल में भारत को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। पर अन्त में सन् १९१९ ई. में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारतवासियों को माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रदान किये। भारत सरकार की शिक्षा नीति पर इस सुधार का अनुकूल प्रभाव पड़ा।

जनियार्थ शिक्षा का प्रसार (१९१८-२०)

एक नवीन दृष्टिकोण.—सन् १९२१ ई० से माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कार्य आरम्भ हुआ। इसके अनुसार शिक्षा हस्तान्तरित होकर भारतीय मन्त्रियों के हाथ आ गयी। तत्पश्चात् गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट (१९३५) ने प्रान्तीय शासन में पूर्ण स्वशासन प्रतिष्ठित किया। इनके फल स्वरूप भारतीय मन्त्रियों ने बड़े परिश्रम और उत्साह से काम किया, और जनता में शिक्षा का चान उत्पन्न किया। इसी समय (१९१६-१९२०) भारतीय राष्ट्रीय जगत में गान्धीजी का उदय हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन को एक नया रूप दिया। उनकी प्रेरणा से यह आन्दोलन देश के गाँव गाँव और घर घर में फैला। सम्पूर्ण देश में एक नया जोश जागृत हुआ, और सभी ने

अपने राज्य के अमरेली तालुके में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी की। तत्पश्चात् सन् १९०६ ई० में, इसका विस्तार अपने पूरे राज्य में कर दिया।

स्वर्गीय गोखले के प्रयास—अंग्रेजी राज्य में जन-प्रमुखों ने अनुभव किया कि स्वयं अपने पाँवों पर खड़े हुए बिना भारत में शिक्षा की उन्नति असम्भव है। इस आन्दोलन के कर्णधार प्रसिद्ध तत्कालीन नेता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले थे। सन् १९१० में उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल में प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का आशय यह था कि भारत के उन भागों में छः से दस वर्ष के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जावे, जहाँ पर ३३ प्रति शत साक्षरता है। किन्तु सरकार के आश्वासन देने पर गोखलेजी ने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया।

पर जब सरकार ने आश्वासन के बावजूद कुछ न किया, तब दूसरे वर्ष श्री गोखले ने अपना दूसरा विधेयक काउन्सिल में उपस्थित किया। विधेयक की शर्तें बहुत ही सावधानी से रखी गयी थीं। मुख्य शर्तें ये थीं : (१) यह योजना केवल उन स्थानों में प्रयुक्त की जावे, जहाँ पर ६ से १० वयोवर्ग वाले बच्चों (बालक-शालिमाओं) के एक निर्धारित प्रतिशत को शिक्षा मिल रही हो। (२) अनिवार्य शिक्षा पहले बालकों के लिए लागू की जावे, और बाद में क्रमशः लड़कियों के लिए व्यवहृत की जाय। (३) इस योजना को अपने सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र या उसके कुछ भाग विशेष में एकदम लागू न करने का अधिकार स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया जाय। (४) अनिवार्य शिक्षा का खर्च चलाने के लिए प्रत्येक स्थानीय मण्डल को कर लगाने का अधिकार दिया जावे। (५) योजना को अमल में लाने के लिए प्रान्तीय सरकार की अनुमति अपेक्षित है।

विधेयक पर दो दिनों तक गरमागरम बहस हुई। पर ५१ सदस्यों में से केवल १३ सदस्यों ने श्री गोखले का समर्थन किया। सरकारी एवं जमींदार सदस्यों ने पौर विरोध किया, किन्तु गोखले हतोत्साह न हुए। उन्होंने अपनी बहस को समाप्त करते हुए कहा था :

मैं जानता था कि मन्थ्या तक मेरा विधेयक उग्याङ्कर फेंक दिया जायगा। इस पर मुझे न कोई शिकायत है और निराशा ही है। मैं मंटेव मोनता हूँ और कर्ता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी मानव-भूमि की सेवा अपनी अमर्यादाओं के द्वारा ही कर सकते हैं। कर्नाटिष्ठ व्यक्तियों के लिए अस्फुटता अस्मरणता से भरस्कर है।†

अनिवार्य शिक्षा प्रायः ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों लिए जारी की गयी है। उन क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर विशिष्ट शिक्षा-कर्म लगाया जाता है।

अनिवार्य शिक्षा की प्रगति—सन् १९२१-३७ के बीच, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

तालिका ४

अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा, १९२१-३७†

वर्ष	नगर पालिका तथा शहरी क्षेत्र	देहाती इलाके
१९२१-२२	८	—
१९२६-२७	११४	१,५७१
१९३१-३२	१५३	३,३९२
१९३६-३७	१६७	३,०३४

ऊपर के अंकों से यह स्पष्ट ही होगा कि अनिवार्य शिक्षा की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं हुई। इसके मुख्य दो कारण थे। प्रथमतः, सन् १९३१-३७ के बीच सम्पूर्ण जगत में एक विश्वव्यापी मन्त्री छा गयी, इस कारण किसी भी शिक्षा-योजना को ठीक ठीक चलाना असम्भव था। द्वितीयतः, हार्टग-समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने टोस नीति अपनायी। इसके अनुसार कम-जोर स्कूलों का ग्वात्मा कर दिया गया। सन् १९३७ ई० के पश्चात् छः प्रदेशों में कांग्रेस के शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुए। साथ ही, आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ। इस कारण अनिवार्य शिक्षा की थोड़ी बहुत प्रगति हुई। सन् १९४६-४७ में, अनिवार्य शिक्षा २२९ शहरों और १०,०२७ गाँवों में, केवल बालकों के लिए, तथा १० शहरों और १,४०४ गाँवों में, बालक-आलिकाओं के लिए, चालू थी।

† K G Sanyal, et. al. *Compulsory Education in India*
op cit pp 147-148.

यह अनुभव किया कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत का काम शिक्षा के बिना कदापि न चल सकेगा; अतएव शिक्षा परम आवश्यक है।

अनिवार्य शिक्षा के कानून.—अगस्त, १९१७ की घोषणा के बाद सभी अंग्रेजी प्रान्तों की विधायिका सभाओं के सदस्यगण निश्चरता दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान दिया। पृष्ठ-भूमि तो स्वर्गीय गोखले ने पहले ही तैयार कर रखी थी। उन्होंने जो बात समूचे देश के लिए चाही थी, उसे श्री विठ्ठलभाई पटेल ने बम्बई के लिए कर दिखाया। सन् १९१७ ई० में उन्होंने बम्बई प्रान्त के, बम्बई नगर को छोड़कर, नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा जारी करने के उद्देश्य से प्रान्तीय धारा सभा में एक विधेयक उपस्थित किया। दो दूरियों को छोड़कर यह बिल गोखलेजी के विधेयक से मिलता-जुलता था : (१) यह बिल केवल नगरपालिका के क्षेत्रों के लिए लागू होता था, पर गोखलेजी के विधेयक में गाँव भी शामिल थे। (२) सरकार पर आर्थिक जवाबदेही नहीं रखी गयी थी। पर यदि सरकार चाहे तो अनिवार्य शिक्षा के कुल खर्च का एक भाग, जिसे वह स्वयं निश्चित करे, दे सकती थी। श्री गोखले के विधेयक की शर्तों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के दो-तिहाई खर्च की जिम्मेवारी सरकार पर रखी गयी थी।

श्री विठ्ठलभाई का विधेयक पारित होकर “बम्बई प्राथमरी एजुकेशन एक्ट, १९१८” के रूप में प्रसारित हुआ। प्राथमिक शिक्षा का यह सबसे प्रथम कानून है। इस एक्ट ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की सार्वजनिक माँग को वैधानिक स्वीकृति दी। इस कानून से भारत के दूसरे प्रान्त भी प्रभावित हुए बिना न रहे। सभी प्रान्तों में घद्दाघद्द अनिवार्य शिक्षा के कायदे बनाये गये। सामान्यतः ये कानून एक दूसरे से मिलते-जुलते-से हैं, और वे गोरखले-बिल या पटेल-एक्ट के आधार पर बनाये गये हैं। जो स्थानीय मण्डल अनिवार्य शिक्षा की इच्छा करते हैं, वे पहले स्थानिक आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे अनिवार्य शिक्षा की एक योजना तैयार करते हैं। यह योजना मण्डल के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से उनकी विशिष्ट बैठक में पारित की जाती है। इसके पश्चात् प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, जो अत्यावश्यक होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि अनिवार्य शिक्षा मण्डल-क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में लागू की जावे। यह धीरे-धीरे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में लागू की जा सकती है। शिक्षा के व्यय के लिये स्थानीय मण्डल शिक्षा-कर लगा सकते हैं।

हैं : चौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, 'केसशिम्' का एक प्रतिनिधि, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि, एक प्रशिक्षण विद्यालय का अध्यक्ष, बुनियादी शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा के दो-दो विशेषज्ञ। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के शिक्षा-परामर्शदाता, इस परिषद के 'अध्यक्ष' तथा उसी मन्त्रालय के बुनियादी और समाज शिक्षा विभाग के प्रमुख 'मन्त्री' हैं। गैरसरकारी सदस्यों का कार्य-काल दो साल निश्चित है।

वित्त

स्रोतवार खर्च — प्राथमिक शिक्षा का खर्च पाँच स्रोतों से निकलता है :
 ① सरकारी (केन्द्रीय तथा राजकीय) निधि, ② स्थानीय मण्डल-निधि, ③ फीस और दूसरे स्रोत (दान, चन्दा आदि)। सन् १९५५-५६ ई० में प्राथमिक शिक्षा के स्रोतवार खर्च का निवरण अधोलिखित तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ६

प्राथमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष व्यय, १९५५-५६†

स्रोत	रकम (रुपयों में)	कुल व्यय का प्रति शत
राजकीय निधि	३९,५५,१०,६७१	७३.६
जिला मण्डल निधि	६,२४,७४,२६६	११.६
नगरपालिका निधि	४,४९,८३,०७९	८.४
फीस	१,७५,२७,१२७	३.३
दान	६२,८२,१६४	१.२
दूसरे स्रोत	१,०४,९४,७५९	१.९
योग ...	५३,७२,७२,०६६	१००.००

† Education in India, 1955-56, Vol 1 p 75

वर्तमान स्थिति

प्रशासन

प्रबन्ध.—प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध तीन विभिन्न कार्य-कर्ताओं के हाथ में है : (१) राज्य सरकार, (२) स्थानीय बोर्ड और (३) स्वसंचालित संस्थाएँ (प्रायः सभी को ग्राण्ट मिलता है)। इस दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों का विभाजन निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका ५
प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†

अनुशासन	स्कूलों की संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय	६४,८२७	२३.३
जिला-मण्डल	१,३३,२९६	४७.९
नगर-पालिका-मण्डल	८,९२७	३.२
स्वसंचालित संस्थाएँ :		
सहायता-प्राप्त	६७,२६३	२४.२
सहायता-रहित	३,८२२	१.४
योग	२,७८,१३५	१००.००

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिपद.—भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए पहली जुलाई, १९५७ को एक 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिपद' की स्थापना की गयी है। इस परिपद के मुख्य उद्देश्य ये हैं : केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की सलाह देना, प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति का सिंहावलोकन, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए योजना तैयार करना, शोध तथा अनुसन्धान, शिक्षकोचित साहित्य तैयार करना, प्रारम्भिक शिक्षा का आदर्श सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम पर विचार, इत्यादि। इस परिपद के २३ सदस्य

घाट देकर दोर ग्वर्च खुद देती हैं। स्वयंचालित सस्थाओं को स्थानीय मण्डलों के द्वारा प्राण्ट दिया जाता है। सरकार कभी-कभी स्थानीय बोर्डों को खण्ट अनुदान भी देती है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि इस आर्थिक सहायता-द्वारा बोर्ड अत्यावश्यक सुधारों को कार्य रूप में परिणत कर सकें।

अन्य प्रश्न

स्कूल तथा छात्र-सख्या — सन् १९४७ के पदचात् प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई है। सन् १९४७ ४८ में देश भर में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल थे। इनकी छात्र-सख्या १,१०,००,९६४ थी। आठ साल बाद प्राथमरी स्कूलों की सख्या २,१५,३२० तथा उनकी छात्र-सख्या १,७९,८५,०७४ पहुँची। पिछले अध्याय में यह ज्तलाया गया है कि आज भारत की स्वीकृत शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा है। इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने की चेष्टा कर रही हैं। नये बुनियादी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। तिस पर भी अधिकतर प्रारम्भिक स्कूल प्राथमिक हैं। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट होगा :

तालिका ७

प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा, १९५१-५२ से १९५६-५७†

वर्ष	स्कूल		छात्र-सख्या (हजारों में)	
	प्राथमिक	बुनियादी	प्राथमिक	बुनियादी
१९५१-५२	२,१५,३६६	३३,७५१	१,९०,२३	२९,८५
१९५२-५३	२,२२,४१०	३४,२२३	१,९५,५१	२९,६०
१९५३-५४	२,३९,८०८	३४,९४०	२,०८,४३	३०,३१
१९५४-५५	२,६४,१३९	३७,३९५	२,२२,४३	३१,५५
१९५५-५६	२,७८,७६८	४२,९७१	२,२९,६६	३७,३०
१९५६-५७	२,८८,०९१	४६,८५५	२,३९,०७	४१,०३

† India, 1959 p 113

इस प्रकार सन् १९५५-५६ ई० में जो कुल खर्च हुआ, सरकार ने उसके प्रायः तीन-चौथाई का खर्च उठाया। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को काफी रकम अनुदान के रूप में देती है। लेकिन यह रकम निश्चित नहीं रहती है। स्थानीय मण्डलों, दान तथा दूसरे स्रोतों का अंश-दान विशेष सराहनीय नहीं है। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, वहाँ शिक्षा निःशुल्क है। दूसरे क्षेत्रों में भी सरकार तथा स्थानीय मण्डल मुफ्त शिक्षा देते हैं। गैरसरकारी स्कूलों में फीस लगती है। सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्रत्येक प्राथमिक छात्र का औसत वार्षिक खर्च २३-४ रुपये था।

ग्राण्ट-इन-एड पद्धतियाँ।—इसकी चर्चा तीन स्तरों में की जा सकती है — केन्द्रीय-राज्यीय अनुदान, राज्यीय-स्थानीय अनुदान और स्वसंचालित संस्थाओं को राज्यीय या स्थानीय अनुदान। प्रथम अनुदान सदैव अनिश्चित रहता है। यह रकम केन्द्रीय योजनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है। द्वितीय अनुदान-नीति पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। वर्तमान तरीकों का सार नीचे दिया गया है :

१. खण्ड अनुदान-नीति — मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर है। इस कार्य के लिए राज्य-सरकार उन्हें एक निश्चित रकम द्वारा मदद करती है।

२. कुल खर्च का एक निर्दिष्ट प्रति शत अनुदान (विहार, बंगूर, पंजाब) — राज्यीय सरकार स्थानीय मण्डलों को कुल खर्च का एक बंधा हुआ हिस्सा अनुदान स्वरूप देती है। यह रकम जिला-मण्डल तथा नगरपालिका-मण्डल के लिए भिन्न होती है।

३. स्थानीय मण्डल अपने राजस्व का एक विशिष्ट अंश प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय स्रोतों की जिम्मेवारी अति सामान्य रहती है। राज्य-सरकार खर्च का अधिक भार स्वयं उठाती है। बंगूर राज्य के जिला तथा अनधिकृत नगर-पालिका-मण्डलों के लिए यह प्रथा लागू है।

वर्तमान समय में पढ़ती प्रथा उठती जा रही है। सरकार अनुभव कर रही है कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर पूर्णतः नहीं छोड़ी जा सकती है। कई राज्य-सरकारें स्वतः स्कूल खोल रही हैं, और कई स्थानीय स्रोतों के अंशदान को

है। स्टन्ट विद्या का प्रचार अधिक है। साथ ही रचनात्मक कार्य का अभ्यास है। पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि सरकार का न्येय है कि प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया जाय। इसी उद्देश्य का पहला कदम है, गेरबुनियादी स्कूलों में उद्योग की शिक्षा देना।

शाला-गृह.—स्कूलों की इमारतें सन्तोषजनक नहीं हैं। केवल सरकार तथा स्थानीय बोर्डों ने रास शाला गृह निर्मित कराये हैं, पर कुल छात्र सख्या का ३० प्रतिशत ही ऐसी इमारतों में शिक्षा पा रहा है। अधिकतर स्कूल किराये के मकानों, सरायों तथा मन्दिरों में लगते हैं। ऐसी जगहों में हवा तथा प्रकाश का नामोनिशान नहीं रहता है। वहाँ बच्चे बगड कमरों में ठूँस दिये जाते हैं।

व्यर्थता.—आज साधारण जनता शिक्षा में दिलचस्पी दिग्ना रही है। तिस पर भी प्राथमिक शिक्षा में व्यर्थता की मात्रा इतनी अधिक है कि शिक्षा के विस्तार से वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है। १९५२-५३ में स्कूलों में पहली कक्षा में भरती हुए प्रति १०० बच्चों में से ६४ दूसरी कक्षा में (१९५३-५४), ५१ तीसरी कक्षा में (१९५४-५५) और सिर्फ ४३ चौथी कक्षा (१९५५-५६) में शिक्षा पाते रहे। † इस प्रकार ५७ बच्चे स्थायी साक्षरता के लिए न्यूनतम माने जानेवाले चार वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पहले ही पढ़ना छोड़ बैठे। व्यर्थता के अनेक कारण हैं, जैसे : (१) अनिवार्य शिक्षा-विषयक एकटों का भली भाँति पालन न करना, (२) लोगों की गरीबी, (३) माता पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता, (४) पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता, (५) शिक्षण की प्रभाव-हीनता, (६) एक शिक्षकवाले स्कूलों का बाहुल्य, (७) बहुत से स्कूलों का नाम मात्र के लिए अस्तित्व, इत्यादि।

अवरोधन.—व्यर्थता (अपव्यय) से सलग दूसरा दोष अवरोधन (स्थिरता) का है जो प्राथमिक शिक्षा में पाया जाता है। अवरोधन का अर्थ है बालक का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक कक्षा में प्रति वर्ष २० से ३० फी सदी विद्यार्थी रोक लिये जाते हैं। सर्वाधिक निराशाजनक स्थिति पहली कक्षा की रहती है। यह कक्षा एक गैदले कुण्ड के समान जनी रहती है।

इस अवरोधन का विपत्तिक परिणाम विद्यार्थी, माता पिता तथा पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। असफलता के फल-स्वरूप ऊँची कक्षा में न जा सकने के कारण विद्यार्थी

अनिवार्य शिक्षा.—सन् १९४७-४८ ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा २२४ शहरों तथा १०,०१० गाँवों में चालू थी, तथा १९५५-५६ में १,०९३ शहरों तथा ३७,२७६ गाँवों में थी। सन् १९५१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में शहरों तथा ग्रामों की संख्या क्रमशः ३,०१८ तथा २,८५,०८९ थी। अर्थात् आज (१९५५-५६) भारत के एक-तिहाई शहर तथा एक-दशांश गाँव अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि अनेक शहरों तथा गाँवों में अनिवार्य शिक्षा सम्पूर्ण क्षेत्र में नहीं, वरन् कुछ अंशों में ही जारी है।

शिक्षक.—सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्राथमिक शिक्षकों की संख्या ६,९१,२९५ थी। औसतन प्रत्येक शिक्षक के अधीन ३३ विद्यार्थी पढ़ते थे। पर सब से खेद की बात यह है कि एक-शिक्षकवाले स्कूलों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका अन्दाज निम्नांकित तालिका से चलेगा :

तालिका ८

एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल

वर्ष	स्कूल
१९४९-५०	६७,७६२
१९५०-५१	६८,८४१
१९५१-५२	७१,७६२
१९५२-५३	८६,०३१
१९५४-५५	१०१,३४२
१९५५-५६	१११,२२०

पाठ्यक्रम.—पाठ्यक्रम में अधिकतर मातृभाषा, गणित, भूगोल, भारत का इतिहास एवं सृष्टि-विज्ञान का समावेश रहता है। पर पढ़ाई का लक्ष्य विद्यार्थियों के वातावरण की ओर नहीं रहता है। गाँव तथा शहर के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर न

निरुत्साह हो जाते हैं, उन्हें उनके माता-पिता स्कूल से रींच लेते हैं, देश की सम्पत्ति का अपव्यय होता है तथा राष्ट्र की भावी निधि — ग्रांकों — का विकास पूर्णरूपेण होना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा की व्यर्थता की वृद्धि होती है। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल में विद्याध्ययन के लिए आते हैं, न कि वार्षिक परीक्षा में टोकर खाकर पश्चात्पद होने के लिए।

प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

भूमिका — स्वतन्त्रता अर्जन करने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की उन्नति अवश्य हुई है, पर वैसी नहीं हुई, जैसी देश की कल्पना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ६-११ वर्ष के वयोवर्ग के ६० प्रतिशत बच्चों की शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करना था। पर आयोजना के अन्त में यह संख्या ५१.० प्रतिशत ही पहुँची। इस निराशाजनक स्थिति के अनेक कारण हैं। संक्षेप में कुछ कारणों पर विचार कर लेना यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

दोष-युक्त सरकारी नीति — पिछले पृष्ठों में अंग्रेजी शिक्षा नीति के दोषों पर पर्याप्त बच्चों की जा चुकी है। वहाँ अंग्रेज सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका है। प्रथमतः, उसने 'शिक्षा छनने के सिद्धान्त' का प्रचार किया, और तत्पश्चात् ठोस नीति का। आज उस पर दोषारोपण करने से कुछ भी लाभ नहीं। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा की उन्नति के लिए कोई सुसंगठित योजना नहीं थी। दो वर्ष पूर्व लोकसभा में अनुमान समिति ने खेड के साथ घोषित किया था कि "शिक्षा मन्त्रालय ने अभी तक ऐसी कोई सुसंगठित योजना प्रस्तुत नहीं की, जिसके द्वारा सविधान का ४५ वाँ अनुच्छेद कार्यरूप में परिणत हो सके।"† विभिन्न राज्य भी अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर सभी 'अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग' वाली कद्दावत के लक्ष्य बन रहे हैं। सारांश यह है कि सम्पूर्ण देश के लिए सुसंगठित योजना की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार आदर्शवादी है। वह यथार्थवादी नहीं है। उसने स्वीकृत शिक्षा प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है, और प्राथमिक शिक्षा को इसके अनुरूप बनाना चाहती है। पर यह तभी संभव हो सकता है, जब कि

† Estimates Committee *Elementary Education 1957-58*
New Delhi, Lok Sabha Secretariat 1958 p 60

भारत में प्राथमिक शिक्षा १९५५-५६

प्राथमिक स्कूलों में ६-११ वयोवर्ग के बच्चे



५३ स्कूल के भीतर



४७ स्कूल के बाहर

स्कूलों का बन्दोबस्त



प्रति ३ गाँवों में १ स्कूल



अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध

प्रति ३ शहरों में १



प्रति १४ गाँवों में १



व्यर्थता

प्रत्येक पूर्ण प्रतिरूप = 20

४३				
५१				
६४				
१००				
	कक्षा १	कक्षा २	कक्षा ३	कक्षा ४

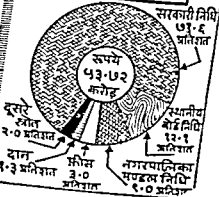
एक-शिक्षक स्कूल



प्रति ३ स्कूलों में १ एक शिक्षक स्कूल



शिक्षा-खर्च



तालिका ९

शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय
१९०१-०२ से १९४७-४८ (करोड़ रुपये)

विवरण	१९०१-०२	१९२१-२२	१९३६-३७	१९४७-४८
एकत्रित शिक्षा व्यय	४००१	१३०३७	२८०५	५९०१८
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	१०१८	३००९	८०३७	१८०९०
प्रति शत ..	२९.६	२७.३	२९.८	२९.२

इस प्रकार ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर कुल शिक्षा-व्यय का ३० प्रति शत से अधिक कमी भी खर्च नहीं हुआ। वर्तमान-समय में प्राथमिक शिक्षा-व्यय अवश्य बढ़ गया है, पर प्रति शत खर्च ज्यों-का-त्यों बना है। उदाहरण स्वरूप सन् १९५६-५७ ई० में शिक्षा पर हुए २०६.३ करोड़ रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय तथा प्रारम्भिक शिक्षा पर हुए ५८.४ करोड़ रुपये का व्यय द्रष्टव्य है, यह प्रारम्भिक शिक्षा-व्यय का २९ प्रति शत है।† इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप में पैसा नहीं मिलता। हमारे देश के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्नत देश प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल शिक्षा-व्यय का दो तृतीयांश और कहीं-कहीं तीन चतुर्थांश तक खर्च करते हैं।

प्राकृतिक बाधाएँ.—भारत की ८२.७ प्रति शत जन-संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण आदि में अनेक बाधाएँ हैं, जैसे : गाँवों का दूर दूर बसा होना, जन-संख्या के घनत्व की कमी, यातायात के साधनों का अभाव तथा प्राकृतिक कठिनाइयाँ। गाँवों में शिक्षक्यग जाना ही नहीं चाहते हैं, और यदि जाते भी हैं तो वे शीघ्र भाग आते हैं।

सम्पूर्ण देश का २२.११ प्रति शत भाग, अर्थात् २,८०,१५९ वर्ग मील स्थल, जङ्गलों से भरा पड़ा है। इसके सिवा देश की सीमा पर्वत-श्रेणियों से घिरी हुई है।

† *Education in the States, 1956-57. p 5*

पर्याप्त द्रव्य हो और यथेष्ट शिक्षक उपलब्ध हों। आज तो हमारे देश के एक-तृतीयांश प्रारम्भिक स्कूल एक-शिक्षकवाले स्कूल हैं।

दुर्बल शासन.—प्राथमिक शिक्षा का भार मुख्यतः स्थानीय मण्डलों पर है, और राज्य-सरकार शिक्षा-नीति निर्धारित करती तथा शिक्षा की देखरेख करती है। इस दोहरे नियंत्रण के कारण अनेक समस्याएँ खड़ी होती हैं। इसके सिवा, स्थानीय मण्डलों के पास न काफी पैसा है और न उन्हें सरकारी अनुदान ही इतना मिलता है कि वे अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी को उठा सकें। शिक्षा कर लगाने के लिए वे सदैव हिचकते हैं। कारण, इससे स्थानीय विरोध बढ़ता है। अनिवार्य शिक्षा के कायदे देश के पुराने ढर्रे पर बनते चले आ रहे हैं। इनमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है।

कुछ वर्षों से, सरकार अनिवार्य कार्यों को यथाविधि अमल में लाने की चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ६,८७,४२१ नोटिसें बच्चों को स्कूल में टाखिल न करने के लिए और २,४०,४५० नोटिसें बच्चों की गैरहाजिरी के कारण जारी हुई। गैरहाजिरी तथा भरती न कराने के कारण क्रमशः ५७,१४६ तथा ३९,५१४ मुकद्दमे चलाये गये। पर पूरे देश से २३,२३९ रुपये ही जुमाने में बसूल हुए।[†] फिर, इस योजना की सार्थकता ही कहाँ रही ?

इसके साथ-साथ निरीक्षकों की अपर्याप्तता भी जुड़ी हुई है। सन् १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा अमल में लाने के लिए केवल ९८१ अफसर थे। निरीक्षकों की संख्या भी कुछ अधिक नहीं है। औसतन एक निरीक्षक को प्रतिवर्ष सौ से अधिक स्कूलों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में स्कूल की शिक्षा में कोई उन्नति की कैसे आशा करे ?

स्कूल के विकास की भी कोई निर्धारित नीति नहीं है। सर्वेक्षण किये बिना ही स्कूल स्थापित होते हैं। स्कूल मनमाने ही खोले जाते हैं तथा स्थानिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका विषमपरिणाम यह होता है कि कहीं तो एक भी स्कूल नहीं होता है, और कहीं इतने स्कूल खुल जाते हैं कि वे आपस में खींचातानी करते हैं।

अर्थाभाव.—प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खर्च का है। अर्थाभाव के कारण, शिक्षा का प्रसार ठीक नहीं हो सक रहा है। अगले पन्ने की तालिका से ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का पता चलेगा :

[†] *Education in India, 1955-56, Vol. I. p. 86.*

अनेक बच्चे ऐसे हैं, जो यदि स्वयं मेहनत न करें तो उन्हें सूखी रोटी भी नसीब न हो। शरीर मजदूर तथा किसान चाहते हैं कि वे उनके कार्य में सहायता दें। तब उनके बच्चों को शिक्षा किस प्रकार मिल सकती है? इस प्रकार कितनी ही कठिनाइयाँ शिक्षा-प्रसार में बाधक हैं।

सुधार की ओर

भूमिका—इंग्लैण्ड का सन् १९४४ ई० का शिक्षा-कानून निम्न-लिखित गन्दों से आरम्भ होता है :

इस देश का भाग्य जनता की शिक्षा पर निर्भर है।

उपर्युक्त विचार का सम्मान सम्पूर्ण विश्व में होना चाहिए। बीसवीं शताब्दी अनिवार्य शिक्षा का युग है। इस शिक्षा का महत्व सभी देशों ने स्वीकार किया है। लोग चाहें, या न चाहें, आजाद देश में किसीको अपठ नहीं रहना चाहिए। आजादी का सब से कट्टर दुश्मन है निरक्षरता। इसी कारण स्वाधीन भारत में यह आवश्यक हो गया है कि देश ने सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कम से कम अवधि में उपलब्ध करा दी जाय। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, भारतीय सन्विधान के ४५ वें अनुच्छेद ने राज्यों को यह निर्देश दिया है :

राज्य इस सन्विधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालक शालिकाओं को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए साधन उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।

इस अवधि के बीतने का समय आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यह निर्देश कागजी आदर्श होकर ही रह गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने आरम्भ होने के पहले ६-११ वयोवर्ग के ४२.०० प्रति शत (१,८६.८० लाख) बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधाएँ थीं। आयोगना के अंत में ५१.०० प्रति शत (२,४८.१२ लाख) बच्चों को ये सुविधाएँ मिलने लगेगी। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में ११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की संख्या १३.९ प्रति शत (३३.७० लाख) से बढ़कर १९.२ प्रति शत (५०.९५ लाख) हो गयी है, और द्वितीय आयोजना में २२.५ प्रति शत (६३.८७ लाख) बच्चों की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।†

† भारत में शिक्षा (लेटा-चित्रों में), पृष्ठ १।

ऐसी जगहों में स्कूल खोलना कठिन है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७ ई० के पहले ईशान देश के सीमान्त क्षेत्र में तीस हजार वर्ग मील का एक ऐसा भाग था, जहाँ कि एक भी स्कूल न था।

सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा-जन्य बाधाएँ.—अनेक स्थानों में लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूलों की माँग है। कारण, कई अपढ़ माता-पिता अपनी कन्याओं को लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते। इसी प्रकार विविध धर्मावलम्बी विभिन्न स्कूल खोलना चाहते हैं। इसके सिवा, प्रत्येक मनुष्य अपने बच्चों को मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा देना चाहता है। यह ठीक है, पर यदि किसी स्थान में किन्हीं अन्य भाषा-भाषियों की संख्या कम हुई तो उनके लिए स्वतन्त्र स्कूल खोलना असम्भव हो जाता है।

सन् १९५६ की संशोधित सूचि के अनुसार इस देश में इस समय अनुसूचित जातियों के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है।† इन जातियों में शिक्षा की अधिकाधिक सुविधा देने के लिए उपाय प्रयुक्त किये जा रहे हैं, पर इनमें शिक्षा का प्रसार करना एक समस्या का विषय है।

शिक्षा-सम्बन्धी तथा आर्थिक बाधाएँ.—वर्तमान पाठ्यक्रम संतोषजनक नहीं है। पाठ्यक्रम पुस्तकीय है, तथा दैनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस शिक्षा को पाकर, विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से घबराते हैं तथा अपने पाप-दाँतों का धन्धा छोड़ बैठते हैं। यही कारण है कि साधारण जनता का विश्वास इस शिक्षा से उठ गया है। इस कमी के निराकरण के लिए ही, बुनियादी शिक्षा का प्रचार आरम्भ हुआ है। पर इस शिक्षा के सिद्धान्तों को लोग पूर्णतः समझ नहीं पाये हैं। स्कूलों में भी शिक्षा ठीक नहीं दी जा रही है। कारण खोजने की अधिक आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के एक-नृतीयांश स्कूल एक-शिक्षकवाले हैं। शिक्षकों की पढ़ाई का स्तर विशेष ऊँचा नहीं है। चालीस प्रति शत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं तथा अनेक शिक्षक अल्पकालिक प्रशिक्षण-प्राप्त ही हैं। इतना होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप में शिक्षक नहीं मिलते हैं।

अनेक माता-पिता स्वयं अपढ़ हैं। इस कारण, वे शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। फिर, भला वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजना चाहेंगे? इसके साथ-साथ ही दरिद्रता।

† भारत, १९५९, पृष्ठ २५८-५९।

आज पूरे देश के सामने यही प्रश्न है कि सविधान के निर्देश को कैसे कार्य-रूप में परिणत किया जाय। हाल में ही योजना-आयोग ने स्वीकार किया है कि ६-१४ वयोवर्ग की अनिवार्य शिक्षा असम्भव है। इस कारण ६-११ वयोवर्ग की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जावे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद ने भी सुझाव दिया है कि तृतीय आयोजना के अन्त तक ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत आ जाना चाहिए। नयी दिल्ली में २८-३० जून, १९५९ को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल की जो संयुक्त बैठक हुई थी उसने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया है। तृतीय पञ्चवर्षीय स्त्रीय योजना का लक्ष्य है कि योजना-काल के दौरान में ६-११ वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले।

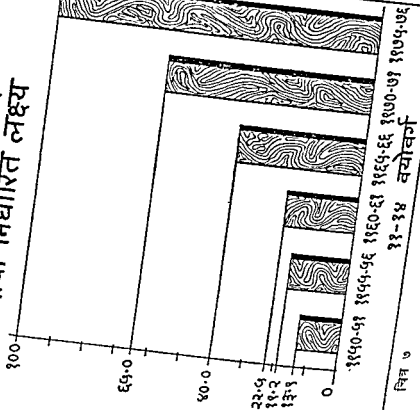
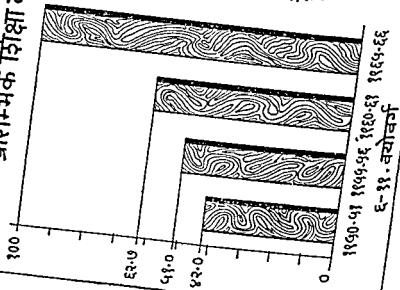
११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की शिक्षा के विषय में, उपर्युक्त सूत्र योजना ने अभिस्ताव किया है कि आयोजना की अवधि में स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा पाने वालों की संख्या ३० प्रति शत पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त १० प्रति शत बच्चों को सातत्य (कन्टिन्यूशन) शिक्षा मिलेगी।† इस प्रकार तृतीय आयोजना के अन्त तक इस वर्ग के शिक्षित बच्चों की संख्या ४० प्रति शत पहुँचेगी। आशा की जाती है कि यह संख्या चतुर्थ एवं पञ्चम योजना के अन्त तक क्रमशः ६५ तथा १०० पहुँचेगी। इस प्रकार सन् १९७५ के अन्त तक सविधान के लक्ष्य के सफल होने की सम्भाना है।

यह हुई हमारे देश में ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की योजना की रूपरेखा। पर इसे सफलीभूत करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुख्य समस्याएँ हैं : (१) प्रशासन, (२) वित्त, (३) अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ तथा प्रसार, (४) स्कूलों का प्रबन्ध, (५) पाठ्यक्रम, (६) शिक्षक, (७) निवास-व्यवस्था और (८) अनुसन्धान।

प्रशासन.—जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संपूर्ण देश के लिए एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता है। पिछले शीर्षक में इस योजना की रूपरेखा दी गयी है। राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों ने स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा ६-११ वयोवर्ग के बच्चों के लिए हो, तथा १९६६ के अन्त तक इस वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले। पर इसके साथ साथ अनेक प्रश्न खड़े होते हैं : (१) केन्द्रीय सरकार की नीति, (२) अनिवार्य शिक्षा प्रशासन-नीति, (३) राज्यों की

† देखिए, अध्याय १०।

प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य



चित्र ७

३३-३४ वयोवर्ग

कि शिक्षा विभाग स्थानीय मण्डलों के कार्यों का निरीक्षण तथा नियन्त्रण करे।

४. राज्य सरकार स्थानीय निकायों को यथेष्ट आर्थिक अनुदान दे।

वित्त.—निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए काफी पैसे की आवश्यकता है। १७ मार्च, १९५७ को लोक सभा में बजट पर भाषण देते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने कहा कि देश में ६-११ वयवर्ग के सभी बच्चों को तृतीय योजना के अन्त तक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के निमित्त ३०० करोड़ रुपये की जरूरत है। यथार्थ में यह उक्ति लोक सभा को चुनौती थी। आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अनिवार्य शिक्षा के लिए इस रकम का प्रबन्ध रहेगा। इसके साथ साथ, राज्य सरकारों को कमर कसना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी योजनाओं में इस महत्वपूर्ण तथा जरूरी कार्य के लिए यथेष्ट अर्थ का प्रबन्ध करें। इसने बिना केन्द्रीय आर्थिक अनुदान का यथोचित लाभ न उठा सकेंगे।

अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ तथा प्रसार.—अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ सोच कर करना चाहिए तथा समझ बूझकर आगे कदम रवाना चाहिए। कुछ सुझाव नीचे दिये गये हैं।

① **प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता**—अनिवार्य शिक्षा चालू करने से पहिले एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार ठीक समय पर करे। सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जावे : राज्य की विदोष जरूरतें, वे केन्द्र जहाँ स्कूल खोलना चाहिए, उन बच्चों की संख्या, जिन्हें अनिवार्य शिक्षा देनी है, स्कूलों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा-साधनों, शिक्षकों तथा शाला-गृहों की आवश्यकता, और सम्पूर्ण योजना पर तर्क। अनिवार्य शिक्षा आरम्भ होने से पश्चात्, सामयिक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है। इसके द्वारा अनुमान किया जा सकता है कि योजना कैसी चल रही है, उसमें कौनसे परिवर्तन की आवश्यकता है, मुख्य बाधाएँ क्या हैं, ये कैसे हटायी जा सकती हैं, आदि।

इसकी बात है कि केन्द्रीय सरकार के सुझाव के कारण प्रत्येक राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये हैं। आशा की जाती है कि इस जॉच का लाभ प्रत्येक राज्य अपनी अनिवार्य शिक्षा-परिकल्पना में उठावेगा।

वित्त-नीति, (४) पाठ्यक्रम, इत्यादि। ये ऐसे प्रश्न हैं, जो समूचे देश से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारण इन मामलों में एक समान नीति की आवश्यकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के विभिन्न राज्य एक ही अनुशासन की शृंखला से जकड़ दिये जावें। स्थानीय तथा विशेष आवश्यकताओं का सदा ध्यान रखना होगा। ऐसी नीति की अनुपस्थिति में अर्थ तथा श्रम के अपव्यय होने की आशंका है।

सब से बड़ी आवश्यकता है केन्द्रीय सरकारों की राज्य-सरकारों से सहकारिता की। राज्य-सरकारों में आजकल यह धारणा है कि भारत-सरकार अधिकार केन्द्रीभूत करना चाहती है, तथा ऐसे क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करती है, जिनका संबंध राज्य-सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस धारणा का निर्मूलनीकरण करे। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच आर्थिक तथा अन्य बातों में अधिकाधिक सहयोग स्थापित हो। अनुदान देते समय, उन राज्यों पर विशेष ध्यान रहे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो और जिनकी शिक्षा पिछड़ी हुई हो।

प्राथमिक शिक्षा के पिछड़े रहने का विशेष कारण हमारे स्थानीय मण्डलों की असमर्थता है। सारजेण्ट योजना ने तो स्पष्ट सुझाव दिया था कि प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों के हाथ से ले लें। इस प्रश्न पर तब से बहस हो रही है, लेकिन अभी तक सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्थानीय निकायों से निकटतम सम्बन्ध है। कारण, वे ही अपनी जरूरतों को ठीक समझ सकते हैं। इसके सिवा जनतन्त्र की इमारत स्थानीय निकायों की बुनियाद पर खड़ी होती है। इस कारण इन्हें अपनी जिम्मेवारी खुद संभालनी चाहिए।

लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि राज्य-सरकारों पर कुछ भी उत्तरदायित्व न रहे। इस प्रश्न पर कुछ सुझाव नीचे दिये हैं :

१. सरकार पूरे राज्य के लिए, एक शिक्षा-नीति तथा न्यूनतम मान-दण्ड स्थिर करे।
२. क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उपर्युक्त नीति तथा मानदण्ड परिवर्तन किया जावे, क्योंकि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ और कोई क्षेत्र उन्नत भी हो सकता है।
३. अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य में एक शक्तिशाली राजकीय विभाग होवे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है

पर विचार करे तथा सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य शिक्षा कानून का एक समान तथा आदर्श ढाँचा निर्मित करे। यह कार्य राज्य-सरकारों के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। हाल में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने भी यह सुझाव दिया है।

(५) मानवीय वैयक्तिक सम्बन्ध—बहुधा देखा गया है कि उपस्थित अधिकारी-गण साधारण जनता के प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी व्यावहारिक रुक्षता का परिणाम यह होता है कि अपढ व्यक्तियों के हृदय में शिक्षा के प्रति वितृष्ण उत्पन्न होती है। वे उपस्थित अधिकारियों को आग्शी विभाग के कर्मचारियों के तुल्य गिनते हैं। स्वाधीन भारत के उपस्थित अधिकारियों को समाज कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। जनता के साथ उनके किये गये व्यावहारिक आचरण पर ही शिक्षा का भविष्य निर्भर है। यह जनता अनुकम्पा, भ्रातृ भाव तथा सहानुभूति की ही अपेक्षा रखती है, यह बात सर्वथा स्मरणीय है।

(६) स्थानीय सहयोग तथा नेतृत्व—यह प्रकट सत्य है कि स्थानीय सहयोग के बिना अनिवार्य शिक्षा योजना सफल नहीं हो सकती है। स्कूल तथा स्थानीय समाज का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्कूल का कर्तव्य है कि वह सदा स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखे तथा समाज की उन्नति की चेष्टा करे। यदि समाज ने एकबार ताड़ लिया कि स्कूल उसके कल्याण के लिए है तो वह स्कूल की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के अनेक स्थानों में, स्तम्भता प्राप्ति के बाद, यह बात देखी गयी है कि जनता स्कूल के कार्यों में यथेष्ट दिलचस्पी ले रही है। एक सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत निम्नांकित विवरण पढ़िए।

देश के अनेक भागों में, जनता ने अपने गाँव के स्कूल के लिए अर्थ, भूमि तथा श्रम का दान किया है। एक जिले में ६०० शाला-गृहों का स्थानीय जनता ने स्वयमेव निर्माण किया था। इसी उत्साह के फलस्वरूप अनेक दुर्गम स्थानों में भी आज स्कूल खोलना समझ हो गया है। उदाहरण स्वरूप सन् १९४७ के पहले भारत की ईशान दिशा में स्थित आदिम जातीय क्षेत्रों में एक भी स्कूल न था। वहाँ सन् १९५३ में १,९०० स्कूल थे।†

इस प्रकार हम 'जहाँ चाह है, वहाँ राह है' वाली लोकोक्ति को प्रत्यक्ष चरितार्थ होते देखते हैं। यदि स्थानीय जनता चाहेगी, तो वह स्वयं स्कूल खोलेंगी। उनकी इस इच्छा को प्राकृतिक रुकावटें भी न रोक सकेंगी। सरकार का कर्तव्य है कि वह

† *Seven Years of Freedom* pp 2-3

(२) राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता—अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन इने-गिने क्षेत्रों या राज्यों में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश में जोर-शोर से चलना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा बूँद बूँद टपकना नहीं चाहिए, वरन् जोर से बरसना चाहिए। शुरू-शुरू में इसकी बहुत आवश्यकता है। अनेक देशों ने इस नीति का अनुसरण किया था; और केवल दस ही वर्षों के भीतर इन देशों के प्रारम्भिक स्कूलों की छात्र-संख्या दुगुनी हो गयी। इस तालिका की छात्र-संख्या पर दृष्टि डालिए :

तालिका १०

कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति†

देश	छात्र-संख्या (वर्ष)	छात्र-संख्या (वर्ष)
इंग्लैण्ड ...	१८,००,००० (१८७१)	४०,००,००० (१८८१)
जापान ...	१७,४६,००० (१८७३)	२३,००,००० (१८७९)
इजिप्ट ...	३,०३,००० (१९२८)	१०,००,००० (१९३८)
चीन ...	२८,००,००० (१९२१)	१,१७,००,००० (१९३१)

इस प्रकार, आरम्भ में सम्पूर्ण देश में एक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय जागृति की ज़रूरत है; पर प्रगति सुचारु रूप से, समझ-बुझकर तथा नियमित हो। प्रत्येक क्षेत्र को अपने सामर्थ्य के अनुसार चलने देना चाहिए। उसीके अनुरूप उसका प्रोग्राम भी हो। पर यह सदा ध्यान में रहे कि पूरे देश का लक्ष्य क्या है, अर्थात् सम्पूर्ण देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब तक हासिल करना है।

(३) अनिवार्य शिक्षा एक्टों का संशोधन—इस देश की अनिवार्य-शिक्षा विषयक कानून लगभग चालीस वर्ष पुराने हैं। ये गोल्लेन्जी के विधेयक या पटेल एक्ट के ढर्रे पर ढाले गये हैं। इनकी कमज़ोरियों पर ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। केन्द्रीय सरकार को उचित है कि राज्य सरकारों के विभिन्न प्राथमिक शिक्षा कानूनों पर

† R. V. Parulekar. *Literacy in India*. Bombay, Macmillan, 1939.
h. XII.

गाँव में स्कूल खोलना कुछ सहज नहीं है, उसमें अनेक अडचनों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर अनेक माता पिता गरीब हैं तथा शिक्षा के विरुद्ध विचार रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करानी पड़ती है। मजदूरी किये बिना उनके कुटुम्ब का पालन-पोषण होना कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें भी अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, तथा इसीलिए उनके बच्चों को स्कूल में रीतिना पढ़ता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उन बच्चों के माता पिताओं की ज़रूरतों की ओर बिलकुल ध्यान न दें। हमें स्कूलों के लगने का समय बदलना पड़ेगा। यदि स्कूल सुबह तथा शाम को लगाये जायें, तो बच्चों को अपने माता पिता की सहायता करने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलने लगेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है। इस कारण किसानों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए स्कूलों के लगने का समय स्थिर करना चाहिए। हम ऐसे समय नियम निम्न — लकीर के फकीर — नहीं रहना चाहिए। उदाहरणार्थ, चीन में ग्रामीण पाठशालाओं का खेती से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वहाँ साधारण सिद्धान्त यह है : “जब तुम्हारे पास अधिक समय है, तब अधिक पढ़ो। जब अल्प अवकाश हो, तब कम पढ़ो। जब तुम बहुत ही व्यस्त हो, तब कुछ समय तक पढ़ना बन्द करो।” †

सार अर्थ यह है कि स्कूल समाज के कल्याणार्थ है। स्कूलों के प्रति ग्रामवासियों की उदासीनता ज़रूर कुछ दूर हो जायगी, यदि पाठ्यक्रम में गाँवों की ज़रूरतों की ओर ध्यान रखकर विषयों का चयन किया जावे। समाज शिक्षा भी इस उदासीनता-रूपी व्याधि की अमोघ औषधि है। बहुधा अपठ व्यक्ति ही शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसके सिवा ग्राम्य स्कूल का जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहती है। स्थानिक समाज की उन्नति भी उसी पर निर्भर है। उमे आज ग्रामवासियों को किसान नहीं बनाना है, बरन् स्वतंत्र भारत का नागरिक निर्मित करना है। इस प्रकार प्राथमिक स्कूल ग्रामोत्थान के केन्द्र हैं। इस कार्य में स्कूल को सम्पूर्ण ग्राम के साथ हाथ बँटना चाहिए, ताकि ग्रामवासियों को गहूर हो कि स्कूल हमारा है। आज मेक्सिको में यही प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ स्कूल तथा गाँव परस्पर एक सूत्र में गुँथ गये हैं। स्कूल समाज की उन्नति के प्रयत्न करता है तथा समाज स्कूल की प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए भरसक कोशिश करता है। मेक्सिको के शिक्षा-उपमन्त्री थी मोयसेज़ सेएज़ का कथन है :

† देखिए पृष्ठ ८१।

‡ *Peking Review* April 15, 1958 p 12

जनता की इस इच्छा को पूर्णरूपेण जाग्रत करे। इस जाग्रति के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में स्कूल खोलना आसान हो जायगा।

(6) स्कूलों का प्रबन्ध.— इसके बाद आता है स्कूलों का प्रबन्ध। कारण, समूचे भारत के कोने-कोने में प्राथमिक शालाओं की ज़रूरत है — शहरों में तथा गाँवों में। इसके अतिरिक्त देश में कई जगह विशेष स्कूलों की माँग है। विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषा-भाषी पृथक् निजी स्कूल चाहते हैं, तथा आदिम जातियों के लिए भी विशेष स्कूलों की ज़रूरत है।

(i) **शहरों में स्कूल.**— शहरों में स्कूल खोलने और चलाने की विशेष अनुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ शाला-ग्रह शीघ्रता-पूर्वक निर्मित किये जा सकते हैं, शिक्षरूग्ण शहरों में रहना चाहते हैं, जनता में शिक्षा की चाह है। वहाँ केवल उपयुक्त उपस्थित-अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इन्हें यथेष्ट प्रशासनिक क्षमता दी जावे। इसके सिवा, जनता के सुभीते की ओर ध्यान रखते हुए, स्कूल अनुकूल समय में लगें।

सन् १९५४ ई० में 'भारतीय उद्योग-गणना' के अनुसार, भारत में ७,०६७ पंजीकृत कारखाने थे। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या १७,१४,७७० थी। इन व्यक्तियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का ठीक प्रबंध होना चाहिए, उनका विशेषकर, जो कि कारखाने के आसपास रहते हों। हमारे देश में एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसके अनुसार औद्योगिक संस्थाओं को अपने कर्मचारियों तथा मजदूरों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्कूल चलाना पड़े। मेक्सिको में सन् १९४२ ई० के शिक्षा-कानून के ६७-७१ अनुच्छेदों के अनुसार कल-कारखानों के स्वामियों पर कुछ प्रतिबन्ध रखे गये हैं। उन्हें स्कूल चलाना पड़ता है, स्वास्थ्यकर शाला-ग्रहों का निर्माण करना पड़ता है तथा विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त देना पड़ता है।

(ii) **गाँवों में स्कूल.**— गाँवों में सोच-विचार कर स्कूल खोलना चाहिए। सन् १९५१ ई० की जन-संख्या के अनुसार सम्पूर्ण देश में कुल ५,५८,०८८ गाँव थे। उनमें से ३,८०,०१९ गाँवों की मनुष्य-संख्या ५०० से कम थी। आर्थिक दृष्टि-कोण से ऐसे छोटे गाँवों में स्वतन्त्र स्कूल खोलना हितकर नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय गाँव में स्कूल स्थापित करना चाहिए। ऐसा गाँव विशेष विचार के साथ चुनना चाहिए, ताकि अन्य गाँव उससे दूर न हों। इस कारण स्कूल खोलने के पहले एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, ताकि स्कूल मनमाने जहाँ-तहाँ न खोले जावें।

होगा। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुल खर्च का साठ प्रति शत प्राण्ट भो मिलेगा।† हम इस योजना की सफलता के लिए शुभाकाशाएँ रखते हैं। पर यदि बुनियादी शिक्षा बुनियादी ही रखना है, तो उसका सूक्ष्म आकार हो ही नहीं सकता है।

हमें आदर्शवादी ने बदले यथार्थवादी होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए एक कार्य योग्य पाठ्यक्रम की ज़रूरत है। इसमें समाविष्ट हो मातृ भाषा, गणित, सरल सृष्टि विज्ञान, समाज शास्त्र की रूप रेखा तथा एक उद्योग। पर इसका उद्देश्य है एक उद्योग का साधारण ज्ञान, न कि उद्योग द्वारा शिक्षा। गाँवों में कृषि या बाग़वानी सिखलायी जा सकती है। विद्यार्थीगण खेतों तथा बगीचों में काम कर सकते हैं। शहरों में स्थानीय कारीगर उद्योग सिखा सकते हैं। मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा रचनात्मक हो तथा स्थानीय वातावरण पर पाठ्यक्रम आधारित हो। विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना को जगाना उचित है तथा उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना सिखाना चाहिए।

⑧ **शिक्षकगण** — हिसाब लगाया गया है कि नि शुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के लिए अर्द्धाईस लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। पर आज प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक सख्या प्रायः सात लाख ही है। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३ ई० में शिक्षित बेकारों की सहायता योजना शुरू की है। इसके अनुसार ३१ जनवरी १९५६ तक राज्यों के लिए कुल मिलाकर ८०,००० शिक्षक और २,००० सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त कर दिये गये।‡ इसी योजना के अन्तर्गत आयोगना आयोग और भी ४०,००० शिक्षक नियुक्त करना चाहता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की घोषणा के अनुसार आज इस देश में ६,३५,५६७ मैट्रिक पास विद्यार्थी बेकार बैठे हुए हैं।§ यदि वे व्यक्ति शिक्षक बन जायें, तो शिक्षक समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

पर केवल इन्हीं चेष्टाओं से काम न चलेगा। शुरू शुरू में आकाशाएँ अधिक ऊँची नहीं होनी चाहिए। हमें मैट्रिक से कम पढे लिखे अर्थात् वर्नाक्युलर फ़ाइनल या मिडिल पास शिक्षकों से काम चलाना पड़ेगा। हमें सदैव सचेत रहना चाहिए कि ये शिक्षक गाँवों में टिकेंगे या नहीं। देखिए, मेक्सिको ने शिक्षक-समस्या का समाधान कैसे किया, जब कि उस देश में प्रति वर्ष एक हजार से अधिक ग्रामीण स्कूल खुल

† *Times of India* March 17, 1959

‡ भारत में शिक्षा — लेखा — पत्रों में, १४ ६।

* *Times of India*, August 10 1959

यह ठीक नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्कूल का काम कहाँ आरम्भ या समाप्त होता है। उसी प्रकार ग्राम्य जीवन के आरम्भ और समाप्ति के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण, गाँव और स्कूल एक ही संस्था हैं, तथा स्कूल ने ग्राम-सुधार का उत्तरदायित्व अपने तिर पर ले लिया है।†

(iii) विशेष स्कूल.—कभी-कभी धर्म एवं भाषा-भेद के कारण, विभिन्न स्कूलों की माँग रहती है। इसके सिवा, कन्या-शालाओं की भी चाह है। वस्तुतः मजहबी स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत एक असांप्रदायिक राष्ट्र है। यद्ये छत्र-संख्या के बिना न स्वतन्त्र भाषा-भाषी स्कूल चल सकते हैं और न कन्या-शालाएँ। यदि विशेष भाषा-भाषी स्वतन्त्ररूप से अपना स्कूल अलग से अपने व्यय के द्वारा चलाना चाहें तो वह दूसरी बात है। इसी प्रकार स्वतन्त्र कन्या-शालाओं की विशेष आवश्यकता नहीं है। कारण, प्राथमिक स्कूलों में बालक-बालिकाएँ बिना रोक टोक साथ-साथ पढ़ सकती हैं। इनकी सह-शिक्षा में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए।

असली समस्या आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल खोले जाने की है। ये वस्तियों से दूर जंगल-पहाड़ों में रहते हैं तथा शिक्षा के महत्व को भी नहीं जानते हैं। हर्ष की बात है कि सम्प्रति इन लोगों में शिक्षा प्रसार के कार्य का भीगणेश हुआ है। इन लोगों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, कई स्वेच्छिक संगठन तथा धर्म-संस्थाएँ पर्याप्त प्रयत्न-शील हैं। सरकार भी अब सजग हो उठी है। सब कुछ होते हुए भी, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति अभी भी अनुत्तमप्रथम है।

(iv) पाठ्यक्रम.—प्रचलित पाठ्यक्रम की त्रुटियों एवं कमियों की आलोचना पूर्ण पृष्ठों में पर्याप्त कर दी गयी है। इसीके प्रतिकार-स्वरूप बुनियादी शिक्षा का आविर्भाव हुआ है। यह शिक्षा आज हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली है। अब इसकी सफलता के लिए यद्ये कुशल शिक्षकों एवं पर्याप्त अर्थ-राशि की आवश्यकता है।

सम्प्रति, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री डाक्टर श्रीनाली ने घोषणा की है कि आगामी दो या तीन वर्षों में देश के वर्तमान प्राथमरी स्कूल बुनियादी स्कूल में बदल दिये जावेंगे। ग्रामीण तथा शहरी स्कूलों के लिए न्यूनतम बुनियादी पाठ्यक्रम आघोत्रित किया जायगा, तथा तहसील और ताउरु केन्द्रों में अल्प-कालिक प्रशिक्षण का बन्दोबस्त

† M. B. L. Filho, et al. *The Training of Rural School Teachers*
Paris, UNESCO, 1952 p. 135

इंग्लैण्ड में ६० (१८९४), जर्मनी में ८० (१८९६), इटली में ६० (१९२२), इत्यादि। यहाँ तक कि सन् १९२२ ई० में इंग्लैण्ड में २८,००० और ५,००० कक्षाएँ ऐसी थीं, जिनमें प्रत्येक की छात्रसंख्या क्रमशः ५० से ६० और ६० से अधिक थी। आज हमारे शिक्षा विभागों के अनुसार एक कक्षा में ४० से अधिक विद्यार्थी भरती नहीं किये जा सकते हैं। हम इस सीमा को ५० तक आसानी से बढ़ा सकते हैं।

९ **निवास-व्यवस्था**—यह बतलाया जा चुका है कि हमारे अधिकांश शाला-गृह अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पर इस कारण हमें हताश न होना चाहिए। लगभग पचास वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड के कुछ स्कूल रेल-पथ के मेहराबों के नीचे लगते थे तथा जर्मन शाला-गृह अँधेरे तथा गन्दे थे। यहाँ तक कि सन् १९२५ में रूस के ग्रामीण प्राथमिक शाला-गृह भड़े तथा पुराने ढङ्ग पर बने हुए थे।

कहा जाता है कि हमारे देश के अनेक स्कूल धर्मशालाओं, सरायों, मन्दिरों तथा मस्जिदों में लग रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ लज्जा नहीं आनी चाहिए। यह प्रथा इस देश में परम्परा से चली आ रही है। हमारे देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है। जबतक उपयुक्त शालागृह न बनें, तब तक क्या हम हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रह सकते हैं? हमें जहाँ भी कोई खाली जगह मिले, वहाँ ही स्कूल खोलना चाहिए। नीले आकाश के नीचे मुक्त वायु (ओपन एयर) में हम स्कूल खोल सकते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से ऐसी संस्थाएँ आदर्श गिनी जाती हैं। भारत पर निसर्ग देवी का वरद हस्त है। तब हमें ऐसे स्कूल खोलने में क्यों हिचकना चाहिए?

१० **अनुसंधान**—हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा समस्याएँ अति गम्भीर तथा पेंचीदी हैं। इन पर बहुत कुछ सोचविचार की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा विभागों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों को चाहिए कि वे इन प्रश्नों की जाँच तथा उपयुक्त शोध करें। कुछ समस्याओं के शीर्षक नीचे दिये गये हैं :

१. प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी रूप देना,
२. अनिवार्य शिक्षा प्रतिपादन की समस्याएँ,
३. अपढ़ माता-पिताओं की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रवृत्ति,
४. द्वैत शिक्षा-पद्धति,

रहे थे। उच्च-शिक्षित व्यक्ति शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे; अतएव अध्यापन कार्य के लिए सच्चरित्र, उत्साही तथा सेवा-प्रेमी स्त्री-पुरुष नियुक्त हुए। युवक तथा युवतियाँ शिक्षकीय कार्य के लिए अधिक पसन्द की गयीं, तथा स्थानीय उम्मेदवारों के प्रति रियायत या उदारता दिखायी गयी। उच्च-शिक्षा प्राप्त न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए। बाद में मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण-द्वारा उनकी साहित्यिक तथा व्यावसायिक कमियाँ दूर की गयीं। भारत में ऐसी योजना की विशेष आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ हमें वर्तमान शिक्षकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चाहिए, जैसे : शिक्षकों का उचित बँटवारा, परिवर्तन-प्रथा का अधिक उपयोग, प्रत्येक कक्षा की छात्र-संख्या-वृद्धि, इत्यादि। यह देखा गया है कि शहरी स्कूलों के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षक मिलते हैं, पर ग्रामीण स्कूल बहुधा एक-शिक्षक-वाली संस्था होते हैं। यह दूषित प्रणाली आज नहीं चल सकती। स्थानिक मण्डलों को शिक्षकों का बँटवारा इस प्रकार करना उचित है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में, चाहे वह शहर में स्थित हो या एक छोटे-से गाँव में, कम-से-कम तीन शिक्षक अवश्य हों। इसी नीति का अवलम्बन करने पर अनेक शिक्षकों का शहरों से गाँवों में तबादला अवश्य होगा। पर न्याय तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह बहुत ही जरूरी है।

उपर्युक्त प्रस्ताव कार्यान्वित होने पर हम देखेंगे कि किसी भी शिक्षक को कमी भी दो से अधिक कक्षाएँ एक साथ नहीं पढ़ाना पड़ेंगी। यदि ये शिक्षक गण द्वैत-शिक्षा में यथोचित प्रशिक्षित किये जायँ तो उनका अध्यापन-कार्य बहुत कुछ सुधर सकता है। इसके अनुसार स्कूल इसके साथ-साथ भारत में परिवर्तन-प्रथा की अधिक जरूरत है। शिक्षकों का काम अवश्य बढ़ जायगा, की कक्षाएँ भिन्न-भिन्न समय में लग सकती हैं। शिक्षकों का काम अवश्य बढ़ जायगा, पर उन्हें एक से अधिक वर्ग एक साथ तो न पढ़ाना पड़ेंगे। यह मानना ही पड़ेगा कि यह प्रथा आदर्श नहीं है, पर शिक्षकों की कमी दूर करने की यह एक अचूक दवा है। यह प्रथा कुछ नयी नहीं है। सभी उन्नत देशों ने अनिवार्य शिक्षा के आरंभ में इस प्रथा को अपनाया था, जैसे : जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, पोर्तुगाल। आज भी यह प्रथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, टर्की, इजिप्ट, चीन, सीलोन तथा डेनमार्क में प्रचलित है।

हम प्रत्येक कक्षा की छात्रसंख्या भी बढ़ा सकते हैं। यह प्रथा बड़े स्कूलों में अपनायी जा सकती है जहाँ एक ही कक्षा के कई वर्ग होते हैं। हम देखते हैं कि किसी-न-किसी समय सभी देशों के प्रत्येक प्राथमिक कक्षा की छात्रसंख्या अत्यधिक थी :

पाँचवाँ अध्याय

✓ माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका

प्रारम्भ.—उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से आज, इस देश के अधिकांश माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी संस्थाएँ हैं। अंग्रेजी स्कूल इस देश में जब प्रथम-प्रथम खुले, तब इनका उद्देश्य धनी भारतवासियों को राज-भाषा (अंग्रेजी) सिखाना था। सन् १८३० में ई० ई० कंपनी के डाइरेक्टरों ने तय कर लिया था कि “भारतवासियों को अंग्रेजी-शिक्षा दी जाय, ताकि इस प्रकार का एक वर्ग तैयार किया जा सके, जो अपनी बुद्धि और नैतिकता के कारण, उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया जा सके।” †

इसी बीच लार्ड मैकाले ने शिक्षा-नीति पर अपनी सम्मति एक प्रसिद्ध लेख-पत्र-द्वारा घोषित की, और लार्ड विलियम बैटिङ्ग ने इस सम्मति को एक सरकारी ऐलान द्वारा स्वीकार किया (७ मार्च, १८३५)। इस ऐलान ने घोषणा करते हुए कहा, “सरकार का मुख्य उद्देश्य इस देश में अंग्रेजी भाषा-द्वारा युरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है।” इसके पश्चात् तुरन्त दो और भी कायदे निकले, जिनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा। सन् १८३७ ई० में ‘अंग्रेजी’ भारत की राज-भाषा बना दी गयी और लार्ड हाडिङ्ग के सन् १८४४ की घोषणा के अनुसार उच्च सरकारी नौकरियों शिक्षित भारतीयों के लिए खुल गयीं। अब तो पाश्चात्य ज्ञान का आदर और भी बढ़ा, और अंग्रेजी स्कूल धड़ाधड़ खुलने लगे।

बुड की घोषणा (१८५४) से भारतीय विश्वविद्यालय कानून (१९०४) तक.—बुड के घोषणा-पत्र की सिकारिशों के कारण माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस पत्र ने जोरदार शब्दों में कहा :

† A. N. Basu, ed. “Letters from the Court of Directors to the Governor of Fort St. George, September, 29, 1830.” *Indian Education in Parliamentary Papers, Part I.* Bombay, Asia Publishing. 1952. p. 195.

५. परिवर्तित शिक्षा-विधि,
६. व्यर्थता तथा अवरोधन,
७. शाला-ग्रह,
८. भिन्न-भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणाली, इत्यादि ।

उपसंहार

इस अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा कुछ उल्लेखनीय समस्याओं पर विचार किया गया है। ब्रिटिश सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन रही। आज यह बात पुरानी हो गयी है। इस पर आलोचना करना व्यर्थ है। आज हमें अपने देश के भविष्य की ओर ध्यान देना है। भारत की उन्नति जनता की साक्षरता पर निर्भर है। ८० प्रति शत से अधिक भारतवासी अभी निरक्षर हैं। मले ही वे न चाहें, किन्तु हमें उन्हें शिक्षित करना है। यह हमारा परम कर्तव्य है।

पर जब हम अनिवार्य शिक्षा की समस्याओं पर विचार करते हैं, तब हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है और हमारा जोश ठण्डा पड़ जाता है। पर ऐसा करने से काम न चलेगा। निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए समुचित अर्थ एवं सर्वाङ्गपूर्ण योजना अपेक्षित होती है, पर इससे भी अधिक मन में शक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता है। — ऐसी दृढ़ता, जो हमें कठिन-से-कठिन मुश्किलों का सामना करना सिखाये, जो हमें हताश न होने दे और जो हमें नीचे न गिरने दे। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा बल प्रदान करें।

प्रत्येक उन्नत देश की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे आगे ही बढ़ते गये। पीछे नहीं हटे। चालीस साल के अरसे में अमेरिका ने फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ज की साक्षरता २ से ५५ प्रति शत बढ़ायी। पच्चीस वर्ष की अवधि में रूस की साक्षरता ८ से ८८ पहुँची। अनेक कठिनायों का सामना करते हुए, चीन तथा टर्की ने अपनी निरक्षरता दूर की। फिर हम क्यों हताश हों?

माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम रखे जावें : (१) अ-कोर्स जो साधारण रूप में साहित्यिक पाठ्यक्रम हो और जिसका उद्देश्य विश्व-विद्यालय में प्रवेश पानेवाले छात्रों को तैयार करना हो, और (२) आ-कोर्स—यह व्यावहारिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रम हो, जिसमें व्यापारिक, व्यावसायिक तथा साहित्यिक विषयों का समावेश हो ।†

आज हम अपने इस देश में बहुदेशीय स्कूलों की चर्चा सुनते हैं, पर इसकी परिकल्पना ८० वर्ष पूर्व हण्टर कमीशन ने की थी। खेद की बात है कि इस मुद्दाव की ओर न सरकार ने ध्यान दिया और न जनता ने ही।

सन् १८८२ से १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा में एक बाढ़ सी आ गयी। सन् १८८२ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३,९१६ थी। इनमें २,१४,६७७ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। सन् १९०२ में स्कूलों की संख्या ५,१२४ तथा उनकी छात्र-संख्या ६,२२,८६८ हो गयी। इसी अवधि में, मैट्रिक परीक्षा में बैठनेवाले परीक्षार्थियों की भी संख्या बढ़ी—१८८२ में ७,४२९ से १९०२ में २२,७६७ हुई। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अत्यन्त हुआ, पर अधिकार एवं सगठन के अभाव में कमजोर स्कूलों की ही संख्या बढ़ी। ये स्कूल अधिकतर बिना सहायता प्राप्त स्कूल थे। वे शिक्षा विभाग के प्रशासन के बाहर थे, कारण, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। वे फीस की आय पर चलते थे, तथा उनके सचालकों को छूट थी कि वे अपने स्कूल, जैसा भी चाहें, चलावें। वे अपने विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में भेज सकते थे। विश्वविद्यालय उन्हें मान्यता अवश्य देता था पर उसे उनके निराक्षण का अधिकार न था।

सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, सभी स्वसंचालित स्कूल-सहायता प्राप्त और बिना सहायतावाले-सरकारी नियन्त्रण के अधीन आये। इस प्रस्ताव में, सरकार ने कुछ मामूली शर्तें निर्धारित कीं, जिनका पालन करना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य हो गया। इन शर्तों के माने बिना स्कूल स्वीकृत नहीं गिने जाते थे। इस तरह बिना सहायतावाले स्कूल सरकारी नियन्त्रण में लाये गये। इसी समय, भारतीय विश्वविद्यालय कानून (१९०४) पास हुआ। इसके अनुसार मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थी भेजनेवाले माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने का अधिकार विश्वविद्यालयों को सौंपा गया। परिणाम स्वरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय ने कुछ शर्तें निर्धारित कीं। समान समय पर विश्वविद्यालयों द्वारा इन विद्यालयों का निरीक्षण भी होने लगा। इससे

† Hunter Commission's Report, para 3

भारतीयों को पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं से पूर्णतः परिचित होना पड़ेगा, ताकि उन्हें युरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक शाखा की जानकारी हो सके। इस विद्या-परिचय का प्रसार भारतीय शिक्षा-पद्धति का भविष्य में मुख्य ध्येय हो।†

इस घोषणा के फल-स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा और भी प्रदलित होने लगी। सन् १८५७ में, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसका माध्यमिक शिक्षा पर अति गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक परीक्षा-द्वारा विश्वविद्यालय माध्यमिक स्कूलों का पाठ्य-क्रम, शिक्षण का माध्यम, अध्यापन-पद्धति, इत्यादि का नियन्त्रण करने लगे। इसके फल-स्वरूप शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थी तैयार करना हो गया।

बुड के घोषणा-पत्र ने स्वसंचालित स्कूलों के सहायतार्थ ग्राण्ट-इन-एड पद्धति के व्यापक व्यवहार का आदेश दिया था। इस सरकारी अनुदान-नीति के फल-स्वरूप निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। सन् १८५४ तक केवल मिशन-संस्थाओं के ही स्वसंचालित स्कूल थे, पर बाद में भारतीय लोग भी माध्यमिक विद्यालय खोलने लगे। इस प्रकार माध्यमिक क्षेत्र में तीन प्रकार के हाई स्कूल प्रचलित हुए : (१) मिशन, (२) राजकीय और (३) भारतीयों द्वारा खोले हुए। सन् १८५४ में राजकीय स्कूलों की संख्या केवल १६९ थी, किन्तु सन् १८८२ में वह बढ़कर १,३६३ हो गयी। निजी स्कूलों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ। सन् १८८२ में, भारतीयों-द्वारा परिचालित माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १,३४१ हो गयी। इसी वर्ष अन्य स्वसंचालित संस्थाओं के द्वारा ७५७ स्कूल क्रियाशील थे।

इस विकास के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक दोष आ गये, जो अब तक अपना असर फैलाये हुए हैं। प्रमुख दोष ये हैं : (१) जीवन की दृष्टि से शिक्षा उद्देश्य-हीन हो गयी थी। (२) मातृ-भाषा के बदले अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो गयी। (३) भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गयी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। (४) परीक्षा का असर बढ़ने लगा। (५) पाठ्यक्रम संकुचित हो गया। (६) औद्योगिक शिक्षा का अभाव रहा।

सन् १८८२ ई० में इण्टर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एक महत्व-पूर्ण सुझाव दिया। आयोग ने कहा :

† Wood's Despatch, Para 10.

मातृ भाषा होना चाहिए न कि अंग्रेजी। १७ मार्च, १९१५ में श्री एस० रायानिन्गार ने एक द्वितीय विधायिका में निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया

यह विधायिका गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति से सिफारिश करता है कि माध्यमिक स्कूलों का शिक्षा माध्यम भारतीय भाषाएँ हों, पर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य भाषा के रूप में रहे। इन प्रश्नों का विचार कार्यकारिणी समिति प्रांतीय सरकारों का परामर्श लेकर करे।

इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ। विरोध के मुख्य कारण ये थे (१) विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में अवनति की आशङ्का, (२) भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव, (३) बहुभाषा भाषी प्रांतों की कठिनाइयाँ और (४) अन्तर प्रादेशिक आदान प्रदान में अंग्रेजी की आवश्यकता। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का प्राधान्य माध्यमिक क्षेत्र में बना रहा।

प्रशासन—सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव की नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हुई। पर स्कूलों की वृद्धि रोकनी न जा सकी। स्कूलों की संख्या क्रमशः बढ़ती हुई सन् १९१७ में ७,६९३ हो गयी। पर इस अवधि में हाईस्कूल का प्रशासन में द्वैध शासन आरम्भ हुआ। कारण, हाईस्कूल को दो अधिकारियों के सामने चलाना पड़ता था। एक ओर उन्हें अनुदान सहायता के लिए सरकारी शिक्षा विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती थी और दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के समक्ष प्रार्थी होना पड़ता था। इस दोहरे नियंत्रण के कारण, शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों में तनावनी चलती थी। शिक्षा विभाग का फथन था कि विश्वविद्यालय की स्वीकृति केवल मैट्रिक वर्ग तक ही सीमित रहे, पर विश्वविद्यालय उस से मस होना नहीं चाहता था।

सैडलर कमीशन से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक (१९१९-४०)—इस अवधि में कई विख्यात रिपोर्टों ने माध्यमिक शिक्षा पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इनमें से मुख्य थे सैडलर कमीशन रिपोर्ट (१९१९), हार्मिंग रिपोर्ट (१९२९), एन्ट बुड रिपोर्ट (१९३७) तथा सार्जेण्ट रिपोर्ट (१९४४)।

सैडलर कमीशन रिपोर्ट—सन् १९१७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, सर मार्सेवल सैडलर की अध्यक्षता में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन' की नियुक्ति की। इस आयोग ने माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के कुछ सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया। कमीशन की

स्कूलों की शिक्षिता निश्चय ही दूर हुई; पर माध्यमिक क्षेत्र में, विश्वविद्यालय का प्रभुत्व बढ़ा तथा प्रशासन में द्वैध शासन शुरू हुआ।

स्वदेशी आन्दोलन से सेडलर कमीशन तक (१९०५-१७).— इस अवधि की मुख्य विशेषतायें हैं : (१) राष्ट्रीय जागृति, (२) शिक्षा के माध्यम पर विचार और (३) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन।

राष्ट्रीय जागृति.—बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से, भारतवासियों ने शिक्षा में दिलचस्पी लेना शुरू किया। पिछली शताब्दी में, इस देश के निवासी सरकार की शिक्षा-नीति के प्रति उदासीन रहे। पर लार्ड कर्जन के सुधारों को भारतवासी सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। देश भर में यह भावना लहरा गयी कि लार्ड कर्जन के शिक्षा-सुधारों का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा का विस्तार रोकना' है। हमारे नेताओं ने यह पूर्णतया समझ लिया कि देश का पुनर्जागरण शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है। यह जागरण केवल सरकार का मुँह ताकने से ही सम्भव न था, बल्कि उनके प्रयत्नों पर अवलम्बित था। इस प्रकार हमारे नेतागण शिक्षा-सुधार के लिए कटिबद्ध हुए।

सन् १९०५ में लार्ड कर्जन की बंग विच्छेद-चेष्टा के कारण, बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन शुरू हुआ। इसका शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् की स्थापना हुई। इसके कर्णधार थे सर गुरुदास बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का यही सबसे प्रथम प्रयास था। परिषद् ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के सुधार की एक विस्तृत योजना तैयार की। कलकत्ते में एक राष्ट्रीय कालेज तथा एक इंजीनियरिंग कालेज (वर्तमान जादवपुर विश्वविद्यालय) स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कालेज के अध्यक्ष थे श्री अरविन्द। कुछ राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल भी खोले गये। इनमें साधारण विषयों के अतिरिक्त, एक उद्योग भी सिखाया जाता था।

परिषद् ने सम्पूर्ण भारत में शिक्षा-सुधार की एक लहर सी फैला दी। किन्तु अल्पकाल में स्वदेशी आन्दोलन के शिथिल होने पर सभी राष्ट्रीय सस्थाएँ बन्द हो गयीं। केवल जादवपुर विश्वविद्यालय आज भी सिर ऊँचा किये खड़ा है। पर परिषद् की चेष्टा के कारण, माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की माँग शुरू हुई।

शिक्षा का माध्यम.—इस अवधि में शिक्षा के माध्यम पर घोर तर्क-वितर्क आरम्भ हुए। कारण, यह सभी अनुभव करने लगे कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम

१. जो बालक ग्रामीण व्यवसायों में लग सकें, उनके लिए ग्रामीण शालाएँ खोली जावें। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में विविधता लायी जाय।

२. मिडिल कक्षाओं में ही पाठ्यक्रम का विभाजन हो जाय, ताकि वहीं से विद्यार्थीगण औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों की ओर मुड़ सकें।

एबट वुड रिपोर्ट—सन् १९३६-३७ ई० में भारत सरकार ने दो अंग्रेज विशेषज्ञों को, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिए नियुक्त किया। ये महानुभाव थे श्री एबट तथा श्री वुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया, तथा मार्च, सन् १९३७ में अपना प्रतिवेदन तैयार किया जो एबट-वुड रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख सिफारिशें ये थीं :

१. ग्रामीण मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम बालकों के वातावरण से सम्बन्धित हो।

२. हस्तकला, कला तथा कौशल के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जावे। प्रत्येक स्कूल के पाठ्य-क्रम में इनका समावेश हो।

३. दो प्रकार के व्यावसायिक स्कूल खोले जावें; (१) अवर (३ वर्ष की शिक्षा) — इनमें आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थीगण भरती हों, और (२) प्रार (२ वर्ष की शिक्षा) — इनमें ग्यारहवीं कक्षा के बाद छात्र भरती किये जावें।

४. चुने हुए स्थानों में भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण कालिज तथा तकनीकी स्कूल स्थापित करे।†

सार्जेण्ट रिपोर्ट—माध्यमिक शिक्षा के विषय में, इस रिपोर्ट ने निम्नलिखित सुझाव दिये :

१. वर्तमान इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष हाईस्कूल में मिलाकर, हाई स्कूल की शिक्षा छः वर्षों की कर दी जावे। हाई स्कूल में भरती की अवस्था ११ वर्ष होनी चाहिए।

२. हाई स्कूल की शिक्षा उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए, जिनकी क्षमताएँ औसत छात्रों से स्पष्टतः ऊँची हों। इस कारण, अवर सुनिश्चिती पाठ्यक्रम रतम करने के बाद चुनाव द्वारा छांट कर केवल २० प्रति शत

राय थी कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के बिना विश्वविद्यालय की उन्नति असम्भव है।[†] इस कारण, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण विश्लेषण किया और इस क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव रखे :

१. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का विभाजन, मैट्रिक परीक्षा की अपेक्षा इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वारा हो।

२. माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त दो परीक्षाएँ ली जावें : (१) हाईस्कूल परीक्षा, जो वर्तमान मैट्रिक परीक्षा के समान हो। इसे परीक्षार्थी सोलह वर्ष की आयु में दे सकें। (२) इण्टरमीडिएट परीक्षा, जिसे विद्यार्थी १८ वर्ष की आयु में दे सकें। यह प्रचलित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समान अवश्य हो, पर इसके पाठ्य-क्रम में विविध विषयों का समावेश हो।

३. इण्टरमीडिएट शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों से हस्तान्तरित होकर एक नये प्रकार के विद्यालय अर्थात् इण्टरमीडिएट कालेजों के हाथ में आवे। इनमें कला तथा विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, प्रशिक्षण, इंजिनियरिंग, कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय के शिक्षण की सुविधा हो। ये कालेज या तो स्वतन्त्र हों या हाईस्कूलों से सलग हों।

४. माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध, प्रवेश एवं परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट मण्डल की स्थापना की जावे। प्रत्येक परिपट्ट में सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रतिनिधि हों।

भारतीय शिक्षा में यह पहला ही अवसर था कि एक शिक्षा-आयोग ने इण्टरमीडिएट शिक्षा का हस्तान्तरण हाईस्कूलों में करने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों का मैट्रिक तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र शिक्षा-परिपट्ट करे।

हारटंग रिपोर्ट—हारटंग कमिटी की दृष्टि में, माध्यमिक पाठ्यक्रम मैट्रिक परीक्षा की आवश्यकताओं से पूर्णतः प्रभावित था। कमिटी ने कहा कि "माध्यमिक शिक्षा की उन्नति सन्तोषजनक हुई है, किन्तु इसके संगठन में अनेक दोष हैं। इसका अन्तः प्रत्येक परीक्षा में अत्यधिक असफल होने वाले छात्रों की संख्या से लगता है।" इस व्यर्थता को दूर करने के लिए, समिति ने यह परामर्श दिया कि :

† Calcutta University Commission's Report, Vol V, p 297.

पर उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इने-गिने विद्यालयों को छोड़कर माध्यमिक स्कूल आज उसी दशा में हैं, जैसे कि वे सन् १८८४ या १९०४ में थे।†

स्वातन्त्र्योत्तर काल.—इस काल में तीन प्रसिद्ध निकायों ने माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया : ताराचन्द समिति (१९४८), विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४९) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३)।

ताराचन्द समिति.—इस समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का अवधि-काल १२ साल का हो : ५ वर्ष अवर-बुनियादी, ३ वर्ष प्रवर बुनियादी तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक स्कूल बहुद्देशीय हों। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि साधारण स्कूल बन्द कर दिये जायें। माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए समिति ने एक कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग.—इस आयोग का सम्बन्ध विश्वविद्यालयीन शिक्षा से था, पर इसने माध्यमिक शिक्षा का भी विश्लेषण किया और उस पर कुछ सुझाव भी दिये। कमीशन ने गौर किया कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है और उसका सुधार अत्यावश्यक है। आयोग ने फिर मत दिया कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट पास करने के बाद होना चाहिए, अर्थात् नारह वर्ष स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालिज में शिक्षा के पश्चात्।

माध्यमिक शिक्षा-आयोग—ताराचन्द समिति तथा 'केसशिम्' की सिफारिशों के कारण भारत सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को यह कमीशन नियुक्त किया। मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डॉ० लक्ष्मनस्वामी मुदालियर, इसके अध्यक्ष थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जून, १९५३ में भारत सरकार को दे दी। इसमें माध्यमिक शिक्षा के पेचीदे प्रश्नों पर विचार किया गया है। मुख्य सिफारिशों की चर्चा इस अध्याय में यथोचित स्थानों पर की जावेगी।

उपसंहार.—स्वातन्त्र्य लाभ के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में उल्लेखयोग्य प्रगति हुई है। इसका पता अगले पन्ने के तालिका से लगेगा :

† H V. Hampton "Secondary Education", *The Educational System Bombay*, O U P, 1943 pp 30-31

छात्र हाई स्कूलों में प्रवेश पावें। पर बुनियादी शिक्षा में जो छात्र योग्यता दिखलावें, उनके प्रवेश के लिए भी हाई स्कूलों में स्थान रखे जावें।

३. हाई स्कूल दो प्रकार के हों—साहित्यिक तथा तकनीकी। दोनों का लक्ष्य विद्यार्थी को एक उत्तम ठोस शिक्षा देना हो, ताकि आखिरी कक्षाओं में उसे एक ऐसे उद्यम की शिक्षा मिले जो उसके स्कूल छोड़ने पर मावी जीवन में काम आवे।

४. प्रत्येक दशा में पाठ्य-क्रम विभिन्न हो। उस पर विश्वविद्यालय या सार्वजनिक परीक्षण संस्थाओं का अनावश्यक प्रभाव न हो।†

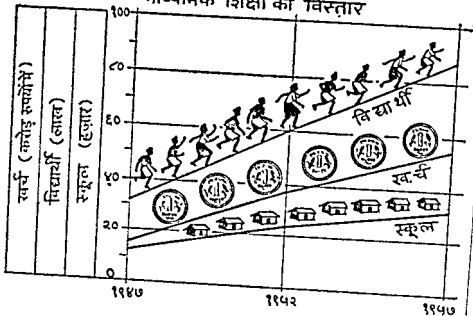
उपसंहार.—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति उत्तरोत्तर होती ही रही। सन् १९४८ ई० में मुख्य प्रान्तों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या १२,६९३ तक पहुँची। इनकी छात्रसंख्या की भी वृद्धि हुई। इस वर्ष मिडिल स्कूलों की तथा हाई और उच्चतर हाईस्कूलों की सम्मिलित छात्रसंख्या क्रमशः ११,६७,२८३ तथा १७,८६,७१२ थी। जनता में माध्यमिक शिक्षा की चाह बढ़ी। देहातों में अनेक माध्यमिक स्कूल खुले तथा कन्या शिक्षा बढ़ी।

सन् १९४७ ई० में, ब्रिटिश राज्य का अन्त हुआ। अंग्रेजी शिक्षा-नीति के माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव की आलोचना करते हुए, श्री हैम्पटन ने कहा है :

माध्यमिक शिक्षा का एक सिंहावलोकन करते समय, हम मानना ही पड़ता है कि यह शिक्षा पूर्ण विकसित न हो सकी—न यह देश के राजनैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वृद्धि के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर बढ़ी, और न आधुनिकतम दैक्षणिक प्रगति के साथ अग्रसर हुई। स्कूलों पर मैट्रिक परीक्षा तथा शिक्षा-विभाग के शालीय स्वीकृत नियमों का अत्यधिक प्रभुत्व है। पाठ्यक्रम नितान्त पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, अंग्रेजी में घोटते घोटते वे अपनी प्रेरणाशक्ति खो बैठते हैं। स्कूलों की पढ़ाई शुष्क तथा नीरस है, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक विषयों का आयोजन नहीं किया गया है, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद तथा मनोरंजन-कार्यों का अभाव है। अनेक शिक्षा आयोग तथा समितियों ने शिक्षा-सुधार पर सुझाव दिये थे,

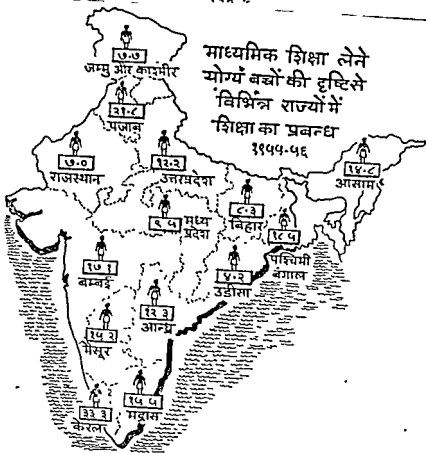
† Sargent Report, pp. 26-27.

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार



चित्र ८

माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य बच्चों की दृष्टिसे विभिन्न राज्यों में शिक्षा का प्रबन्ध 1944-46



तालिका ११

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७

वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	खर्च (करोड़ रुपये)
१९४७-४८	१२,६९३	२९,५३,९९५	१४
१९५२-५३	२४,०५९	५९,०६,६६६	३७
१९५६-५७	३५,८३८	९३,३०,०००	५८

इस काल में माध्यमिक शिक्षा के ध्येय, पाठ्यक्रम, संगठन इत्यादि में अनेक-नेक हेरफेर हुए। उल्लेखयोग्य सुधार ये हैं : (१) पाठ्यक्रम में विविधता तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश, (२) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, (३) नये प्रकार के उत्तर-प्राथमिक स्कूलों का आविर्भाव, (४) क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्र-भाषा की ओर अधिक झुकाव, (५) व्यायाम तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन, इत्यादि। इतना होते हुए भी, भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा सबसे निकम्मी उदासी जाती है।

वर्तमान स्थिति

स्कूलों का वर्गीकरण.—साधारणतः माध्यमिक स्कूलों की शिक्षाबधि सात वर्ष होती है। इस अवधि को हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (१) मिडिल या प्रवर बुनियादी या अवर माध्यमिक प्रकरण — यहाँ ११-१३ वयोवर्ग के विद्यार्थीगण अध्ययन करते हैं, और (२) हाईस्कूल — जहाँ १३ से १६ वयोवर्ग के छात्रगण शिक्षा पाते हैं। यह अवश्य है कि यह व्यवस्था पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विशेषता है। बहुधा मिडिल स्कूल हाई-स्कूलों से संलग्न रहते हैं।

हाल ही में कुछ नये प्रकार के माध्यमिक स्कूल खुल गये हैं। वे ये हैं : उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा उत्तर-बुनियादी स्कूल। उच्चतर माध्यमिक स्कूल की अवधि किसी राज्य में तीन वर्ष और किसी में चार वर्ष है। इनके सिवा, अनेक स्कूलों को बहुदेशीय स्कूलों में बदल दिया गया है।

इस प्रकार एक-पंचमाश संस्थाएँ राजकीय हैं तथा लगभग आधे स्कूल गैरसरकारी हैं। प्रायः एक-चतुर्थाश स्वसंचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता तथा प्रायः एक-तृतीयाश स्कूल स्थानीय निकायों द्वारा परिचालित हैं।

प्रशासन.—माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेवारी राज्यों पर है तथा इनका प्रशासन शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा-विभाग शाला-स्वीकृति के नियम बनाता है, स्कूलों के प्रशासन के लिए फायदे-कानून ठीक करता है, पाठ्य-पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तथा स्कूलों का निरीक्षण करता है। पर स्कूल-इन्स्पेक्टरों की सख्या पर्याप्त न होने के कारण, स्कूल निरीक्षण ठीक नहीं हो पाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा ही है :

प्रचलित निरीक्षण-पद्धति की अनेक साक्षियों ने तीव्र समालोचना की है। उनका कहना है कि निरीक्षण-कार्य असावधानी से किया जाता है, तथा स्कूल का निरीक्षण अल्प-कालिक होता है।†

सैडलर कमीशन की सिफारिशों के कारण आज प्रायः प्रत्येक राज्य में इंटरमीडिएट या। और माध्यमिक शिक्षा-मण्डल स्थापित हुए हैं। सन् १९५७ ई० में इनकी संख्या पन्द्रह थी। इनके नाम तथा प्रत्येक का स्थापन वर्ष इस प्रकार हैं :

(१) बिहार स्कूल परीक्षा मण्डल, पटना, १९५२, (२) राज्य-परीक्षा-मण्डल, त्रिवेन्द्रम १९४९, (३) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली, १९२६, (४) आन्ध्र माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, ग्वालियर, १९५६, (६) उत्तर-प्रदेश माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, अलाहाबाद, १९२२, (७) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मद्रास, १९११, (८) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, कटक, १९५६, (९) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल, जयपुर, १९५०, (१०) पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५१, (११) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, अजमेर, १९२९, (१२) महाकोशल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५६, (१३) मैसूर माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, बंगलोर, १९१३, (१४) माध्यमिक स्कूल सर्टीफिकेट मण्डल, पूना, १९४८ और (१५) विदर्भ माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, नागपुर, १९२२। इनमें से अजमेर मण्डल को छोड़कर शेष अपने-अपने क्षेत्र या राज्य के इंटरमीडिएट या। और शालान्त परीक्षाओं का परिचालन करते हैं। अजमेर-मण्डल की परीक्षाओं में भारत के किसी भी भाग के विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये परीक्षाएँ उन छात्रों के लिए सुविधाजनक हैं, जिनके अभिभावकों की बदली भारत के विभिन्न भागों में बहुधा हुआ करती है।

स्कूल तथा छात्र-संख्या.—सन् १९५६-५७ में कुल स्वीकृत माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३६,२९१ थी, जिनमें से २६ उत्तर-यूनियादी, २४,४८६ मिडिल तथा ११,७७९ उच्च एवं उच्चतर स्कूल थे। इनमें से ४,३७३ कन्या-शालाएँ थीं। देहातों की कुल स्कूल-संख्या २४,९३६ थी, जिनमें १९,७१३ मिडिल तथा ५,२२३ हाई स्कूल थे।

इसी वर्ष माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या थी : ७९,७१,५९५ (५४,३५,७९६ लड़के और २५,३५,७९९ लड़कियाँ)। इन विद्यार्थियों में से ४८,२३,३४४ (३८,३०,७८४ लड़के और ९,९२,५६० लड़कियाँ) मिडिल कक्षाओं में, तथा २०,३३,२६१ (१६,५५,७५० लड़के और ३,४७,५११ लड़कियाँ) उच्च वर्गों में अध्ययन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य सम्पूर्ण देश के बच्चों का १३.५ प्रति शत स्कूलों में शिक्षा पा रहा था। इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों का शिक्षा-प्रबन्ध चित्र ९ से मिलेगा।

प्रबन्ध.—प्रबन्ध की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों का विभाजन निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका १२
माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†

अनुदान	स्कूल-संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय	६,५७३	२०.२
ज़िला-मण्डल	९,१५४	२८.१
नगर-पालिका-मण्डल	१,२३६	३.८
स्वसंचालित स्कूल :		
सहायता-प्राप्त	११,६३२	३५.७
स्वाश्रित	३,९७३	१२.२
योग...	३२,५६८	१००.००

† Education in India, 1955-56, Vol. I. p. 122.

स्वसंचालित संस्थाओं को बहुधा राजकीय अनुदान मिलता है। पर इस प्रश्न पर प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्र नीति होती है निम्न लिखित विषयों में से किसी भी एक मद पर अनुदान प्राप्त हो सकता है .

१. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वृत्ति,
२. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा का खर्च;
३. अनाथ बच्चों के छात्रावासों का सञ्चालन,
४. स्कूल तथा छात्रावास की इमारतों के निर्माण तथा प्रसार पर खर्च,
५. अस्वास्थ्य, शिक्षा साधन, विज्ञान शिक्षा तथा पुस्तकालय पर व्यय,
६. स्कूल की इमारतों, छात्रावासों तथा खेल कूद के लिए जमीन खरीदने का खर्च,
७. हस्त-कला, कला तथा कौशल के शिक्षण पर व्यय, तथा
८. निवाँद अनुदान। †

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं को कुछ अनुमोदित विषयों के लिए अनुदान देती है। प्रथम योजना काल में केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के कारण माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधार किये गये। ४७० स्कूल बहुद्देशीय स्कूलों में बदल दिये गये। १,०७२ स्कूलों को समाज शास्त्र तथा २१४ स्कूलों को विज्ञान अध्यापन की उन्नति के लिए, १,४७९ स्कूल-पुस्तकालयों तथा १,११९ मिडिल स्कूलों को हस्तकला आरम्भ करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था की गयी। १० प्रशिक्षण केन्द्रों और १३ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को ग्राण्ट मिला तथा २१ संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के ३१ विषयों पर शोध करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मद में अनावर्ती खर्च का ६६ प्रति शत तथा आवर्तक खर्च का २५ प्रति शत स्वयं अनुदान के रूप में दिया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के कारण, भारत सरकार ने इस परिषद की स्थापना २२ मार्च, १९५५ में की। परिषद एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में काम करती है, तथा केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देती है। सितम्बर, १९५८ को परिषद की कार्यवाही की जाँच केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त एक

वित्त.—माध्यमिक शिक्षा का स्रोतवार खर्च का विवरण निम्नांकित तालिका में मिलेगा :

तालिका १३

माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६†

स्रोत	रकम (रुपये)	कुल खर्च का प्रति शत
राजकीय निधि	२४,६८,२६,९५२	४६.६
जिला मंडल निधि	२,४९,३०,७६५	४.७
नगर पालिका मंडल निधि	१,०७,६१,५४४	२.०
फीस	२०,०४,९२,२६७	३७.८
दान	१,५०,३९,४५५	२.८
दूसरे स्रोत	२,८६,७८,७३०	६.८
योग...	५३,०१,९८,६१९	१००.००

ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा का आधा खर्च स्वतः चलाती है, पर यह रकम सब राज्यों में एक-सी नहीं है। सबसे अधिक यह मध्यप्रदेश (५७.३) में थी तथा सबसे कम आन्ध्र प्रदेश (२३.९) में। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश का आधे से अधिक खर्च फीस द्वारा चला। दान और दूसरे स्रोत का भी हिसाब भिन्न-भिन्न था — कुल खर्च का १५.१ प्रति शत उद्दीना में तथा ४.६ प्रति शत आन्ध्र प्रदेश में।

† Education in India, 1955-56, Vol 1. p. 144.

पाठ्यक्रम—बहुधा माध्यमिक पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित रहते हैं (१) अंग्रेजी, (२) मातृ भाषा, (३) इतिहास तथा भूगोल, (४) गणित, (५) विज्ञान और (६) सांस्कृतिक या आधुनिक भाषा। हाल ही में औद्योगिक विषयों का भी समावेश हुआ है। पाठ्यक्रम के दोषों की आलोचना करते हुए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा *

- १ प्रचलित पाठ्यक्रम अति सकुचित है,
- २ यह निरा पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है,
- ३ पाठ्य विषयों की अधिकता होते हुए भी, इसमें उन क्रियाओं का अभाव है, जिनसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो सके,
- ४ यह किशोरों की विभिन्न क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता,
- ५ इसमें परीक्षा की प्रधानता रहती है, और
- ६ इसमें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश की आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है।†

ताराचन्द्र रिपोर्ट के निकलते ही देश में विविध पाठ्यक्रम की माँग गुरु हुई तथा कुछ औद्योगिक स्कूल खुले। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों ने फल-स्वरूप इस कार्य में एक नवीनता आयी। अब नूहदरीय स्कूल खुलते जा रहे हैं तथा पाठ्यक्रम का वृत्त फैल रहा है। शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की आयोजना की गयी है।

शाला गृह तथा शिक्षा-साधन—इसमें कुछ विशेष उन्नति नहीं दिखायी दे रही है। अनेक स्कूल अंधेरा इमारतों तथा गन्दी गलियों में स्थित हैं। पुस्तकालयों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। जनता इन दायों से पूर्णतया परिचित है, पर उन्नति की आशा नहीं रख रही है। इसका मुख्य कारण है माध्यमिक शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार। कभी-कभी हमारे नेतागण इतोत्साह होकर कह बैठते हैं कि शिक्षा प्रसार अभी होने दो। शिक्षा-साधनों एवं शाला गृहों की चिन्ता हम भविष्य में करेंगे।

परीक्षा—हमारी शिक्षा-पद्धति में परीक्षा का प्रमुख स्थान है। परीक्षाएँ दो प्रकार की होती हैं आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों

समिति ने की। इस समिति के परामर्श के अनुसार, परिषद पुनर्गठित हुई। इस पुनर्गठित परिषद के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है : (१) संचालक, माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण - कार्यक्रम - संचालक-मण्डल, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय, (२) नायब वित्त-परामर्शदाता, केन्द्रीय मन्त्रालय, (३) प्रत्येक संस्था से एक प्रतिनिधि — (अ) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद, (आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (इ) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद, (ई) अखिल भारतीय शिक्षण-संघ और (उ) शिक्षण महाविद्यालय - आचार्य-समा, (४) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, (५) पाँच नामजद शिक्षा-शास्त्री - केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा मनोनीत। इस तरह सभासदों की संख्या चौबीस है।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के संयुक्त शिक्षा-परामर्श-दाता माध्यमिक शिक्षा-विभाग, तथा इसी विभाग के प्रधान क्रमशः इस परिषद के अध्यक्ष एवं मंत्री हैं। परिषद के मुख्य कार्य निम्न-लिखितानुसार हैं :

१. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की आलोचना करना तथा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना;

२. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये हुए प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर उपयुक्त सुझाव देना;

३. माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए, नये प्रस्तावों को उठाना; और

४. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शोधों पर विचार करना तथा गवेषणा के लिए नये तथ्य सुझाना।†

मूल परिषद के विधायक कार्य अब एक स्वतन्त्र 'माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण-कार्यक्रम-संचालक-मण्डल' को सौंप दिये गये हैं। यह मण्डल केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय से संलग्न है। नये परिषद का प्रथम अधिवेशन २७ जुलाई, १९५९ को हुआ, जब कि माध्यमिक शिक्षा के मुख्य पाँच प्रश्नों पर विचार करने के लिए पाँच उप-समितियाँ नियुक्त हुईं : (१) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा बहुदेशीय स्कूल, (२) पाठ्य-विषयक तथा परीक्षा-सम्बन्धी सुधार, (३) मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण, (४) शिक्षक तथा प्रयोग और (५) विज्ञान-शिक्षा।

† Government of India Resolution No. F. 13-36/58-SE. 3, March 28, 1959.

है। इत के साथ साथ उसके माता-पिता के तथा देश के अर्थ का नाश या अपव्यय होता है।

पर इस परीक्षा का सबसे बुरा परिणाम हमारी शिक्षा-पद्धति पर पड़ता है। कारण, एक शिक्षक की योग्यता तथा एक स्कूल की दक्षता शालान्त परीक्षा फल के आधार पर की जाती है। शिक्षक का ध्येय हो जाता है विद्यार्थियों को परीक्षा में पास कराना। वह वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली भूल जाता है। पढ़ाते समय वह उन अंशों पर जोर देता है, जिन पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को भी ऐसे स्थल बिना समझे-बूझे कठस्थ करने पड़ने हैं। इस परीक्षा के विरुद्ध पचास वर्षों से आवाज उठती आ रही है, पर परीक्षाओं के बोझ से भारतीय शिक्षा मुक्त नहीं हो पायी है।

✓ माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

भूमिका.—आज विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा की नुकताचीनी हो रही है, और इस शिक्षा की आशानुरूप प्रगति नहीं हुई है। असन्तोष के अनेक कारण हैं। पूरे विश्व के माध्यमिक क्षेत्र में आज एक नवीन विचार धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नये नये विषयों का समावेश हो रहा है तथा उपयोगिता और व्यावहारिक ज्ञान की पुकार मची है। इन सब बातों की आँच हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा पर अवश्य लगी रही है, पर आशानुरूप परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लगभग दस वर्षों से हम प्रजातान्त्रिक हैं, पर आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली प्रजातान्त्रिक नहीं है। विद्यार्थियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पाठ्यक्रम सकीर्ण है, निर्देश तथा परामर्श का अभाव है, परीक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, जीवन की आवश्यकताओं से शिक्षा वा कोई सम्बन्ध नहीं है, इत्यादि। सारांश यह है कि आज माध्यमिक शिक्षा के सामने अनेक समस्याएँ हैं। उनमें से मुख्य ये हैं: (१) उद्देश्य, (२) माध्यमिक शिक्षा की इद्द, (३) सागठनिक ढाँचा, (४) पाठ्यक्रम, (५) विशेष स्कूल, (६) निर्देश तथा परामर्श, (७) प्रशासन, (८) परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण और (९) विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण। अब इन समस्याओं पर क्रमशः संक्षेप में विचार किया जाय।

उद्देश्य.—अभी तक माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों के योग्य तैयार करना था, अथवा दफ्तरों के झुकों के लायक बना देना था। अगर माध्यमिक शिक्षा का यही उपयुक्त लक्ष्य है तो हमारे माध्यमिक स्कूल आशातीत सफलीभूत हुए हैं। कारण, कालिज खचागच भरे हुए हैं। यहाँ तक कि अनेक विद्यार्थियों को वहाँ आज जगह नहीं मिल रही है। इसके सिवा, हजारों मैट्रिक

के विभाजन तथा उनकी क्षमता की जाँच होती है। आन्तरिक परीक्षाएँ साप्ताहिक, मासिक, सात्रिक तथा वार्षिक होती हैं। इन सबमें वार्षिक परीक्षा ही सबसे महत्व-पूर्ण होती है। कारण, इस परीक्षा-फल के आधार पर विद्यार्थीगण उपर की कक्षाओं में चढ़ाये जाते हैं, अथवा अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में रोक लिये जाते हैं।

बाह्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने पर ली जाती है। भिन्न-भिन्न राज्यों में इस शालान्त परीक्षा के विविध नाम हैं: मैट्रिक, स्कूल फायनल, स्कूल सर्टीफिकेट, आदि। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस परीक्षा में समूचे देश के ५० प्रति शत से भी कम परीक्षार्थी सफल होते हैं। निम्नांकित तालिका पर दृष्टि-निक्षेप कीजिए :

तालिका १४

मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल

वर्ष	परीक्षार्थियों की संख्या	'पास' संख्या	उत्तीर्णता का प्रति शत
१९५१-५२	५,८३,५७८	२,६१,०५९	४४.७
१९५२-५३	७,२४,७९९	३,३४,७६०	४६.२
१९५३-५४	८,१८,६२०	३,९७,००५	४८.५
१९५४-५५	८,३०,००१	४,००,०१४	४८.२
१९५५-५६	९,२०,०२६	४,२९,४९४	४६.७

परीक्षार्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक, समाज तथा शिक्षा-पद्धति पर इस परीक्षा का विपाक परिणाम होता है। घोंटते-घोंटते विद्यार्थी निष्प्राण-सा हो जाता है, और उसकी शारीरिक सम्पत्ति निस्तेज पड़ जाती है। परीक्षा में वह जो कुछ भी उगल धाता है, उसी पर से उसका मूल्यांकन होता है। उसके आन्तरिक परीक्षा-फल की कोई तनिक भी परवा नहीं करता है। उस मूल्यांकन में परीक्षकों की वैयक्तिक रुचियों एवं विचारों का ही प्राधान्य रहता है। यदि परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होता है, तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, विलाप करने लगता है और आत्म-विश्वास गवाँ देता

सुनकर कोई भी घबरा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा के मुख्य तीन क्रम हैं : प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च। इन्हीं तीन पारिभाषिक शब्दों का हमारे देश में उपयोग किया जाय।

इन तीन क्रमों में एकता की बहुत जरूरत है। पहले, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर विचार कीजिए। दोनों शिक्षा प्रणाली की अवधि, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। उनमें एक समानता चाहिए। जब कि बुनियादी शिक्षा हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा प्रणाली है, तब पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा का दौरान ५ वर्ष (अथवा बुनियादी) क्यों न हो ?

इस शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए ? माध्यमिक शिक्षा अयोग ने सिफारिश की है कि चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक अथवा अथवा बुनियादी के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो, तथा इस शिक्षा में दो चरण हों (१) मिडिल अथवा अथवा माध्यमिक अथवा प्रथम बुनियादी—तीन वर्ष की शिक्षा, और (२) उच्चतर माध्यमिक—४ वर्ष की शिक्षा।

प्रथम बुनियादी को माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत लेकर आयोग ने ठीक सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा के लिये वाञ्छित बौद्धिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता दोनों ही की प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ाना अपेक्षित है। इस विचार को कार्यान्वित करने लिए यह सुझाव दिया गया कि .

१. माध्यमिक शिक्षा की वय अवधि ११ से १७ वर्ष हो।
२. उच्चतर माध्यमिक के चार वर्ष के पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष सम्मिलित हो।
३. द्वितीय वर्ष डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाय। इस प्रकार डिग्री कोर्स तीन वर्ष का कर दिया जाये।
४. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्, किसी भी व्यावसायिक शिक्षण में प्रवेश किया जा सके।
५. जब तक माध्यमिक हाईस्कूल का नया ढाँचा कार्यान्वित न हो तब तक पुराने हाईस्कूल जारी रखे जावें। इन स्कूलों से गफलीभूत विद्यार्थियों के लिए कालिजों में एक वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम आयोजित किया जाय।†

पास युवक और युवतियाँ नौकरों की अर्जों लिये धके खाते हुए फिर रही हैं। इस प्रकार वास्तविक जीवन की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य-हीन हो गयी है। हिसाब लगाया जाता है कि केवल ५०-५५ प्रति शत मैट्रिक पास विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। इसके सिवा गत पचास वर्षों में माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या पन्द्रह गुना बढ़ गयी है। सन् १९०१-०२ में ६.२३ लाख छात्र थे, जो सन् १९५६-५७ में ९३.३ लाख हो गये। इसका अर्थ यह है कि अब विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक स्तर के विद्यार्थीगण माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। इन शिक्षा-सम्बन्धी वृत्ति में अधिकतर विविधता पायी जाती है। निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा का और भी विस्तार होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की केवल पृष्ठभूमि न रहेगी, अपितु स्वतः पूर्ण भी होगी। हाँ, यह विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिभा-सम्पन्न छात्र तैयार करके अवश्य देवेगी; पर यह भी आवश्यक है कि इस शिक्षा के समाप्त करने पर वे किसी कार्य-क्षेत्र में सीधे लग सकें और जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करने में समर्थ हो सकें। चूँकि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्ग-पूर्ण विकास करना है, इस कारण माध्यमिक स्कूल का ध्येय विद्यार्थी की मानसिक उन्नति के सिवा उसका शारीरिक तथा नैतिक गठन भी होगा।

आजादी मिलने के पश्चात् हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक नवीन उत्तरदायित्व आ गया है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है कि इन स्कूलों के छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए "जिससे वे धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र के सारे उत्तरदायित्वों को वहन कर सकें, और देश का नैतिक अभ्युत्थान कर सकें।"† माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के लिए मध्यवर्ती नेता तैयार करना होना चाहिए। हर्ष की बात है कि हमारे देश में अनेक विश्व-विख्यात उच्चश्रेणी के नेतागण हैं; पर मध्यवर्ती नेताओं का अत्यन्त अभाव है। किसी भी देश की उन्नति मध्यवर्ती नेताओं पर ही रहती है। कारण, ये ही स्थानिक समाज के कर्णधार होते हैं। ये ही सामान्य जनता को समुचित निर्देश दे सकते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माध्यमिक स्कूलों ने अभी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

माध्यमिक शिक्षा की हद्द.—आज हमारे देश के शिक्षा-जगत् में विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का उपयोग हो रहा है : अवर तथा प्रवर अनिवार्य, प्राथमिक, प्रारम्भिक, मिडिल, जूनियर माध्यमिक, हाई, उच्चतर माध्यमिक, विश्वविद्यालय, इत्यादि। इन्हें

अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार अथवा पाँच वर्षीय — जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था। इस अवधि को अनिर्णीत न छोड़ देना चाहिए।

प्रारम्भिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रवर बुनियादी (११-१४ वयोवर्ग के लिए), और तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवर्ग के लिए)। यहाँ यह भी कहना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रवर बुनियादी विद्याध्यायन वे-रोकटोक दाखिल हो सकें। यह आवश्यक है कि प्रवर बुनियादी के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अध्ययन करें। इस तरह माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न-भिन्न स्तर होंगे : (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च (वर्ग ९-११)। इस तरह उच्च माध्यमिक का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार चार वर्ष। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा।

उपर्युक्त ढाँचे को कार्यान्वित करने में दो अड़चनें आवेंगी : (१) वर्तमान हाई स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाठ्यक्रम को और भी कम समय में समाप्त करना—अर्थात् छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वर्ष में। चूँकि अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिज तथा विश्वविद्यालय पूर्व-विश्वविद्यालय कोर्स चलावेंगे। पर कम से-कम प्रत्येक जिले में एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाठ्यक्रम को विचारपूर्वक एकीकरण के द्वारा। यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक चुनौती है। कारण, उन्हें सात या आठ वर्ष के पाठ्यक्रम को छः वर्ष के वृत्त में जमाना पड़ेगा।

पाठ्यक्रम.—माध्यमिक पाठ्यक्रम की कमियों की चर्चा पहले ही की गयी है। अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा। कारण, ऐसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा का ध्येय है, “उत्पादन-कार्य कुशलता का विकास करना, राष्ट्र का धन बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में ऊँचा उठाना।”[†] हमें यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-गठन करना भी है। अस्तु, इन विचारों से माध्यमिक पाठ्यक्रम को व्यापक बनाना अनिवार्य हो जाता है। साहित्यिक

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अवधि बच्चों की सत्रह वर्ष आयु तक है। उपर्युक्त सुझाव के अनेक कारण थे। माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष जोड़ने का मुख्य ध्येय था कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ क्षमता बढ़े तथा कालिजों में अधिक आयु के तैयार विद्यार्थीगण आवें। यह भी देखा जाता है कि हार्ड स्कूल पास विद्यार्थियों को अपने कालिज-अध्ययन का प्रथम वर्ष खुद को सँभालने में लग जाता है, और सँभलते-सँभलते उन्हें इण्टरमीडिएट परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तीन वर्ष स्नातक शिक्षा की आयोजना इसीलिए रखी गयी है। सब से अच्छा तो यह होता कि उच्चतर माध्यमिक स्तर वर्तमान इण्टरमीडिएट का स्थान ले लेता, और उसके बाद विश्वविद्यालयों का तीन वर्ष का डिग्री कोर्स आता। राष्ट्रीय आयोग का यही सुझाव था, पर इससे शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाती और माता-पिताओं पर अपने बच्चों के एक वर्ष के खर्च का बोझ लड़ जाता। यह सब सोच-विचार कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढ़ानी चाही।

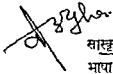
सांगठनिक ढाँचा.—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर कई समितियों तथा परिषदों ने विचार किया। अन्त में 'केसशिप' तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक में (१२-१४ जनवरी, १९५५) भारत की शिक्षा के ढाँचे के विषय में कुछ प्रस्ताव पास हुए। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया। इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा:

१. आठ वर्ष की अवधि की अष्टत बुनियादी शिक्षा — ६-१४ वर्षोवर्ग के बच्चों के लिए;
२. तीन वर्ष की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें बहुसुगी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी — १४-१७ वर्षोवर्ग के हेतु; और
३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के परन्तान्-विश्वविद्यालयों का तीन वरीय डिग्री कोर्स।

इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है; पर इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा: (१) प्रारम्भिक ६-११ तथा (२) निम्न माध्यमिक या प्रारंभिक बुनियादी ११-१४। इसके मुख्य दो कारण हैं: प्रथमः, ६-११ वर्षोवर्ग के बच्चों की शिक्षा के अभाव में, अगस्त्य है। द्वितीयः, ११ वर्ष की आयु के पक्षपात अनेक विद्यापीठ बुनियादी स्तर में पढ़ना नहीं चाहेंगे। अन्ती कारण के कारण मुख्य प्रारम्भिक शिक्षा के बच्चों के

उच्चतर माध्यमिक स्तर.—निम्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सभी विषय अनिवार्य हैं। इस न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता सभी शिक्षित मनुष्य को रहती है। पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-विषयों का प्रवन्ध होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, निम्न माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की बुनियाद पर अब विरोधीकृत अध्ययन शुरू हो सकता है। द्वितीयतः, किशोरों की विभिन्न क्षमताओं का ठीक अनुमान १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर भाषे से अधिक विद्यार्थियों के सामने दाल-रोटी का प्रश्न आ जाता है। इस कारण उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक विशेष ध्येय होना चाहिए— प्रत्येक विद्यार्थी को एक व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करना। इन जरूरतों को सामने रखते हुए दो विशिष्ट निकायों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार किया जाय, अर्थात् माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद (अभासाक्षिप)।

१. माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रस्ताव.—इस आयोग ने सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर में निम्न लिखित विषय सम्मिलित किये जायें :

 **अ. भाषाएँ.**—(१) मातृ-भाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृ भाषा तथा सांस्कृतिक भाषा सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, (२) इनमें से कोई भी एक भाषा : (अ) हिन्दी (जिनकी यह भाषा मातृ भाषा न हो), (आ) सुरल अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्कूल में अंग्रेजी न पढ़ी हो), (इ) उच्च अंग्रेजी (इस भाषा का जिन्होंने पहले अध्ययन किया हो), (ई) एक आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर), (उ) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर), (ऊ) एक सांस्कृतिक भाषा।

आ. (१) समाज शास्त्र और (२) सामान्य विज्ञान (गणित के साथ) — प्रथम दो वर्ष।

इ. स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए, इनमें से एक द्राष्टः (१) कतारें तथा बुनाई, (२) बड़ईगिरी, (३) घातु का काम, (४) बाग-बानी, (५) दर्जीगिरी, (६) छापने की कला, (७) कारखाने का काम, (८) सूचिकर्म तथा कसीदाकारी, और (९) मूर्ति-कला।

ई. निम्न-लिखित वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के कोई भी तीन विषय : (१) माननीय विषय—(अ) एक सांस्कृतिक भाषा या अन्य कोई

विषयों के सिवा, इसमें औद्योगिक तथा तकनीकी विषयों का रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सज्जात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया जाय।

निम्न माध्यमिक स्तर.—इस स्तर के पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन से सम्बन्धित आवश्यक विषयों का दिग्दर्शन कराना है। इस कारण पाठ्यक्रम में, भाषाएँ, समान शास्त्र, सामान्य विज्ञान तथा गणित का समावेश हो। इनके अतिरिक्त विद्यार्थियों में सांख्यिक-वृद्धि के लिए कला एवं संगीत और क्राफ्ट की, तथा उन्हें नीरोग रखने के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद का ज़रूरत है। इन आवश्यकताओं की ओर ध्यान रखते हुए, माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया है :

१. भाषाएँ : (१) राष्ट्र-भाषा (हिन्दी), (२) मातृ-भाषा — जिन क्षेत्रों में हिन्दी मातृ-भाषा हो, वहाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जावे, और (३) अंग्रेजी अथवा उच्च मातृ-भाषा या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा;

२. समाज-शास्त्र — इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समावेश;

३. सामान्य विज्ञान;

४. गणित : अंकगणित, सरल बीजगणित, सरल रेखागणित;

५. कला या संगीत;

६. एक क्राफ्ट (स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए; देहातों में कृषि); और

७. शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाएँ।†

शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो। पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतन्त्र विषयों में न बँटा हुआ हो, बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान-क्षेत्रों में बँटा हुआ हो, जो कि जीवन से सम्बन्धित हों। इसके अतिरिक्त जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने प्रस्ताव किया है कि “मिडिल तथा प्रवर बुनियादी पाठ्यक्रम एक से हों। इनकी अध्यापन-पद्धति में ही केवल विभिन्नता की आवश्यकता है।”‡

† Ibid., p. 89.

‡ Ibid., pp. 86-87.

प्रथम सूत्र : (१) — (अ) मातृ भाषा या (आ) क्षेत्रीय भाषा या (इ) मातृ भाषा तथा कोई क्षेत्रीय भाषा-सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, या (ई) मातृ भाषा और सांस्कृतिक भाषा सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, या उ) एक क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक भाषा-सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, (२) हिन्दी या अंग्रेजी, (३) कोई आधुनिक भारतीय या पाश्चात्य भाषा जो कि (१) या (२) में न ली गयी हो ।

द्वितीय सूत्र : (१) प्रथम सूत्र के समान, (२) अंग्रेजी या कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा; (३) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए) या कोई भी भारतीय भाषा (हिन्दी क्षेत्रों के लिए) ।

उपर्युक्त सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएँ सीखना जरूरी हो गया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो अनिवार्य भाषा का सुझाव दिया था। खेद की बात है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या 'अभामाशिप' ने पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक भाषा को योग्य स्थान नहीं दिया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी देश का सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन सांस्कृतिक भाषा के अध्ययन पर ही निहित है। यह सोच विचार कर भाषा-अध्ययन पर एक मुझाव नीचे दिया जाता है।

१. राष्ट्र भाषा या अहिन्दी क्षेत्रों के लिए अन्य कोई भारतीय भाषा,

२. कोई भी दो भाषाएँ : (१) कोई अन्य भारतीय भाषा जो ऊपर न ली गयी हो, (२) एक सांस्कृतिक भाषा, (३) अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा।

स्वाधीन भारत में राष्ट्र भाषा का ज्ञान किसी भी भारतवासी के लिए अनिवार्य होगा। जिनकी मातृ भाषा हिन्दी हो, वे कोई भी एक भारतीय भाषा सीखें। आज देश के अनेक भागों में यह धारणा है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में अहिन्दी क्षेत्रों में लदा जा रही है। यह तनातनी बहुत कुछ दूर हो सकती है, यदि हिन्दी भाषा भाषी अन्य कोई भारतीय भाषा का अध्ययन करें।

द्वितीय समूह से, विद्यार्थी कोई भी दो भाषा चुन सकते हैं। अनेक विद्यार्थी अंग्रेजी लेना चाहेंगे। कारण, यह एक प्रधान आन्तर्राष्ट्रीय भाषा है तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार अन्य एक भाषा सीख सकता है — एक भारतीय भाषा या एक सांस्कृतिक भाषा या अंग्रेजी छोड़कर कोई भी एक युरोपीय भाषा।

भाषा, जो कि अ(२) में न ली गयी हो, (आ) इतिहास, (इ) भूगोल, (ई) सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (उ) सरल मानस और तर्क शास्त्र, (ऊ) गणित, (ए) संगीत, (ऐ) गृह-विज्ञान। (२) विज्ञान — (अ) पदार्थ विज्ञान, (आ) रसायन शास्त्र, (इ) प्राणी-विज्ञान, (ई) भूगोल, (उ) गणित, (ऊ) सरल शरीर तथा आरोग्य विज्ञान। (३) प्राविधिक व्यावहारिक विज्ञान, (इ) सरल मैकेनिकल इंजिनियरिंग, (ई) सरल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग। (४) वाणिज्य विषय — (अ) व्यवसायी अर्थशास्त्र, (आ) लेखा-कार्य, (इ) व्यावसायिक भूगोल या सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (ई) शॉर्टहेण्ड तथा टाईपिंग। (५) कृषि — (अ) साधारण कृषि, (आ) पशु-पालन, (इ) उद्यान-विद्या तथा बागवानी, (ई) कृषि-सम्बन्धी रसायन तथा वनस्पति-शास्त्र। (६) कला — (अ) कला-इतिहास, (आ) नक़्शा तथा रेखा-चित्र, (इ) चित्र-कला, (ई) मूर्ति-कला, (उ) संगीत, (ऊ) नृत्य। (७) गृह-विज्ञान — (अ) गृह अर्थशास्त्र, (आ) आहार तथा पाक-कला, (इ) मातृ-कला तथा शिशु-पालन, (ई) गृह-प्रबंध तथा सुश्रूपा ।†

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि आयोग ने दो प्रकार के विषयों का सुझाव दिया है : (१) अनिवार्य अर्थात् अ, आ, इ समूह और (२) बहुमुखी अर्थात् ई समूह। इसके अन्तर्गत ई समूह के ७ वर्ग आ जाते हैं। इनमें से किसी भी वर्ग के तीन विषय लिये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार दूसरे प्रकार के विविध विषय भी अवश्य सम्मिलित किये जा सकते हैं। आयोग ने यह सिफारिश की है कि बहुमुखी पाठ्यक्रम उच्चतर स्तर के द्वितीय वर्ष से शुरू किये जावें।

२. अभाषाशास्त्र के प्रस्ताव.—माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावों का विचार कई निकायों ने किया। भाषा के विषय में 'अभाषाशास्त्र' की एक बैठक (११ जनवरी, १९५६) ने सुझाव दिया कि उच्चतर पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ अनिवार्य हों। 'केसशिम' ने अपनी सन् १९५७ ईस्वी की जनवरी की बैठक में इस सुझाव को मान लिया तथा राज्य-सरकारों की विवेचना के लिए निम्न-लिखित दो सूत्र प्रस्तुत किये :

दिया है। योजना के दो अङ्ग हैं : (१) हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलाना, तथा (२) वर्तमान स्कूलों को बहुद्देशीय स्कूलों में बदलकर नया रूप देना।

प्रथम योजना के अवधिकाल में ३६७ बहुद्देशीय स्कूल खोले गये। द्वितीय योजना का लक्ष्य है ९३७ बहुद्देशीय तथा १,१८७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करना। इस प्रकार द्वितीय योजना की समाप्ति तक १० प्रति शत माध्यमिक स्कूल बहुद्देशीय रूप में बदल दिये जायेंगे। तृतीय योजना का लक्ष्य है और भी १,००० बहुद्देशीय स्कूल स्थापित करना।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल.—देखा गया है कि योजनानुसार बहुद्देशीय स्कूल खुलते जा रहे हैं, पर हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने का काम धीरे-धीरे हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं। ^(१)प्रथमतः, राज्य सरकारें बहुद्देशीय स्कूल खोलने में दिलचस्पी ले रही हैं, और जनता में इन सस्थाओं की अधिक माँग है। द्वितीयतः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना ने प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता का कारण है केन्द्रीय सरकार की अनुदार नीति। इस कार्य के लिए केन्द्रीय महायत्ना कुछ ही समय तक मिलेगी। वर्तमान समय में ^(२)इस र्च का ४० प्रति शत राज्य-सरकारों दे रही हैं, और शेष केन्द्रीय सरकार पर द्वितीय योजना के अवधिकाल के बाद, राज्य सरकारों को इस कार्य का कुल व्यय स्वयं उठाना पड़ेगा। तृतीयतः, राज्य सरकारें अपना अधिकांश द्रव्य बहुद्देशीय स्कूल योजना पर र्च कर रही हैं। इस र्च को मिटाने के बाद, उनके पास अधिक पैसा नहीं बचता। चतुर्थतः, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने तीन वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स १९५७-५८ में आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम के चले बिना, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रसार असम्भव है। पर सबसे कठिन समस्या है उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए उपयुक्त शिक्षकों का अभाव। आज पूरे देश में लगभग २,००० उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से ७०० स्कूल हाल ही में खोले गये हैं। इनके लिए प्रति वर्ष २०,००० उत्तर स्नातक डिग्री-धारी शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य सरकार का अनुभव है कि ऐसे शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। समूचे देश में प्रति वर्ष औसतन १४,००० एम० ए० निकलते हैं। यदि ये सब भी शिक्षक बनें, तो भी देश की आवश्यकता पूरी न होगी।

बहुद्देशीय स्कूल.—माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्देशित बहुमुखी पाठ्यक्रम में से तीन या उससे अधिक विषयों का प्रबन्ध एक बहुद्देशीय स्कूल में रहता है। इस स्कूल की लोक-प्रियता के कारण अगले पक्ष में दिये गये हैं :

तीन भाषाओं के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में समाज-शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान आधारभूत विषय होंगे। इन दो बुनियादी विषयों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना भविष्य में अन्य विषय पूर्णतः नहीं समझे जा सकते हैं। ये विषय, कई विषयों के समावेश से बनाये गये हैं। वर्तमान युग में ज्ञान के विस्तार के कारण, ऐसे सम्मिलित विषयों की सृष्टि हुई है। इन दोनों बुनियादी विषयों की पढ़ाई प्रथम दो वर्ष में खतम कर देनी चाहिए, तथा तृतीय वर्ष से विशिष्ट विषयों का अध्ययन आरम्भ किया जाय। विद्यार्थीगण बहुधा असमञ्जस में पड़ जाते हैं, जब कि उन्हें बुनियादी और विशिष्ट विषय साथ-साथ सीखना पड़ता है।

३. उपसंहार.—इस प्रकार पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ और दो बुनियादी विषय आधारभूत होंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक क्राफ्ट तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाये हुए बहुमुखी पाठ्यक्रम के किसी भी समूह से तीन विषय लेने पड़ेंगे। क्राफ्ट के द्वारा विद्यार्थियों की कलात्मक तथा सृजनात्मक भावनाओं का विकास होता है। बहुमुखी पाठ्यक्रम की आयोजना के समय सदा दो प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरतों की ओर लक्ष्य रहे : (१) वे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर, जीवन-क्षेत्र में घुसना चाहते हों, और (२) वे, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों। ऐसी स्थिति में बहुमुखी पाठ्यक्रम दो प्रकार के होना चाहिए : (१) शालान्त और (२) प्रवेशक। पाठ्यक्रम के विषय, किशोरों की व्यक्तिगत रुचियों, विशेष क्षमताओं और योग्यताओं की ओर लक्ष्य रखते हुए, चुने जावें। इनके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हों।

अध्यापन तथा पाठ्यक्रम में, सदा निम्न-लिखित विषयों की ओर ध्यान दिया जावे :

१. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो;
२. जहाँ तक हो सके, पाठ्य-विषयों का एकीकरण किया जाय;
३. पाठ्यक्रम का सञ्चालन सही रीतियों से हो;
४. स्थानीय आवश्यकताओं तथा विद्यार्थियों की रुचि का सदा ध्यान रहे; तथा
५. छात्रों को निर्देश तथा परामर्श देने का प्रबन्ध रहे।

विशेष स्कूल.—माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट निकलने के बाद, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की ओर विशेष रूप से ध्यान

एक-उद्देशीय स्कूल.—यह किसीने न समझ लेना चाहिए कि एक-उद्देशीय स्कूल बहुद्देशीय सस्याओं से कम महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा क्षेत्र में स्वतन्त्र प्राविधिक, व्यावसायिक या साहित्यिक स्कूलों का एक विशिष्ट स्थान है। उदाहरण स्वरूप इंग्लैण्ड बहुद्देशीय स्कूलों का समर्थन नहीं करता है। उसके विरोध के मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं:

१. बहुद्देशीय स्कूलों का इतना अनुभव नहीं हुआ है कि ये वाञ्छनीय गिने जा सके।

२. एक-उद्देशीय सस्या का मान दण्ड सदा ऊँचा कायम रखा जा सकता है।

३. बहुद्देशीय स्कूलों द्वारा सामाजिक एकता नहीं बढ़ती है। सामाजिक एकता का अर्थ विद्यार्थियों की अधिकता नहीं है। यह भावना आध्यात्मिक होती है; और इसका विकास तभी सम्भव है, जब विद्यार्थीगण एक ही विचार में मग्न रहें।

४. एक उद्देशीय स्कूलों का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। बहुद्देशीय स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा लक्ष्य की एक रिचडी सी पक जाती है।

५. बहुद्देशीय स्कूलों के उपयुक्त अनेक विषयों के विशारद प्रधानाध्यापकों का अत्यन्त अभाव है।†

इस प्रकार इंग्लैण्ड में बहुद्देशीय स्कूलों के विषय में घोर मतभेद है। इस देश में द्वि उद्देशीय स्कूल फैल रहे हैं, जैसे: ग्रामर-तकनिकी, मॉडर्न तकनिकी, इत्यादि। अचम्भे की बात है कि एक सौ छियालीस स्थानिक निकायों में से सिर्फ़ दसों ने बहुद्देशीय स्कूल रोले हैं। इस प्रकार हमारे देश में भी ये स्कूल सोच विचार कर थापित किये जायें।

ग्रामीण तथा कृषि-विद्यालय.—किसी भी शिक्षा योजना में हमारे देशांतों का ध्यान सदा सम्मुख रहना चाहिए। कारण, ८० प्रति शत भारतवासी गाँवों में रहते हैं, तथा कृषि से अपनी गुजर करते हैं। पर गाँवों की दशा दिन-प्रति दिन गिरती जा रही है। ग्राम वासी शहरों की ओर भाग रहे हैं। गाँवों में मुखिया का अभाव है। शिक्षा-सुधार ग्राम सुधार का एक प्रधान अङ्ग है।

† T L Reller, 'The Comprehensive Secondary School Controversy in England, Educational Administration and Supervision, October, 1955

१. इस संस्था-द्वारा सामाजिक एकता बढ़ती है। कारण, यहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थीगण पढ़ सकते हैं तथा उनमें भेद-भाव बढ़ने नहीं पाता है।

२. ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों को उनके बौद्धिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता के अनुसार छाँटकर उचित पाठ्य-क्रम की शिक्षा देना सहज होता है। तत्पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को अनुभव के आधार पर एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में बदलने के लिए कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

३. चूँकि ऐसे स्कूल में अनेक स्तर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इस कारण छात्रों तथा उनके अभिभावकों में कोई न्यूनता या श्रेष्ठता का भाव नहीं उपजता। यह भाव विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिल होने या न होने के कारण उत्पन्न होता है।

बहुद्देशीय योजना के कार्यान्वित होने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं।
 प्रथमतः, इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा उनकी आवश्यकताओं को अनेक स्कूल-संचालकगण ठीक तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रत्येक शिक्षा-विभाग का यह कर्तव्य है कि वह उचित मार्गदर्शन करे। इसमें विविध प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान रहे, यथा: शालागृह, प्रयोग-शाला, कर्म-शाला, शिक्षा-साधन, पुस्तकें इत्यादि। द्वितीयतः, ये स्कूल जहाँ तहाँ स्थापित न किये जायँ। इनके खोलने के समय, सदा स्थानिक जरूरतों तथा साधनों का ख्याल रहे। अधिक छात्र-संख्या के बिना एक बहुद्देशीय स्कूल चल नहीं सकती है। यदि तीन ही विविध विषय एक स्कूल में रखे जायँ, तो प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम तीन वर्ग होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षा-विभाग अपने राज्य का एक सर्वेक्षण करे, और तत्पश्चात् ऐसे स्कूल ठीक जगहों में खोले तथा अनुकूल विषय स्थिर करे। तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललितकला तथा गृह-विज्ञान सराखे विषयों के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के मिलने में विशेष कठिनाई अनुभव की जाती है। इसके सिवा, ये विषय व्यय-साध्य भी हैं; अतएव स्वसंचालित संस्थाएँ इन्हें बड़ी कठिनाई से चला पाती हैं। शिक्षा-विभाग के अनुसार इन विषयों के पढ़ाने के लिए बहुमूल्य प्रयोग-शालाएँ, विशाल कर्म-शालाएँ तथा विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। इन्हें सब समय जुटाना टेढ़ी खीर है। सबसे अच्छा तो यह हो कि अधिनाश व्यावहारिक कार्य कल-कारखानों, व्यवसाय-केन्द्रों तथा विद्यार्थियों के निजी खेतों पर किया जाये। यह प्रथा अनेक पाश्चात्य देशों में आज प्रचलित है।

हाईस्कूल पाठ्य-विषयों के निर्वाचन के लिए निर्देश



सन् १९५६-५७ ई० में देहातों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल २४,९३६ (इनमें उच्च या उच्चतर ५,२२३ और १९,७१३ मिडिल) थी।† इनके तथा शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोई भी फर्क नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि देहाती मिडिल स्कूल प्रवर बुनियादी स्कूलों में बदल दिये जावें। पर इनके पाठ्यक्रम का केन्द्रीय उद्योग कृषि या बागवानी होवे। जहाँ तक हो सके हाई स्कूल की पढ़ाई का सम्बन्ध ग्रामीण वातावरण से रहे, तथा क्राफ्ट एक देहाती विषय या कुटीर शिल्प हो। इसके साथ-साथ कृषि हाई स्कूल पर्याप्त रूप में खोले जावें। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरीखे कृषि-प्रधान देश में ऐसे स्कूलों की संख्या सिर्फ ८४ (१९५६-५७) है। कृषि विद्यालयों में कृषि के साथ-साथ, बागवानी तथा पशु-पालन पढ़ाया जाय।

निर्देश तथा परामर्श.—बहुमुखी पाठ्यक्रम के आयोजना के कारण, शिक्षकों तथा स्कूलों पर एक नयी जिम्मेवारी आ गयी है। वह जिम्मेवारी यह है कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं रुचियों का भान हो जाय तथा उन्हें इस प्रकार निर्देश तथा परामर्श मिले कि उनके उपयुक्त कौन-कौन से विषय हैं, जिनके अध्ययन से उन्हें अधिकतम सफलता मिले। विषयों के निर्वाचन के समय प्रत्येक विद्यार्थी को आठवीं कक्षा में यह परामर्श मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर एक छात्र को एक ऐसा निर्देश दिया जाय कि अपनी माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर उसे एक उपयुक्त नौकरी मिले; या, वह एक अनुकूल व्यवसाय में घुस सके अथवा, उसे किसी उपयुक्त उच्च विद्यालय में शिक्षा मिले। इसके साथ-साथ प्रतिभा-सम्पन्न तथा धीम-बुद्धि छात्रों की समस्या है। यह सब सोच-विचार कर, माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सिकारिश की है, "सभी स्कूलों को प्रशिक्षित पथ-परामर्श-दाताओं तथा व्यवसाय-निर्देशकों की सेवाएँ अधिकाधिक मात्रा में क्रमशः उपलब्ध करायी जावें।"‡ इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप कई प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा राज्य-निर्देश-केन्द्रों ने इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कोर्स आरम्भ किये हैं। आज जनता भी निर्देश तथा परामर्श में दिलचस्पी लेने लगी है। १९५१-५९ के बीच ब्रम्हई राज्य सरकारी निर्देश-केन्द्र ने ४२,००० व्यक्तियों को व्यक्तिगत परामर्श तथा २३,००० पुरुष-ल्लियों को व्यवसायी संवाद दिया था। इसी दौरान में, केन्द्र ने ५० व्यवसाय-सम्मेलन चलाये तथा १,००० व्यवसाय-निर्देशक प्रशिक्षित किये।

† *Education in the States, 1956-57, Vol. I, p 123.*

‡ *Secondary Education Commission's Report, p 143.*

निरीक्षण.—हमारी स्कूल-निरीक्षण पद्धति का आज तीव्र प्रतिवाद हो रहा है। इस प्रथा के सम्बन्ध में शिक्षा जगत् में असन्तोष व्याप्त हो रहा है। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह पद्धति दोष पूर्ण है। इसका मुख्य कारण निरीक्षकों की कमी तथा निरीक्षकों में पर्याप्त क्षमता का अभाव ही है। हमारे देश में ऐसा कोई उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है, जिनके द्वारा हमारे निरीक्षकगण शिक्षा प्रशासन-कला में प्रशिक्षित किये जा सकें। जून, १९५६ में शिक्षा-प्रशासन की एक गोष्ठी श्रीनगर में हुई थी। उसमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुए थे :

१. शिक्षा शासकों को प्रशासन कला में प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर सक्षित तथा दीर्घ कोर्सों, गोष्ठियों एवं कर्म शालाओं का आयोजन किया जावे। इसके सिवा, नवीन अधिकारीगण कुछ समय तक अनुभवी शासकों के साथ पद-शिक्षार्थी के रूप में रखे जावें।

२. निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है।

३. प्रत्येक राज्य में एक संचालक की नियुक्ति हो, जो शिक्षा शासकों के प्रशासन का उपयुक्त प्रबन्ध करे। प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक शोध-विभाग की स्थापना हो, जिसका काम शिक्षा तथा शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी तथ्यों का शोध करना हो।†

स्वाधीन भारत में निरीक्षण-पद्धति में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। आधुनिक जगत् में निरीक्षण का ध्येय अध्यापन की उन्नति है। यह कार्य शिक्षकों को डॉटने डपटने से ही नहीं पूरा होगा। निरीक्षकों तथा अध्यापकों के पारस्परिक सहयोग से ही अध्यापन में उन्नति हो सकती है। इस कार्य में निरीक्षक शिक्षकों का मित्र, परामर्श दाता तथा मार्ग निर्देशक है। यह भी शिक्षकों से बहुत कुछ सीख सकता है। इस भाव के अभाव के कारण, निरीक्षण बहुधा व्यर्थ ही चला जाता है।

प्रबन्ध.—तालिका १२ में प्रबन्ध के अनुसार माध्यमिक स्कूलों का विभाजन किया गया है : राजकीय स्कूल (२०-२), स्थानीय निकाय (३१-९) तथा स्वसंचालित (४७-९)। जहाँ तक धन सकता है, सरकार स्वतः माध्यमिक स्कूल चालना नहीं चाहती है। सरकारी नीति निजी स्कूलों को प्राप्त देकर प्रोत्साहन देने की है। हाँ, सरकार कन्याशालाएँ तथा व्यावसायिक स्कूल स्वयं स्थापित करती है तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में निजी माध्यमिक स्कूल चालती है।

† Administration Seminar Proceedings, Srinagar June, 1956

प्रशासन : सहयोग की आवश्यकता.—शिक्षा-विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रशासनीय विभागों का भी शिक्षा से सम्बन्ध रहता है, जैसे: कृषि-विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग-विभाग, प्राविधिक विभाग, श्रम-विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, इत्यादि। इनके निजी स्कूल रहते हैं, और ये अपना-अपना रहँटा राग अलग-अलग अलापते हैं। इस कारण श्रम तथा अर्थ के नाश की सम्भावना रहती है। शिक्षा में इस द्वैध शासन को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है :

१. प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विभागों के मन्त्रियों की एक समिति स्थापित हो। इस समिति का मुख्य उद्देश्य हो कि शिक्षा-विस्तार के निमित्त विभिन्न विभागों के अर्थ का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाय।

२. शिक्षा की उन्नति तथा प्रसार की विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के लिए, प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों की एक सहयोग-समिति की विशेष आवश्यकता है।

माध्यमिक शिक्षा-मण्डल.—शालान्त या/और माध्यमिक परीक्षा चलाने के लिए इस देश में आज पन्द्रह माध्यमिक शिक्षा-मण्डल हैं।† पर यह देखा गया है कि कई मण्डलों के सदस्यों की संख्या अत्यधिक है। कुछ सदस्य तो ऐमे रहते हैं, जिनका शिक्षा से कुछ सरोकार नहीं है। काम सुधारने के बदले वे काम बिगाड़ते हैं। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है :

माध्यमिक शिक्षा के यथोचित विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-मण्डल की रचना ठोस हो। इसके सदस्य शिक्षा-विद् हों तथा उनका कार्य केवल शिक्षा-नीति निर्धारित करना हो।‡

अनेक राज्यों में इन मण्डलों की स्थापना के कारण, द्वैध-शासन आ गया है। कारण, शालान्त कक्षा का पाठ्यक्रम का मानदण्ड निम्न कक्षा के पाठ्यक्रम से बृद्धा निरूप रहता है। शिक्षा में नैरन्तर्य की आवश्यकता है। द्वैध शासन के कारण, अनेक हानियाँ होती हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा परीक्षा-नीति स्थिर करने की जिम्मेवारी शिक्षा-मण्डल को दी जाय, पर उन सबका निरीक्षण शिक्षा-विभाग करे।

† देखिए पृष्ठ १०९।

‡ Secondary Education Commission's Report, p 191.

अनेक सुधार हुए हैं, तथा होते जा रहे हैं, जैसे: विविध विषयों का समावेश, क्रमबद्ध शिक्षा, शिक्षकों की वेतन-वृद्धि, किशोर-कल्याण, इत्यादि। अतः स्कूलों का स्तर बढ़ गया है तथा निजी स्कूलों को अधिक सरकारी प्राण्ट की ज़रूरत है। प्रत्येक राज्य में प्राण्ट की रकम स्थिर रहती है, पर स्कूलों को यथेष्ट सहायता नहीं मिलती। इस कारण, एक युक्ति-पूर्ण वित्त-नीति की आवश्यकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा उत्तति के कार्य में, केन्द्रीय तथा राज्य का पूर्ण सहयोग स्थापित हो।

२. यह सोचना गलत है कि केन्द्रीय सरकार की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। विशेषतः, प्राविधिक तथा नागरिक शिक्षा के प्रचार का उत्तरदायित्व भारत सरकार अपने ऊपर ले।

३. माध्यमिक शिक्षा पर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए एक उपकर लगाया जाय, जो 'औद्योगिक शिक्षा-उपकर' कहा जाय।

४. शिक्षा-दान की रकम पर कोई उपकर न लगाया जाय।†

परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण.—भारतीय शिक्षा पर परीक्षा का कितना गहरा प्रभाव है, यह तो सबको विदित ही है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का ध्यान सदा परीक्षाओं की ओर खिँचा रहता है। हमारी परीक्षा-पद्धति में अनेक दोष हैं। फिर भी हम परीक्षा को बहिष्कृत नहीं कर सके। कारण, परीक्षा ज़रूरी है। इसके मुख्य तीन कार्य हैं : (१) परीक्षा, अध्यापन का एक अङ्ग है, (२) विद्यार्थियों के वर्गीकरण का यह एक साधन है, और (३) विद्यार्थियों की प्रतिभा तथा शिक्षकों की कार्य कुशलता की जाँच करने की यह एक कसौटी है।

परीक्षाएँ बन्द नहीं की जा सकती हैं। उनमें सुधार की विशेष आवश्यकता है। इस विषय पर कुछ सुझाव दिये जाते हैं : (१) विद्यार्थियों की उन्नति-विषयक लेखा रखे जायें, (२) वार्षिक परीक्षा-फल घोषित करने के समय सावधिक तथा शैक्षणिक परीक्षा-फल एवं उन्नति-विषयक लेखा पर विचार किया जाय, (३) सावधिक परीक्षा में केवल उतने ही अंश की परीक्षा ली जाय, जो उम नियत काल में पढ़ाया गया हो। काल की अपेक्षा ४० दिनों से अधिक न हो, (४) सावधिक परीक्षा के परचे में केवल

† *Ibid.*, p. 227.

स्थानिक बोर्डों-द्वारा परिचालित माध्यमिक स्कूल प्रायः सफल नहीं होते। इन संस्थाओं की आलोचना करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मत दिया, "इन स्कूलों में अनेक सुधारों का प्रयोजन है।" देश की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय निकाय अपना सम्पूर्ण ध्यान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ओर दें।

वर्तमान काल में स्वसञ्चालित स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ये स्कूल चाहे जहाँ, खुलते ही जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो दो-तीन स्कूल पास-पास स्थापित हो जाते हैं, पर अनेक स्थानों में कोई भी माध्यमिक स्कूल नज़र नहीं आते हैं। यह भी देखा गया है कि अनेक अच्छे मिडिल स्कूल कमज़ोर हाई स्कूल में बदल दिये जाते हैं। बहुते निजी स्कूल अस्वास्थ्यकर स्थानों में लगते हैं। उनमें शिक्षा-साधनों, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि का अभाव रहता है। वहाँ शिक्षकों की बुरी दशा रहती है। यथार्थ में इन स्कूलों का वहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। पर किसी-न-किसी रीति-द्वारा वे शिक्षा-विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। इन स्कूलों की दशा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने गौर किया है :

अमाग्यवशा इस शिथिलता के फल-स्वरूप अनेक निकम्मे स्कूल संचालकों के खीसे गरम करने के लिए चलते रहते हैं। न उनके पास उपयुक्त स्कूल-गृह रहता है, और न शिक्षा-साधन। शिक्षा-विभागों को मजबूर होकर, उन्हें स्वीकृति देनी पड़ती है। कारण, उनके भरती किये हुए विद्यार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है।†

पर इन स्वसञ्चालित स्कूलों से बड़तर हैं अस्वीकृत स्कूल। हाल ही में दिल्ली सेण्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन ने एक सर्वेक्षण किया है। इससे ज्ञात होता है कि जितने विद्यार्थी दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठते हैं, उनसे दुगुने परीक्षार्थी निजी अस्वीकृत स्कूलों द्वारा पञ्जाब मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं। एक बड़े अस्वीकृत स्कूल के प्रिंसिपल का मासिक वेतन ₹,२००) है। इसी प्रकार एक अस्वीकृत मण्डल के अन्तर्गत १२ संस्थाएँ हैं जिनमें से छः संस्थाएँ एक मील के अर्ध व्यास में स्थित हैं। शिक्षा में यह व्यभिचार नहीं तो क्या है ?

वित्त.—अर्थोभाव के कारण, अनेक माध्यमिक स्कूल कमज़ोर हैं। उन्हें विद्यार्थियों की फीस पर अपना निर्वाह करना पड़ता है। प्रायः २५ प्रति शत स्वयं संचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता। कुछ बच्चों से माध्यमिक शिक्षा में

† Secondary Education Commission's Report, pp. 197-98.

उपसंहार

आज पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा सुधार की पुकार मच रही है। नये दृष्टि से स्कूलों का प्रादुर्भाव हो रहा है। शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके अनुसार एक माध्यमिक विद्यार्थी सत्रह वर्ष की अवस्था में उच्चतर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने की आशा रखता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूरा देश एक ही रंग में रंग जाय। आरिण, इसमें हर्ज ही क्या है कि एक विद्यार्थी अपनी माध्यमिक शिक्षा १६ या १७ या १८ वर्ष की आयु में समाप्त करे। विद्यार्थी का योग्यता तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न प्रकारों की अवधि में हेरफेर होना उचित है। राधाकृष्णन आयोग ने देश को यह चेतावनी दी है, “भारतीय शिक्षा में सदैव एक प्लान्नी एकरूपता कायम रही। यह देश के लिए हितकर नहीं है।”†

इस कारण, हमें शिक्षा-सुधार सोच समझ कर करना चाहिए। तेजी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रा एक ही प्रश्न पर विचार कीजिए — “हमारे देश के ११,००० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलने की समस्या।” ये स्कूल तो कमर कस कर बैठे ही हैं। एक इशारा मिलते ही, ये स्वयं को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलना आरम्भ कर देंगे। ये तनिक भी विचार नहीं करेंगे कि इस परिवर्तन के लिए किन किन योजनाओं की आवश्यकता है। उच्चतर स्कूल होने पर सस्या एवं सचालक की प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी, तथा प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी। यही विचार-धारा उनके मस्तिष्क में प्रवाहित है। कोई जरा सोचता भी नहीं है कि वह स्वयं इस उच्चतर कार्य के लिए योग्य, सक्षम अथवा उपयुक्त है या नहीं है।

इस प्रकार हमें समझ बूझकर काम करना चाहिए। हमें इस देश के लिए उपयुक्त माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें हमारे किशोरों को उपयुक्त शिक्षा मिले। प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान् मैथ्यू एनाल्ड ने कहा था, “हमारे देश का मध्यम वर्ग बहुत ही कमज़ोर है।” इस कथन के पश्चात् इंग्लैण्ड की माध्यमिक शिक्षा पद्धति को पूर्ण एवं सशक्त होने के लिए सत्र वर्ष लगे। भगवान् जाने भारतीय शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी कब मजबूत होगी !!

† University Commission's Report p 546

नवीन परीक्षा-प्रणाली के प्रश्नों का समावेश हो। त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में आधे निबन्ध-प्रश्न और आधे नवीन परीक्षण-प्रणाली के प्रश्न हों, (५) सार्वजनिक परीक्षा-फल में आन्तरिक परीक्षाओं, छात्रों की उन्नति-विषयक लेखा तथा साल भर के किये गये कार्य पर विचार किया जाय।

सितम्बर, १९५९ के माध्यमिक शिक्षा-मण्डल के मंत्रियों के एक सम्मेलन ने शालान्त परीक्षा के दोषों पर विचार करते हुए स्थिर किया : (१) एक सतुलित पाठ्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है; इस कारण, प्रचलित पाठ्यक्रम की परीक्षा शिक्षकगण तथा राज्यीय पाठ्यक्रम समिति करे। (२) पाठ्यक्रम के ध्येय, अध्यापन-विधि तथा परीक्षा-पद्धति में एक विशेष समन्वय की आवश्यकता है, ताकि परीक्षार्थी की बौद्धिक क्षमताओं की जाँच हो न कि स्मरणशक्ति की। (३) सार्वजनिक परीक्षा दो प्रकार की हो : (अ) शालान्त — उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे न पढ़ना चाहते हों, और (आ) प्रवेशिका — जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों।†

विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण.—आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना है; परन्तु खेद की बात है कि हमारे अधिकांश माध्यमिक स्कूलों का ध्येय शिक्षा-विभाग-द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समाप्त करना तथा विद्यार्थियों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार करना ही हो गया है। वे न तो शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की ओर ही ध्यान देते हैं और न विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा चरित्र-निर्माण के प्रति ही सचेष्ट रहते हैं। स्कूल का आखिरी घण्टा बजते ही मानो उनका दैनिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र घोष की निम्नोक्त युक्ति सर्वथा उपयुक्त एवं आश्चर्य-विरहित है :

क्या हम अपने नवयुवकों को मनुष्य बना रहे हैं या और कुछ ?
क्या हम उन्हें कुछ संभाव्य प्रश्नों के उत्तर कंटस्य करने के सिवा और भी कुछ सिला रहे हैं ? क्या हम उनकी चिन्तन-शक्ति, आत्म-निर्मता तथा आत्म-विश्वास बढ़ाने की दिशा में कुछ भी प्रयत्न कर रहे हैं ?

उपयुक्त कथन मले ही अत्यन्त कटु हों, पर यह अतीव सत्य है। हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक गुस्तर उत्तरदायित्व है। उन्हें अपने विद्यार्थियों को एक प्रजातन्त्र राज्य का सुयोग्य नागरिक बनाना है, उनमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से सोचने तथा कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना है, जिससे वे समाज के कल्याणकारी अङ्ग बन सकें।

† Times of India, September 27, 1959.

कालिज काल.—इस काल का प्रारम्भ कलकत्ता मदरसा की स्थापना से होता है, तथा अन्त मूल विश्वविद्यालय (कलकत्ता, बम्बई और मद्रास) के सुनपात के साथ होता है। इस काल में कई अभिजी और प्राच्य — सरकारी और निजी — महाविद्यालय खुले। इन सस्थाओं का रूप वर्तमान कालिजों से विभिन्न था। प्रारम्भ में ये सस्थाएँ माध्यमिक स्कूल थीं, पर शीघ्र ही वे कालिज के रूप में वर्द्धित हो गयीं। इसी कारण प्रत्येक सस्था के दो अङ्ग थे. कालिज और हाई स्कूल। इस काल के प्रसिद्ध कालिज थे: कलकत्ता मदरसा (१७८१), बनारस संस्कृत कालिज (१७९१), हिन्दू कालिज, कलकत्ता (१८१७), श्रीरामपुर कालिज (१८१८), स्कटिश चर्च कालिज, कलकत्ता (१८३०), विडसन कालिज, बम्बई (१८३२), एलफिन्स्टन कालिज, बम्बई (१८३५), क्रिश्चियन कालिज, मद्रास (१८३७), पठैया कालिज, मद्रास (१८४१), सेण्ट जॉन्स कालिज, आगत (१८५२), इत्यादि। इस बीच में कलकत्ता (१८३५), मद्रास (१८४३) और बम्बई (१८४५) में मेडिकल कालिज तथा रुड़की में इजिनियरिंग कालिज (१८४७) स्थापित हुए। इनने सिना, जुठ कानून की कक्षाएँ भी खुलीं।

सन् १८४५ और सन् १८५२ में विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने के प्रयत्न हुए, पर वे प्रयत्न कार्यान्वित न हो सके। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड एलफिन्स्टन ने कोर्टे ब्लॉक डायरेक्टर के पास मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा (१८३९)। यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका। इस काल के कालिजों की स्थिति का पता निम्न लिखित तालिका से मिलेगा

तालिका १६

कालिजों की संख्या, सन् १८५७†

प्रान्त	प्रबन्ध	साहित्यिक कालिज	मेडिकल कालिज	इजिनियरिंग कालिज
बङ्गाल	राजकीय	७	१	—
	मिशनरी ...	७	—	—
बम्बई	राजकीय	२	१	—
	मिशनरी ..	—	—	—
उत्तर पश्चिम प्रान्त	राजकीय	४	—	१
	मिशनरी ...	—	—	—
मद्रास	राजकीय	१	१	—
	मिशनरी ...	२	—	—
कुल योग		२३	३	१

† S Nurullah and J P Nair *History of Education in India* Bombay, Macmillan, 1951, p 279

छठा अध्याय

विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना

पहले अध्याय में हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयीय शिक्षा की चर्चा की गयी है। यह शिक्षा इस देश के लिए कोई नयी वस्तु नहीं है। वैदिक युग में, कितने ही कुलपतियों के आश्रम खासे सावास विश्वविद्यालय थे। बाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा इत्यादि आचार्यों के आश्रमों में प्रायः दस सहस्र शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उपनिषत्काल में परिषदों की स्थापना हुई थी। उनमें आधुनिक विश्वविद्यालयों के समी उपकरण प्रस्तुत थे।

बौद्ध युग में 'बिहार' या 'संचाराम' शिक्षा-केन्द्रों में संगठित होने लगे। धीरे-धीरे वे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गये। इन शिक्षा-केन्द्रों में नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं बलभी मुख्य थे। कई एक विश्वविद्यालयों में दूर-दूर देशों के विद्यार्थीगण विद्याध्ययन के लिए आते थे।

मुस्लिम युग में, अनेक मदरसे खुले। ये कालिजों के समकक्ष थे। कई एक मदरसों की तुलना आधुनिक विश्वविद्यालयों से की जा सकती है। दिल्ली, आगरा, रामपुर, जौनपुर, बीदर, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, आदि स्थानों में प्रख्यात मदरसे थे। इसी समय में अनेक टोल एवं पाठशालाएँ स्थापित हुईं। इन संस्थाओं में हिन्दू-पद्धति पर उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था थी। बनारस, नव-द्वीप (वर्तमान 'नदिया'), मिथिला, पूना तथा अहमदनगर मुख्य हिन्दू-शिक्षा-केन्द्र थे। जॉन टॉमास, एक बेट्टिस्ट पादरी, ने नव-द्वीप की तुलना आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ की है, (१७९१)।

आधुनिक काल में उच्च शिक्षा भूमिका.—उच्च शिक्षा के अनुशासन के लिए, हम आधुनिक काल को चार उपकालों में बाँट सकते हैं: (१) कालिज कॉल (सन् १७८१ से सन् १८५७ तक), (२) मूल विश्वविद्यालय काल (सन् १८५७ से सन् १९१७ तक), (३) आधुनिक विश्वविद्यालयों का उदय-काल (सन् १९१७ से सन् १९४० तक) और (४) स्वातन्त्र्योत्तर काल।

पर इस विस्तार के साथ साथ, अनेक दोष भी दृष्टि आने लगे। प्रथमतः, विश्वविद्यालय इतने अधिक कालिजों का भार वहन नहीं कर सकते थे, तथा उन्हें कालिजों की कार्यवाही को नियन्त्रित करने का कुछ भी अधिकार न था। इसी कारण शिक्षा के स्तर में पतन हो चला था। द्वितीयतः, सदस्यों की संख्या की वृद्धि के कारण, सिनेट का रूप अत्यन्त बोज़िल हो गया था। वे अपना काम-काज ठीक रूप में संभाल न पा रही थीं। इनके अतिरिक्त लोग यह अनुभव करने लग गये थे कि परीक्षा सञ्चालन के सिवा, विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान तथा अध्यापन कार्य करना चाहिए।

इतने में लार्ड कर्जन भारत के वाइसराय होकर आये। उन्होंने उच्च शिक्षा के पुनर्संरक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। कमीशन की जाँच का निष्पत्ति रखा गया — “ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशा तथा उनके भविष्य की जाँच करना और उनके विधान एवं कार्य प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।” अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, लार्ड कर्जन ने सन् १९०४ में एक कानून निकाला, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्य नियम निम्न-लिखितानुसार हैं :

१. विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये जावें। इनको अधिकार है कि वे परीक्षा लेने के अतिरिक्त अनुसन्धान तथा शिक्षण-कार्य आरम्भ करें। इसके लिए वे प्रोफेसर तथा लेक्चरर नियुक्त करें; पुस्तकालय, अजायब घर तथा प्रयोग-शालाएँ स्थापित करें, एवं विद्यार्थियों के आवास-गृह चलावें।

२. सिनेट के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय—यह कम-से-कम ५० और अधिक-से-अधिक १०० रहे। उनकी सदस्यता की अवधि आजीवन न होकर पाँच वर्षों के लिए हो। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या चीन तथा अन्य विश्वविद्यालयों की निर्वाचित सदस्य संख्या पन्द्रह रखी जावे।

३. सिण्डिकेटों को कानूनी स्वीकृति दी जावे, और उनमें विश्व-विद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

४. सम्बद्ध कालिजों को मान्यता देने के नियमों में सख्ती की जावे, तथा सिण्डिकेट-द्वारा उनके निरीक्षण की नियमित रूप से व्यवस्था हो।

मूल विश्वविद्यालय-काल.—बुड के घोषणापत्र में निर्दिष्ट सिफारिशों के कारण कलकत्ता, ब्रम्हई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गये (१८५७)। ये विश्वविद्यालय तात्कालिक लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर स्थापित हुए। लन्दन विश्वविद्यालय उस समय केवल एक परीक्षक संस्था थी। तीनों विश्वविद्यालयों के लिए भारत-सरकार ने निश्चिततः अलग-अलग कानून बनाये। तथापि उनके ढाँचे और अधिनियम आपस में मिलते जुलते थे। इन कानूनों के अनुसार, विश्वविद्यालयों का उद्देश्य था: “परीक्षाओं के द्वारा उन छात्रों की योग्यता की जाँच करना, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता प्राप्त की हो, तथा इस क्षमता के आधार पर उन्हें शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना।”

विश्वविद्यालयों का शासन सिनेट को सौंपा गया। इसका संगठन कुलपति, उपकुलपति तथा सदस्यों के द्वारा होता था। स्थानीय गवर्नर ‘कुलपति’ होते थे, तथा उपकुलपति सपरिपद गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। सिनेट के सदस्य दो प्रकार के थे: पदेन तथा सामान्य। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गयी थी, तथा उनकी नियुक्ति भी आजीवन रखी थी। इस प्रकार सरकार द्वारा सदस्यों की संख्या इच्छानुसार बढ़ाना सम्भव था, तथा अन्तिम सौत चलते तक कोई भी सदस्य सिनेट में बैठ सकता था। इसके अतिरिक्त, कानूनों में सिण्डिकेट की कोई व्यवस्था न थी। बाद में प्रत्येक सिनेट ने अपने अपने सिण्डिकेट निर्मित किये। चूँकि इनका कोई कानूनी हक न था, अतएव इनका कोई वैधानिक महत्व भी न था।

विश्वविद्यालय माड़े के मकानों में लगते थे। परीक्षा लेने तथा प्रमाण-पत्र-वितरण के अतिरिक्त, उनका और कुछ काम न था। उनमें अच्चापन की व्यवस्था न थी। स्कूलों तथा कालिजों को मान्यता प्रदान करने का उन्हें अधिकार अवश्य था, पर विश्वविद्यालयीय कानूनों की अनिर्दिष्टता के कारण स्कूलों तथा कालिजों का विश्व-विद्यालयों से स्थापित सम्बन्ध अस्पष्टप्रायः था।

सन् १८८२ तथा १८८७ में पंजाब तथा बलाहाबाद विश्वविद्यालय पुराने विश्व-विद्यालयों के आधार पर क्रमशः स्थापित हुए। विश्वविद्यालयों की छत्र-छाया में कालिजों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ। सन् १८८२ में कालिजों की संख्या ६८ थी, किन्तु २० वर्ष बाद यह संख्या १७९ हो गयी — १३८ अंग्रेजी भारत में, ३२ देशी रजवाड़ों में तथा ९ लड्डा-द्वीप में।

डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (१९१७)। इनकी स्थापना से विश्वविद्यालयीय शिक्षा के नये विचार स्पष्ट दृष्टि आने लगे। बनारस सबसे पहला एकात्मक तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है; पटना प्रथम प्रादेशिक एवं सम्बन्धीय विश्वविद्यालय है; मैसूर तथा हैदराबाद तत्कालीन देशी राजाओं के प्रथम विश्वविद्यालय हैं; एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, भारत में उच्च स्त्री शिक्षा के प्रसार का एक अनूठा दृष्टान्त है। इसके माथ-माथ ढाका, पूना तथा अहमदाबाद में क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की चेष्टा होने लगी। सन् १९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग खोले गये।

आधुनिक विश्व-विद्यालयों का उदय-काल.—इस प्रकार पिछले उपकाल के अन्त में कुछ नये विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। फिर भी विश्वविद्यालयों की समस्या हल न हुई। सन् १९१७ में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। इसकी माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्तावों की चर्चा पहले की गयी है।[†] विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में आयोग ने ये सिफारिशें कीं :

१. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन—जहाँ तक हो सके, ये एकात्मक, सावासरू, शैक्षणिक संस्थाएँ हों।

२. स्नातक का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो तथा 'पाम कोर्स' के अलावा 'थानर्स कोर्स' आरम्भ हो।

३. छात्रों की भलाई के विचार से, हर विश्वविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा-संचालक नियुक्त किया जाय।

४. भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिये, युनिवर्सिटी प्रोफेसर या रीडर नियुक्त हो।

५. अध्यापन, कानून, इंजीनियरिंग, डाक्टरी, कृषि, एवं आदि की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालय में किया जावे।

६. विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचारविमर्श करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का सामयिक सम्मेलन किया जावे।

इस आयोग की रिपोर्ट के बाद, भारत में धड़ाघड़ विश्वविद्यालय खुल गये : ढाका और रंगून (१९२०), अलीगढ़ और लखनऊ (१९२१), दिल्ली (१९२२),

५. सरकार आवश्यकतानुसार सिनेट-द्वारा बनाये गये नियमों को संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती है। यदि निर्धारित तिथि तक सिनेट कानून न बनावे, तो सरकार स्वतः कानून बना सकती है।

६. सपरिषद् गवर्नर जनरल प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर दे।

इतना सब कुछ होते हुए, इस कानून ने न अलीगढ़, बनारस, ढाका, पटना, रंगून तथा नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग को स्वीकृति दी, और न सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों की कल्पना ही की। लेकिन कानून ने भारतीय उच्च शिक्षा में कई उछेला-योग्य परिवर्तन किये। प्रथमतः, सिण्डिकेट एक वैधानिक समिति हो गयी; इस कारण उस पर किसीका दबाव न रहा। द्वितीयतः, नव संगठित सिनेट पहले सिनेटों की अपेक्षा अधिक टोस तथा प्रभाव-युक्त बनी। तृतीयतः, सम्बद्ध कालिजों के निरीक्षण तथा नियन्त्रण के कारण उच्च शिक्षा की उन्नति हुई। कुछ निरुद्ध कालिज तो छूत ही हो गये। चतुर्थतः, विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगा।

लाई कर्जन के सुधार के दस वर्ष बाद, उच्च शिक्षा के पुनर्निरीक्षण की फिर से आवश्यकता पड़ी। कालिजों की संख्या-वृद्धि होती जा रही थी तथा विश्वविद्यालयों पर बोझ बढ़ रहा था। इतने पर भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा की माँग पूरी न हो रही थी। फलतः, सन् १९१३ में सरकारने अपनी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता स्वीकार की गयी। इसने फिर सुझाव दिया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की अधिकार सीमा इतनी विस्तृत हो गयी है कि उसे घटाकर नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जावें। यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है : (१) प्रत्येक बड़े-बड़े प्रान्त में सम्बद्ध विश्वविद्यालय खोले जावें और (२) नये स्थानीय तथा साप्तासिक विश्वविद्यालय मुख्य उच्च विद्या-केन्द्रों में स्थापित किये जावें। इस प्रस्ताव ने धोषणा की कि सरकार ने पटना एवं नागपुर में प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा ढाका, अलीगढ़ और बनारस में स्थानीय विश्वविद्यालय खोलना अङ्गीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव ने उचित समझा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक उन्नति के लिए उपयुक्त वातावरण हो।

इस शिक्षा-नीति की सिफारिशों के कारण, नवीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए : बनारस और मैसूर (१९१६), पटना (१९१७), हैदराबाद (१९१८) तथा एम० एन०

वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ

वर्तमान विश्वविद्यालयों की ठीक तरह से समझने के लिए हमारी उच्च शिक्षा की कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है। इस कारण, इस प्रकरण में इन विषयों की चर्चा की गयी है : (१) कालिजों का वर्गीकरण, (२) विश्वविद्यालयों के प्रकार, (३) विश्वविद्यालय प्रशासन और (४) कतिपय प्रशासन निकाय।

कालिजों का वर्गीकरण.—सन् १९५५-५६ में, सम्पूर्ण देश में, कुल १,२०४ कालिजें थे : ७४६ कला तथा विज्ञान कालिजें, ३४६ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले कालिजें तथा ११२ विविध शिक्षाप्राले कालिजें (संगीत, नृत्य, ललित कला, प्राच्यविद्या, समाज विज्ञान तथा गृह-विज्ञान)। प्रबंध की दृष्टि से इन कालिजों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

तालिका १८

प्रबन्धानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६†

प्रबन्ध	कला तथा विज्ञान कालिजें	व्यावसायिक कालिजें	विविध कालिजें	प्रति शत
राजकीय	१८६	१९४	२८	३३.९
स्थानीय मण्डल ...	३	३	१	०.६
स्वसंचालित सहायता प्राप्त ...	४५८	१०१	६८	५२.३
स्वाश्रित ...	९९	४५	१५	१३.२
कुलयोग	७४६	३४६	११२	१००.००

उपर्युक्त अङ्कों से स्पष्ट होगा कि : (१) दो तिहाई कालिजें स्वसंचालित हैं, (२) ५६ प्रति शत व्यावसायिक कालिजें राजकीय हैं और (३) स्थानीय मण्डलों का कालिजों के साथ नाम मात्र सम्बन्ध है।

† *Education in India, 1955-56, Vol 1 p. 121*

नागपुर (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७), अनामलय (१९२९), त्रावणकोर (१९३७), उत्कल (१९४३), सागर (१९४७), सिंध तथा राजपूताना (१९४७)। कालिजों तथा उनके छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। इसका पता निम्नांकित तालिका से चलेगा।

तालिका १७

अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४७†

विवरण	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४६-४७
कालिज-संख्या	२३१	४१७	९३३
छात्र-संख्या	५९,५९१	९९,४९३	१,९९,२५३

स्वातन्त्र्योत्तर काल.—देश के विभाजन के बाद, अठारह नवीन विश्व-विद्यालय स्थापित हुए : पंजाब (१९४७), गौहाटी, पूना, रुड़की तथा जम्मू और कश्मीर (१९४८), बड़ौदा (१९४९), कर्नाटक और गुजरात (१९५०), बिहार (१९५२), श्रीलंका (१९५४), जायपुर तथा सरदार वल्लभभाई विश्वपीठ, आनन्द (१९५५), कुरुक्षेत्र (१९५६), गोरखपुर, जयपुर, विक्रम-विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७), मराठावाड़ा तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर (१९५८)। इसके अतिरिक्त सन् १९५१ में विश्व-भारती तथा एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय को वैधानिक स्वीकृति दी गयी है।

नवम्बर, १९४८ में, भारत सरकार ने डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, एक विश्वविद्यालय-आयोग नियुक्त किया। आयोग को यह निर्देश दिया गया कि वह "भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके विकास तथा विस्तार के लिए यत्न करे, जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से आवश्यक हो।" अगस्त १९४९ में, कमीशन ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा-मन्त्रालय को प्रेषित कर दिया। इसके मुताबिक की नयां हम आचार्य के यथोचित अंशों में की जायेगी।

† S. N. Mukherji, *History of Education in India*, Books & Journals Book Depot, 1957 p 189.

(६) वित्त, (७) पुस्तकालय, (८) प्रयोग शाला, (९) रजिस्टर और (१०) विविध विषय ।†

शुरू शुरू में ये विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धीकरण की व्यवस्था तथा परीक्षा सञ्चालन करते थे । पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के कारण, इस प्रकार के प्राय सभी विश्वविद्यालय कुछ-न-कुछ अध्यापन की व्यवस्था स्वतः करने लग्य हैं । इस देश के सम्बन्धीय विश्वविद्यालय ये हैं • आगरा, आन्ध्र, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, गोरखपुर, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मद्रास, मराठावाड़ा, मैसूर, नागपुर, ओस्मानिया, पंजाब, पूना, राजस्थान, सागर, एस० एन० डी० टी०, व्यक्तेश्वर, उत्कल तथा विक्रम ।

एकात्मक.—ऐसा विश्वविद्यालय सांवासिक तथा शैक्षणिक होता है । इसका क्षेत्र किसी भी एक केन्द्र में सीमित रहता है, जहाँ पर वह स्वतः सम्पूर्ण अध्यापन कार्य की व्यवस्था करता है । अपने निजी विभागा या अधीन कालिजों के द्वारा वह शिक्षण कार्य स्वतः चलाता है । यहाँ तक कि सभी अध्यापक विश्वविद्यालय की मातृहृती में काम करते हैं । इस प्रकार, एसा विश्वविद्यालय अपने प्रबन्ध, प्रशासन तथा अध्यापन का परिचालन स्वतः करता है । भारत के मुख्य एकात्मक विश्वविद्यालय ये हैं : अलीगढ़, अल्हाबाद, अन्नामलय, बनारस, उड़ीसा, बादवपुर, कुश्केन, लखनऊ, पटना, रुड़की, आनन्द तथा विश्व भारती ।

सघात्मक.—सघात्मक विश्वविद्यालय के विशिष्ट लक्षण ये हैं : (१) विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक केन्द्र में ही सीमित रहता है, जहाँ कि उसके सबद तथा अधीन कालिज पास पास अवस्थित होते हैं । (२) प्रत्येक कालिज में उच्चतम शिक्षा का प्रबन्ध रहता है । (३) विश्वविद्यालय ने प्रबन्ध की उन्नति के लिए प्रत्येक कालिज को उसने प्रशासन में भाग लेना पड़ता है । इस कारण, कालिजों को अपनी स्वायत्तता थोड़ी ब्रुत छोड़नी पड़ती है । (४) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कालिज अध्यापन कार्य चलाते हैं । सारांश यह है कि सघात्मक विश्वविद्यालय विभिन्न कालिजों का एक ऐसा सघ है जहाँ कि शैक्षणिक कार्य अधीन कालिज समुदाय मिलजुल कर करते हैं । सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा प्रशासन के वे भागीदार हैं । इस कारण, उन्हें अपनी स्वायत्तता को कुछ-न-कुछ विसर्जन करना पड़ता है । बम्बई तथा जबलपुर के विश्वविद्यालय इस वर्ग में सम्मिलित हैं ।

† Ibid, p 29

विश्वविद्यालयों के प्रकार.—आज भारत में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या ३८ है।† ये विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं : (१) सम्बन्धीय, (२) एकात्मक तथा (३) संघात्मक।

सम्बन्धीय.—प्रत्येक सम्बन्धीय विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है शहरी कालिजों को मान्यता देना। ऐसे विश्वविद्यालय का क्षेत्र विस्तृत रहता है तथा इसके सम्बद्ध कालिज दूर-दूर के शहरों तथा गाँवों में फैले हुए रहते हैं। विश्वविद्यालय सम्बन्धीकरण के नियम तथा शर्तें ठीक करता है तथा समय-समय पर वह अपने कालिजों का निरीक्षण भी करता है। सम्बद्ध कालिजों को विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाना पड़ता है तथा उसकी सार्वजनिक परीक्षाओं में अपने विद्यार्थियों को बैठाना पड़ता है। कालिजों के सफलीभूत परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा मिलता है।‡

विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध कालिजों का पारस्परिक सम्बन्ध भारतीय विश्वविद्यालय कानून, १९०४ के द्वारा नियन्त्रित होता है। कायदे के मुख्य मुद्दों का अनुमान एक सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत निम्न-लिखित अंश से मिलेगा :

एक भारतीय विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ कालिजों का निरीक्षण करता है तथा उससे सम्बन्ध स्थापित करता है, पाठ्यक्रम स्थिर करता है, परीक्षाएँ चलाता है तथा डिग्री प्रदान करता है। वह अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी कालिज को, मान्यता प्रदान कर सकता है। इन कालिजों को वह स्वतः नहीं चलाता है, पर सम्बन्धीकरण की शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें कालिजों को पालना पड़ता है। निरीक्षण-द्वारा विश्वविद्यालय जाँच करता है कि सम्बद्धकालिजें शर्तों का यथोचित पालन कर रहे हैं या नहीं।*

कानून की २१ वीं, २२ वीं तथा २४ वीं धाराओं में सम्बन्धीकरण की शर्तों का विस्तार-पूर्वक वर्णन है। इन प्रतिबन्धों की सन्तोषप्रद परिपूर्ति हुए बिना विश्वविद्यालय किसी भी कालिज को मान्यता प्रदान नहीं करता है। संक्षेप में, ये धाराएँ कालिजों के इन विषयों के साथ सलग हैं : (१) व्यवस्था तथा प्रबन्ध, (२) कर्मचारीणा (३) इमारतें तथा छात्रावास, (४) शिक्षा-साधन तथा असशत्र, (५) विद्यार्थी,

† देखिए, दूसरा परिशिष्ट।

‡ *Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I. p. 54.*

* *Progress of Education in India, 1902-07, Vol. I p. 18.*

माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट शिक्षा मण्डल.—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामर्श के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या वर्तमान काल में पन्द्रह है। पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है।†

अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल.—ऐसे मण्डल की आवश्यकता का सुझाव सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। तत्पश्चात् सन् १९२४ में भारतीय विश्व-विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का सफल किया गया। एक वर्ष पश्चात् यह विचार कार्यान्वित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

१. अन्तर्विश्वविद्यालय संगठन एवं सूचना केन्द्र के रूपमें कार्य करना,
२. अध्यापकों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना,
३. विश्वविद्यालयों में विचार विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाना,
४. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करना,
५. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

प्रत्येक विश्वविद्यालय इस मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। शुरु से ही मण्डल उच्च शिक्षा-विषयक मामलों को हल करने में महत्व-पूर्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवल एक परामर्श दात्री संस्था है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग.—सार्जेंट योजना के प्रस्ताव के कारण, भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन् १९४५ में की थी। इसका सम्बन्ध केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से था। पाच वर्ष बाद, यह समिति बन्द कर दी गयी। इतने में राष्ट्रावृष्टान-आयोग के सुझाव के अनुसार सन् १९५३ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य अगले पन्ने में दिये गये हैं :

† दोसरे पृष्ठ १०२।

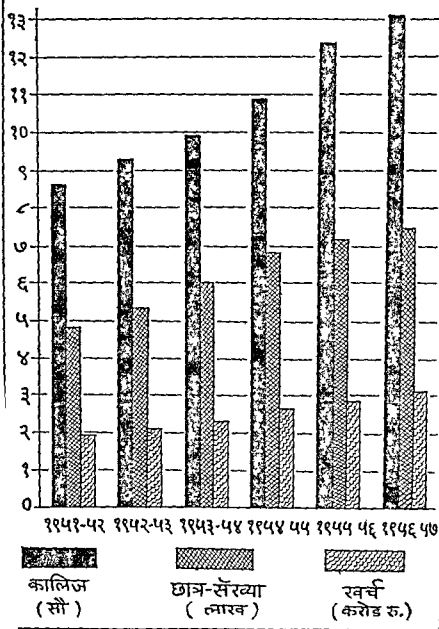
विश्वविद्यालय-प्रशासन.—विश्वविद्यालय का प्रशासन नाना प्रकार के निकायों-द्वारा सम्पादित होता है। इनमें श्रेष्ठतम है कोर्ट या सिनेट। प्रत्येक शैक्षणिक या दैनिक कार्यों का अन्तिम निर्णय यही करती है। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्यों के स्थान, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपलों द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की तालिका प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकगण तथा पंजीयत स्नातक-मण्डल अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुछ सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।

सिनेट के बाद आते हैं, एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिण्डिकेट। प्रथम निकाय का सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों से। सिण्डिकेट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी सभा होती है। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र अभ्यास-समिति संगठित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियाँ होती हैं, जैसे : परीक्षा, अन्वेषण, प्रकाशन, युवक-कल्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद, छात्रावास, पुस्तकालय, आदि।

विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, चांसलर या कुलपति। बहुधा स्थानीय राज्यपाल कुलपति होते हैं, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के संविधान में कुलपति-निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। वास्तव में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुलपति की नियुक्ति की प्रथा सर्वत्र एक-सी नहीं है। कहीं ये स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिण्डिकेट-द्वारा और कहीं सिनेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति की अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के संविधान के अनुसार तीन से पाँच वर्ष की है। शुरू शुरू में उपकुलपति अवैतनिक तथा कोई प्रतिष्ठित महानुभाव होते थे। इस कारण, वे अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्य में नहीं लगा सकते थे। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा वेतन-भोगी उपकुलपतियों की माँग है।

कतिपय प्रशासन निकाय—विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं : (१) माध्यमिक या/और इंटरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, (२) अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग। इन तीनों निकायों की चर्चा इस प्रकरण में की गयी है।

उच्च शिक्षा की प्रगति (१९५१ से १९५७)



चित्र ११

१. केन्द्रीय सरकार को एक विशेष संस्था के रूप में उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के मान-दण्डों को ऊँचा करने के विषय में परामर्श देना,
२. विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा की जाँच-पड़ताल करके, उनको अनुदान देना,
३. यदि कोई प्राथमिक आवश्यक समझे तो नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उसे सलाह देना, एवं पुराने विश्वविद्यालयों को सुधार के मार्ग बताना अथवा उनकी किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाना,
४. केन्द्रीय या राज्य-सरकारों को किसी विश्वविद्यालय की डिग्रियों की मान्यता के विषय में सलाह देना, तथा
५. केन्द्रीय सरकार के अनुसार उच्च शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करना ।

सन् १९५६ में, संसद के एक अधिनियम-द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था मान लिया गया है । आयोग का संगठन इस प्रकार है : (१) अध्यक्ष (२) मन्त्री तथा (३) नौ सदस्य : विश्वविद्यालयों के उपकुलपति - तीन, भारत-सरकार-द्वारा मनोनीत - दो, तथा नामजद प्रमुख शिक्षा-शास्त्री - चार । इस आयोग को शिक्षा-सम्बन्धी अधिकांश मामलों की देखरेख का भार सौंपा गया है । आयोग को विभिन्न विश्व-विद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के भी अधिकार प्राप्त हैं ।

कतिपय समस्याएँ

इस प्रकरण में विश्वविद्यालयीय शिक्षा-सम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर विचार किया गया है । मुख्य प्रश्न ये हैं : (१) भविष्य के विश्वविद्यालय, (२) सरकार तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा, (३) वित्त, एवं (४) स्वसंचालित कालिज ।

भविष्य के विश्वविद्यालय : उच्च शिक्षा की प्रगति.—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण विस्तार हुआ है । सन् १९४८ में मुख्य राज्यों के कला तथा विज्ञान कालिजों की छात्र-संख्या १,७९,१७३ थी । सन् १९५७ में यह संख्या ६,२५,४०७ अर्थात् प्रायः चौगुनी हो गयी । इसी अरसे में स्नातकोत्तर कालिजों की छात्र-संख्या ४४,६०४ से १,५९,९७३ पहुँची ।† इतना

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। ऐसे पुराने कालिजों के बन्द होने के कारण, स्थानीय जनता के हृदय में धक्का पहुँचता है। इस कारण शुरू शुरू में जब दिल्ली में एक एकात्मक विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी, तब लोगों ने उसका विरोध किया। यदि वह कल्पना कार्यान्वित होती तो हिन्दू कालिज, सेण्ट स्टीफन्स कालिज तथा रामजस कालिज सरोगे तीन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं को बन्द करना पड़ता। इस समस्या को हल करने के लिए ही दिल्ली में एक सघीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अतएव कुल कालिजों में ताला बन्द कर, एक एकात्मक विश्वविद्यालय न खोला जाय। एक विशाल कालिज को बढाकर ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इस पन्थ का अप्रलम्भन अलीगढ़, बनारस, बडौला, अनामल्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय किया गया था। जिस जगह अनेक कालिज हों, वहाँ एक सघीय विश्वविद्यालय खोलना श्रेयस्कर है।

भारत में कुछ ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो कि केवल एक ही विषय में विशेषज्ञ हों। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। ऐसे विश्वविद्यालय कई जगह खुल सकते हैं टाटानगर में धातु विज्ञान, सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा, अहमदाबाद में वस्त्र विद्या आदि।

हर्ष की बात है कि सम्प्रति भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जैसे कृषि शोध संस्था, दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर (लखनऊ के पास), संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला, संगीत तथा ललितकला विश्वविद्यालय, राँचीगढ़।

उचित व्यवस्था—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के निमित्त, एक विशेष योजना की आवश्यकता है। ये अत्यन्त समझ बूझ कर खोले जावें। स्वातन्त्र्य काल में सत्रह नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इनमें से कुछ के लिए भूमि आवश्यक तैयार थी, पर अन्य विश्वविद्यालय खींचतान कर खडे किये गये हैं। ये ऐसी जगह स्थापित हुए हैं, जहाँ कि शायद एक भी कालिज न था। कहीं कहीं, किसी दानवीर ने दान दिया था, पर इस दान से शायद विश्वविद्यालय की एक इमारत भी खड़ी न हो सकी। पर अधिकांशों की स्थापना क्षेत्रीय आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए या राजनैतिक मँगों को पूरा करने के लिए हुई है। यह प्रवृत्ति अत्यन्त ही हानिकर है। कोई भी विश्वविद्यालय एकाएक खड़ा नहीं हो सकता है। वह ऐसी जगह स्थापित हो, जहाँ कि अनेक स्कूल हों, विविध विषय के कालिज हों, उपयुक्त प्रयोग शालाएँ तथा पुस्तकालय हों, अनुसन्धान की व्यवस्था हो तथा जहाँ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या पर्याप्त रूप में हो। इन सुविधाओं के अभाव में एक विश्वविद्यालय ठीक नहीं चल सकता है। किन्तु यदि

होते हुए भी, भारत की उच्च शिक्षा अनेक देशों की अपेक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है। जहाँ इस देश में १० लाख में २,००० उच्च शिक्षित हैं, वहाँ अमेरिका में २५,०००, सोवियट संघ में २०,००० तथा आस्ट्रेलिया में ८,००० हैं।†

आजकल हमारे देश के लोगों में उच्च शिक्षा पाने की तीव्र आकांक्षा है। कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की छात्र-संख्या इतनी बढ़ रही है कि अनेक विद्यार्थियों को वहाँ प्रविष्ट होना दुष्कर हो रहा है। अतएव नवीन कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पर्याप्त माँग है।

नये विश्वविद्यालय.—मलक्ता आयोग की सिफारिशों के कारण, देश में एकात्मक विश्वविद्यालयों की सृष्टि हुई है। ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा अध्यापकगण निकट सम्पर्क में आते हैं, अध्यापन सन्तोषप्रद होता है, पढ़ाई और परीक्षा का घना सम्बन्ध रहता है, विद्यार्थियों के खेल-कूद का विशेष सम्बन्ध रहता है, इत्यादि। चूँकि सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों का सम्पर्क अनेक कालिजों से रहता है, इसलिए उन्हें अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में इस देश में केवल एकात्मक विश्वविद्यालय ही खोले जावें। यदि ऐसा हो तो हमारे विद्यमान १,३०० कालिजों को यह रूप देना पड़ेगा और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती ही जावेगी।

इस कारण से स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों का सदैव आवश्यकता पड़ेगी। सार्जेंट योजना का मत है, “आर्थिक दृष्टि की ओर से भारत में सदा सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी। उच्च-शिक्षा अभी भी कुछ चुने हुए केन्द्रों में सीमित नहीं रह सकती है।”‡ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना सौराष्ट्र, मियिला तथा तामिल क्षेत्र में अर्थात् त्रिचनापल्ली के आसपास हो सकती है। वर्तमान (पश्चिम बंगाल) में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलनेवाला है।

एकात्मक विश्वविद्यालय बड़े-बड़े शहरों में खोले जा सकते हैं, जैसे : अमृतसर, अजमेर, बंगलौर, मदुरा, कानपुर, मेरठ, इत्यादि। देखा गया है कि अतीत में कई एकात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय कुछ प्रसिद्ध कालिजों का बलिदान हुआ था, जैसे : अलाहाबाद इर्विंग क्रिश्चियन कालिज, तथा लखनऊ क्रिश्चियन कालिज।

† *Times of India*, August 23, 1958.

‡ *Sargent Report*. p. 31.

आगरा, सानासरा (सीराष्ट्र), राजपूरा (पंजाब), कोयम्बटूर, भमरावती तथा गागोंटी । परिपद द्वारा अनुमोदित इन सस्थाओं के लिए चार पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये : (१) ग्राम सेवाओं का तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स — इस डिप्लोमा को विद्वविद्यालय की सर्व प्रथम डिग्री के समान ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है, (२) दो वर्ष का कृषि विज्ञान का सर्टीफिकेट कोर्स, (३) तीन वर्ष का सिविल तथा ग्राम्य इंजीनियरिंग का कोर्स; तथा (४) मैट्रिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष का पूर्व डिप्लोमा कोर्स ।

इन ग्रामीण सस्थाओं के विषय में, कतिपय विचार मन में उठते हैं : (१) क्या देहाती भारत की समस्या इन मुद्रिमेय सस्थाओं से हल हो सकती है, जब कि हमारे देश में प्रायः छः लाख गाँव हैं ? (२) क्या हम इस प्रकार उच्च शिक्षा पर खर्च करना चाहिए जब कि ग्रामों में प्रारम्भिक शिक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं है ? इसके सिवा कभी कभी हमे गहरी साँस भरनी पड़ती है जब हम देखते हैं कि अधिकांश सस्थाएँ गाँवों में नहीं, बल्कि शहरों में खोली गयी हैं । यह भी ज्ञात नहीं कि ये स्थान किस आधार पर चुने गये हैं ।

आशा की गयी थी कि ये सस्थाएँ ऐसे ग्रामीण नेता तैयार करेंगी, जो कि हमारे देश की देहातों के समस्याओं को मुलज्ञाने का प्रयत्न करेंगे । पर देखा जाता है कि इन सस्थाओं के अधिकांश स्नातक गाँव छोड़कर शहर की ओर दौड़ रहे हैं, तथा वहाँ की बेकारी की समस्या को बढ़ा रहे हैं ।

ये सब नयी धुनें सोच विचार कर आरम्भ की जावें । इन नवीन सस्थाओं की ऐसी कुछ विगेण आवश्यकता न थी । इस प्रकार के कोर्स हमारे कृषि-कालिजों में आसानी से थोड़े ही खर्च में खोले जा सकते थे । हमारे देहातों का भविष्य कृषि-कालिजों पर निर्भर है, न कि इन टिमटिमाती हुई दस पाँच ग्रामीण सस्थाओं पर । जब तक हमारे कृषि कालिज तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कन्धे से कन्धा लगाकर काम न करेंगे, तब तक हमारे देहातों की उन्नति नहीं हो सकेगी । इन्हीं कृषि कालिजों को हमें ग्रामीण विश्वविद्यालयों के रूप में धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ेगा ।

सरकार तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा : सन्निधान तथा विश्व-विद्यालय.—भारतीय सन्निधान के अनुसार, विद्वविद्यालयीय शिक्षा एक राज्तीय विषय है, पर उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा सस्थाओं एवं गवेषणा के स्तर को ऊँचा स्थित रखने तथा उनमें एकसूत्रता स्थापित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्वविद्यालयों तथा कतिपय राष्ट्रीय गौरवशाली वैज्ञानिक एवं

विश्वविद्यालय का अर्थ एक परीक्षा-कार्यालय ही हो तब तो मुझे इस विषय पर कुछ कहना ही नहीं है ।

ग्रामीण विश्वविद्यालय.—भारत एक कृषि-प्रधान देश है, और इस देश की ८३ प्रति शत जनता देहात में रहती है । पर इस जनता की शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । सम्पूर्ण देश के शिक्षा-व्यय का प्रायः एक-तिहाई गाँवों पर खर्च होता है । प्रचलित स्कूलों तथा कालिजों के पाठ्यक्रम का ढाँचा शहरी है । जैसा कि अमेरिकन विद्वान् मर्गन ने कहा है, “इन पाठ्यक्रमों से ऐसी धारणा होती है कि सम्भवतः भारत में बिरले ही गाँव हैं ।”†

गाँवों की शिक्षणीय आवश्यकता की ओर सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था । आयोग ने प्रस्ताव किया था :

ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय स्थान में की जावे । इसका सम्बन्ध अनेक छोटे-मोटे सावासिक पूर्व-स्नातक कालिजों से हो, जोकि इसके चारों ओर वृत्ताकार-रूप में स्थित रहें ।‡

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, भारत सरकार ने एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति अक्टूबर, १९५४ में नियुक्त की । इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है । समिति ने कहा कि अभी ग्राम्य विश्वविद्यालय खोलना आवश्यक नहीं है । आरम्भ में कुछ ग्रामीण उच्चतर संस्थाओं की स्थापना हो और क्रमशः ये विश्वविद्यालय के रूप में बढ़ायी जावें । इन संस्थाओं में उत्तर बुनिवादी तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के सफ़न्दीभूत विद्यार्थी भरती किये जावें । इनमें ग्राम्य विषयों से सम्बन्धित तीन-वर्षीय डिप्लोमा, या दो-वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्सों का आयोजन हो । इसके अतिरिक्त उनमें ग्राम्य-शोध, समाज-शिक्षा तथा समाज कल्याण-विस्तार का प्रबन्ध हो ।

समिति के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद्’ स्थापित हो चुकी है । परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए ग्यारह संस्थाएँ चुनी हैं, जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है । ये इन गाँवों या शहरों में स्थित हैं : भीमिफेतन, महदुग, जामियानगर, उदयपुर, मुरेन्द्रनगर, विगडगी (बिहार),

† A. E. Morgan. *Higher Education in Relation to Rural India* Wardha. Hindusthani Talimi Sangh, 1950 p 8

‡ University Commission's Report. p 675.

के समान सम्पूर्ण स्वार्थीन हैं, और न युरोपीय युनिवर्सिटियों की नाई पूर्णतः राज्य-शासित हैं। इनकी स्थिति इन दोनों विपरीत दिशाओं के बीच में है। हमारे विश्व-विद्यालय सरकार पर दो विषयों के लिए निर्भर रहते हैं : (१) इनकी सृष्टि राष्ट्रीय विधान-सभा द्वारा होती है, अतएव इनके सन्निधान तथा अधिकार का निर्णय राज्य सरकार करती है, एव (२) राज्य सरकार इन्हें अनुदान देती है। ग्राण्ट की रकम विधान सभा निर्धारित करती है। इन दोनों प्रतिबन्धों के सिवा, हमारे विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वार्थीन हैं।

विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तता.—वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की विशेष आलोचना हो रही है। कारण, लोगों की धारणा है कि सरकार आजकल विश्वविद्यालय प्रशासन में निरर्थक हस्तक्षेप कर रही है। कुछ उदाहरणों की आलोचना यहाँ की जा रही है। प्रथम दृष्टांत है अग्यई विश्वविद्यालय का। कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय डॉ० जान मथाई इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ नियुक्तियों की याचत उन्हें राज्यपाल तथा राज्य मन्त्रियों के बीच भटकना पड़ा। उन्होंने भारत में प्रचलित इस प्रथा का विरोध किया कि विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्य के राज्यपाल पदेन रहें। ब्रह्मदा जय राज्यपाल पदेन कुलपति होता है, तब वास्तविक शक्ति प्रान्तीय सरकार के हाथ में पहुँच जाती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का वैधानिक शीर्ष है। राज्य की सरकारें स्वभावतः सभी प्रश्नों को राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि से देखती हैं। किन्तु इससे विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है, और यदि उनमें विचारों का स्वातन्त्र्य न रहे तो वे न तो स्वस्थ शिक्षा ही दे सकते हैं और न मार्गप्रदर्शन ही कर सकते हैं। सचिवालय की मनोवृत्ति में सरकारी नीति को अक्षरशः पालन करने की प्रवृत्ति होती है। वह शिक्षा के मुक्त वातावरण से सर्वथा भिन्न होती है। उसके प्रखर ताप से विश्वविद्यालय का सचेत्य पौधा झुलस सा जाता है। नियमों, नज़ीरों, आर्थिक विधानों के शिकजों में वह इतना जकड़ जाता है कि उसकी सारी शक्ति उन्हींको सुलझाने में लग जाती है, और विश्वविद्यालय के वे अधिकारी जिनका कार्य मुक्त चिन्तन, मनन, अध्यव्यवसाय और विप्रार्थियों के निकट संपर्क में आकर उनको प्रेरणा देना और उनका मार्ग दर्शन है, राजनीति और नियमों की भूल भूलैया में फँसकर अपने असली काम की ओर ध्यान

प्राविधिक संस्थाओं का सरोकार केन्द्रीय सरकार से है। इन विषयों के लिए सम्पूर्ण देश में एकरूपता का प्रयोजन है। कारण, इनका सम्बन्ध पूरे देश से है। केवल केन्द्रीय सरकार ही यह समानता सुस्थिर रख सकती है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार.—उच्च शिक्षा-विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यीय सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। पर यह देखा गया है कि अनेक राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर यथेष्ट अर्थ खर्च नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-व्यय ही इतना ऊँचा होता है कि उनके पास अनुरूप अनुदान के लिए भी पर्याप्त अर्थ नहीं रहता। अतएव वे केन्द्रीय उच्च-शिक्षा-योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इस आर्थिक समस्या पर विचार करते हुए, कई शिक्षा-विशों का मत है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकार ले ले।

राधाकृष्णन आयोग इस विचार से सहमत नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे। केन्द्रीय शासन का सबसे बड़ा खतरा रहता है अपरिवर्तनीय एकरूपता। केन्द्रीय सरकार सदा शिक्षा को एक ढाँचे में ढालने की चेष्टा करती है। शिक्षा की प्रगति के लिए यह रवैया अहितकर है। हमें सदा स्थानिक ज़रूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नहीं चाहा कि उच्च शिक्षा शासन हस्तान्तरित होने के कारण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में अनबन हो। इन अड़चनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफ़ारिश की कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाय। आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार वित्त, विशिष्ट विषयों की सुविधाओं का संयोजन, राष्ट्रीय नीति प्रचलन, प्रशासन के मान-दण्ड का निर्धारण, वैज्ञानिक संवैक्षण तथा विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सम्पर्क-स्थापन तक ही सीमित रहे।† आयोग की सिफ़ारिशों के कारण, विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग की सृष्टि हुई है, और इसीके जरिये विश्वविद्यालयों को भारतीय सरकार से ग्राण्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच मनोमालिन्य होने की सम्भावना दूर हुई।

विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार.—केन्द्रीय सरकार के मातहत चार विश्व-विद्यालय हैं : अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती। अन्य विश्वविद्यालयों का सम्पर्क राज्य सरकारों से है। पर हमारे देश के विश्वविद्यालय न ब्रिटिश विश्वविद्यालयों

† *Ibid*, pp. 406-7.

की जीव के लिए एक समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति के प्रतिवेदन पर काफी गरमागरम बहस भी हुई। यह सत्र को विदित ही है। इस नियम की चर्चा करते हुए, सरस्वती के सम्पादक लिखते हैं :

इस प्रकार विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी है। सरकार के मनोनीत लोगों से परिचालित और शिक्षा मन्त्रालय के अधीन रहनेवाली संस्था से स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्रचेता और आत्माभिमानी नागरिक उत्पन्न नहीं हो सकते। ऐसी संस्था 'जी हुजूरों' और टोडियों का ही निर्माण कर सकेगी। †

ये हुए विश्वविद्यालयीय स्वायत्तता सम्बन्धी कुछ ज्वलन्त उदाहरण। अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को विश्वविद्यालयीय स्वायत्तता पर इस्तक्षेप करना उचित है ? प्रायः सभी एकमत हो स्वीकार करते हैं कि विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए स्वशासन नितान्त आवश्यक है, पर सम्पूर्ण स्वायत्तता हितकर नहीं है। श्री चिन्तामन देशमुख ने कहा ही है :

कभी-कभी यथेष्ट स्वायत्तता के कारण विश्वविद्यालयों में कुप्रबन्ध तथा कुशासन देखा गया है। उचित नियन्त्रणाओं के अभाव के कारण, कई विश्वविद्यालयों में आन्तरिक झगडे तथा पड्यन्न खडे हुए। निश्चय ही विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त शासन विभाग नहीं गिने जा सकते; पर इसके साथ ही केंद्रीय तथा राज्य-सरकारों का भी हक है कि वे विश्वविद्यालयों पर निगरानी रखें ताकि उनका स्तर गिरने न पावे और वे सरकारी अनुदान का यथोचित उपयोग करें।

चिन्त : वर्तमान स्थिति.—सन् १९५५-५६ में, विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीन तथा मान्यता प्राप्त कालिजों की कुल आय ३७.८२ करोड़ रुपये थी। इसके विपरीत, यह रकम १९५३-५४ में २८.५३ करोड़ रुपये तथा १९५४-५५ में ३१.८२ करोड़ रुपये थी। सन् १९५५-५६ की आय का स्रोतवार बँटवारा तालिका १९ में दिया गया है :

नहीं दे पाते। डा० जान मथाई ने इस संबंध में अपने बंधु के अनुभवों की चर्चा की और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष-युक्त बात कही, “राज्यपालों के पदेन कुल्यति होने की प्रथा बन्द कर दी जाय। कारण, उनके द्वारा विश्वविद्यालयों पर राजनैतिक प्रभाव पड़ता है।” † इस निष्कर्ष के लिए, भारतीय शिक्षा जगत् स्वर्गीय जान मथाई का आभारी है।

कुछ ही महीने बाद, मद्रास में राज्य-सरकार तथा विश्वविद्यालय के बीच झगड़ा खड़ा हुआ। झगड़ा तीन विषयों पर था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रारम्भ, (२) कालिजों में मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा और (३) सरकार-द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन।

सरकार का कहना था कि तीन-वर्षीय डिग्री-कोर्स का तात्पर्य है इण्टरमीडिएट कोर्स का अन्त, तथा उसके फल-स्वरूप प्रथम वर्ष का माध्यमिक शिक्षा से योग एवं द्वितीय वर्ष का स्नातक कोर्स से सन्निविष्ट होना। विश्वविद्यालय अकेले यह सुधार अमल में नहीं ला सकता है। कारण, उसका माध्यमिक शिक्षा पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय का कथन था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की शुरुआत, सिनेट तथा एक्जामिनिक काउन्सिल में पूर्ण विवेचना के पश्चात् हुई है; (२) कालिजों की शिक्षा का माध्यम शीघ्र बदल जाय; और, (३) सरकार-द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के कारण, शिक्षा में अपरिवर्तनीय एकरूपता की सृष्टि होगी। — वाद-विवाद के फल-स्वरूप विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार तङ्ग आ गये। सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने कहा :

जैसी स्वायत्तता चली आ रही है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ... हरगिज यह स्वायत्तता नहीं है। शिक्षा-मन्त्रालय से उपदेशों का ताँता लगा ही रहता है। एक सचिव के बाद दूसरा सचिव वह निर्देश देता ही रहता है कि यह शुरू करो और वह बन्द करो। ‡

वर्तमान समय की सबसे क्लेशदायक घटना है भारतीय सभ प्रेसीडेण्ट की चौदहवीं जून, १९५८ की विशेष आज्ञा, जिसके द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक्ट का सुधार हुआ। इसके अनुसार, सिनेट को केवल परामर्श देने का अधिकार रह गया, तथा सदस्यों का चुनाव बन्द हो गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की कार्यवाही

† *Times of India*, February 28, 1957.

‡ *Ibid.*, November 20, 1957.

सरकारी अनुदान — यह पहले ही स्पष्ट किया जाय कि विश्वविद्यालय का र्च सरकारी अनुदान, फीस, दान एवं दूसरे स्रोतों से चलता है, पर मान्यता प्राप्त कालिजों को विश्वविद्यालयों से कुछ भी ग्राण्ट नहीं मिलता है। इन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी नीति है। कहीं तो कालिजों को कुल र्च का ५० प्रति शत ग्राण्ट मिल जाता है, और कहीं भति अल्प। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यथेष्ट सरकारी ग्राण्ट के बिना गैरसरकारी कालिज अपना कार्य ठीक ठीक नहीं चला सकते। राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी अनुदान इन मदों के लिए दी जावे (१) इमारत, (२) अखान तथा शिक्षा साधन, (३) पुस्तकालय, (४) छात्रावास, (५) अध्यापकों का वेतन, पेंशन तथा प्रावीडेण्ट फण्ड, (६) ज्ञान वृत्ति एवं परिषद् वृत्ति, (७) अध्ययन अकाश और (८) गवेषणा तथा स्नातकोत्तर कार्य, विशेषतः प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में।†

अधिकतर राज्य-सरकारें खण्ड अनुदान नीति का अनुसरण करती हैं। यह रकम पिछले कई वर्षों की कुछ स्थिर मदों के व्यय का हिसाब लगाकर निर्धारित होती है। इस कारण उनके आय व्ययक में सदा घाटा बना ही रहता है। अनुदान निर्धारण करते समय सदा स्वाभाविक तथा अन्य विचारपूर्ण र्चों का ध्यान रहे। सरकारी अनुदान का पता वर्ष के प्रारम्भ में चल जाना चाहिए। इससे शिक्षा संस्थाओं को अपने आय व्ययक निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है।

केन्द्रीय ग्राण्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्राप्त होता है। इस अनुदान में आवण्टन विगत कई वर्षों में इस प्रकार हुआ है

तालिका २०।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-द्वारा अनुदान-आवण्टन

वर्ष	रकम
१९५४-५५	१,७८,४६,५४६
१९५५-५६	२,६६,१५,३३०
१९५६-५७	३,४१,८९,६३५

† University Education Commission's Report p 449

‡ Ten Years of Freedom, p 13

तालिका १९†

उच्च शिक्षा की आय का स्रोतवार बँटवारा, १९५५-५६
(करोड़ रुपये)

स्रोत	रकम	प्रति शत
आवर्ती		
केन्द्रीय सरकार	३.११	८.२
राज्य सरकार	१०.५३	२७.८
स्थानीय मण्डल	०.०८	०.२
फीस	१३.२५	३५.०
दान	०.५६	१.५
अन्य स्रोत	२.६१	६.९
अनावर्ती		
केन्द्रीय सरकार	२.४८	६.६
राज्य सरकार	२.५२	६.७
अन्य स्रोत	२.६८	७.१
कुल योग...	३७.८२	१००.००

ऊपर के अङ्कों से स्पष्ट होगा : (१) ४७.६ प्रति शत खर्च सरकार ने उठाया, (२) दूसरा उल्लेख योग्य स्रोत फीस है एवं (३) स्थानीय मण्डलों का अंश नहीं के बराबर है। अब यह विचार किया जाय कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न स्रोतवार खर्च का अधिकतम उपयोग किस तरह किया जा सकता है।

†. *Education in India, 1955-56, Vol I, p 191.*

५. राज्य-सरकार ने प्रतिनिधि (यदि कालेज को सरकारी अनुदान मिलता हो), एवं

६. कुछ नामन्नः शिक्षा-शास्त्री (अधि निर्वाचित सदस्य) ।†

अध्यापकों तथा सञ्चालक गण के बीच प्रायः सदा झगड़ा चलता रहता है। इसे निवटाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक गैरसरकारी न्याय सभा की आवश्यकता है, पर इसके फैसले को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बिना सम्पूर्ण कार्यवाही हास्यास्पद हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसी सभा के भूतपूर्व रसायनशास्त्र के अध्यापक श्री० एस्० दत्त के मुकदमे का बयान नीचे दिया जाता है :

सन् १९४९-५१ के बीच, विश्वविद्यालय ने साथ मेरी काफी बनवन हुई। मामला विश्वविद्यालय न्याय सभा को सौंपा गया। सनद्वी जून, सन् १९५३ को सभा ने अपनी राय मेरे पक्ष में दी, पर विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इमने फलस्वरूप सरकारी अदालत में मुकदमा दायर करने के सिवा मेरे पास कोई चारा न रहा।

मुकदमा छ. वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में चला। तथा न्यायालय ने राय दी कि यद्यपि विश्वविद्यालय न्याय सभा को झगड़ा निवटाने का पूर्ण अधिकार है, तो भी न्यायालय उस फैसले को पंच निर्णय-स्वरूप प्रयुक्त करने में असमर्थ है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह अनुभव है तब तो दूसरों का कहना ही क्या है ! कानून में इस प्रकार उद्ध रहने के कारण, निस्सहाय अध्यापकों की यह दुर्दशा होती है। पिछले वर्ष लोफ सभा में शिक्षा मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने ऐसी न्याय सभाओं की उपयोगिता की चर्चा की थी। इस विषय में तर्क वितर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल इन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे इनकी रायों का आदर हो।

स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय

भूमिका

इस प्रकार हमारे देश में उच्च शिक्षा की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का शिक्षण। इससे जुड़ा हुआ है अनुसन्धान, क्योंकि विश्वविद्यालय का लक्ष्य सदा उच्चतम शिक्षा देना है। उनीमरीं शताब्दी में हमारे देश में, सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की सृष्टि

† *University Education Commission's Report*, p 419

उपयुक्त अनुदान इन विषयों के लिए दिये गये : (१) वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा इंजीनियरिंग गवेषणा, (२) पुस्तकें, अस्त्रात्र तथा शिक्षा-साधन, (३) इमारतें, (४) युनिवर्सिटी-अध्यापकों के वेतन की उन्नति, (५) हाँथी कर्मशाला, (६) विश्व-विद्यालयीय अध्यापकों-द्वारा प्रसारण-कार्य, (७) तीन-वर्षीय डिग्री-कोर्स तथा (८) सामान्य शिक्षा का आरम्भ। अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक शिक्षा पर अनुदान, राज्य सरकारों या/और विश्वविद्यालयों को इस शर्त पर दिया जाता है कि वे आवर्तों खर्च का आधा तथा अनावर्तों खर्च का एक-तिहाई स्वतः वहन करेंगे। अन्य मदों के विषय में यह समझौता है कि द्वितीय बोजना-काल के पश्चात् विश्वविद्यालय तथा/या राज्य-सरकार सम्पूर्ण खर्च स्वतः चलायेंगे।

दान, चन्दा इत्यादि.—हमारी उच्च शिक्षा का अति सामान्य खर्च दान, चन्दा आदि से निकलता है। इसके विपरीत अमेरिका तथा युरोप में जनता विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए काफी धन इकट्ठा करती है। हमारे देश में इस ओर लोगों का ध्यान विशेष आकर्षित नहीं हुआ है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों तथा अनेक शिक्षा-संस्थाओं में एक स्वतन्त्र अधिकारी रहता है, जिसका कार्य ही चन्दा एकत्र करना होता है। हमें सदा यह न सोचना चाहिए कि पैसा केवल दान-वीरों से ही मिलता है। छोटे-मोटे चन्दों को जोड़कर भी बृहत् रकम बन सकती है। सन् १९५१ में अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाओं को करीब डेढ़ करोड़ डालर पुराने विद्यार्थियों तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के चन्दे से मिले थे।

स्वसञ्चालित कालिज.—हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है स्वसञ्चालित कालिजों का। तालिका १८ से स्पष्ट होगा कि हमारे देश के दो-तिहाई कालिज स्वसञ्चालित हैं। इनकी कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है उपयुक्त प्रबन्ध समिति। गणकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक निजी कालिज की प्रबन्ध-समिति में १२ से १५ तक सदस्य हों, जिनमें इस प्रकार के सभासद सम्मिलित हों :

१. दान देनेवाले निकायों के प्रतिनिधि,
२. प्रिन्सिपाल एवं अध्यापक-वर्ग के प्रतिनिधि,
३. कालिज के पुराने छात्र-संघ के प्रतिनिधि,
४. विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि,

तालिका २१

विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम, १९५५-५६†

परीक्षा	ठैठनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या	पास संख्या	प्रति शत
इण्टर आर्ट्स ...	२,०७,११८	९०,१८२	४३.५
इण्टर साइन्स	९३,४०५	४१,५५७	४४.५
बी० ए० पास तथा बानर्स.	७९,९२०	३७,९९२	४७.५
बी० ए० सी० ,, ...	३२,६६७	१५,९९७	४९.०
एम० ए० .	१३,२१५	९,३१३	७०.२
एम० एस० सी०	३,१४२	२,४५६	७८.२
व्यावसायिक विषय ..	४८,४५०	३५,७७२	७३.८

इस व्यर्थता की व्याख्या करते हुए राधकृष्णन आयोग ने गौर किया :

इस प्रकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय अर्थ-नाश हो रहा है, पर न इस ओर किसीका ध्यान आकर्षित होता है और न विद्यार्थी तथा उनके माता पिता के समय, श्रम तथा पैसे की बर्बादी की और लक्ष्य जाता है। उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है, तथा उनकी भविष्य की कल्पनाएँ चूर-चूर हो जाती हैं †।

बार-बार कहा जाता है कि अनेक अयोग्य विद्यार्थी कालिजों में भरती कर लिये जाते हैं, एव इसीके फल-स्वरूप वे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में लुटक जाते हैं। सुझाव दिया जाता है कि विश्वविद्यालयों में केवल योग्य विद्यार्थी ही भरती किये जावें। इस विषय की आलोचना करते हुए, विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष

† *Education in India, 1955-56, Vol I p. 197.*

‡ *University Education Commission's Report, p 16*

हुई। इस प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों पर एक नवीन उत्तरदायित्व आ पड़ा — सम्बद्धीकरण का।

स्वाधीनता-अर्जन करने के पश्चात् हमारे विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी और भी बढ़ गयी है। विद्यार्थियों को शिक्षा दान तथा अनुसन्धान के साथ-साथ, इनकी जिम्मेवारी खतम नहीं हो जाती है। इन्हें समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण देश की उन्नति करना है। इस प्रकार एक आधुनिक विश्वविद्यालय के कार्य-कलाप की सीमा उसकी वृहत् अटालिका की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह जाती। इसे समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता की ओर ध्यान रखना पड़ता है, यथा: उच्च शिक्षित और अशिक्षित, पुरुष और स्त्री, धनी और मजदूर, किसान एवं कारीगर। उपयुक्त प्रसारण कार्यक्रम-द्वारा ही इनकी ज्ञान-वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार स्वाधीन भारत में विश्वविद्यालय के चार मुख्य कर्तव्य हैं: (१) शिक्षण, (२) अनुसन्धान, (३) संबद्धीकरण और (४) प्रसारण।

शिक्षण

प्रायः सभी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है अपने-अपने विद्यार्थियों का शिक्षण। शिक्षण के साथ अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं। कुछ मूल प्रश्नों की चर्चा इस प्रकरण में की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश.—कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सन् १९४७ में इनकी छात्र-संख्या अढ़ाई लाख थी। आज (१९५७) यह आठ लाख है। द्वितीय योजना के अन्त तक इस संख्या के दस लाख तक पहुँचने की सम्भावना है। प्रायः प्रत्येक उच्च शिक्षा-संख्या की छात्र-संख्या गत दस वर्षों में दुगुनी हो गयी है। पर इस छात्र-वृद्धि के अनुपात में न उनमें स्थान-विस्तार ही हुआ और न उनके असवात्र या शिक्षा-साधन ही बढ़ाये गये। इतना होते हुए भी विद्यार्थियों को तो कालिजों में भरती होना मुश्किल है। कई एक को तो 'एडमीशन बन्द' की तख्ती ही टाँग देनी पड़नी है। इस सूचना-पत्र को देखकर विद्यार्थियों को बैसा ही मनस्ताप होता है, जैसा कि एक दर्शनाभिलाषी व्यक्ति को सिनेमा-गृह या नाटक-घर में 'हाऊस फुल' का पाटिया देखकर, या, नौकरों के उग्मेठवार को किसी कार्यालय में 'नौकरों खाली नहीं' की सूचना सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है।

इतना होते हुए भी सभी शिक्षायत्त करते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता ही जा रहा है। अगले पन्ने के तालिका में विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम दिया जाता है :

भी चिन्तामन देशमुख ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, "अब वह समय आ गया है जब कि हमें निर्णय करना है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल चुनिन्दे विद्यार्थियों के लिए है; या, उन सबके लिए, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर इसका लाभ उठाना चाहें।" देश की आर्थिक उन्नति की आज विशेष आवश्यकता है। इस कारण हमें चाहिए कि देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल उपयुक्त व्यक्तियों को दी जावे। 'केसशिम्' ने भी अपने छन्वीसवें वार्षिक अधिवेशन के समय इस प्रश्न पर विचार किया। मण्डल ने कहा, "विद्यार्थियों की योग्यता की और ध्यान रखते हुए कालिजों में एडमीशन (प्रवेश) नियन्त्रित किया जाय।" †

पर इसके साथ-साथ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह विश्वविद्यालय प्रवेश नियन्त्रण-नीति देश के लिए हितकर होगी, जब कि हम देखते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की उच्च शिक्षा पिछड़ी हुई है? आज भारत की जन-संख्या तीस करोड़ से अधिक है, पर हमारे विश्वविद्यालयों से केवल ४५ हजार स्नातक प्रति वर्ष निकलते हैं। इसके विपरीत अनेक छोटे छोटे देशों में इससे दुगुने त्रेणुएट सालाना उर्चीर्ण होते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि देश की उन्नति के लिए उच्च शिक्षा विस्तार की यथेष्ट आवश्यकता है। पर जब हम देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करते हैं तब हमें मानना ही पड़ता है कि अभी उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जरूरत है, न कि संख्यात्मक विस्तार की।

पाठ्यक्रम : उपयुक्त पाठ्यक्रम की आवश्यकता.—बहुधा हमारे विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में आर्ट्स, विज्ञान तथा वाणिज्य के इने-गिने विषयों को अपनी इच्छा के विरुद्ध लेना पड़ता है। इसका फल अत्यन्त विपाक होता है। अथवा, वे विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में छूटक जाते हैं या, उन्हें मनचाहा विभाग नहीं मिल पाता है। इस तरह ये विद्यार्थी निकम्मे गिने जाते हैं। कोई तनिक सोचना भी नहीं कि ये विद्यार्थी निकम्मे नहीं पैदा हुए थे, बरन उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में ये निकम्मे कर दिये गये हैं।

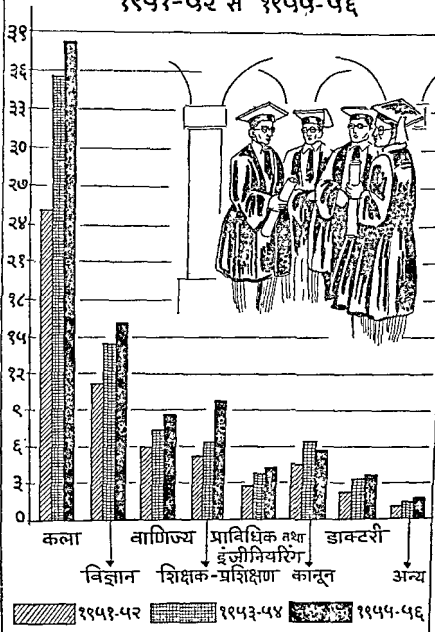
इस टोप को दूर करने का एक मात्र उपाय पाठ्यक्रम में सुधार ही है। माध्यमिक पाठ्यक्रम की नाई विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में विविधता की आवश्यकता है। आर्ट्स

† Ministry of Education Indian University Administration, Delhi, Manager of Publications, 1958 p. 16,

‡ Times of India, January 19, 1959

उत्तीर्ण ग्रेजुएट संख्या (हजार)

१९५१-५२ से १९५५-५६



चित्र १२

विद्यार्थी ठीक तरह समझ नहीं पाते कि निश्चय तथा वैज्ञानिक पद्धति ने किम प्रकार उस विश्व को बदल दिया है, जिस पर वे वास करते हैं ।।

शिक्षा की इस कमी को अनुभव करते हुए, राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव उपस्थित किया था कि इण्टरमीडिएट तथा विश्वविद्यालय के विशेषीकृत शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए कला तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जावे । इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नर एव नारी को वह ज्ञान देना है जो उनको उनके विशेषीकृत अध्ययन के कारण नहीं मिल पाता है । इस प्रकार सामान्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विशेषीकृत शिक्षा के दोषों को दूर करना है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गपूर्ण विकास हो सके । साथही उसे उसने विशिष्ट क्षेत्र में पूरा प्रशिक्षण मिले, और वह एक उपयुक्त नागरिक बन सके ।

गत पच्चीस वर्षों से शिक्षा की इस समस्या पर खूब गहस हो रही है । अमेरिका तथा युरोपीय अनेक देशों में सामान्य शिक्षा का सम्प्राक्षण चल रहा है । साधारणतः इस शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित किसी भी तीन तरीके से होता है :

१. पाठ्यक्रम का कुछ मुख्य भागों में विभाजन.—विद्यार्थी को प्रत्येक भाग से कुछ न कुछ कोर्स लेना पड़ता है ;

२. उन सर्वेक्षण कोंसों का आयोजन, जिन्हें विद्यार्थी अपने विशेषीकृत अध्ययन के कारण नहीं ल पाते, एव

३. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम.—जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा शास्त्र का समावेश रहता है ।

उपर्युक्त तीन पद्धतियों पर, विश्वविद्यालयीय एक समिति ने विचार किया (१९५५) । समिति ने निर्णय किया कि हमारे देश के लिए तीसरी पद्धति अनुमूल होगी । अन्त में सन् १९५६ में एक अध्ययन मण्डली इंग्लैण्ड तथा अमेरिका भेजी गयी । इस मण्डली ने अपना प्रतिवेदन जनवरी, १९५७ में सरकार को दिया । मण्डली ने सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तैयार की हैं । इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी स्नातक पूर्व गैर-व्यावसायिक सहायों के लिए अनिवार्य रखी जानी है । वैकल्पिक योजना में डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा

† K G Sastry Education, Culture and Social Order Bombay, Asia Publishing House, 1952, p 163

(कला), वाणिज्य के अतिरिक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय को गृह-विज्ञान तथा ललित-कला की शिक्षा का अन्दोबस्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक शाखाओं में विविध विषयों के समावेश की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार से अनेक उपकारों की सम्भावना है। प्रथमतः, प्रत्येक कालिज की अपनी-अपनी विशिष्टता रहेगी। वे कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध कर सकेंगे। द्वितीयतः, विविध विषयों के समावेश के कारण, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल विषय चुन सकेगा। वह निकम्मा नहीं ठहराया जायगा। तृतीयतः, कालिज की कक्षाओं की छात्र-संख्या घटेगी क्योंकि कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध होगा। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक विषय में तथा व्यावसायिक कालिजों में चुनिन्दे विद्यार्थी विद्याध्ययन करेंगे।

तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स.—तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की आवश्यकता की चर्चा पहले की जा चुकी है। वड़ोदा, कर्नाटक, केरल, मद्रास, ओस्मानिया तथा सागर विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम का आरम्भ १९५७-५८ या उसके पहले ही किया था। अलीगढ़, आन्ध्र, अन्नामलय, मैसूर, नागपुर, आनन्द तथा व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय इस योजना को १९५८-५९ में एवं पूना, राजस्थान, उत्कल, विक्रम तथा महिला विश्वविद्यालय इसे १९५९-६० में शुरू करनेवाले थे। बचे हुए विश्वविद्यालय इस योजना के विषय में सोच-विचार कर रहे हैं। द्वितीय योजनाकाल में इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए पन्द्रह करोड़ रुपयों का प्रबन्ध किया गया है। यह अर्थ १८० इण्टरमीडिएट कालिजों को डिग्री कालिजों में बढ़ाने के लिए तथा ३६० डिग्री कालिजों के पुनर्गठन के हेतु खर्च किया जायगा।†

सामान्य शिक्षा.—देखा गया है कि कालिजों में चार वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात् भी हजारों स्नातकों की शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास नहीं होता है। उन्हें संसार के अनेक विषयों का ज्ञान नहीं रहता है, जिनकी आवश्यकता एक शिष्ट मनुष्य के लिए है। जैसा कि श्री सेयदैन ने कहा है :

विश्वविद्यालयीय शिक्षा-द्वारा हम संकीर्ण, कल्पना-हीन विशेषज्ञ प्रस्तुत करते हैं। हमारे विज्ञान के स्नातकों को कला तथा कविता, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इसी प्रकार कला के

† Evaluation Committee Report of the Three-Year Degree Course. Delhi, Ministry of Education, 1958, p. 12.

तथा काम काज के घण्टों का यथोचित प्रबन्ध हो। इसके सिवा, अध्यापकों के भरती करने की प्रथा में विशेष सुधार की जरूरत है। अनेक अध्यापक नये रंगरूट होते हैं, तथा उन्हें अध्यापन कार्य का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार कालिज बलात् सफलता पूर्वक चला सकते हैं? अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रत्येक कालिज तथा विश्वविद्यालय में कुछ शोध शिष्य वृत्ति के पद हों, जिनमें कुछ होनहार उत्तर-ब्रेजुएट विद्यार्थी कम-से-कम दो वर्ष के लिए नियुक्त हों। इनमें से कुछ चुने हुए विद्यार्थी भविष्य में अध्यापक नियुक्त किये जावें।

इसके साथ-साथ नये अध्यापकों की शिक्षण पद्धति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य रहना चाहिए। इस ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा विधि रोचक बन जाती है। सम्प्रति विश्वविद्यालय के उपन्युलपतियों के एक सम्मेलन में इस विषय की दिशत रूपेण आलोचना हुई थी, तथा सम्मेलन ने कालिजों के अध्यापकों के लिए एक संक्षिप्त पूर्व अध्यापन प्रशिक्षण कोर्स आवश्यक समझा गया।† इस कोर्स में उच्च शिक्षा अध्यापन की आवश्यकताओं का ध्यान रहना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि कालिज अध्यापकों को एक से अधिक विषय तथा बीस से पच्चीस पीरियड प्रति सप्ताह लेना पड़ता है। इस अतिरिक्त बोझ के दबाव के कारण, वे हॉफने लगते हैं। उनमें नवीन ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती है और वे अपने व्याख्यान के लिए जो मसाला एकबार इकठा कर लेते हैं, उसे ही वषों चलाते हैं या किसी बाजारू नोट से कुछ अंश पढ़कर विद्यार्थियों को सुना देते हैं। जब तक अध्यापकों का अध्यापन भार कम न किया जायगा, तब तक यह परिस्थिति सुधर नहीं सकती है। न किसी आचार्य को एकाधिक विषय ही पढ़ाना पड़े, और न उसे सप्ताह में सोलह से अधिक पीरियड ही लेना पड़े। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सत्या को अध्यापकों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि श्री एस० एन० बोस ने कहा है :

प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेक तरह अध्यापकों को अनुविधाओं का सामना करना पड़ता है — न उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान ही मिलता है, न अनुसन्धान के लिए साधन तथा उपयोगी पुस्तकें, और न अन्य सहकारियों के साथ विचार-विमर्श करने की सुविधा।‡

† देखिए नवौं अध्याय।

‡ Ministry of Education Indian University Administration
op cit. p 97

के लिए सप्ताह में छः पीरियड के अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करना स्वीकार किया है और अधिकांश ने इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ भी कर दिया है।

निर्देश तथा परामर्श.—विविध विषयों तथा सामान्य शिक्षा के समावेश के साथ साथ आवश्यक है छात्रों को निर्देश तथा परामर्श। इनके अभाव में प्रत्येक विद्यार्थी के अनुकूल उपयुक्त विषयों का चुनाव असम्भव होगा। इस कारण प्रत्येक कालिज तथा विश्वविद्यालय में एक निर्देश तथा परामर्श कार्यालय की आवश्यकता है। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य हो, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि की जाँच करना तथा उसकी पिछली शिक्षा एवं भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए संस्था के प्रचलित पाठ्यक्रम से उसके उपयुक्त विषय स्थिर करना, ताकि उनके अध्ययन से उसे अधिकतम सफलता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के उन्नति-विषयक रेकार्ड की भी आवश्यकता है। कार्यालय इन रेकार्डों की छानबीन करे तथा विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श दे।

शिक्षण का मान-दण्ड.—बहुतो का कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक मान-दण्ड विशेष ऊँचा नहीं है, तथा अध्यापन का स्तर धीरे-धीरे नीचे की गिरता ही जा रहा है। यह आक्षेप बहुत कुछ सत्य है। शिक्षा की इस असन्तोषजनक स्थिति के मुख्य कारण ये हैं :—अध्यापकों की नियुक्ति, उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का अभाव, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच निकट सम्पर्क का अभाव।

एक विश्वविद्यालय अध्यापकों का केन्द्र-स्थल है। वे ही उसे बढ़ा सकते हैं या गड़बड़े में टकेल सकते हैं। इस कारण उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए उपयुक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। पर गत-दस वर्षों से कालिजों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि योग्य शिक्षकों का मिलना कठिन हो गया है। किसी-किसी कालिज में तो कोई भी एम० ए० पकड़कर अध्यापक बना दिया जाता है। अनेक होनहार नवयुवक कालिज या विश्वविद्यालय में आचार्य होकर अवश्य प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य रहता है अधिकतर वेतनवाले पदों के लिए प्रस्तुत होना। आजकल अनेक अध्यापक आई० ए० एस० परीक्षाओं में बैठते हैं। यदि वे यहाँ सफलीभूत न हुए तो वे शिक्षा-कार्य छोड़कर अन्य पदों पर चले जाते हैं। कोई-कोई तो न्यूनतम वेतनवाले पदों को स्वीकार करते हैं; कारण, यहाँ अतिरिक्त अर्थोपार्जन की संभावना रहती है।

इस विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि कालिज एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सन्तोषजनक वेतन मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रावीण्येण्ट फण्ट, छुट्टी

अंग्रेजी का स्थान — आजकल उच्च शिक्षा के माध्यम एवं पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान देने या न देने के सम्बन्ध में घोर वाद विवाद चल रहा है। यह सत्य है कि हमारे विद्यार्थी यन् भाषा खूबी के साथ सीखते हैं तथा अनेक विद्यार्थियों ने इस भाषा में पर्याप्त दक्षता दिखलाई है, पर अंग्रेजी घटते घटते अनेक विद्यार्थियों का दम निकल जाता है। इतने पर भी उनका सम्पूर्ण वैयक्तिक विकास नहीं हो पाता है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र की प्रगति निजी भाषाओं द्वारा ही होती है, न कि एक विदेशी भाषा के द्वारा।

राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इस प्रस्ताव पर घोर वाद विवाद हुआ। उच्च शिक्षा का माध्यम कोई अंग्रेजी रखना चाहते हैं, कोई हिन्दी अर्थात् राष्ट्र भाषा, एवं कोई क्षेत्रीय भाषा। अपने मत की पुष्टि के लिए प्रत्येक पक्ष कुछ न कुछ न्यायसंगत युक्ति प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण यह विवाद बढ़ता ही जाता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होना चाहिए। जिस प्रकार एक नवजात शिशु के लिए मातृ दुग्ध हितकर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र तथा व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मातृभाषा द्वारा शिक्षा आवश्यक है। पर इस शिक्षा माध्यम का एक बड़ा पतरा यह है कि हमारे विश्वविद्यालय सर्वांग क्षेत्रीय संस्थाएँ न बन जावें। क्षेत्रीय भाषाएँ हमारे देश के लिए हितकारी नहीं हैं। भारत का उत्तरोत्तर विकास तभी सम्भव है जब कि समूचे देश में एकता कायम रहे। इसी कारण, दूसरा दल राष्ट्र भाषा के माध्यम का समर्थक है।

तीसरा दल अंग्रेजी के पक्ष में है। उनका कथन है कि चूँकि यह भाषा विदेशी है, इस कारण हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी ने इस देश में एकता की सृष्टि की है, हमें इसी भाषा के द्वारा विश्व का सन्देश प्राप्त होता है तथा उसीके द्वारा हम समस्त सभार पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अतएव हमारे द्वारा अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा किया जाना एक अपराध है।

इस समस्या को सुलझाने के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्टूबर, १९५५ में एक समिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष थे श्री हृदयनाथ कुलरू। समिति की जाँच के विषय थे ये - (१) विश्वविद्यालयीय शिक्षा के माध्यम पर विचार करना, तथा (२) अंग्रेजी भाषा के स्तर को ऊँचा रखने के लिए उपाय सुझाना। प्रथम प्रश्न पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात्, समिति ने प्रस्ताव किया है कि पूर्ण

शिक्षा-स्तर के पतन का एक और प्रधान कारण है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच निरुद्ध सयोग का अभाव। दस वर्ष पूर्व, किसी भी कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या ५०-६० से अधिक नहीं रहती थी। इस कारण विद्यार्थीगण तथा शिक्षकवर्ग परस्पर अपरिचित नहीं रहते थे, तथा शिक्षकगण विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर ध्यान रख सकते थे। पर आज तो अनेक कालिजों की छात्र-संख्या दो-तीन हजार से अधिक है तथा प्रत्येक कक्षा में १५०-२०० विद्यार्थी बैठते हैं। इस अत्यधिक छात्र-संख्या का विपरीत परिणाम पड़े बिना नहीं रहता। हाल ही में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी कालिज तथा कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या क्रमशः १,५०० तथा ८० से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त आयोग ने उपरिक्षा-प्रणाली पर विशेष जोर दिया है।

पाठ्य-अवधि की दृढ़ता.—उच्च शिक्षा में व्यर्थता का एक प्रधान कारण है पाठ्य-अवधि की दृढ़ता। हमारे देश की प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा लेने की अवधि निर्धारित रही है, जैसे: बी० ए० या एम० ए० कोर्स दो-दो वर्ष, डाक्टरी कोर्स पाँच वर्ष, इंजीनियरिंग कोर्स चार वर्ष, इत्यादि। यह अवधि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार घटायी या बढ़ायी नहीं जा सकती है। इसके दो प्रमुख दोष हैं। प्रथमतः, इस पद्धति के अनुसार एक कमजोर विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा निर्धारित समय में समाप्त करनी पड़ती है। उसे सभी परीक्षाओं में एक साथ बैठना पड़ता है, एवं वह दो-तीन बार बाह्य परीक्षाओं में हलुकी है और सम्भवतः वह कभी पास भी नहीं होता है। यदि उसे वही पाठ्यक्रम कुछ अधिक समय में समाप्त करने को दिया जाय, तो उसके असफलभूत होने की संभावना कम रहती है। द्वितीयतः, वर्तमान शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर कम देती है। यदि पाठ्यक्रम कुछ निर्धारित समय के बटले अमेरिकी पद्धति के अनुसार पाइण्टों में बाँट दिया जाय, तो विद्यार्थियों की यह कठिनाई दूर होगी। कारण, काम करते हुए भी, वे अपने अवकाश के समय में कालिज में विद्याध्ययन कर सकेंगे। उन्हें एक पूरा काम करनेवाले विद्यार्थी की अपेक्षा समय अवश्य अधिक लगेगा, पर अन्त में उन्हें पूर्ण शिक्षा का लाभ तो मिलेगा। हमारी उच्च शिक्षा में इस सुधार की बहुत ही ज़रूरत है।

† श्रीधरनाथ मुकर्जी: अमेरिका में शिक्षण—यूनाइटेड स्टेट्स इनफार्मेशन सर्विस, १९५४, पृष्ठ २३।

परीक्षा.— भारतीय शिक्षा का एक बड़ा दोष 'उसकी परीक्षा पद्धति' है। इसके विरुद्ध गत पचास वर्षों से आवाज उठायी जा रही है। सन् १९०२ में विश्वविद्यालय आयोग ने गौर किया कि " विश्वविद्यालयीय शिक्षा का ध्येय है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिये तैयार करना। इस कारण, परीक्षा की विशेष छाप अध्यापन तथा अध्ययन पर पड़ती है।" और, सन् १९४९ में राधाकृष्णन आयोग ने परीक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा, " यदि विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर हमें केवल एक ही सुझाव देना हो तो हम कहेंगे कि वह परीक्षा सुधार है।"† पर परीक्षाओं के उन्मूलन का समर्थन न कर कमीशन ने उनमें सुधार वाछनीय जतलाया है। आयोग ने निम्न लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. शिक्षा मन्त्रालय शिक्षण योगता जाँच विषयक विविध परीक्षाओं का सर्वेक्षण करे।

२. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्थायी, पूर्ण कालिक परीक्षा मण्डल संगठित हो। यह मण्डल अध्यापकों की वस्तुगत प्रश्न के निर्माण तथा प्रयोग के संबंध में परामर्श दे।

३. वर्ष में किये गये कक्षा कार्य को भी परीक्षा की सफलता असफलता में सम्मिलित किया जावे। प्रत्येक परीक्षा में जो अङ्क निर्दिष्ट रहें, उन अङ्कों का एक-तृतीयांश इस कार्य के लिए सुरक्षित रखा जावे।

४. कालिक की तीन वर्ष की पढाई में, एक अन्तिम परीक्षा के बदले विभिन्न कालिक परीक्षाएँ ली जावें।

५. परीक्षकों का चुनाव काफी सावधानी से किया जाय। कोई भी ऐसा व्यक्ति उस विषय में परीक्षक न बना दिया जाय, जिसे उसने कम से कम पाँच वर्ष तक न पढाया हो।‡

उपर्युक्त सुझाव अति हितकारी हैं। ब्राह्म परीक्षा-फल निर्णय करते समय आन्तरिक परीक्षाओं, कक्षा तथा उपकक्षा रेकार्ड पर विचार करना अत्यावश्यक है। परीक्षाओं में निबन्ध रूप प्रश्नों के अतिरिक्त, वस्तुगत प्रश्नों का समावेश किया जाय। परीक्षा-सुधार पर सम्प्रति अनेक गोष्ठियाँ हुई हैं। सभी ने परीक्षा सुधार का प्रयोजन एक मत होकर स्वीकार किया है। प्रश्न केवल यही है कि यह सुधार किम प्रकार किया जाय ?

† *Ibid*, p 328

‡ *Ibid*, pp 337 42

तैयारी के पश्चात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी भारतीय भाषा में बदला जावे। इस परिवर्तन के बाद भी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय रहे। इनके अतिरिक्त समिति ने प्रस्ताव किया :

१. जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में अंग्रेजी के प्रति विशेष जोर दिया जाय;

२. चूँकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स अपनाया है, इस कारण पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है; और

३. नवीन अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का अध्ययन आवश्यक है, और यह ज्ञान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को दिया जावे।

इस रिपोर्ट पर राज्य सभा में बहस हुई (२६ फ़रवरी, १९५९)। सरकार ने अनुमोदन किया कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा दी जावे। पर उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह निर्णय हुआ कि यह कार्य कुछ समय तक स्थगित रखा जाय। इस अवधि में अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम रहे, अतएव इस भाषा का स्तर गिरने न पावे।

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द.—जहाँ तक हो सके, प्रत्येक भारतीय भाषा के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत शब्द हों। उच्चतर शिक्षा के लिए यह ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। हमारी भाषाओं में पारिभाषिक शब्द-कोष निर्माण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने इस विषय पर कहा ही है, “अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का उपयोग भारतीय भाषाओं में किया जाय, पर उनके हिज्जे तथा उच्चारण प्रत्येक भाषा के स्वरूप के अनुसार अपनाये जावें।”† यह मानना ही पड़ेगा कि पारिभाषिक शब्द र्खीचातानी कर अनुवादित होते हैं। अनेक अनुवादित शब्दों का ठीक अर्थ ही नहीं निकलता। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान का सम्बन्ध किसी प्रदेश या देश से नहीं है, वरन् सम्पूर्ण विश्व से है। इस कारण, अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हितकर तथा आवश्यक है।

† *University Education Commission's Report.* p. 326.

इन कमियों के दूर हुए बिना अनुसन्धान की उन्नति नहीं हो सकती है। सम्प्रति सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। अब सरकार गवेषणा की वृद्धि के लिए पर्याप्त चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ५२७ छात्रों को सरकारी शोध वृत्ति मिली।[†] विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने तो अनुसन्धान में एक नया जीवन ही डाल दिया है। विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं की उन्नति के लिए पर्याप्त द्रव्य मिलने लगा है, अध्यापकों को गवेषणा के निमित्त आर्थिक सहायता दी जा रही है तथा अनुसन्धान फ़ैलो नियुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयीय शिक्षा में गवेषणा को एक प्रमुख स्थान मिला रहा है। पर यह शोध केवल नैतिक न हो। भारत की उन्नति के लिए व्यावहारिक अनुसन्धान की विशेष आवश्यकता है।

उपयुक्त अनुसन्धान तभी सम्भव है, जब अध्यापक-बग इस कार्य में दिलचस्पी लें तथा उन्हें यथोचित अवकाश मिले। इस कारण प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे प्राध्यापक हों, जो अपना अधिकांश समय शोध के निमित्त वितावें, तथा उनके नीचे कतिपय रिमर्च-मैन्स काम करें। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक आदर्श कथन है: “या तो गवेषणात्मक लेख प्रकाशित करो, या विनष्ट हो जाओ, या तो विद्वत्ता एवं ज्ञान अर्जित करने ऊपर उठो, या विश्वविद्यालय से निरल जाओ।” इस प्रकार अध्यापन क्षेत्र में उन्हीं लोगों की जरूरत है, जो वास्तव में विद्या प्रेमी हैं, और जो ज्ञान की शलिप्रेक्षा पर मूल सुविधाओं को चढ़ा सकते हैं।

सम्बद्धीकरण

हमारे देश ने आर्थिक से अधिक विश्वविद्यालय संबद्धीय हैं। इनके कार्य-कलाप की चर्चा हम कर चुके हैं। इस पद्धति के अनुसार सभद्र कालिजा के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें तथा परीक्षाएँ एक सी होती हैं। इसने परिणाम-स्वरूप सख्याएँ अपनी स्वाधीनता को खेँठी हैं, तथा उनकी स्थानिक आवश्यकताओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

शिक्षा में एक माप-दण्ड कायम रखने के लिए, उपर्युक्त पद्धति प्रचलित की गयी थी; पर प्रत्येक कालिज की निजी समस्याएँ तथा स्थानिक आवश्यकताएँ रहती हैं। इस कारण उनके पाठ्यक्रम में कुछ हेर फेर प्रयोजनीय होता है। संबद्धीय विश्वविद्यालयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कालिज अपनी निजी समस्याओं को अपने निर्वाचित सिनेट के सदस्य के द्वारा विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करे। विश्वविद्यालय की स्थानिक निर्धारण समिति इन पर विचार करे तथा विचार-संगत विषयों का

[†] *Education in India, 1955-56* Vol 1 p. 197

विद्यार्थियों की आर्थिक समस्या.—उच्च शिक्षा दिनों-दिन अधिकतर खर्चीली होती जा रही है। इस कारण अनेक निर्धन, किन्तु योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। सम्प्रति कालिजों में ५ से १५ प्रति शत विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा अवश्य मिलती है, तथा सरकार ने अनेक छात्र वृत्तियों का प्रबन्ध भी किया है। सन् १९५६-५७ में छात्रवृत्ति पर कुल सरकारी व्यय प्रायः तीन करोड़ रुपये था।

पर यह व्यय यथेष्ट नहीं है। इंग्लैण्ड में ७२.८ प्रति शत विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति या मुफ्त शिक्षा मिलती है। अनेक पाश्चात्य देशों में सरकारी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थानिक विद्यार्थियों की फीस बहुत ही कम रहती है। पर अर्थाभाव के कारण यह योजना हमारे देश में अभी स्वप्नातीत है। अमेरिका में उच्च शिक्षा के विस्तार का एक प्रधान कारण यह है कि उस देश के अधिकांश विद्यार्थी कमाई भी किया करते हैं और पढ़ते भी हैं। साथ ही कालिज का 'नियुक्त-कार्यालय' विद्यार्थियों को नौकरा दिलाने में उनकी पूर्ण सहायता करता है। हमारे देश में भी ऐसी ही शिक्षा-व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है।

अनुसन्धान

राधाकृष्णन-आयोग ने कहा है कि 'अनुसन्धान के बिना अध्ययन मृत हो जायगा' — यह अतीव सत्य है। पर हमारे विश्वविद्यालयों ने अनुसन्धान की ओर हाल ही में ध्यान दिया है। यह अनुसन्धान पर्याप्त रूप में नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं :

१. अर्थाभाव।

२. अध्यापकों पर अधिक दायित्व-भार, जिसे उनका अधिकांश समय क्लास लेक्चरों में व्यतीत हो जाता है। इसीसे अनुसन्धान-कार्य के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता है।

३. उपयुक्त पुस्तकालय, अजायबघर तथा प्रयोग शालाओं का अभाव।

४. शोध शिष्य-वृत्ति की अपर्याप्तता।

५. पी० एच० डी० के प्रशिक्षण में अनुसन्धान-रीतियों की अनुपस्थिति।

६. विश्वविद्यालयों का अन्य निम्नो के साथ सहकारिता का अभाव, जैसे : सरकार, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इत्यादि।

गाँवों में काम करना पड़ता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसके अनुसार प्रत्येक स्नातक के लिए राष्ट्र-सेवा अनिवार्य होगी। शिक्षा मन्त्रालय इस योजना को तृतीय पंच वर्षीय योजना में आरम्भ होते ही चलाना सोच रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के अनुकूल छ. महीने से दो वर्ष उन क्षेत्रों की उन्नति में भाग लेना पड़ेगा, जो पिछड़े हुए हैं। आशा की जाती है कि प्रथम वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में ९०,००० विद्यार्थी इस कार्य में जुट जावग। इसीके आधार पर अन्दाज लगाया जाता है कि योजना का वार्षिक खर्च पाँच करोड़ रुपया पड़ेगा।†

उपसंहार

ये हमारे विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ हुईं। इसने लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राजकीय कामकाज के लिए कर्मचारी जुटाना था। इनका ध्येय अध्यापन या अनुसन्धान एकात्म नहीं था। ये तो छोटे मोटे दफ्तर थे, जिनका उद्देश्य था परीक्षा चलाना और प्रमाण पत्र वितरण करना। ये विश्वविद्यालय न हमारे देश के तक्षशिला या नालन्द से मिलते जुलते थे और न आक्सफोर्ड या पेरिस से। फिर हम उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य के लिए कैसे ठोपी टहरा सकते हैं ?

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे विश्वविद्यालयों को नवीन जीवन प्रदान किया है, और उनके सामने नया उद्देश्य रखा है। यथार्थ में हमारी विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल चालीस वर्ष पुरानी है। इस अरसे में हमारे विश्वविद्यालयों ने जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। इन्होंने सम्पूर्ण देश में एकता की सृष्टि की, और यहाँ से निम्ले हुए स्नातकों ने अग्नेय सरकार के विरुद्ध मोर्चा लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय कभी सत्य से न डिगें, तथा सदा उच्च आदर्श सामने रखें। जैसा कि राधाकृष्णन आयोग ने कहा है।

उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य ज्ञान के संचरण, नवीन ज्ञान के अन्वेषण, जीवन के प्रयोजन की निरन्तर खोज, तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा के आयोजन हैं। आदर्श बहुधा म्वन्न होते हैं, किन्तु इनकी ओर निरन्तर प्रयत्न करना प्रत्येक नागरिक तथा राजनीतिज्ञ का कर्तव्य है।‡

† *Times of India*, July 25 1959

‡ *University Education Commission's Report* p 66

अनुमोदन करे। समिति के निर्णय के अनुसार, कालिज को अपने कार्य-कलाप में कुछ हेर-फेर करने की स्वाधीनता मिले। इस प्रकार संयुद्धीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है। इन्हें सदा लकीर के फकीर रहकर काम न करना चाहिए।

प्रसारण

भूमिका.—हमारे कालिज तथा विश्वविद्यालय सामान्य जनता के सम्पर्क में बहुत ही कम आते हैं। यह नीति ठीक नहीं है। चूँकि जनता के अर्थ से ये सस्थाएँ स्थापित होती हैं, अतएव इन्हें जनता की आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में कालिज तथा विश्वविद्यालय दो प्रकार के काम कर सकते हैं : (१) प्रौढ़ शिक्षा तथा (२) समाज-सेवा।

प्रौढ़ शिक्षा.—प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम तीन प्रकार के हैं : (१) सातत्य शिक्षा — यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है, जो कालिज के साधारण विद्यार्थियों के साथ कुछ विषय पढ़ना चाहते हों। नवीन विद्या पाने की आकांक्षा के कारण, अनेक प्रौढ़ इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। (२) पुनर्संजीवन कोर्स — अनेक व्यक्तियों की छात्र-जीवन में अर्जित विद्या में जंग लग जाता है, पर वे आधुनिकतम विद्या का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे वयस्क व्यक्तियों के लिए संक्षिप्त कोर्स लाभदायक होते हैं। (३) नेतृत्व कार्यक्रम — इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, हमारे गाँवों तथा शहरों के अगुओं को संसार के विविध क्षेत्रों की प्रगति से परिचय कराना।

समाज-सेवा.—वर्तमान समय में हमारे विश्वविद्यालय जनता में ज्ञान-प्रसारण के लिए कुछ वक्तुताओं का आयोजन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक मनोरञ्जन तथा वक्तुता कार्य-पीठ की आवश्यकता है। ऐसी सस्थाएँ प्रायः प्रत्येक अमरीकी सरकारी विश्वविद्यालय में रहती हैं। नीचे अमेरिका के वायोमिंग विश्वविद्यालय कार्य-पीठ के कार्यकलाप का वर्णन दिया जाता है :

कार्य-पीठ अपने राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रखती है। उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी माँगों को पूरा करने के लिए, वह अपने कालिजों तथा विभिन्न शिक्षा-विभागों से उपयुक्त वक्तुता भेजती रहती है। साथ ही मनोरञ्जक कार्यक्रम, नाट्याभिनय, प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी करती है।†

समाज-सेवा की ओर हमारे कुछ विश्वविद्यालयों का ध्यान अभी-अभी गया है। उदाहरण-स्वरूप डाक्टरों की डिग्री मिलने के पहले अनेक विद्यार्थियों को कुछ समय तक

† *University of Wyoming, Bulletin, 1953-54 Vol. XLX, No. 1,*
p. 405.

के लिए हैं। स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो अन्धकार में डूबी हुई हैं।”†

इस प्रकार कम्पनी के राजत्व काल में लड़कियों के लिए एक भी सरकारी स्कूल न था। इनी गिनी कुछ गालिकाएँ लड़कों के स्कूलों में शिक्षा पाती थीं। इस काल में प्रतिपय निजी तथा मिशनरी गालिका विद्यालय अवश्य खोले गये थे। उदाहरण-स्वरूप सन् १८५१ में, प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी सत्र ८६ सावास स्कूल तथा २८५ साधारण स्कूल चल रहे थे। इनकी छात्र सख्या क्रमशः २,२७४ और ८,९१९ थी। रोमन कैथलिक सघों ने भी कुछ स्कूल खोले थे, पर इनकी सख्या का कुछ ठीक पता नहीं है। कई उदार सज्जनों तथा सरकारी अफसरों ने भी कुछ कन्या शालाएँ खोलीं। इनमें मुख्य है वेथून स्कूल, जिसकी स्थापना ट्रिंकवाटर वेथून साहब ने सन् १८४९ में की थी। ये भारत सरकार के कानून विषयक तत्कालीन सदस्य थे। अपने जीवन की सारी कमाई इन्होंने इस स्कूल में लगा दी थी। इस सस्था ने लोगों में कन्या शिक्षा के प्रति एक नवीन प्रेरणा दी, और उसीके आदर्श पर गालिका विद्यालय खुलने लगे।

सन् १८५७ से सन् १९०२ तक.—सन् १८८२ के शिक्षा-आयोग ने कहा • “स्त्री शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसे विस्तार करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं।” कमीशन ने प्रस्ताव किया कि सरकार स्त्री शिक्षा पर अधिकतर अर्थ व्यय करे। इस कारण सरकार ने स्वतः कई गालिका विद्यालय खोले, तथा निजी स्कूलों को अनुदान देना स्वीकार किया। अतएव स्त्री-शिक्षा की यथेष्ट प्रगति हुई। सन् १९०१—१९०२ में गालिका सस्थाओं की सख्या इस प्रकार थी : १२ कालिज, ४६७ माध्यमिक स्कूल तथा ५,६२८ प्राथमिक स्कूल। इनमें ४,४७,४७० लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं।

सन् १९१२ से सन् १९१७ तक.—शनैः शनैः स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता दूर होने लगी, तथा जनता स्त्री शिक्षा में रुचि लेने लगी। इसके कई कारण थे। अनेक माता पिता अनुभव करने लग कि उनकी लड़कियों की शिक्षा उतनी ही आवश्यक है, जितनी उनके लड़कों की, एव लोगों में शिक्षिता स्त्री की चाह बड़ी। शिक्षा विभाग भी स्त्री शिक्षा विस्तार के लिए प्रयत्न करने लगा : स्वतन्त्र तथा सरकारी गालिका विद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों में गालिकाओं के आवागमन के लिए यान का प्रबन्ध, इन्स्पेक्ट्रसों तथा शिक्षिकाओं की नियुक्ति, लड़कियों के लिए वृत्ति तथा कम

† A N Basu, ed, *Adam's Reports*, Calcutta University, 1941, p 452

सातवाँ अध्याय

स्त्री-शिक्षा

प्रस्तावना

यर्तमान युग की सबसे उल्लेखयोग्य घटना है, नारी-प्रगति। यदि एक शताब्दी पूर्व का कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर भारत में लौट आवे, तो वह हमारे देश के महिला-जीवन में आमूल परिवर्तन देखकर निश्चय ही दङ्ग रह जायगा। यहाँ पर एक शताब्दी पूर्व अनेक व्यक्ति स्त्री-शिक्षा के घोर विरोधी थे, पर आज सभी स्वीकार करते हैं कि इस शिक्षा के विस्तार के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। स्त्री-शिक्षा को अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा : पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-शिक्षा के प्रति माता-पिताओं की उदासीनता, पाश्चात्य शिक्षा पर अविश्वास, मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्या, लड़कियों के उपयुक्त पाठ्यक्रम का अभाव, शिक्षिकाओं की अपर्याप्तता, इत्यादि। धीरे-धीरे ये कठिनाइयाँ हल होती जा रही हैं। आज देश में कन्या-शिक्षा की चाह बढ़ रही है। राष्ट्रीय संगठन में स्त्रियों का विशेष स्थान है।

स्त्री-शिक्षा का विस्तार

भूमिका.—सब कुछ होते हुए भी, आज केवल १२ प्रति शत भारतीय स्त्रियाँ शिक्षिता गिनी जाती हैं। गत सौ वर्ष में स्त्री-शिक्षा बहुत ही धीरे-धीरे फैली। सरकार तथा जनता की उदासीनता के कारण, इसका विस्तार आशानुरूप न हुआ। इसका पता निम्न-लिखित विवरण से मिलेगा।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में.—स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता के प्रति, कम्पनी का ध्यान कमी नहीं गया। शायद उसे नारी क्लर्क एवं अफसरों की आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा के विषय में लोगों में एक भ्रम-मूलक धारणा थी, जो कि परम्परा से चली आ रही थी। स्त्री शिक्षा के विषय में, एडम्स साहब अपनी रिपोर्ट (१८३८) में लिखते हैं, “देश के सभी विद्यालय पुरुषों

यह अग्रधि भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी इसमें दो विश्व युद्ध हुए, सामाजिक क्रान्ति आयी, आर्थिक स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ, समूचे देश में राष्ट्रीय जागृति हुई तथा अन्त में १५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ। इसी समय अमेरिका तथा अनेक युरोपीय देशों में नारी-स्वाधीनता का आन्दोलन पूरे दम पर चला। इसी आँच भारत में भी पहुँची। हमारे देश की ललनाएँ भी सगाठ होने लगी। सन् १९१७ में डा० एनी बेसेण्ट तथा श्रीमती मार्गेट कस्सिस ने प्रयत्नों के कारण अखिल भारत महिला सघ का सूत्रपात हुआ। इसके आठ वर्ष पश्चात्, स्त्री जातीय परिषद स्थापित हुई। वर्तमान काल में, भारत में इस परिषद की चौदह राज्यीय शाखाएँ हैं, तथा परिषद विश्व स्त्री परिषद से सम्बन्धित है। सन् १९२७ में सर्व प्रथम अखिल भारत स्त्री परिषद से सम्मेलन का आदि अधिवेशन हुआ। तबसे यह सम्मेलन वार्षिक हुआ करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही नारी प्रगति है। इसका साथ ही सामाजिक दोषों का उन्मूलन तथा स्त्री शिक्षा का विस्तार इस सम्मेलन के लक्ष्य हैं।

इसी समय गान्धीजी का नेतृत्व अस्तित्व में आया। उन्होंने भारतीय नारी जीवन में एक नवीन प्राण का सञ्चार किया। स्वातन्त्र्य युद्ध के लिए उन्होंने भारतीय ललनाओं को आह्वान किया। राष्ट्रीय भावनाओं से उनका हृदय परिपूर्ण हुआ। वे परदे से निरल कर स्वाधीनता-संग्राम में कूद पड़ीं, और पुरुषों की नाईं उन्होंने सभी यातनाओं को सहन किया। उन पर लाठियों चलायी गयीं, उन्हें कैद भुगतना पड़ा, उन्होंने अपने स्वामियों तथा सन्तानों का रक्तपात देखा, पर वे न डिगीं। इस प्रकार नवीन जागृति हुई। समाज सुधार तथा स्त्री-शिक्षा विस्तार की आकाशाएँ बढ़ीं। क्या पुरुष, क्या स्त्री सभी यह अनुभव करने लग कि बालिका शिक्षा के द्वारा ही माता तथा कुटुम्ब की शिक्षा हो सकती है। शिक्षिता बालिकाएँ ही सुगृहिणी बन सकती हैं, तथा समाज का अधिकांश सुधार भी उन्हीं पर निर्भर है।

वर्तमान स्थिति

भूमिका — स्वातन्त्र्योत्तर काल में स्त्री शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। सन् १९४७-४८ में सम्पूर्ण देश में कुल १६,९५१ बालिका विद्यालय थे, तथा इनकी छात्रसंख्या ३५,५०,५०३ थी। सन् १९५६-५७ में विद्यालयों की संख्या २६,४२५ पहुँची, तथा इनकी छात्र-संख्या ९९,९७३३९ हुई। छात्र संख्या की सबसे अधिक

† *Seven Years of Freedom* p 25

‡ *Education in the States, 1956-57* pp 3-4

फीस की व्यवस्था, कन्याशालाओं के लिए उदार सरकारी अनुदान-नीति, प्रान्तीय महिला-शिक्षा-समितियों की नियुक्ति, इत्यादि।

उपर्युक्त चेष्टाओं के कारण, स्त्री-शिक्षा फैलने लगी। सन् १९०४ में, श्रीमती एनी बीसेण्ट ने बनारस में 'सेण्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय' की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं में हिन्दू-धर्म के आधार पर पाश्चात्य विद्या का प्रसार। सन् १९१६ में लेडी हाडिग्न मेडिकल कालेज, दिल्ली स्थापित हुआ। इस देश में चिकित्सा-शास्त्र का यही सर्व प्रथम नारी महाविद्यालय है। इसी वर्ष महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गया। सन् १९१७ में बालिकाओं के लिए १२ आर्ट्स कालिज, चार व्यावसायिक कालिज, ६८९ माध्यमिक स्कूल तथा १८,१२२ प्राथमिक स्कूल थे। इन समस्त शालाओं में इसी वर्ष १२,३०,४१९ लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं।

सन् १९१७ से १९४७.—इस अवधि में स्त्री-शिक्षा का सन्तोषप्रद विस्तार हुआ, लोगों के अनेक ग़लत ख्याल दूर हुए तथा स्त्री-शिक्षा की चाह बढ़ी। इसका पता निम्न-लिखित तालिका से मिलेगा :

तालिका २२

स्कूल तथा कालिजों में लड़कियों की संख्या,

१९२१-२२ से १९४६-४७†

संख्या	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४१-४२	१९४६-४७
प्राथमिक स्कूल ..	१०,५७,१३१	१९,४४,०७०	३१,२३,६४३	२७,१५,२३०
माध्यमिक स्कूल ...	१,२४,९५४	१,९६,१७०	४,१०,१३३	४,४२,५०३
आर्ट्स तथा साइंस कालिज	१,२०७	२,६८५	११,७७८	१६,२८४
व्यावसायिक कालिज ...	२६६	५२१	१,७२५	२,४६८
व्यावसायिक स्कूल ...	१९,५७०	१७,५६८	४०,८६९	३८,३७५

[†नोट : सन् १९२१-२२ से १९४१-४२ तक के अंक तथा १९४६-४७ के अंक ब्रिटिश भारत उत्तर-विभाजित भारत से सम्बन्धित हैं।]

वृद्धि कालिज स्तर में व्यावसायिक और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुई। इसने बाएँ विश्व विद्यालय और कालिज की सामान्य शिक्षा का स्तर आता है। इसने सिवा, माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की संख्या दुगुनी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह दृढ़ गुनी हुई।†

प्रशासन — कहा जाता है कि उपयुक्त प्रशासन के अभाव के कारण, स्त्री शिक्षा का प्रगति ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य में अथ डिप्टी डायरेक्टर आफ एजुकेशन अर्थात् शिक्षा उप सचालिका का पद नहीं है, एक सम्पूर्ण देश में निराश्रितियों की संख्या ६९ है।‡ अतएव स्त्री शिक्षा का प्रशासन अधिकतर पुरुषों के हाथ में है। इन्हें बालिकाओं की विशेष जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए।

स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए मई, १९५८ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नारा शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकार में एक प्रशासन मण्डल की आवश्यकता है जो कि स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देखभाल करे। समिति के सुझाव के कारण, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के मातहत राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना सन् १९५९ में हुई। परिषद में एक अध्यक्ष, चौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दो सदस्य तथा योजना आयोग, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का एक-एक प्रतिनिधि और शिक्षा मन्त्रालय के दो प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी व्यक्तियों का कार्य काल दो वर्ष रहेगा।*

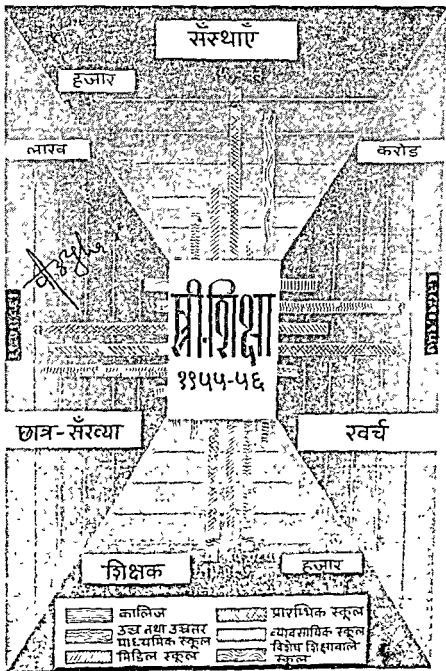
परिषद की पहली बैठक १६ अक्टूबर, १९५९ में भरी। इसमें यह स्थिर हुआ कि स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों की देखरेख के लिए केन्द्रीय सरकार में एक सयुक्त शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षा मन्त्रालय में स्त्री शिक्षा का एक अलग युनिट बना देना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सलाहकार परिषदों के अतिरिक्त एक सयुक्त निर्देशक भी नियुक्त किया जाय, जो स्त्रियों तथा लड़कियों की शिक्षा के काम की देखरेख करे।§

† शिक्षा मन्त्रालय भारत में शिक्षा-लेख चित्रों में। डि.डी. मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन १९५७, पृष्ठ २०।

‡ *Education in India 1955-56 Vol I p 123*

* भारतीय समाचार, १ अगस्त १९५९, पृष्ठ ४०७।

§ तद्वै, १६ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ६५९।



तालिका २३

शालिका माध्यमिक शिक्षा में प्रगति

वर्ष	स्कूल	छात्रा संख्या	बालक विद्यालयों में पढ़नेवाली बालिकाओं का कुल प्रति शत	शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या
१९५१-५२	२,८६३	९,०८,७७५	२९.६	३६,२९५
१९५२-५३	३,००७	९,८७,६४५	२९.७	४५,५०८
१९५३-५४	३,२६८	१०,९२,६२१	३०.७	५८,८८८
१९५४-५५	३,४०२	११,९७,७००	३२.७	६५,४८१
१९५५-५६	३,९२०	१३,४०,०७१	४०.२	७२,३२८

संख्या-वृद्धि के साथ ही, स्त्री शिक्षा में गुणात्मक उन्नति भी हुई है। लड़कियाँ अब स्कूलों में पहले की अपेक्षा अधिक ठहरने लगी हैं। शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी है। तथापि अभी भी स्थिति सतोपदायक नहीं कही जा सकती है। आज देश में १४-१७ वयोवर्ग की लड़कियों की संख्या १२० लाख है। इस संख्या के ३ प्रति शत को शिक्षा मिल रही है। वर्तमान पाठ्यक्रम भी दूषित है। इसमें लड़कियों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियाँ भी प्रायः उन्हीं विषयों का अध्ययन करती हैं, जिन्हें बालक पढ़ते हैं।

उच्च शिक्षा.—उच्च शिक्षा की माँग भी स्त्रियों में बढ़ रही है। सन् १९५६-५७ में लड़कियों के लिए ११५ कला तथा विज्ञान के कालिज, ३४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले कालिज तथा १६ विशेष शिक्षावाले कालिज थे। इस वर्ष ८५,८१७ बालिकाएँ उच्च शिक्षा पा रही थीं। विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या तालिका चौबीस में देखिए।

उपयुक्त अधिकारियों के अनिश्चित, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा उप-मन्त्रालय तथा प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक की आवश्यकता है। स्थानीय मण्डलों को चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए कुछ परियोजनाएँ नियुक्त करें। मार अर्थ यह है कि स्त्री-शिक्षा की प्रगति के लिए उपयुक्त सहाय, प्रबन्ध तथा निराश्रय की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा.—भारतीय ग्रियों की मातृवर्तीन शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी एक लम्बा मार्ग तय करना है। आज लगभग एक-तिहाई लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। सन् १९५०-५१ में ६-११ वयोवर्ग के पढ़नेवाले बालक तथा बालिकाओं की मज्जा प्रमाणाः ५९ तथा २५ प्रति शत थी। १९५५-५६ में यह संख्या ६९ लड़कों के लिए तथा ३३ लड़कियों के लिए हो गयी। द्वितीय आयोजन के अंत तक संभवतः ८६ प्रति शत बालक तथा ४० प्रति शत बालिकाएँ शिक्षा पाने लगेंगी। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में ११-१४ वयोवर्ग के छात्रों तथा छात्राओं की संख्या २२ तथा ५ प्रति शत से बढ़कर प्रमाणाः ३० और ८ हुई, एवं दूसरी आयोजना में ३६ और १० प्रति शत लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सांगंश यह है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसके सिवाय लड़कियाँ स्कूलों में ज्यादा दिन नहीं ठहरतीं। स्कूलों की पहली कक्षा में भरती किये हुए प्रति १०० बच्चों में से प्रायः ४३ चौथी कक्षा में पढ़ना छोड़ देते हैं, पर १०० में से केवल ३० लड़कियाँ चौथी कक्षा में पहुँचती हैं। इस प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, प्राथमिक अवस्था में व्यर्धता अधिकतर है। लड़कियों में अनिवार्य शिक्षा भी अधिक नहीं फैली। सन १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी : २८४ शहर (केवल लड़कों के लिए) तथा ७९९ शहर (बालक-बालिकाओं के लिए), एवं ८,९५९ गांव (केवल लड़कों के लिए) तथा ३०,३१७ (बालक-बालिकाओं के लिए)।†

माध्यमिक शिक्षा.—लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई है। अनेक बालिका-विद्यालय खुले, छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई, बालकों के स्कूलों में पढ़नेवाली बालिकाओं की तादाद बढ़ी तथा शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाली बालिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। बालिका तैईस से इस प्रगति का स्पष्टीकरण होता है :

† *Education in India, 1955-56, Vol. II, p. 90*

प्रशिक्षण केन्द्र' का आविर्भाव हुआ है। आज भारत में ऐसे ४३ केन्द्र हैं। इनमें मैट्रिक पास छात्राएँ प्रविष्ट होती हैं। पाठ्यक्रम डेढ़ वर्ष का होता है। प्रथम वर्ष में कृषि तथा गृह-विज्ञान सिखलाया जाता है, और अन्तिम वर्षार्द्ध में प्रसारण पद्धति का साधारण ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षित ग्राम-सेविकाएँ सामुदायिक विकास खण्डों में सेवार्थ नियुक्त होती हैं।

प्रौढ शिक्षा—सन् १९४७-५७ में स्त्री-प्रौढ शिक्षा की सबसे अधिक उल्लेख्य उन्नति हुई है। सन १९५७ में एकत्र १,४५,१३९ महिलाएँ ४,७१६ शिक्षा-केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। एक सरकारी रिपोर्ट का कथन इस प्रकार है :

देखा गया है कि क्या शहर और क्या गाँव—सर्वत्र—विवाहिता स्त्रियों में समाज शिक्षा पाने की उत्कट आकांक्षा है। जहाँ कहीं उन्हें ऐसी शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ, उसका लाभ उन्होंने पूरा लिया। †

सह-शिक्षा—बालिका विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, हमारे देश में सह शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। सन् १९५५-५६ में विभिन्न शिक्षा स्तरों में सह शिक्षा पानेवाली छात्राओं की संख्या का कुल छात्राओं की संख्या का इस प्रकार प्रति शत था : प्राथमिक—७९.२, माध्यमिक—४०.२, कला तथा विज्ञान कालिज—५३.१, एवं व्यावसायिक तथा विशेष शिक्षावाले कालिज—६४.३। प्राथमिक तथा कालिज स्तरों में, सह शिक्षा का विशेष विरोध नहीं है। कारण प्राथमिक शालाओं में बालिकाएँ निरी बच्चियाँ रहती हैं, तथा कालिजों में पहुँची हुई लड़कियाँ अपने आपको बहुत कुछ नियन्त्रित रखना सीख जाती हैं। पर माध्यमिक स्तर में सह शिक्षा वाञ्छनीय नहीं है। किशोर अवस्था के कारण बहुधा बालक-बालिकाएँ इस स्तर में अनेक नैतिक त्रुटियाँ कर बैठती हैं। पर जब तक लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूल एवं कालिज पर्याप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सह-शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए।

आलोचना

एक नवीन दृष्टि-कोण.—यह पहले ही श्रुतलाया जा चुका है कि भारतीय नारी-प्रगति राष्ट्रीय जाग्रति के फल-स्वरूप हुई है। देशोद्धार का बीड़ा लेकर भारत के अनेक सुपुत्र तथा सुपुत्रियाँ एक रङ्ग में रँग गयीं। उन्होंने इस देश की रमणियों के समक्ष एक नवीन आदर्श प्रस्तुत किया, तथा पकिल समाज को कर्दममुक्त किया। यद्यपि यह प्रयत्न राजनैतिक आन्दोलन से संबद्ध था, तथापि वह शीतल एवं शान्तिमय था। इसमें वह ज्वाला तथा भस्मक न थी, जो पाश्चात्य नारी-आन्दोलन में पायी जाती है।

† *Seven Years of Freedom*, p 25.

तालिका २४

विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या

परीक्षा	१९८९-५०	१९५५-५६
इण्टरमीडिएट	८,२५२	१९,९२१
बी. ए. तथा बी. एससी.	४,६९४	८,९४८
एम. ए. तथा एम. एससी ...	६४०	२,१६६
व्यावसायिक विषय (केवल डिग्री)	१,१६८	३,८२१

इस प्रकार गत पाँच वर्षों में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी है। इतना होते हुए भी, सम्पूर्ण देश में १७-२३ बयोवर्ग की स्त्रियों में से केवल एक प्रति शत ही को शिक्षा मिल रही है। पाठ्यक्रम भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों का पाठ्यक्रम एक सा ही है। हाँ, कहीं-कहीं संगीत तथा नृत्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। सम्प्रति कुछ गृह विज्ञान महाविद्यालय खोले गये हैं, जैसे : लेडी इरविन कालिज, दिल्ली; होम साइन्स फेकल्टी, बड़ौदा; मोहनलाल हरगोविन्ददास महिला गृह-विज्ञान कालिज, जबलपुर, इत्यादि। इनके सिवा कुछ संस्थाएँ केवल महिलाओं के लिए ही हैं, जैसे : एस० एन० डी० टी० महिला महाविद्यालय, बम्बई; प्रयाग महिला विद्यापीठ, अलाहाबाद; आर्यभट्टा महाविद्यालय, बड़ौदा, इत्यादि।

व्यावसायिक और विशेष शिक्षा.—इस क्षेत्र के कालिज स्तर में विशेष उन्नति हुई है। सन् १९५६-५७ में १२,७७३ लड़कियाँ यह शिक्षा पा रही थीं। इनमें से सर्वाधिक छात्रा-संख्या ४,६६१ और शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की थी। इसके परवान् डाक्टरी कालिजों की छात्रा-संख्या ४,५७७ और ललित कला महाविद्यालयों की छात्रा-संख्या २,११० थी। स्कूल-स्तर में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ती ही रही। आत्र ल्यामन सीम ह्वार महिनारै शिक्षिका-प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षित हो रही हैं। स्वर्षीन भारत में, त्रिषोचित एक नरीन शिषन-संस्था अषोन् 'प्रान-सेविश-

स्त्री-शिक्षा का आदर्श.—उपर्युक्त विवरण इस बात का सूचक है कि महिलाएँ पुरुषों के साथ जीवन-यापन के लिए मुकाबला कर रही हैं। वे पुरुषों से किसी भी अङ्ग में हीनतर नहीं हैं। राधाकृष्णन आयोग ने कहा ही है, “वे कोई भी साहित्यिक कार्य उसी प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण सम्पन्न कर सकती हैं, जिस प्रकार पुरुष करते हैं। नर और नारी की योग्यता में विशेष कुछ प्रभेद नहीं है।”† पर इसके साथ ही प्रश्न उठता है कि स्त्रियों की शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए? इस विषय में दो विरुद्ध मत हैं। प्रथम पक्ष का मत है कि नारी का स्थान गृह में है। इस कारण उनका शिक्षा पुरुषों से भिन्न हो। द्वितीय पक्ष का मत है कि मनुष्य जीवन एक गाड़ी के समान है, जिसके नर और नारी दो पहिये हैं, अतएव दोनों की शिक्षा समान हो।

दोनों पक्षों का कथन बहुत कुछ सत्य है। परम्परा से भारत में रमणी सदृशहिणी बन कर बाया और जननी के रूप में इस देश की उन्नति करती रही हैं, अतएव गृह ही उसका प्रधान रंग मन्त्र है। ऐसी रिथति में स्त्री शिक्षा के पाठ्य क्रम का ध्येय गृह एवं परिवार की उन्नति होना चाहिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे गृह रूपी कबूतरराने में बन्द रहा करें, उन्हें मुक्त-वायु सेवन करने न दिया जाय, एव पारिवारिक आर्थिक अवस्था शोचनीय होने पर भी, उन्हें कमाने का अवसर न दिया जाय। जो स्त्रियाँ पुरुषों के साथ साथ एक ही पाठ्यक्रम का अभ्यास कर जीवन यात्रा में उनसे प्रतियोगिता करना चाहती हैं, उनके लिए भी कोई रुकावट न हो। वर्तमान शिक्षा में अनेक दोषों के रहते हुए भी इस शिक्षा ने सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकौर सरसीली देवियों को समुद्भूत किया है। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ऐसी शिक्षित नारियाँ अपने गृह के प्रति उदासीन हों। नारी गृह की अधिष्ठात्री देवी है। नारी ही पत्नी-रूप में पति की सहयोगिनी और परामर्श-दात्री बनकर उसे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर करती है, तथा गृह रथ का सुसञ्चालन करती हुई राष्ट्र निर्माण का मार्ग परिष्कृत करती है।

हम यह कदापि नहीं चाहते हैं कि आज शिक्षिता नारी बेकारी के दलदल में फँस जावे। बंगाल की एक शिक्षा रिपोर्ट ने बीस वर्ष पूर्व चेतावनी दी थी : “हमें शिक्षित पुरुषों की बेकारी से शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि स्त्री शिक्षा का भी वही परिणाम न निकले। हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को हमें दूर करना चाहिए।”

† *University Education Commission's Report*, p. 393

आज इस देश में नारी और पुरुष का समान अधिकार है। भारतीय संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिभ्रमिक की व्यवस्था करे, और अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे। गत दो विश्व युद्धों ने स्पष्ट कर दिया है कि नारी अब अबला नहीं है, वह 'बहुबल धारिणी' है। वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अब जीविकोपार्जन करने लगी है। आज वह पिछड़ी नहीं, बरन् अग्रगामिनी है। कार्यालयों में नारी-वाहिनी देखकर लोगों को दङ्ग रह जाना पड़ता है। निम्न लिखित तालिका में कुछ क्षेत्रों में कार्यरत महिला-कर्मचारियों की (सन् १९५७ की) संख्या दी जाती है :

तालिका २५
कतिपय क्षेत्रों में नारी†

क्षेत्र	संख्या
राजकीय प्रशासन	२,७२,४८३
डाक्टरी तथा स्वास्थ्य	७९,६२५
शिक्षा तथा अनुसन्धान	१,१८,४९१
डाक विभाग	२,०४७
टेलीफोन विभाग	२,६२३
पुलिस	४,१२९
कानून तथा वाणिज्य	८,९५९

† Tar Ali Beg, ed. *Women of India*, Delhi, Publications Division, 1958. pp 260.

शिक्षार्जन करना चाहें, और उसके द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति तथा अपना मानसिक विकास करने का विचार रखती हों। ऐसी महिलाओं को माध्यमिक स्कूलों में भरती करने की बाधाओं को एकदम हटाना चाहिए तथा उन्हें शालान्त परीक्षा में प्राइवेट बैठने देना चाहिए। अनेकों को आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत हो सकती है, अतएव उनके लिए उचित वृत्ति एवं मुफ्त शिक्षा वाञ्छनीय है। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की पहली बैठक में यह तय हुआ कि प्रौढ स्त्रियों को मिडिल तथा मैट्रिक शिक्षा देने के लिए छोटे पाठ्यक्रम तैयार करके ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे १०० गावों के एक खण्ड में इस प्रकार के दो पाठ्यक्रम पूरे किये जा सकें।

उच्च शिक्षा.—उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष सुधार की आवश्यकता है। कई विश्वविद्यालयों में यह विज्ञान का अध्ययन आरम्भ हुआ है, पर हम विद्य के इनेगिने कालिन्न ही हैं। इसके सिवा, पाठ्यक्रम में विविध ललित-कलाओं के समावेश की आवश्यकता है, जैसे : चित्रकारी, संगीत, नृत्य, नाट्य-कला, इत्यादि। ऐसे दिनों के अभ्यास से नारीत्व प्रस्फुटित होने की विशेष सम्भावना है।

तृतीय योजना-काल के दौरान में साठे आठ लाख स्त्री-कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस कार्य के लिए ऐसी यत्नशील नारियों की आवश्यकता होगी, जिनकी माध्यमिक शिक्षा समाप्त हो चुकी हो। इनके लिए अल्प-कालिक टोंग केंद्रों का आয়োजन किया जाये। स्त्रियों के उपयुक्त नौकरियों के अनेक मार्ग खुलते जा रहे हैं, जैसे : मरफट-शिक्षित, धात्री, पाप, प्रान-मेविका, स्टैनोमाफर, आदि। हम और महिलाओं को अधिकतर सीनना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओर महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

शिक्षिका प्रशिक्षण.—नारियों स्वभावतः अध्यापन-कार्य गुणात्मक रूपक कर सकती हैं, परन्तु देश में स्त्रियों का अल्पत्व प्रति शत शिक्षिकाओं का है : प्राथमिक स्तर १६.८ प्रति शत, मिडिल स्तर १७.७ प्रति शत, एव हाईस्कूल स्तर १९ प्रति शत। इनमें से अनेक शिक्षिकाएँ तो स्कूलों के विद्यालयों में काम कर रही हैं, आर्यर स्त्रियों के अधिकांश शिक्षक पुंर हैं। ये लड़कियों की आवश्यकताओं को पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं।

नारी का हृदय सामान्य से ओत प्रोत्त रहता है। प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्तरों का अध्यापन-कार्य स्त्रियों को ही सीनना चाहिए। अन्ततः सम्भव है कि तृतीय योजना के दौरान में पन्द्रह लाख शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, यदि पूर्व प्राथमिक

भगवान् इस देश को इस समस्या से बचावें। यों तो पुरुषों की बेकारी ही दुःखदायिनी है, उस पर नारियों की बेकारी तो अत्यन्त भयावह होगी ! !

स्त्री-शिक्षा की कतिपय समस्याएँ : भूमिका.—हर्ष की बात है कि लोगों में स्त्री-शिक्षा की चाह बढ़ रही है। पर देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, बालिका विद्यालयों की संख्या यथेष्ट नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। इस प्रश्न की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय नारी-शिक्षा-समिति ने कहा ही है :

यद्यपि देश में स्त्री तथा पुरुषों की संख्या समान है; पर लड़कों तथा लड़कियों की छात्र-संख्या एकसी नहीं है। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल तथा कॉलेजों की कुल संख्या का क्रमशः '२८', '१८', '१३' तथा '१०.४' प्रति शत भाग लड़कियों का है।†

समिति ने सिफरिश की है कि द्वितीय योजना-काल की शेष अवधि में स्त्री-शिक्षा के लिए निर्धारित रकम के ऊपर दस करोड़ रुपये खर्च किये जावें, एवं तृतीय योजना के दौरान में कम-से-कम सौ करोड़ रुपये नारी-शिक्षा के लिए व्यय हों। अब नारी-शिक्षा के मूल प्रश्नों पर विचार किया जाय।

प्राथमिक शिक्षा.—प्राथमिक शिक्षा की मूल समस्या ६-११ बयोंवर्ग की बालिकाओं को स्कूलों में लीचने की है तथा वहाँ उन्हें रोक कर इस योग्य बनाने की है कि वे जो कुछ भी सीखें, उसे न भूलें। यह सब तभी सम्भव है, जब कि माता पिता एवं अभिभावक अपनी कन्याओं की शिक्षा में दिलचस्पी लें। साथ ही, विशेषकर ग्रामस्थ बालिका विद्यालयों तथा ग्राम्य-गृहों का निकटतर सम्पर्क स्थापित होवे। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में लड़कियों के उपयोगी किसी उद्योग या फ़ाफ़्ट का होना आवश्यक है।

माध्यमिक शिक्षा.—अनेक माता-पिता अपनी किशोरी बालिकाओं को लड़कों के विद्यालयों में शिक्षार्थ भेजने में हिचकते हैं, क्योंकि वे सह-शिक्षा को हानिकारक समझ उसका विरोध करते हैं। अतएव स्वतन्त्र कन्या माध्यमिक स्कूल काफी तादाद में खोले जावें। इन बालिकाओं के सिवा, हमें अनेक विघवाओं तथा वयस्का गृहणियों की ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें से सम्भवतः कितनों को किशोरावस्था में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग न मिल पाया हो। हो सकता है कि वे अब

† भारतीय समाचार, २५ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ६६०।

प्रवृत्ति धीरे धीरे खो रही है।”† हमें इस चेतावनी का लाभ उठाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि स्त्री अपनी नारी-सुलभ लज्जा को खो बैठे। पतजी ने कहा ही है, “आधुनिके ! तुम नहीं कुछ अगर नहीं सिर्फ तुम नारी।”

और न हम यही चाहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के परिणाम-स्वरूप नारी अब स्वच्छन्द-विशारिणी तितली का-सा रूप धारण कर यहाँ-वहाँ विशार करने लगे। भारतीय नारियों का सदा आदर्श रहा है सदृशहिणी बनकर माता एव स्त्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करना। सारल्य-प्रिय भारतीय लज्जा गाईस्थाभम को कैसे भूल सकती है ! हमें पाश्चात्य देशों के दृष्टान्त से लाभ उठाना चाहिए। इन देशों में तो जैसे पारिवारिक जीवन लुप्त हो रहा है, और उसके बदले क्लब तथा होटल जीवन का प्रसार हो रहा है। हमें नीर-शीर विवेकी बनकर कर्तव्य-पथ का अनुकरण करते हुए, पश्चिम से एी नहीं वरन् विश्व के किसी भी कोने से किसी भी सद्भाव को ग्रहण करना है।

परम्परा से हमारे देश में नारी के जीवन ग्रन्थ के चार अध्याय रहे हैं : पुत्री, भगिनी, भार्या तथा माता। वर्तमान काल तक नारी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप में अथवा सुयोग्य सन्तति सुमनों द्वारा राष्ट्र-निर्माण के हेतु न जाने कितना धीर्ति मकरन्द विरीर्ण किया है। आज वर्तमान की शाकी भी समुज्ज्वल दृष्टिगोचर हो रही है। नारी स्वात्म्य सोपान पर आरोहण कर राष्ट्रोन्नति की ओर शनैः शनैः अग्रसर हो रही है। अपनी श्रद्धाञ्जलि हम नारा को सादर अर्पित करते हैं। कविवर ‘प्रसाद’ की अमृतमयी उक्ति हमारे कर्ण कुहर में ध्वनित हो उठती है :

नारी, तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नभ-पद-तल में ;
पीयूष स्रोत-सी बहा करो,
जीवन के समतल हृद-तल में।

† H M S. O *Differentiation of Ouricula, etc* London, H M S O 1933, p 18.

तथा प्राथमिक स्कूलों में फेवल महिलाएँ ही नियुक्त हों। पन्नु शिक्षित महिलाएँ शिक्षिका बनना पसन्द नहीं करती। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, शिक्षकों का वेतन आकर्षक नहीं है। द्वितीयतः, महिलाएँ घर छोड़कर बाहर, विशेषकर देहात में, नहीं जाना चाहती हैं। तृतीयतः, शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का पर्याप्त रूप में प्रबन्ध नहीं है। इन असुविधाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षिकाओं को ठीक वेतन दिया जाय, ताकि शिक्षित लड़नाएँ इस ओर आकर्षित हों। यदि ये पूर्ण समय तक कार्य न करना चाहें, तो ये आंशिक काल के लिए ही नियुक्त की जायें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की पढ़ी-लिखी स्त्रियों को भी इस कार्य के लिए खींचना शिक्का है। यह भी देखा गया है कि अध्यापिकाएँ बहुधा अकेली रहने के लिए हिचकिचाती हैं। यह ठीक ही है। इस कारण स्थान स्थान पर सयुक्त-गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ कुछ शिक्षिकाएँ एक साथ रह सकें।

प्रौढ़ शिक्षा.— इस विषय की विवेचना दसवें अध्याय में की जावेगी। यहाँ यह मतलब उचित है कि प्रौढ़ाओं की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण, पुरुष की शिक्षा एक व्यक्तिमाय की ही शिक्षा है, किन्तु नारी की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्त्रियों को चाहिए बच्चों के पालन-पोषण, सुचि-कर्म तथा परिवारिक कार्य का ज्ञान। उन्हें घर संभालना तथा सुधारना है। वह गृहिणी है, जननी है। राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ है।

उपसंहार

इस देश में नारी-जागरण पूर्ण रूप से हो चुका है। सैकड़ों बपों की सुपुत्रा नारी ने पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर शुभ जागरण को प्राप्त किया है। इस सभ्यता से वह इतनी प्रभावित हुई है कि वह घर की चहार दीवारी से निकलकर सामाजिक राजनैतिक और साहित्यिक क्षेत्र में पक्षपात करने लगी है। वह पुरुष की सहयोगिनी बनकर प्रति पल कदम बढ़ाती हुई, उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँची रही है।

पाश्चात्य सभ्यता की आँच हमारे देश की स्त्री-शिक्षा पद्धति पर लग रही है। भारतीय रमणियों स्कूलों तथा कालिजों की ओर दौड़ रही हैं, जहाँ उन्हें पुरुषोचित पाठ्यक्रम सिखाया जा रहा है। पाश्चात्य देश भी शिक्षा के इस दोष को अनुभव कर रहे हैं। इंग्लैण्ड की एक सरकारी रिपोर्ट का कथन है, “यद्यपि इस शिक्षा के द्वारा नारी में एक नवीन जीवन का संचार हुआ है, पर वह अपनी सुकुमार, सुकोमल

थी, फिर माध्यमिक शिक्षा का, और उसके बाद प्राविधिक शिक्षा का नम्बर आता था। यूरोप में भी यही स्थिति थी। आरम्भ में तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं जाता था। कार्डिनल न्यूमेन का कथन है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष स्थान न हो।

आज समय ने पलटा रखा है। फलतः हमारे देश में इस समय प्राविधिक शिक्षा की सर्वाधिक माँग है। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए माता पिता अपनी सन्तान को यही—प्राविधिक—शिक्षा देना चाहते हैं। कारण, शिल्पी तथा प्राविधिकों की मासिक आय पर्याप्त उच्च होनी है। आधुनिक सम्पत्ता मशीन, गणित तथा ऊर्जा पर निर्भर है। यह जमाना एटम बम का है। एक शक्तिशाली राष्ट्र भी इसका सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार शारारिक बल का मान घट रहा है तथा वैज्ञानिक ज्ञान का आनर बढ़ रहा है।

भारत में आज उठकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा है। हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। आज यह सभी अनुभव कर रहे हैं कि देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा बेकारी की समस्या का निवारण के लिए इस शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इसका बिना हम कृषि की उन्नति कर सकते हैं, न उद्योग बढ़ा सकते हैं और न अन्य राष्ट्रों का मुकाबिला ही कर सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा का विस्तार एवं सुधार की अनेक योजनाएँ, देश के सामने हैं। इस अध्याय में इन सब बातों पर विचार किया जायगा।

ब्रिटिश शासन काल में प्राविधिक शिक्षा

भूमिका—प्राविधिक शिक्षा का कई रूप हैं—औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा शिल्प विज्ञान। यह शिक्षा दो स्तरों में दी जाती है—कालेज तथा विश्वविद्यालय, और स्कूल। अंग्रेजों के शासन-काल में, इस शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह काल मुख्य तीन समयों में विभक्त किया जा सकता है (१) १८००-१८५७, (२) १८५७-१९०२ और (३) १९०२-१९४७।

प्रथम उपकाल (१८००-१८५७)—इंस्ट्रु इंडिया कम्पनी के समय में कुछ इनी गिनी संस्थाएँ स्थापित हुईं। इनके खोलने का मुख्य उद्देश्य सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र था। अपने शासन-काल में कम्पनी को डाक्टरों, इंजीनियरों तथा परिदरीक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसी प्रणाली के कारण इन संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, न कि जन हित के लिए। इस अवधि में रुढ़ी, क्लृप्ता तथा मद्रास में इंजीनियरिंग

आठवाँ अध्याय

प्राविधिक शिक्षा

प्रस्तावना

किसी समय भारत अपने शिल्प एवं विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। महेन्द्रोदारी ध्वंसावशेषों के अवलोकन से पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को शहर-निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग तथा भवन-निर्माण का विशेष ज्ञान था। ऋग्वेद में बाँध तथा नहर का उल्लेख है। अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व हमारे देश का इस्पात सारे विश्व में विख्यात था। स्वदेश लौटते समय सिकन्दर यहाँ से इस्पात लाट कर यूनान ले गया था। तत्पश्चात् इस देश के प्राविधिक ज्ञान का धीरे धीरे हान होता गया।

जहाँ एक ओर भारत की क्रमशः अवनति होती गयी, वहाँ दूसरी ओर अन्य देशों की क्रमोन्नति हुई। दो सौ वर्ष पूर्व अमेरिका एक ध्वंश देश गिना जाता था। आज वही देश विश्व का सिरमौर है। यहाँ पर खाद्य-सामग्री के उत्पादन की इतनी प्रचुरता है कि ऊँची कीमत कायम रखने के लिए ज्वार और भुट्टा जला दिये जाते हैं तथा दूध नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। पचास वर्ष पूर्व जापान भी हमारे देश से बहुत पिछड़ा हुआ था। इस स्वल्पावधि में ही जापान ने अपनी कृषि-उद्योग विषयक अतीव उन्नति की और हम सोते ही रहे। देखते-ही-देखते सोवियट रशिया का रूप बदल गया। एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश ने अपनी उन्नति करके सारे संसार को चन्द्रमा तक पहुँचने का मार्ग दिखा दिया है।

हमारी अवनति के अनेक कारण हैं। प्रथमतः, यहाँ औद्योगिक ज्ञान वश या परिवारगत ही हुआ करता था। द्वितीयतः, वर्तमान युग में प्राविधिक शिक्षा की पर्याप्त उपेक्षा की गयी थी। इस ओर सरकार का ध्यान अभी-अभी गया है। सन् १९४७ तक इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। तृतीयतः, अभी अभी तक प्राविधिक शिक्षा अल्प-मति बालकों के लिए ही उपयुक्त समझी जाती थी। विद्वद्विद्यालयीय शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती

प्राप्ति के समय भारत में अट्टाईस इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक कालिज थे। इसी अवधि में कई टेक्नोलौजिकल कालिज स्थापित हुए। इनमें से मुख्य हैं द्वितीय स्कूल ऑफ़ माइन्स, धानबाद, हारकोर्ट ग्लर, टेक्नोलौजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, स्कूल ऑफ़ केमिकल टेक्नोलौजी, बम्बई, इत्यादि।

इस प्रकार राज्य तथा जनता-दानों-ने प्रयास स्वरूप प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो चला। इस कार्य को दो अग्र घटनाओं ने कारण और भी प्रवृत्तियाँ प्राप्त हुईं। शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी समस्या की बाढ़ व कारण, लोगों का ध्यान तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। इस शिक्षा के प्रति लोगों के जो सर्वांगीण विचार थे, वे बदल गये, और लोगों में इस शिक्षा की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई। दूसरी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की थी, जिसने इस देश की प्राविधिक शिक्षा में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध की तात्कालिक माँगों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक फेब्रुअरी को तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में व्यवहृत करना पड़ा। इस प्रकार इस देश में प्राविधिक शिक्षा की बुनियाद तैयार हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एक देश व्यापी प्राविधिक शिक्षा योजना चलाना आरम्भ किया। उसकी प्रमुख संस्थाएँ निम्नान्वित हैं

१. औद्योगिक शोध-कार्य की सहायता के लिए 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद' की स्थापना (सन् १९४०)।

२. दिल्ली पॉलीटेक्नीक का आरम्भ (सन् १९४१)।

३. उच्च तकनीकी शिक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए श्री नलिनीरजन सरकार की अध्यक्षता में टेक्नोलौजिकल समिति की नियुक्ति (सन् १९४५)। यह समिति 'सरकार कमिटी' के नाम से मशहूर है।

४. ३० नवम्बर, १९४५ में 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद' की स्थापना।

५. सम्पूर्ण देश की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न स्तर के वैज्ञानिक शिल्पी, यंत्री तथा प्राविधिकों की एक सूची तैयार करके लिए 'वैज्ञानिक तथा मानवीय शक्ति समिति' की नियुक्ति (सन् १९४७)।

कालिज क्रमशः १८४७, १८५७ तथा १८५८ में स्थापित हुए। पूने में एक इंजीनियरिंग क्लास सन् १८५४ में खोल गयी।

द्वितीय उपकाल (१८५७-१९०२).—प्राविधिक शिक्षा का क्रमबद्ध विकास सन् १८५७ के बाद हुआ। सन् १८६६ में, पुना इंजीनियरिंग क्लास एक कालिज के रूप में वर्द्धित हुआ। सन् १८५७ में विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना बम्बई में हुई। यह संस्था बम्बई में स्थित पुतलीघरों के लिए कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण के निमित्त उद्घाटित हुई थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी औद्योगिक शिक्षा के प्रति भी उदासीन थी। हाँ, ईसाई मिशनरों ने कई औद्योगिक स्कूल अवश्य स्थापित किये थे। सन् १९०१-१९०२ में भारत भर में कुल चार इंजीनियरिंग कालिज तथा अस्सी तकनीकी या औद्योगिक स्कूल थे। स्कूलों में पुरानी परिपाटी के अनुसार कई देशी कारीगरी (बढ़ईगिरी, लुहारी, आदि) सिखायी जाती थी।

तृतीय उपकाल (१९०२-४७).—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में देश में प्राविधिक शिक्षा की माँग आरम्भ हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन (सन् १८८७) में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए सरकार तकनीकी शिक्षा की ओर ध्यान देवे। तब से कई परवर्ती अधिवेशनों में भी प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की माँग बुलन्द की गयी। सरकार हाथ-पर-हाथ रखकर मौन न रह सकी। उसने वजीफे देकर कुछ चुनिन्दे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युरोप तथा अमेरिका भेजना आरम्भ किया।

तथापि अनेक प्रगतिशील भारतवासी इस वृत्ति-व्यवस्था मात्र से सन्तुष्ट न हुए। सन् १९०४ में कलकत्ता में 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रसार-संघ' नामक एक संस्था की स्थापना हुई। कुछ चुने हुए सुयोग्य भारतीय विद्यार्थियों को शिल्प एवं उद्योग सम्बन्धी उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश भेजना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्' ने जादवपुर में इंजीनियरिंग और टेकनोलोजिकल कालिज की स्थापना की। इस संस्था ने मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स सन् १९०५ में शुरू किया, तथा केमीकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स सन् १९२१ में प्रारम्भ किया। पर डिग्री कोर्स आरम्भ करने का श्रेय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालिज को मिला है, जिसने सन् १९१७ में मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मेटलर्जी का अध्यापन आरम्भ किया। स्वतन्त्रता-

प्राविधिक शिक्षा के प्रबन्ध के लिए, परिपट्ट ने चार विभागीय समितियों— उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम—नियुक्त की हैं। ये अपने-अपने विभागों की जरूरतों का अध्ययन करती हैं एवं उनके अनुसार अपनी योजनाएँ चलाती हैं। इन समितियों के अतिरिक्त परिपट्ट ने सात पाठ्यक्रम मण्डल विविध विषयों के सुधार के लिए स्थापित किये हैं : सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा वैमिकल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, केमिकल टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड आर्ट्स। प्रत्येक विषय के राष्ट्रीय डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम अब तैयार हैं। परिपट्ट ने एक विशेषज्ञ समिति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की है।

परिपट्ट की बैठक प्रति वर्ष एक बार होती है। लेकिन समन्वय समिति तथा विभागीय समितियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय बैठ सकती हैं।

शिक्षा व्यवस्था. - प्रत्येक उद्योग में तीन प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है : (१) मैनेजर (२) परिदर्शक कर्मचारी एवं (३) कारीगर। इसीके अनुसार प्राविधिक शिक्षा तीन स्तर में दी जाती है : डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट।

डिग्री कोर्स. - डिग्री कोर्स की शिक्षा कालिज तथा विश्वविद्यालय में दी जाती है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट या उच्च माध्यमिक पास विद्यार्थी भरती किये जाते हैं। स्नातक कोर्स ३½-४ वर्ष का होता है, पर इस कोर्स में प्रवेश के पूर्व उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को एक वर्ष पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है।

स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि दो साल की होती है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश में इस पाठ्यक्रम का अभाव था। इस कमी को दूर करने के लिए 'अभाप्रशिप' ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर 'अभाप्रशिप' ने चुने हुए बीस संस्थानों में तैतीस विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है। हाल ही में 'अभाप्रशिप' की सिफारिश पर भारत सरकार ने इंजीनियरिंग और शिल्प विज्ञान की पढाई की प्रगति की समीक्षा करने और स्नातकोत्तर ट्रेनिंग तथा अनुसंधान की व्यवस्था के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त

स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा

भूमिका—स्वाधीनता मिलने के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की पूरे दम से चेष्टा हो रही है। कारण, यह स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति—कृषि, क्या स्वाद्य, क्या सिंचाई, क्या उद्योग, क्या व्यापार, क्या यातायात—इसी शिक्षा पर निर्भर है। प्रथम योजना का उद्देश्य था, देश के प्रत्येक राज्य में डिग्री स्तर पर प्राविधिक शिक्षा बढ़ाना तथा इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलौजीकल के उन पाठ्य-क्रमों का आरंभ करना, जिनकी व्यवस्था इस देश में नहीं थी। द्वितीय योजना काल में औद्योगिक प्रसार-विषयक दो प्रकार के कार्य-क्रम हैं। एक के द्वारा पहली योजना में जो कार्य शुरू किये गये, उन्हें विरुद्ध, समुन्नत तथा विस्तृत करना है; और दूसरे कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि में औद्योगिक शिक्षा के नये कार्य शुरू करना तथा नयी संस्थाएँ स्थापित करना है। द्वितीय योजना-काल में ५२ करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किये गये हैं। प्रथम योजना-काल में इस शिक्षा पर केवल तेईस करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अब तृतीय पंच-वर्षीय योजना की चर्चा हो रही है। उसमें भी तकनीकी शिक्षा का महत्व-पूर्ण स्थान है।

स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा के यथार्थ रूप को समझने के लिए, हमें इन विषयों का ज्ञान आवश्यक है : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा-व्यवस्था, (३) प्राविधिक शिक्षा का विस्तार और (४) नवीन योजनाएँ।

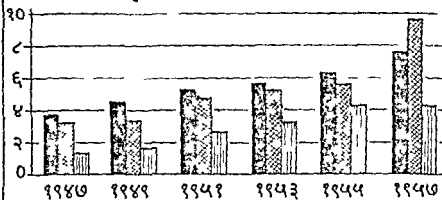
प्रशासन—१० फरवरी, १९५८ तक प्राविधिक शिक्षा का प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय के एक विभाग के मातहत था। पर अब इसका सम्बन्ध केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और मस्कृति मन्त्रालय से है। प्राविधिक शिक्षा समस्याओं पर विचार करने के लिए तथा नवीन योजनाओं को चलाने के निमित्त भारत-सरकार समय-समय पर विशेषज्ञों की समितियाँ नियुक्त करती रहती है।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्यीय सरकारों को 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद' (अभाप्रशिप) परामर्श देती है। † यह परिषद विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों-द्वारा संगठित होती है : संसद, विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय, राज्य सरकारें, अन्तर्विश्वविद्यालयीय मण्डल तथा प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न गैरसरकारी संस्थाएँ (उद्योग, वाणिज्य, श्रम, व्यवसाय, इत्यादि)। कुल सदस्यों की संख्या ६० है। दैनिक कामकाज एक समन्वय मण्डली चलाती है।

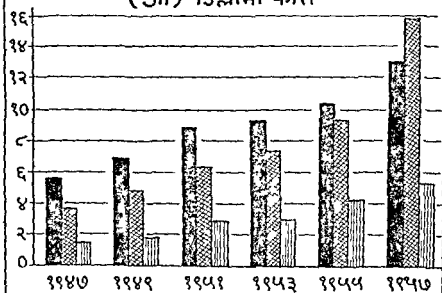
प्राविधिक शिक्षा की प्रगति

१९४७ से १९५७

(अ) डिग्री कोर्स



(आ) डिप्लोमा कोर्स



संस्थाएँ
(दस)



स्वीकृत छात्र-संख्या
(हजार)



उत्तीर्ण छात्र-संख्या
(हजार)

समिति नियुक्त की है। वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के सचिव प्रो० एस० एस० थैकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति स्नातकोत्तर ट्रेनिंग-केन्द्रों और अनुसन्धान शालाओं का दौरा करेगी तथा वहाँ के प्रधानों एवं अनुमती प्रोफेसरों से विचार-विमर्श करेगी।†

डिप्लोमा कोर्स.—डिप्लोमा कोर्स में विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा के बाद भरती किये जाते हैं। इसका दौरान तीन वर्षों का होता है। यह शिक्षा बहुधा पॉलीटेक्नीक तथा तकनीकी स्कूलों में दी जाती है। सफलीभूत विद्यार्थीगण विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में परिदर्शक कर्मचारी नियुक्त होते हैं।

सर्टीफिकेट कोर्स.—कारीगर दो प्रकार के होते हैं : (१) कुशल कारीगर और (२) अर्द्ध-कुशल और सामान्य श्रमिक। पहले प्रकार के व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूल, अथवा तकनीकी स्कूल, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल एवं उत्तर-बुनियादी स्कूलों में ट्रेनिंग मिलती है। पर अर्द्ध-कुशल अथवा सामान्य श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए, हमारे देश में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आशा है कि प्रवर बुनियादी स्कूल इस माँग को पूरा करेंगे। किसी-किसी उद्योग संस्था ने अपने श्रमिकों के लिए अंश-कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

प्राविधिक शिक्षा का विस्तार.—स्वाधीनता मिलने के पश्चात् भारतीय शिक्षा में सबसे उल्लेखयोग्य विस्तार प्राविधिक शिक्षा का हुआ। सन् १९४७ तक, हमारी तकनीकी संस्थाओं से पर्याप्त रूप में शिक्षार्थी नहीं निकलते थे, तथा शोध एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम निशान नहीं था। उस वर्ष पूरे देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षावाले ३८ डिग्री-संस्थान तथा ४१ पॉलीटेक्नीक संस्थान थे। सन् १९५७ में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थानों की संख्या क्रमशः ७४ तथा १२९ पहुँची।

इसी अवधि में छात्र-संख्या में भी विशेष वृद्धि हुई। सन् १९४७ में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्सों में क्रमशः २,९४० तथा ३,६७० विद्यार्थियों के प्रवेश की स्वीकृति दी जा चुकी थी। सन् १९५७ में यही संख्या तिगुनी हो गयी। याने ९,७७८ डिग्री कोर्स के तथा १५,९९५ डिप्लोमा कोर्स के हो गये।‡ यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजना-काल के अन्त में प्राविधिक संस्थाओं में डिग्री-पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा २४,००० विद्यार्थियों को प्रवेश

† भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९।

‡ भारत, १९५९, पृष्ठ ८३।

नवीन योजनाएँ.—स्नातकोत्तर काल में, प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ चलायी हैं। इनमें से मुख्य ये हैं (१) भारतीय विज्ञान सस्था, बंगलोर की क्रमोन्नति, (२) उच्चतर प्रौद्योगिकी सस्थाओं की स्थापना, (३) नवीन पाठ्यक्रमाँ का आरम्भ (४) वृत्ति की व्यवस्था, (५) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना एवं (६) अनुसन्धान।

भारतीय विज्ञान सस्था, बंगलोर—इस प्रसिद्ध सस्थान की स्थापना सन् १९११ में हुई, और तभी से यहाँ उच्चतर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इस सस्था से ३,००० से अधिक रसायन शास्त्री, भौतिकविद्, इंजीनियर, भूगर्भ शास्त्री इत्यादि अभी तक निकले हैं। ये भारत की उच्चतम शिक्षा सस्थाओं, सरकारी ओहदों तथा औद्योगिक केन्द्रों में काम कर रहे हैं। सन् १९४६ से भारत-सरकार इस सस्थान को उदार अनुदान दे रही है। मई, १९५८ में, यह सस्था विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हुई। इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा व विभिन्न क्षेत्रों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का समुचित प्रबन्ध है।

उच्चतर प्रौद्योगिक सस्थाएँ—हमारी पचवषाय योजनाओं ने उद्योगों के विस्तार पर बल दिया है। इस कार्य के लिए उच्चतर प्राविधिकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'सरकार-समिति' ने चार उच्चतर प्रौद्योगिकी सस्थाओं—भारत के प्रत्येक विभाग में एक—की स्थापना की सिफारिश की थी। 'अभाप्रसिप' ने इस सुझाव का अनुमोदन किया। सन् १९५१ में सर्व प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी सस्था कलकत्ते के पास खड़गपुर में स्थापित हुई। बम्बई की भारतीय प्रौद्योगिकी सस्था में विद्यार्थीगण सबसे पहले सन् १९५८ में प्रवेश हुए। कानपुर तथा मद्रास में दो और सस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। इन दोनों सस्थाओं में कुल मिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी।

नवीन पाठ्यक्रम—'अभाप्रसिप' की सिफारिश के फल-स्वरूप कुछ नवीन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। मुद्रण कला, प्रबन्ध-व्यवस्था तथा शहर-ग्राम कल्पना। देश में इन विषयों के अध्ययन की माँग है, पर इनके प्रशिक्षण का यथोचित प्रबन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकारों के द्वारा समुक्त रूप से अलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित चार मुद्रण-सूत्रों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष २०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आठ सस्थाओं में प्रबन्ध व्यवस्था-सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। इनके

दिया जा सकेगा। इतना होते हुए भी योजना-आयोग का अन्दाज है कि द्वितीय योजना के अन्त में १५,००० इंजीनियरिंग स्नातक तथा ३०,००० डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों की कमी पड़ेगी।†

अनुमान है कि तीसरी योजना में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त क्रमशः ४५,००० और ९०,००० इंजीनियरों की और जरूरत पड़ेगी, अर्थात् वर्तमान संख्या को तिगुना करना पड़ेगा। इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए नौ नये टेक्नोलोजीकल कालिजों की स्थापना विभिन्न शहरों में होगी : मैंगलोर, बरंगल, नागपुर, भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, अलाहाबाद, श्रीनगर एवं दिल्ली। प्रत्येक संस्थान से प्रति वर्ष ५०० अर्थात् कुल मिलाकर ४,५०० स्नातक निकलेंगे। शेष ४,५०० स्नातक मौजूदा संस्थानों से निकलेंगे। यह निश्चित है कि इन कालिजों को विशेष रूप से बढ़ाना पड़ेगा।

डिप्लोमा-शिक्षा के प्रसार के लिए 'अभाप्रशिप' ने अपनी २४ मार्च, १९५८ की बैठक में सिफ़ारिश की है कि भारत सरकार द्वितीय योजना-काल में २७ पॉलीटेक्नीक भारत के विभिन्न राज्यों में खोले : बुझाल (३), बम्बई (३), उत्तर प्रदेश (३), पंजाब (३), बिहार (२), मध्य प्रदेश (२), मद्रास (२), मैसूर (२), आन्ध्र (२), राजस्थान (२), आसाम (१), उड़ीसा (१) तथा केरल (१)।‡ इन संस्थानों में प्रतिवर्ष सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ४,०२० विद्यार्थी भरती किये जावेंगे। तृतीय योजना-काल में भारत-सरकार प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय प्राविधिक संस्थान स्थापित करने का विचार कर रही है। प्रत्येक संस्थान से सम्बन्धित अनेक तकनीकी स्कूल रहेंगे। स्कूलों की स्थापना किसी उद्योग-केन्द्र के पास होगी, और वे उससे मिल जुल कर ये काम करेंगे।

कारीगरों के प्रशिक्षण के प्रति भी ध्यान दिया गया है। अम तथा नियोजन मंत्रालय के १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिल्प-प्रशिक्षण-केन्द्रों में १०,५०० कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत-सरकार ने द्वितीय योजना-काल में, २६,००० अतिरिक्त कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का निश्चय किया है। इनमें से २१,६३० जगहों का प्रबन्ध विभिन्न राज्यों में हो चुका है।

† *Times of India*, March 19, 1959.

‡ *Ibid*, March 27, 1958.

का अर्थ 'सम्पूर्ण देश में ३२० विज्ञान-मन्दिर--अर्थात् प्रत्येक जिले के लिए एक--स्थापित करना' है। प्रत्येक सभ्यता का सम्बन्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रहेगा।

अनुसन्धान.—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध के लिए भारत सरकार ने, मन् १९४० में, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद' की स्थापना की थी। आज यह परिषद वैज्ञानिक अनुसन्धान और सृष्टि मन्त्रालय का भाग है। परिषद शोध-संस्थानों में लग वैज्ञानिकों को साहाय्य अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्र वृत्तियाँ देने तथा विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। मन् १९५८-५९ में परिषद का आवरतक व्यय ३ ३१ कराड रुपये तथा अनुमानित पूँजीगत व्यय १.७८ करोड रुपये हुआ।†

स्वाधीनता प्राप्ति के शत से परिषद देश के विभिन्न मन्दा म राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी है। इनका विवरण इस प्रकार है - (१) केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था, जीलंगोडा (बिहार), (२) केन्द्रीय कौंच तथा कुम्भार कार्य शोध संस्था, जादवपुर, (३) केन्द्रीय रत्न शोध केन्द्र, धानबाद, (४) केन्द्रीय राय प्रौद्योगिकी शोध संस्था, मैसूर, (५) केन्द्रीय चर्म-शोध संस्था, मद्रास, (६) केन्द्रीय नमक शोध संस्था, भायनगर, (७) केन्द्रीय भयन-शोध संस्था, रुटकी, (८) केन्द्रीय भोजन शोध संस्था, लखनऊ, (९) केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध संस्था, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), (१०) केन्द्रीय नियुक्त इंजीनियरिंग शोध-संस्था, पिलानी, (११) केन्द्रीय नियुक्त रसायन शोध संस्था, कराइडुडी (मद्रास), (१२) केन्द्रीय सड़क शोध-संस्था, नयी दिल्ली, (१३) केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध संस्था, नागपुर, (१४) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला, हैदराबाद; (१५) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला, जम्मू-तावी (जम्मू तथा काश्मीर), (१६) विडला-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी सभ्रहालय, कलकत्ता, (१७) भारतीय जीव रसायन तथा परोक्षात्मक औषधि संस्था, कलकत्ता, (१८) राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, (१९) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली, (२०) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना, एवं (२१) राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान, लखनऊ।†

कतिपय समस्याएँ

भूमिका.—इस प्रकार हमारे देश की प्राविधिक शिक्षा की प्रगति गत दस वर्षों में हुई। पूर्व स्वानन्व्योत्तर-काल में इस शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया

† भारत १९५९, पृष्ठ ९३।

नाम हैं : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मडगपुर; अर्थशास्त्र-स्कूल, दिल्ली; अर्थशास्त्र विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय; अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल, बम्बई; भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर; समाज-कल्याण तथा कारोबार-प्रबन्ध-संस्था, कटकता; और सिक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था, बम्बई ।

दिल्ली में एक 'शहर-ग्राम-कल्याण' विद्यालय (स्कूल आफ टाऊन एण्ड कण्ट्री प्लेनिंग) स्थापित हुआ है । इसमें उत्तर-स्नातक स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है : (१) दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा (२) एक महान कोर्स, उन शिल्पी, इंजीनियर इत्यादि के लिए जिन्हें अपने विषय का कुछ व्यावहारिक अनुभव हो ।

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की ओर से बंगलोर में एक 'औद्योगिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था' स्थापित होनेवाली है । यहाँ औद्योगिक उत्पादन का उच्चतर ज्ञान दिया जावेगा । सयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था को ९,००० डालर अनुदान देना स्वीकार किया है ।

वृत्ति.—तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिए भारत सरकार ने गत दस वर्षों में तीन प्रकार की वृत्तियों का आयोजन किया है : प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टाइपेण्ड, राष्ट्रीय शोध शिष्य-वृत्ति-योजना तथा विश्वविद्यालयीय शोधवृत्ति । प्रथम योजना के अनुसार, चुने हुए स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी शिक्षा समाप्त करने पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए मासिक स्टाइपेण्ड मिलना है—प्रति स्नातक १५० रु. तथा डिप्लोमा प्राप्त-व्यक्ति १०० रु. । इनके ट्रेनिंग का बन्दोबस्त सरकारी तथा विशेष गैरसरकारी केन्द्रों में किया जाता है । अभी तक १,००० स्टाइपेण्ड दिये गये हैं । द्वितीय योजना के अधीन ४०० रु. मासिक की ८० शिष्य वृत्तियाँ तथा प्रति वर्ष यंत्र तथा अन्य साधनों के लिए एक हजार रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी है । यह योजना सन् १९५५-५६ में शुरू की गयी थी । इनके अतिरिक्त २०० रु. मासिक की ८०० शोध-वृत्तियाँ विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थाओं को दी गयी हैं ।

विज्ञान-मंदिर.—सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं । ये केन्द्र ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं, तथा उन्हें इसके उपयोग की साधकता के विषय में समझाते हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के मन्त्री श्री हुमायूँ कबीर

उद्योग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा का आयोजन सावधानी से किया जावे। श्री एचट की यह चेतावनी हमें सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए :

देश की यह बदनसीबी होगी, यदि अपनी लम्बी प्राविधिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् अनेक व्यक्तियों को अपने ज्ञान का उपयोग करने का सुअवसर ही प्राप्त न हो ।।

गत दस वर्षों में प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा देश की तकनीकी मानव-शक्ति की आवश्यकता का अनुमान करने के लिए यथेष्ट चेष्टा की गयी है। पर सरकार माँग और प्रदान का समुचित सन्तुलन न कर सकी। किसी औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी देखी जा रही है और किसी क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। यदि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार देश का आर्थिक विकास न हुआ तो तकनीकी व्यक्तियों में बेकारी बढ़ती ही जायगी ।†

कुशल तकनीकी कारीगरों की अपर्याप्तता.—प्राविधिक शिक्षा विस्तार में, सरकार का ध्यान अधिकतर स्नातक तथा डिप्लोमा कोर्सों की ओर गया है, पर देश में सबसे अधिक आवश्यकता कुशल कारीगरों की है। बल कारखानों में नये रँगस्ट भग्ती होते हैं। उन्हें उत्पादन का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इन हुनरवाले मजदूरों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण की यथोचित आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश के कुटीर शिल्प की पर्याप्त प्रगति हो रही है; पर सभ्यता के विकास के साथ, इनमें एक नवीनता प्रयोजनीय है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन कारीगरों को परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

प्रशासकों का अभाव.—हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है 'विकास-कार्य आरम्भ करना', जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर उठाया जा सके, और उन्हें उन्नत जीवन जिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें। प्रथम योजना-काल में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को भी प्राथमिकता मिली। द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य है 'मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ द्रुतगति से औद्योगीकरण'। इन योजनाओं के फल स्वरूप नये-नये ग्रँध

† *Abbott Wood Report*, p 38

‡ *Times of India*, February 3, 1959

था। इसके फलस्वरूप हमारे देश का औद्योगिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ था। छोटे-मोटे यन्त्रों की बात छोड़ दीजिए। हमने मुई तक बनाना नहीं सीखा था। हमारा देश विदेशी मालों से छा गया था, तथा प्रत्येक वस्तु के लिए हमें विदेशों का मुँह ताकना पड़ता था।

अब समय में परिवर्तन व्याप्त हो गया है। हमारे उद्योगों की दिन-प्रति-दिन उन्नति होती जा रही है। साथ ही, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की पूर्णतः चेष्टा हो रही है। परन्तु एक विशाल भवन खड़ा होने के लिए समय लगता है, तथा पग-पग पर विघ्न-श्राधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारी प्राविधिक शिक्षा तथा औद्योगिक विकास के सामने आज मुख्य समस्याएँ ये हैं : (१) मानव-शक्ति की आवश्यकता, (२) कुशल तकनीकी कारीगरों की अपर्याप्तता, (३) प्रशासकों का अभाव, (४) संकीर्ण पाठ्यक्रम, (५) नये कालिजों की माँग, (६) शिक्षकों की कमी, (७) शिक्षा का माध्यम, (८) कर्मशाला-अभ्यास, (९) उत्तर-विद्यालय शिक्षा, (१०) अनुसन्धान एवं (११) सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोग।

मानव-शक्ति की आवश्यकता.—भारत की प्रगति एवं औद्योगिक विकास के लिए विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित तकनीकी मानव-शक्ति की आवश्यकता है। आज प्राविधिक शिक्षा का विस्तार, इस देश में, द्रुतगति से हो रहा है। तिस पर भी योजना-आयोग को आशङ्का है कि तृतीय योजना-काल में तकनीकी मानव शक्ति का अभाव रहेगा।† इस कारण प्राविधिक शिक्षा का और भी प्रचार करना पड़ेगा।

तकनीकी मानव-शक्ति के ट्रेनिंग में तीन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रथमतः, इसे प्रत्येक क्षेत्र की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करनी पड़ेगी। द्वितीयतः, प्राविधिक शिक्षा का मान-दण्ड न गिरने पावे। तृतीयतः, शिक्षा-संस्थाओं से निकलनेवाले यंत्रियों की संख्या तथा देश की प्रशिक्षित मानव-शक्ति की माँग में एक सन्तुलन रहे। लेकिन जब किसी देश का औद्योगिक विकास शीघ्र किया जाता है, तब प्रायः केवल पहले ही विषय पर ध्यान दिया जाता है। बहुसंख्यक प्रशिक्षित शिल्पी तकनीकी संस्थाओं से निकाले जाते हैं। पर यदि इस संख्यात्मक विस्तार के साथ शिक्षा स्तर गिर जाय, तो औद्योगिक विकास को भारी धक्का लगता है। सदा याद रहे कि तकनीकी शिक्षा में कोई भी छोटे रास्ते की गुंजाइश नहीं है।

† देखिए पृष्ठ २०२।

सामान्य शिक्षा का मूल लक्ष्य है, व्यावसायिक योग्यता की वृद्धि। इस ज्ञान के कारण, मनुष्य की दृष्टि सर्कीणता दूर होती है, कार्य कुशलता बढ़ती है और वह समाज को स्पष्टतर समझ सकता है।†

पर प्रचलित पाठ्यक्रम के सुधार के बिना, सामान्य शिक्षा का समावेश नहीं हो सकता है। 'अमाप्रशिप' ने अपने २२ मार्च, १९५७ के अधिवेशन में यह तय किया है कि एक उचित मान दण्ड स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि इंजीनियरिंग एव टेक्नोलोजीकल की प्रथम डिग्री के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् पञ्चवर्षीय अविच्छिन्न कोर्स का आयोजन किया जाय। वर्तमान पाठ्यक्रम के रहो-बदल के अतिरिक्त परिपद का उद्देश्य है नवीन कोर्स में विशेषीकृत शिक्षा के सिवा, कुछ अतिरिक्त विषयों का समावेश करना। परिपद ने यह काम अपने पाठ्यक्रम मण्डलों को सौंपा है।

आज की दुनिया में साधारण ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक श्रद्ध-कुशल एवं सामान्य श्रमिक को भी है। बीसवीं शताब्दी मशीन तथा सामूहिक उत्पादन का युग गिना जाता है। दिन-प्रतिदिन मशीन क्रिया अधिकतर पेंचीदा होती जा रही है। इसे समझने के लिए, लिखने-पढ़ने का ज्ञान एक श्रमिक को भी जरूरी है। अतएव केवल हथौड़ी-विद्या से एक मजदूर या कारीगर का काम इस संसार में अब भली भाँति नहीं चलेगा। यदि उसे भाषा, गणित तथा समाज-शास्त्र का ज्ञान दिया जाय, तो उसके वैयक्तिक विकास के साथ ही उसकी उत्पादन शक्ति की भी अवश्य उन्नति होगी, जिसकी मूलतः आवश्यकता है।

नये कालिजों की माँग.—इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि तृतीय योजना के दौरान में नौ नये टेक्नोलोजीकल कालिज एव सत्ताइस पॉली-टेकनीक स्थापित होंगे। ये मौजूदा संस्थाओं के समान छोटे-मोटे न होंगे, और न उनमें कतिपय विषयों के अध्यापन का रुदोरस्त होगा। ये वृहत्काय होंगे तथा उनमें विविध विषयों के पढ़ाने का आयोजन होगा। इसी पाठ्यक्रम के अनुसार, उनमें कर्म-शालाओं तथा प्रयोग-शालाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

शिक्षकों की कमी.—संस्थानों की संख्या-वृद्धि के साथ-साथ उपयुक्त शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते हैं। किसी किसी कालिज में जैसे-तैसे शिक्षक नियुक्त

† President's Commission on Higher Education. *Higher Education for American Democracy*, Vol I, Harper, 1946, p 61

बोधे जा रहे हैं, बड़े-बड़े कारखानों की सृष्टि हो रही है, आवागमन के साधनों में उन्नति हो रही है, नगर-पुनर्रचना चल रही है, परिवहन का विकास हो रहा है, इत्यादि, इत्यादि ।

पर इन योजनाओं को कौन तैयार कर रहा है ? इन्हें कौन चला रहा है ? खेद के साथ हमें उत्तर देना पड़ता है कि “विदेशी विशेषज्ञ” । हमें उस समय हताश होना पड़ता है, जब हम देखते हैं कि स्वाधीन होते हुए भी, ऐसे कार्यों के लिए हमें विदेशी परामर्श-दाताओं का मुँह ताकना अनिवार्य होता है । विशेषज्ञों की बात जाने दीजिए । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विकास-कार्य बहुत कुछ हो रहा है; पर प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में, प्रौद्योगिक प्रशासकों का विशेष अभाव है । वर्तमान जगत में एक औद्योगिक प्रशासक के लिए केवल प्राविधिक ज्ञान ही ब्येष्ट नहीं है । भाषा पर उसका समुचित अधिकार होना चाहिए तथा उसे वक्तुत्व-कला-दक्ष भी होना चाहिए । उसे देश तथा विश्व की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि इन सबका घना सम्बन्ध प्रौद्योगिक योजनाओं से है । उसे प्रशासन कार्यक्रम का अनुभव चाहिए, अन्यथा उसे लिपिकों के इशारों पर नर्तन करना पड़ता है । परन्तु उसे सबसे अधिक आवश्यकता ‘मानव-सम्बन्धी ज्ञान’ की है, क्योंकि उसकी अधीनता में कितने ही कर्मचारी कारीगर तथा अभिरु क्रिया-रत रहते हैं, जिनके साथ कार्य करना तथा उनसे काम कराना असाधारण कार्य होता है । इन कठिनाइयों का अनुभव करते हुए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने यह विचार किया कि “विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई संख्या में प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।”

‘अभाप्रशिप’ की चेष्टाओं के कारण हमारे देश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हाल ही में शुरू हुए हैं तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं की सृष्टि हुई है । प्रबन्ध-व्यवस्था के कालिज भी खुल गये हैं । आशा की जाती है कि इस उच्चतर शिक्षा के मिलने के पश्चात्, हमारे देश में भी पर्याप्त रूप में प्राविधिक प्रशासक निकलने लगेंगे ।

संकीर्ण पाठ्यक्रम.—पिछले शीर्षक की चर्चा से यह भी स्पष्ट हुआ होगा कि हमारे देश के प्राविधिक पाठ्यक्रम संकीर्ण हैं । उनमें केवल तकनीकी विषयों का ही समावेश रहता है । पर एक प्राविधिक के लिए भाषा, अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान का ज्ञान जरूरी है । तकनीकी शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए, अमेरिका ने प्राविधिक पाठ्यक्रम में मामान्य शिक्षा एक अनिवार्य विषय रखा गया है । अमेरिकी उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रेसीडेंट आयोग का कथन है :

बाहरी सहायता और भी आवश्यक है। पर यह सहायता हमारे देश में पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है। सरकार ने सम्प्रति प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की उन्नति के लिए कुछ छात्र वृत्तियों का बन्दोबस्त किया। पर यह यथेष्ट नहीं है। जहाँ तक बने, सरकार को अपने कल कारखानों में व्यावहारिक अभ्यास की सुविधा देनी चाहिए। अनेक विना वजीफा वाले विद्यार्थी अग कालिक नौकरी व्यापारी फर्मों में कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कम से कम चार लाभ हैं (१) विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलनी है (२) उनको स्वामादिक वातावरण में व्यावहारिक अभ्यास मिलता है, (३) उन्हें विभिन्न स्तर के कर्मचारियों तथा श्रमिकों से मिलने का सुअवसर मिलता है, एवं (४) काम करते-करते, उनकी स्थायी नौकरी भी ठीक हो जाती है, और शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्हें नौकरी के लिए यहाँ यहाँ भटकना नहीं पड़ता है। यह प्रथा अनेक देशों में प्रचलित है।

उत्तर विद्यालय-शिक्षा — जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त, मनुष्य को ज्ञानार्जन करने का सुअवसर रहता है। पर बहुधा भारतवासियों की शिक्षा स्कूल या कालिज छोड़ने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। विशेषकर यह पन्थ एक प्राविधिक के लिए हानिकारक है। बीसवीं शताब्दी में प्राविधिक ज्ञान की दिन प्रति दिन उन्नति हो रही है। जो कल था, वह आज नहीं है, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। अतएव एक शिल्पी या यन्त्री अपने पूर्व ज्ञान के भरोसे निष्क्रिय बैठ नहीं रह सकता है। उसे नवीन विद्या के सस्पर्श में रहना पड़ेगा। अतएव उत्तर विद्यालय शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। हमारे देश में ३८ विश्वविद्यालय, ७४ डिग्री कोर्सवाली तथा १२९ डिग्रीमा कोर्स वाली प्राविधिक संस्थाएँ हैं। पर इनका ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। उन्हें प्राविधिक के लिए पुनर्संजीवन कोर्स का आयोजन करना चाहिए, ताकि उन्हें आधुनिकतम विद्या का लाभ मिले और उनके ज्ञान में जग न लगे।

हमारे कारीगरों तथा श्रमिकों के लिए अग कालिक कोर्स की अति आवश्यकता है। ये कोर्स सायकल में चलाये जा सकते हैं, ताकि नौकरी करते हुए भी वे अपना काम सीखें। उनकी औद्योगिक निपुणता की वृद्धि करने का यह एक अचूक उपाय है। हम अतिरिक्त इन लोगों की अवकाश शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे श्रमिकों की फुरसत का समय गप्पे हँकने, बिड़ी पीने या पर निन्दा करने में बीत जाता है। कई तो व्यभिचार में डूब रहे हैं या न्लारियों की शरण में पड़े रहते हैं। परन्तु उनके इस अवकाश-काल का सदुपयोग हो सकता है, यदि उनका लिए समाज

होते हैं। अध्यापकों के अभाव के कारण, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में धका पहुँचने की सम्भावना है। कर्मरक्ष व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में रोकने के लिए उचित घेतन की अवश्य जरूरत है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि तमनीकी अध्यापकगण शिक्षण-कार्य छोड़कर इधर-उधर न भागने पावें।

कुछ बयों से नवीन तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस कार्य के लिए भी काफी अध्यापक नहीं मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए तथा कुछ समय तक तो हमें विदेशियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तथा हमारे कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना पड़ेगा।

शिक्षा का माध्यम.—२ सितम्बर, १९५६ को श्री नेहरू ने राज्यीय मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि यह स्पष्ट ही है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। वर्तमान परिस्थिति को देखने हुए श्री नेहरू का अभिप्राय शायद ठीक ही है; पर भविष्य में सरकारी नीति क्या होगी, यही प्रश्न है। यदि प्राविधिक शिक्षा के माध्यम का निर्णय अनिश्चित काल तक छोड़ दिया जाय तो सभी वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी, और विज्ञान की नीति दूसरे विषयों के लिए भी खलाना पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके, मातृ-भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।

पर विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक संस्थाओं में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य विषय रहे। इसके सिवा, भारतीय भाषाओं में, प्राविधिक साहित्य लिखने का यत्न किया जावे। यह स्मरण रहे कि चीन तथा जापान सर्रासे पूर्वीय देशों में मातृ-भाषा ही प्राविधिक शिक्षा का माध्यम है, पर अंग्रेजी एवं रशियन सीखने पर यथेष्ट जोर दिया जाता है।

कर्म-शाला-अभ्यास.—हमारी प्राविधिक संस्थाएँ अपने विद्यार्थियों को सर्वाङ्ग-पूर्ण कर्म-शाला-अभ्यास नहीं दे सक रही हैं। यह याद रहे कि दूसरी विद्याओं का अध्यापन तो संस्था की चहारदीवारी के भीतर हो सकता है, पर प्राविधिक शिक्षा संस्थान के अन्दर सीमित नहीं रह सकती है। मुख्य ज्ञान तो विद्यालय की कर्म-शाला बाहरी कर्म-शालाओं, कारखानों तथा खलिहानों की शरण लेनी पड़ती है। तकनीकी शिक्षा की दृष्टता बहुत-कुछ भीतरी व्यावहारिक अभ्यास के समन्वय पर निर्भर है। अनेक संस्थानों में उपयुक्त कर्म-शालाओं तथा प्रयोग-शालाओं का अभाव है। इस कारण

कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि का नवीनीकरण इस शोध के बिना नहीं हो सकता है, अतएव हमारे अनुसन्धान कर्त्तागण इस ओर विशेष ध्यान दें।

सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोग.—अन्य शिक्षा क्षेत्र तो अपने पाँव पर खड़े रह सकते हैं, पर प्राविधिक शिक्षा एकलन नीति का अलम्बन नहीं कर सकती है। सरकार तथा उद्योग से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सरकार कुछ प्राविधिक संस्थाएँ स्थापित करती है, कुछ को आर्थिक अनुदान देती है, एव शोध तथा व्यावसायिक अभ्यास का बन्दोबस्त करती है। उसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा को भी राज्य की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे, किस क्षेत्र में तथा कितने प्राविधिकों की आवश्यकता है। इसके लिए उचित सर्वेक्षण होना चाहिए।

इससे अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा तथा उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाएँ उद्योगों की माँगों को पूरा किया करती हैं। पर उद्योग तकनीकी विद्यार्थियों को व्यावहारिक अभ्यास की सुविधा प्रदान करता है, तथा शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त उन्हें नौकरी देता है। किन्तु प्रत्येक उद्योग मूलक शिक्षा क्षेत्र का ध्येय सब समय स्पष्ट रहना चाहिए। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् लार्ड यूस्टेस पसा का कथन है :

हम उद्योग को सूचना देनी होगी कि शिक्षा का ढाँचा आज क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, हम इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, और हमें व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों की ओर ध्यान देते हुए उनके उपयुक्त यंत्र औजार तैयार करना पड़ेगा। साथ ही उनके अनुकूल नवीन योजनाएँ चलानी पड़ेगी।

उपसंहार

इस अध्याय में भारतीय प्राविधिक शिक्षा की वर्तमान रूपरेखा की चर्चा की गयी है, तथा उससे सम्बन्धित कतिपय समस्याओं पर विचार किया गया है। बीसवीं शताब्दी विज्ञान का युग है। विज्ञान की प्रगति को न हम रोक सकते हैं और न रोकना चाहते हैं। यदि हम सम्यक् राष्ट्रों में अपनी गगना कराना चाहते हैं, तो हमें भी उसी स्रोत के साथ भाग बढ़ाना पड़ेगा।

हमारी पंच वर्षीय योजनाओं का भी ध्येय है, विशाल कारखानों एवं फैक्टरियों की स्थापना, उनके उपयुक्त शिल्पी, यन्त्री तथा प्राविधिकों को तैयार करना तथा देश

शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाय। किन्तु हमारी औद्योगिक संस्थाएँ, इस ओर उदासीन हैं। अनेक पाठ्यालय देशों में मजदूरों के लिए नाट्य शालाएँ, स्नानागार, लीढ़ा-स्थल, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है। ऐसी समुचित सुविधाओं के कारण धार्मिक अदानी यकायक को भूल जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद नहीं होता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास पूर्णता की ओर उन्मुख होता है। हमारे देश में ऐसी परिस्थितियाँ इस समय स्वप्नप्रत, प्रतीत होती हैं।

धर्मियों के लिए उत्तर-विद्यालय-शिक्षा का आयोजन पाठ्यालय देशों में जल्दी सम्पन्न जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियट रुम में क्रिमान तथा मजदूरों के लिए अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा आरम्भ हो गयी है। शिक्षा रात्रि शालाओं में दी जाती है। पत्र-व्यवहार-भाग भी शिक्षा का प्रबन्ध है। ये पाठ्यक्रम लोक-प्रिय हैं। प्रायः २०,००,००० व्यक्ति इस शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं, और १२,००,००० धर्मिक इस आयोजन का लाभ प्रति वर्ष ले रहे हैं। सरकार इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुबल खर्च करती है।†

अनुसन्धान.—स्वाधीन भारत ने अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान दिया है, तथा दस ही वर्ष में अनेक शोध-प्रयोग-शालाएँ स्थापित हुई हैं। पर सेट के साथ कहना पड़ता है कि हमें मशीन, कल-पुर्जे तथा अन्न-यन्त्र के लिए भी दूसरे देशों की ओर अब भी निहारना पड़ता है। हमारे देश की पर्याप्त सम्पत्ति बाहर चली जाती है, हम देश की बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सक रहे हैं, तथा उपयुक्त हथियार-औजार के अभाव के कारण हमारी योजनाओं का ठीक-ठीक विस्तार नहीं हो पा रहा है। अतएव औद्योगिक अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, उत्पादन-शोध लीजिए। इस शोध का लक्ष्य हो : (१) उत्पादनों की गुणात्मक प्रगति; (२) माल, क्रियाओं तथा कलाओं की वृद्धि; (३) उत्पादन-क्रिया में किफायत करना; (४) उत्पादन सम्बन्धी-क्रियाओं की तकलीफों को रोकना; (५) एक स्तरोन्नयन स्थापित करना; एवं (६) क्रेता-विक्रेताओं के मध्य सद्भाव फैलाना।

इस प्रत्येक क्षेत्र में गवेषणा का प्रयोजन है। देश की जरूरतों को देखते हुए भारत में आज बौद्धिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुसन्धान की विशेष आवश्यकता है।

नवाँ अध्याय

शिक्षक प्रशिक्षण

पूर्व पृष्ठिका

भूमिका.—संसार में शिक्षा एक प्रधानतम व्यवसाय क्षेत्र है। भारत में आज वारह लाख से अधिक व्यक्ति शिक्षण कार्य द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। जीवन क्षेत्र में अध्यापन का महत्व सर्वाधिक है। शिक्षकों का सम्बन्ध केवल एक वृहत् छात्र समुदाय से ही नहीं रहता, बरन् विभिन्न आयु व विचारधाराओं से भी रहता है।

प्राचीन एवं मध्य युगीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई विधिवत् नियम न था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक छात्राध्यापक प्रणाली (मानीटर पद्धति) प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार सम्पूर्ण स्कूल या कक्षा कतिपय एकरूप टुकड़ियों में बँट दी जाती थी। प्रत्येक टुकड़ी एक मानीटर या वयस्क विद्यार्थी के मातहत में रहती थी। मानीटर अपनी टुकड़ी को पढ़ाता था। अतः में टुकड़ी के विद्यार्थीगण अपनी पाठ शिक्षक को सुनाते थे।

डा० एन्ड्रू वेल ने, जो कि मद्रास सैनिक अनाथालय के सुपरिटेण्डेण्ट थे, इसी प्रथा को इस संस्था में अपनाया (सन् १७८७ ई०)। बाद को उन्होंने इसका प्रचार ग्रन् ब्रिटेन में भी किया। सन् १८०१-१८४५ की अवधि में उस देश के प्राथमिक स्कूलों में यही पद्धति प्रचलित थी। यह प्रथा कम एचींकी थी, तथा शिक्षक समस्या समाधान की अमोघ औषधि भी। इस प्रथा के कई नामकरण हुए, मानीटर पद्धति, मद्रास प्रथा, लेकास्ट्रियन पद्धति, पेसालोजी विधि, ग्लासगो प्रथा, इत्यादि। वस्तुतः यह प्रणाली भारतीय प्रचलित देशी पद्धति का अनुकरण थी।

शिक्षक प्रशिक्षण एक नयी कला है। भारत में इसका अभ्युदय आधुनिक युग में ही हुआ है। इसके विकास का अध्ययन तीन मुख्य कालों में किया जा सकता है (१) छात्राध्यापक प्रणाली, (२) शिक्षक ट्रेनिंग और (३) शिक्षक प्रशिक्षण।

की आर्थिक उन्नति करना। पर हमें याद रखना चाहिए कि सभ्यता अर्थ पर नहीं, बल्कि मानव विकास पर निर्भर रहती है। जापान तथा जर्मनी का उदाहरण लीजिए। द्वितीय विश्व-युद्ध के फल स्वरूप ये देश भूल में मिला दिये गये थे। शहर, बन्दरगाह, फेक्टरी, कारखाने सभी तहस-नहस हो गये थे, खाने को अन्न तथा पहनने-ओढ़ने को वस्त्र न थे। इस प्रकार इन देशों का आर्थिक सर्वनाश हुआ, पर मानवी शक्ति अक्षुण्ण रही। उसी शक्ति ने देश को फिर से नये सिरे से बसाया। ध्वंसावशेषों पर नवीन अट्टालिकाएँ, नये कारखाने फिर से सिर ऊँचा कर खड़े हुए। इस प्रकार पुरातन काया में नूतन जीवन का संचार हुआ। ये राष्ट्र फिर से उठ बैठे। यहाँ तक कि हाल ही में पश्चिम जर्मनी ने हमारे देश की कृषि की उन्नति के लिए चीम लाल मार्क के अनुदान की घोषणा की है। हमारे वित्त-मंत्री श्री मोरारजी देसाई को अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए भिन्ना शोली लेकर देश-विदेश घूमते रहना पड़ना है। न जाने कब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे! हमें सदा याद रखना चाहिए कि किसी भी देश की उन्नति मानव-शक्ति के विकास पर निर्भर रहती है, न कि केवल आर्थिक सचय पर।

विशेष व्यवस्था रखी गयी। इन विधेयों व फल-स्वरूप शिक्षण क प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सन् १८८२ में ब्रिटिश भारत में १०६ नार्मल स्कूल थे, शिक्षार्थियों की संख्या ३,८८६ थी तथा प्रशिक्षण पर चार लाख रुपये व्यय किये गये थे।

यह ध्यान रहे कि ये प्रशिक्षण मस्थाएँ नवल प्राथमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए थीं। नहुधा शिक्षार्थी प्राथमरी स्कूल पाठ विद्यार्थी हुआ करते थे। पाठ्य क्रम म स्कूल ने विषयों के प्रति विशेष जल दिया जाता था, ताकि शिक्षाधायक इसका उपयोग अपनी शिक्षा-समाप्त व नव स्कूलों म कर सक। उस समय शिक्षण विधि पर विशेष ध्यान न था। शुरू शुरू म शिक्षार्थियों का मानीटर पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में एक उम्मीदवार पद्धति शुरू हुई। इसने अनुसार एक पद शिक्षार्थी को कुछ समय तक एक अनुभवी शिक्षक व निराक्षर में काम करना पड़ता था। उदाहरणार्थ, जेम्स शिक्षा विभाग का तत्कालीन एक आदेश पट्टिए

प्रत्येक ताउका स कुछ विद्याभा चुने जावें। ये तीन वर्षों तक तीन से पाँच रुपये मासिक स्टाइपेंड पर किसी सफल शिक्षक के निरीक्षण में उम्मीदवार की भौति काम करें। तत्पश्चात् वे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल म छ रुपये मासिक स्टाइपेंड पर भरती किये जावें।

अब तक माध्यमिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। नवल दो ट्रेनिंग कालिज स्थापित हुए थे। एक मद्रास में (सन् १८०६) तथा दूसरा, लाहौर में (सन् १८८१)। इनमें स्नातकों और उपस्नातकों को साथ ही प्रशिक्षित किया जाता था। पाठ्यक्रम म स्कूल ने शिक्षणोत्तर विषयों के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता था, किन्तु व्यावसायिक विषयों का विशेष ध्यान न था।

शिक्षक-ट्रेनिंग (१८८२-१९४७)—इस प्रकार शुरू शुरू में ट्रेनिंग म्थाओं व पाठ्यक्रम म अध्यापन विधि का विशय स्थान न था। सन् १८८२ के भारतीय शिक्षा आयोग तथा सन् १९०४ की शिक्षा नीति ने प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण को एक नवीन रूप प्रदान किया। प्रथम निकाय ने सिफागिश की कि नार्मल और ट्रेनिंग मस्थाएँ देश व भिन्न भिन्न भागों म आवश्यकतानुसार स्थापित की जावें। † माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण व लिए आयोग ने प्रस्तावित किया।

† As quoted by Bhagwan Dayal *The Development of Modern Indian Education* Bombay Longmans 1950 p 474

छात्राध्यापक प्रणाली.—इस काल का विस्तार सन् १८०१ से सन् १८८२ तक है। इस अवधि में शिक्षक-प्रशिक्षण को विशेष मान्यता नहीं दी गयी थी। कुछ प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ-वहाँ अवश्य खुले थे, पर ये प्राथमिक शिक्षकों के निमित्त खोले गये थे, तथा अधिकतर ये गैरसरकारी संस्थान थे।

आरम्भ में डेनिश मिशनरी पादरियों ने अपने स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ प्रयत्न किये, तथा श्रीरामपूर में डा० कारे ने एक नार्मल स्कूल स्थापित किया। तत्पश्चात्, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता की शिक्षा-समितियों ने शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की और इसके लिए कुछ केन्द्र खोले। बम्बई रैशनी शिक्षा मण्डल ने २८ प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित किया तथा उन्हें प्रेसीडेन्सी के विभिन्न भागों में प्राथमिक शिक्षण के निरीक्षण के लिए भेजा (सन् १८२६)। मद्रास में सर टामस मनरो ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक केन्द्रीय स्कूल खोला (सन् १८२६)। कलकत्ता में स्थानीय स्कूल-समिति ने एक शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया (सन् १८१९)। तत्पश्चात् कलकत्ता महिला शिक्षा समिति ने भी शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के निमित्त एक दूसरा केन्द्र खोला।

इन गैरसरकारी संस्थाओं के सिवा कुछ सरकारी संस्थाएँ भी स्थापित हुईं। उदाहरणार्थ, बम्बई एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूशन, पूना संस्कृत स्कूल एवं सूरत अंग्रेजी स्कूल में नार्मल बक्षाएँ आरम्भ हुईं। सन् १८४९ में कलकत्ते में एक नार्मल स्कूल स्थापित हुआ, और इसके दस वर्षों के भीतर बंगाल में और भी तीन नार्मल स्कूल खोले गये। उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आगरा, मेरठ तथा बनारस में क्रमशः १८५२, १८५६ तथा १८५७ में नार्मल स्कूल स्थापित हुए।

यूट के घोषणा-पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया। इसने आदेश दिया कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में नार्मल स्कूल खोले जावें।† इस आदेश की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तथा सन् १८५९ के घोषणा पत्र को कहना ही पड़ा कि “कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के निर्देश के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र यथेष्ट संख्या में स्थापित नहीं हुए हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।”‡ सन् १८५९ के पश्चात् निर्मित अनुदान-प्रथा में भी, प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान की

† J. A. Riche. *Selections from Educational Records, Vol II.*
p 38

‡ *Stanley's Despatch.* para 44.

कहा, "प्रशिक्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।"[†] फलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने शिक्षण में अनुसन्धान, प्रशिक्षित शिक्षकों की सख्या-वृद्धि की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने का परामर्श दिया। हार्टग समिति ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जैसे : प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, पुनर्संजीवन कोर्सों का आयोजन, इत्यादि।

उपर्युक्त सुझावों के कारण, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित हुए, प्रशिक्षण-अनुसन्धान डिग्री आरम्भ हुई, ट्रेनिंग सस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हुई तथा पुनर्संजीवन कोर्सों का प्रारम्भ हुआ। देश में तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण सस्थाओं की सृष्टि हुई : (१) स्नातकों के लिए ट्रेनिंग कालिज, (२) उप स्नातकों या मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल तथा (३) प्राथमरी स्कूलों के लिए ट्रेनिंग या नार्मल स्कूल। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था इस देश में अब तक अविदित थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति (सन् १९४७) तक भारत में ३४ शिक्षण महाविद्यालय, ३३९ (पुरुषों के लिए) नार्मल स्कूल तथा १८९ (स्त्रियों के लिए) नार्मल स्कूल खुल चुके थे। इनमें शिक्षार्थियों की सख्या क्रमशः २,४९३, २३,७५४ और १०,१९३ थी।[‡]

शिक्षक-प्रशिक्षण (१९४७-६०) — इस प्रकार शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति सन् १९४७ के पूर्व हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में नये विचार उत्पन्न हुए। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, स्वाधीन भारत में अनेक शिक्षा योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इनको सफलीभूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त रूप में आवश्यकता है। द्वितीयतः, पूर्व स्वातन्त्र्योत्तरकाल की शिक्षा नीति आज नहीं चल सकती है। जन-तान्त्रिक राज्य में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकगण लोक तन्त्रीय गुण तथा पद्धति से सम्पूर्ण रूप में परिचित हों। तृतीयतः, सम्पूर्ण विश्व में शिक्षकों की पूर्व अध्यापन-क्रिया में आमूल परिवर्तन हो रहा है। इसका सम्बन्ध विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन से है। इसकी परिधि कतिपय पाठ्य-पिरियडों तक मर्यादित नहीं रह सकती है। प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मिलियम मिलपेक्टिक ने कहा ही है, "जानवर तथा सर्कस के नट ट्रेण्ड होते हैं, शिक्षकगण प्रशिक्षित होते हैं।"[†]

[†] Government of India's Resolution on Educational Policy, 1913, para 51.

[‡] Progress of Education in India, 1937-47, Vol I, p 31.

‘अध्यापन सिद्धान्त एव प्रयोग’ पर एक परीक्षा आरम्भ की जाय। इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षकगण स्थायी रूप से क्या सरकारी और क्या गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त हों।†

कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि स्नातकों तथा उपस्नातकों का प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार का हो। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत में छः ट्रेनिंग कालिज (मद्रास, लाहौर, राजमहेन्द्री, कुसैयांग, जबलपुर तथा अलाहाबाद) एवं पचास ट्रेनिंग स्कूल माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे। कुछ प्रान्तों ने ‘अध्यापन प्रमाण-पत्र-परीक्षा’ की व्यवस्था भी कर ली थी।

भारत-सरकार की सन् १९०४ की शिक्षा नीति ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर सुचारुरूप से अपना मत व्यक्त किया। शिक्षा-नीति ने प्रस्ताव किया :

१. स्नातक शिक्षकों का कोर्स एक वर्ष का हो तथा प्रशिक्षण समाप्त होने पर सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीय डिग्री या डिप्लोमा मिले। पाठ्यक्रम में त्रैक्षणिक सिद्धान्तों तथा अध्यापन-अभ्यास पर विशेष जोर दिया जाय। उप-स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण कोर्स दो वर्ष का हो। अध्यापन-विधि के अतिरिक्त, इस पाठ्यक्रम में साधारण ज्ञान के प्रति लक्ष्य रहे।

२. शिक्षण-सिद्धान्तों के अध्यापन का अभ्यास के साथ संदिल्लिप्त सम्बन्ध रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बन्धित एक अभ्यास विद्यालय रहे।

३. ट्रेनिंग महाविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे, ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रत्येक शिक्षार्थी महाविद्यालय में सिखाये हुए सिद्धान्तों का यथोचित अभ्यास करे।‡

इस घोषणा के फल-स्वरूप ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई, स्नातकों तथा उपस्नातकों के प्रशिक्षण का स्वतन्त्र-रूप से अलग-अलग आयोजन प्रारम्भ हुआ—स्नातकों के लिए एक-वर्षीय कोर्स तथा उप-स्नातकों के लिए द्वि-वर्षीय कोर्स। इसके साथ-साथ, प्रत्येक ट्रेनिंग संस्था में अभ्यास विद्यालय स्थापित हुए। सन् १९१३ की सरकारी शिक्षा-नीति ने इस कार्य को और भी प्रभावित किया। इस नीति ने स्पष्ट रूप से ही

† Report of the Indian Education Commission. para 2

‡ Government of India's Resolution on Educational Policy, 1904. para 39.

इनका कोर्स एक वर्ष का है तथा इनमें बहुधा मैट्रिक तथा अपर प्रायमरी पास शिक्षाया भरती किये जाते हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता का अभाव का कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में भी समानता नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन मोंटेसरी पद्धति एवं पूर्व प्राथमिक। तिस पर भी पाठ्यक्रम में बहुत कुछ समानता रहती है। मद्रास प्रांत की 'नर्सरी/मोंटेसरी/किंडरगार्टन सर्टिफिकेट पराभा' के लिए निम्न लिखित विषयों के प्रश्न पत्र स्वीकृत हैं (१) मनोविज्ञान, (२) आरोग्य विज्ञान एवं आहार, (३) स्कूल प्रशासन, (४) शिक्षण पद्धति (५) संगीत या चित्रमला या सूत्रा क्रम और हण्डी क्राफ्ट एवं कवायद।[†] इसी प्रकार पूर्व बुनियादी पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विभाग हैं (१) सामाजिक जीवन की व्यवस्था, (२) समाज प्रशिक्षण, (३) शिशु अवलोकन, (४) शिशु शिक्षा का इतिहास, (५) पूर्व बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त एवं ध्येय (६) पूर्व बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, (७) कार्यमाला आयोजन, (८) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (९) सृष्टिबिज्ञान, (१०) भाषा, (११) संगीत तथा ताल, एवं (१२) कला तथा क्राफ्ट।[‡]

गत वर्ष से बड़ीदा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान कालिज ने एक स्नातकोत्तर पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया है। इसका उद्देश्य है निरीक्षक, प्रधानाध्यापक तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए व्यूथ्यापक तैयार करना। सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक 'भारतीय शिशु शिक्षा-समिति' स्थापित की है। इस समिति का उद्देश्य है शिशु शिक्षा के विषय में सलाह देना, तथा देश के विभिन्न भागों में इस शिक्षा में हो रहे कार्यों में एकवृत्तता स्थापित करना।

नार्मल तथा प्रायमरी ट्रेनिंग स्कूल भूमिका हमारे देश में दो प्रकार के प्रायमरी स्कूल हैं। बुनियादी एवं गैर बुनियादी इसीने अनुसार प्रायमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं। सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में, ५८१

† Madras Government Revised Syllabuses for Nursery Montessori Kindergarten Training School Leaving Examinations 1948 p 1

‡ Hindi-stani Talimi Sangh Pre Basic Education 953 p 6

अन्ततः, बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव ने भारतीय शिक्षा-जगत् में एक क्रान्ति उत्पन्न की है। यह नवीन शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन, उनके सम्पूर्ण वातावरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देती है। इस विचार-धारा ने हमारे देश की शिक्षक-प्रशिक्षण पद्धति को एक नया जीवन दिया है। इसके साथ-साथ राधाकृष्णन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कारण यह विचार-धारा और भी प्रभावित हुई है। प्रथम कमीशन ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा कोरी स्कूली पढ़ाई तथा घुटन्त विद्या पर निर्भर नहीं रहती है। इसका सम्बन्ध है दैनिक जीवन तथा आशयपूर्ण कार्य-कलाप से।” † तात्पर्य यह है कि पूर्व-अध्ययन पाठ्यक्रम के सुधार की पर्याप्त चेष्टा हो रही है। इसका ध्येय है, ‘अध्यापक ट्रेनिंग’ से ‘शिक्षक-प्रशिक्षण’ की ओर अग्रसर होगा।

वर्तमान-परिस्थिति

भूमिका.—स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्, इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है। सन् १९४७-४८ में शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं की छात्र-संख्या ४२,१५७ थी; सन् १९५६-५७ में यह संख्या, १,०५,१९४ तक पहुँची गयी। इसी अवधि में खर्च १-१६ करोड़ रुपये से २-६३ करोड़ रुपये बढ़ गया।

आज इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ साधारणतः छः प्रकार की हैं :

- (१) पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- (२) नार्मल या प्रायमरी ट्रेनिंग स्कूल;
- (३) माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल (उपस्नातक शिक्षकों के लिए);
- (४) ट्रेनिंग कालिज (स्नातक शिक्षकों के लिए);
- (५) विशेषज्ञ ट्रेनिंग-केन्द्र; एवं
- (६) शिक्षिका-प्रशिक्षण-संस्थाएँ।

पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र.—वर्तमान समय में इस देश की पूर्व-प्राथमिक-प्रशिक्षण-स्थिति शैशवावस्था में है। सारे देश में केवल २४ पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। इनमें से तीन सरकारी संस्थाएँ हैं, और शेष स्वसञ्चालित हैं। ‡

† *University Education Commission's Report*, p 215

‡ *Report of the All-India Child Education Conference*, 1956

इनका कोस एक वर्ष का है तथा इनमें बहुधा मैट्रिक तथा अपर प्रायमरी पास शिक्षावा भर्ती किये जाते हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता का अभाव का कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में भी समानता नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षार्थियों का प्रशिक्षित करते हैं, जैसे नर्सरी स्कूल, किंडरगार्न मोण्टेसरी पद्धति एवं पूर्व प्राथमिक। तिस पर भी पाठ्यक्रम में बहुत कुछ समानता रहती है। मद्रास प्रान्त की 'नर्सरी/मोण्टेसरी/किण्डरगार्न सर्तीफिकेट पराप्ता' के लिए निम्न लिखित विषयों के प्रश्न पत्र स्वीकृत हैं (१) मनोविज्ञान, (२) आरोग्य विज्ञान एवं आहार, (३) स्कूल प्रशासन, (४) शिक्षण पद्धति (५) संगीत या चित्ररत्न या सूची क्रम और हेण्ड्री क्राफ्ट एवं कव्यायत्। इसी प्रकार पूर्व बुनियादी पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विभाग हैं (१) सामाजिक जीवन की व्यवस्था, (२) समाज प्रशिक्षण, (३) गिण्टु अवलोकन, (४) शिशु शिक्षा का इतिहास, (५) पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त एवं व्यय, (६) पूर्व बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम (७) कार्यकलाप आयोजन, (८) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (९) सृष्टिविज्ञान, (१०) भाषा, (११) संगीत तथा ताल, एवं (१२) कला तथा क्राफ्ट।

गत वर्ष से वलौन विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान कालिज ने एक स्नातकोत्तर पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोस आरम्भ किया है। इसका उद्देश्य है निरीक्षक, प्रधानाध्यापक तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अध्यापक तैयार करना। सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक 'भारतीय शिशु शिक्षा-समिति' स्थापित की है। इस समिति का उद्देश्य है शिशु शिक्षा के विषय में सलाह देना, तथा देश के विभिन्न भागों में इस शिक्षा में हो रहे कार्यों में एकसूत्रता स्थापित करना।

नार्मल तथा प्रायमरी ट्रेनिंग स्कूल भूमिका हमारे देश में दो प्रकार का प्रायमरी स्कूल है। बुनियादी एवं गैर बुनियादी इसी अनुसार प्रायमरी शिक्षक प्रशिक्षण सत्याएँ भी दो प्रकार की हैं। सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में, ५८१

† Madras Government Press Revised Syllabuses for Nursery Montessori Kindergarten Training School Leaving Examinations 1948 p 1

‡ Hindustani Tahim Sangh Pre Basic Education 953 p 6

अन्ततः, बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव ने भारतीय शिक्षा-जगत् में एक क्रान्ति उत्पन्न की है। यह नवीन शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन, उनके सम्पूर्ण वातावरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देती है। इस विचार-धारा ने हमारे देश की शिक्षक-प्रशिक्षण पद्धति को एक नया जीवन दिया है। इसके साथ-साथ राधाकृष्णन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कारण यह विचार-धारा और भी प्रभावित हुई है। प्रथम कमीशन ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा कोरी स्कूली पढ़ाई तथा घुटन्त विद्या पर निर्भर नहीं रहती है। इसका मन्त्र है दैनिक जीवन तथा आगम्यपूर्ण कार्य-कलाप से।” † तात्पर्य यह है कि पूर्व-अध्यापन पाठ्यक्रम के सुधार की पर्याप्त चेष्टा हो रही है। इसका ध्येय है, ‘अध्यापक ट्रेनिंग’ से ‘शिक्षक-प्रशिक्षण’ की ओर अग्रसर होगा।

वर्तमान-परिस्थिति

भूमिका.—स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्, इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है। सन् १९४७-४८ में शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं की छात्र-संख्या ४२,१५७ थी; सन् १९५६-५७ में यह संख्या, १,०५,१९४ तक पहुँची गयी। इसी अवधि में खर्च १-१६ करोड़ रुपये से २-६३ करोड़ रुपये बढ़ गया।

आज इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ साधारणतः छः प्रकार की हैं :

- (१) पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- (२) नार्मल या प्रायमरी ट्रेनिंग स्कूल;
- (३) माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल (उपस्नातक शिक्षकों के लिए);
- (४) ट्रेनिंग कालिज (स्नातक शिक्षकों के लिए);
- (५) विशेषज्ञ ट्रेनिंग-केन्द्र; एवं
- (६) शिक्षिका-प्रशिक्षण-संस्थाएँ।

पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र.—वर्तमान समय में इस देश की पूर्व-प्राथमिक-प्रशिक्षण-स्थिति शैशवावस्था में है। सारे देश में केवल २४ पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। इनमें से तीन सरकारी संस्थाएँ हैं, और शेष स्वसञ्चालित हैं। ‡

† *University Education Commission's Report*, p 215

‡ *Report of the All-India Child Education Conference* 1956

बुनियादी पाठ्यक्रम — बुनियादी पाठ्यक्रम में नयी तालीम के निम्नलिखित आदर्शों की ओर लक्ष्य रहता है

१. सामाजिक जीवन में शिक्षार्थियों को भाग लेना तथा उन्हें मिलनसार बनाना,

२. उन्हें नयी तालीम के सामाजिक आदर्शों का तथा शिक्षा के साथ सत्य एवं अहिंसा के सम्बन्ध का परिचय कराना,

३. शिक्षार्थी के आचारिक, नैतिक, नैतिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करना, ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, एवं

४. उसे अपने व्यावसायिक क्षेत्र के लिए तैयार करना, ताकि वह बच्चों के शारीरिक, नैतिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ सके।†

कुछ राज्य तो हिन्दुस्तानी तालीम के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, और कुछने इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया है। नीचे ब्रम्हई राज्य के प्राथमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम दिया जाता है

पहला ग्रूप (क्राफ्ट)—३०० गुण (१) तीन बुनियादी क्राफ्ट (कताई, कृषि, लकड़ी का काम) एवं (२) चार सहायक क्राफ्ट (कताई, बागजानी, दफ्तरीगिरी, गृह क्राफ्ट)। — प्रत्येक विद्यार्थी को एक बुनियादी क्राफ्ट और इसे छोड़कर दो और कोई सहायक क्राफ्ट लेना पड़ता है। महिलाओं के लिए गृह क्राफ्ट एक अनिवार्य विषय है।

दूसरा ग्रूप (शिक्षा)—(अ) लिखित परीक्षा (१५० गुण)—तीन पत्रों (१) शिक्षण सिद्धान्त, (२) स्कूल-व्यवस्था एवं प्रबन्ध, (३) अध्यापन विधि एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास (१५० गुण—१०० गुण समूचे वर्ष के कार्य के लिए एवं ५० गुण अन्तिम पाठ के निमित्त)। वर्ष के कार्य में शामिल हैं—(१) २० समवाय पाठ, (२) ५० पाठों का अवलोकन, (३)

† Hindustani Talimi Singh Revised Syllabus of the Training of Teachers 1952 pp 8-9

बुनियादी तथा ३३५ गैर-बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र थे।† सभी राज्यों में गैरबुनियादी संस्थाओं को बुनियादी रूप देने की चेष्टा की जा रही है।

सर्टीफिकेट-व्यवस्था.—दोनों प्रकार के केन्द्रों में दो प्रकार के सर्टीफिकेट की व्यवस्था है : (१) अपर-प्राथमरी पास शिक्षार्थियों के लिए एवं (२) मैट्रिक शिक्षार्थियों के लिए। प्रथम वर्ग के शिक्षार्थियों को 'अवर शिक्षक सर्टीफिकेट' तथा द्वितीय वर्ग के विद्यार्थियों को 'प्रवर शिक्षक सर्टीफिकेट' मिलता है। दोनों कोसों की अवधि दो वर्ष की होती है।

गैर-बुनियादी पाठ्यक्रम.—प्रत्येक राज्य के पाठ्य क्रम में कुछ-न-कुछ विशिष्टता रहती है। पंजाब राज्य की 'अवर सर्टीफिकेट परीक्षा' के पाठ्य-क्रम का विवरण नीचे दिया गया है :

- (अ) लिखित कार्य : छः पंचे : (१) एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, हिन्दी या पंजाबी), (२) शिक्षण पद्धति १ — (भाषा एवं गणित), (३) शिक्षण-पद्धति २—(सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र तथा दैनिक विज्ञान), (४) कक्षा-प्रबन्ध, (५) शिक्षा-सिद्धान्त एवं शिक्षा-मनोविज्ञान, तथा (६) हिन्दी या पंजाबी (वह भाषा जो पहले प्रश्न-पत्र में न ली गयी हो)।
 (आ) अध्यापन-अभ्यास तथा मौखिक कार्य : (१) भाषा, भूगोल या कृषि एवं दैनिक विज्ञान, (२) दो हेण्डी-क्राफ्ट (प्रत्येक विभाग से एक) — प्रथम विभाग — लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, ज़िल्द-साजी, बुनाई, कुक्कुट-पालन, चित्रकारी एवं रेखा-चित्र; तथा द्वितीय विभाग—ईंट बनाना, टोकनी बुनना, दफ्ती का काम, साबुन-निर्माण, स्याही बनाना, छींट की छपाई, कसरत, फर्स्ट एड एवं स्काउटिंग।

प्रवर परीक्षा के पाठ्यक्रम की रूप-रेखा भी इसी प्रकार है, पर स्वाभाविक ही यह कार्य अधिकतर गुप्तवर्ण होता है। अन्तर केवल इन मद्रों पर है : (१) दूसरे पंचे में बीजगणित तथा रेखागणित शामिल हैं, (२) चौथे पंचे में क्लास-प्रबन्ध के अतिरिक्त स्कूल-व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, (३) हेण्डी-क्राफ्ट-शिक्षा में ये विषय शामिल हैं — कुक्कुट-पालन, राजगिरी, चर्मकारी, धातु-कार्य, रँगरेजी, फल तथा सब्जी-परिरक्षण, रस्सी बौटना, टाट बनाना, रेशम के कीड़े पालना, मसुमकली-पालन, मसु-पालन।

ट्रेनिंग कालिज.—छात्रक शिक्षकगण ट्रेनिंग कालिजों में प्रशिक्षित होते हैं। ये संस्थाएँ दो प्रकार की हैं : बुनियादी एवं गैरबुनियादी। सन् १९५६-५७ में बुनियादी कालिजों की संख्या ३३ थी तथा गैरबुनियादी कालिजों की १००। इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,४६९ तथा १२,६४७ थी। अधिकतर संस्थाएँ राजकीय हैं। कतिपय संस्थाएँ आर्ट्स एव साइन्स कालिज चलाते हैं; और कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभाग हैं, जैसे : अलीगढ़, अलाहाबाद, अनामलाय, बड़ौदा, बनारस, गौहाटी, कलकत्ता, ओस्मानिया, लखनऊ, गोरखपुर, नागपुर, लखनऊ एव पटना।

गैरबुनियादी संस्थाएँ.—इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होती है, तथा इनके सफलीभूत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीय या राज्यीय शिक्षा-विभाग के नियमों के अनुसार बी० टी०, बी० एड०, एल० टी० या डिप० एड० डिग्री मिलनी है।

पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित होता है : (अ) सैद्धान्तिक (पाँच पच्चे) : (१) शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, (२) शिक्षा-सिद्धान्त, (३) स्कूल-प्रशासन एवं आरोग्यशास्त्र, (४) अध्यापन-विधि, (५) शिक्षा-इतिहास तथा वर्तमान शिक्षा-समस्याएँ; और (आ) अध्यापन-अभ्यास।

बुनियादी संस्थाएँ.—बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव के साथ-साथ बुनियादी प्रशिक्षण कालिज स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों के लिए निरीक्षक एवं बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों के लिए अव्यापक तैयार करना। इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम एक-सा नहीं है। प्रत्येक राज्य अपना-अपना पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस विषयता को दूर करने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग कालिजों के प्रिंसिपलों की एक समिति ने अधोलिखित पाठ्यक्रम की सिफारिश की है :

१. प्रश्न-पत्र : (१) शिक्षण तत्वज्ञान एवं समाजशास्त्र (विशेषकर बुनियादी शिक्षा सम्पर्कित), (२) शिक्षा-मनोविज्ञान, (३) शिक्षण-प्रशासन एवं निरीक्षण, या प्रयोगिक शिक्षा एवं शिक्षण अनुसन्धान विधि, (४) बुनियादी शिक्षा विधि तथा (५) क्राफ्ट शिक्षा—सिद्धान्त एवं अभ्यास।

२. क्राफ्ट : (अ) मुख्य बुनियादी क्राफ्ट (कोई भी एक)—(१) कृषि (पशु-पालन-सहित), (२) बुनाई एवं कताई, (३) दफ्तरीगिरी, लकड़ी का काम एवं सम्बन्धित धातु कार्य; और (आ) सहायक क्राफ्ट (कोई

† *Education in the States, 1956-57. pp 3 4*

किसी बुनियादी स्कूल में एक सप्ताह का लगातार अध्यापन-अभ्यास, (४) तीन अपवर्त्य पाठ, (५) दो शिक्षण-साधनों की तैयारी ।

तीसरा ग्रूप (साहित्यिक विषय) : ३०० गुण—छ : पंचे—
 (१) क्षेत्रीय भाषा १ (पाठ्य पुस्तक) (२) क्षेत्रीय भाषा २ (साधारण),
 (३) हिन्दी, (४) समाजशास्त्र, (५) साधारण विज्ञान एवं (६) साधारण
 गणित या एक सांस्कृतिक भाषा ।

चौथा ग्रूप (सामाजिक अनुभव) १०० गुण—इस ग्रूप की कोई परीक्षा नहीं है । गुण पूरे वर्ष के कार्य पर दिये जाते हैं । इसमें शामिल हैं स्वास्थ्य-अभ्यास तथा कालिज एवं अभ्यास-विद्यालय के सामाजिक जीवन में भाग-ग्रहण ।

अब एव प्रवर परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एकसा है । केवल ग्रूप तीन का पाठ्यक्रम प्रवर विद्यार्थियों के लिए उच्चतर होता है ।

माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल—मिडिल स्कूलों के शिक्षणगण अधिकतर मैट्रिक या इण्टरमीडिएट पास होते हैं । ये माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षित होते हैं । इनका कोर्स एक या दो वर्ष का होता है, एवं सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्व विद्यालय या शिक्षा-विभाग से डिप्लोमा मिलता है । उदाहरण-स्वरूप, बड़ौदा, बम्बई, गुजरात, पूना, कर्नाटक, नागपुर, सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालयों में उप-स्नातक शिक्षकों के लिए टी० डी० (प्रथम पाँच विश्वविद्यालय) या डिप० टी० (अन्तिम तीन विश्वविद्यालय) कोर्स की व्यवस्था है । टी० डी० कोर्स की अवधि एक वर्ष की होती है । इसमें तीन वर्ष के अनुभव-प्राप्ति शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के प्रथम वर्षीय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रगण भरती हो सकते हैं । डिप० टी० कोर्स में उप-स्नातक लिये जाते हैं । इसकी अवधि दो वर्षों की है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक वर्षीय एल० टी० कोर्स चालू है, जिसमें इण्टरमीडिएट पास शिक्षार्थी भरती होते हैं । इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, प्रायः सभी राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग उप-स्नातक शिक्षकों के लिए स्वतः पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा परीक्षाएँ चलाते हैं ।

राज्य-शिक्षा-विभागीय या विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में समानता नहीं है, पर टॉचा प्रायः एक-सा है । इसके मुख्य दो भाग हैं : (अ) सैद्धान्तिक कार्य (चार पंचे)—
 (१) शिक्षा-मनोविज्ञान, (२) शिक्षण-सिद्धान्त, (३) अध्यापन-विधि और (४) स्कूल-प्रबन्ध तथा आरोग्य-शास्त्र; एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास ।

ललित कला.—कतिपय केन्द्रों को छोड़कर, इस महत्त्वपूर्ण विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध हमारे देश में नहीं है। कुछ मुख्य संस्थाएँ ये हैं : (१) विश्व-भारती (संगीत, नृत्य तथा चित्रकला), (२) सर जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, बम्बई (चित्रकारी), (३) ललित कला फेकल्टी, बडौदा विश्वविद्यालय (चित्रकला और संगीत), (४) कला-क्षेत्र, अडयार, मद्रास (नृत्य), (५) संगीत शिक्षण महाविद्यालय, मद्रास (संगीत), (६) राजकीय आर्ट्स स्कूल, लगनऊ (कला), (७) आर्ट प्रशिक्षण संस्था, जामिया मिलिया, दिल्ली (आर्ट एव क्राफ्ट)।

गृह विज्ञान.—माध्यमिक स्कूलों के लिए अनेक गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध निम्न लिखित संस्थाओं में है : लेडी इरविन कालिज, दिल्ली; एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय बम्बई; गृह-विज्ञान फेकल्टी, बडौदा; राजकीय गृह-विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलाहाबाद; इत्यादि।

क्राफ्ट.—आज मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम में क्राफ्ट एक अनिवार्य विषय है। इस कारण, क्राफ्ट शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है। प्रायः सभी राज्यों ने अपने प्राविधिक हाईस्कूलों तथा क्राफ्ट स्कूलों में इन शिक्षकों के प्रशिक्षण का बन्दोबस्त किया है।

विविध विषय.—अनेक राज्यीय शिक्षा विभाग तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय कतिपय विशेष विषयों का कोर्स चलाते हैं। मुख्य विषय हैं : अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा अर्थात् हिन्दी, भूगोल, निर्देश तथा परामर्श। बहुधा ये कोर्स एक-वर्षीय होते हैं।

शिक्षिका प्रशिक्षण संस्थाएँ.—शिक्षिकाएँ स्त्री अध्यापन संस्थाओं तथा पुरुष महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होती हैं। सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में ३१ स्त्री अध्यापन कालिज (एक बुनियादी तथा तीस गैर-बुनियादी) तथा २५८ स्कूल (१४६ बुनियादी एव १४२ गैरबुनियादी) थे। इस वर्ष कालिजों की छात्रा-संख्या थी ४,५६१ (बुनियादी ४०७ एव गैरबुनियादी ४,१५४), और स्कूलों की छात्रा-संख्या २५,९१४ (बुनियादी १३,३६४ एव गैरबुनियादी १२,५५०) थी।†

अनुसन्धान एवं उत्तर स्नातक कार्य

उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य इस देश में हाल ही में आरम्भ हुआ है। यह पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता है : (१) एम० ए० (शिक्षा) या एम० ईडी०

† *Education in States, 1956-57, p p 3-5*

भी एक) — (१) गृह-निर्माण, (२) कताई (यदि यह मुख्य क्राफ्ट न हो), (३) सब्जी की बागवानी (यदि कृषि मुख्य क्राफ्ट न हो), (४) चमड़े का काम, (५) मधु-मक्खली पालन, (६) कुम्हार काम ।

३. अध्यापन-अभ्यास — (१) अभ्यास-योजना रचना, (२) किसी स्कूल कक्षा के उपयुक्त निर्वाचित विषयों का योग्यता-परीक्षण निर्माण, (३) वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों का परिचालन, (४) अपने अभ्यास पाठों के विषयों पर शिक्षा-साधन तैयार करना, (५) बुनियादी स्कूलों से सम्बन्धित समुन्नत सामग्री-निर्माण । †

यह याद रहे कि इने-गिने दो-चार विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बुनियादी उत्तर-स्नातक-डिप्लोमा का परिचालन राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग ही करते हैं । इस कारण, ऐसे डिप्लोमा धारी व्यक्तियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । बहुधा ये विश्वविद्यालयीय उत्तर-स्नातक कोर्सों में भरती नहीं हो सकते हैं । इस कारण, बुनियादी अनुमान-निर्धारण-समिति ने प्रस्ताव किया है कि विश्वविद्यालय भी बुनियादी महाविद्यालय चलावें तथा उत्तर-स्नातक बुनियादी डिप्लोमा को मान्यता दें । 'केसशिप' ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

विशेषज्ञ प्रशिक्षण-केन्द्र. — विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए भी आयोजन किया गया है । ये क्षेत्र हैं : शारीरिक शिक्षा, ललित कला, गृह-विज्ञान, क्राफ्ट एवं विविध विषय ।

शारीरिक शिक्षा — शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण कालिजों में स्नातकों को तथा स्कूलों में उप-स्नातकों को मिलता है । सम्पूर्ण देश में केवल बीस केन्द्र हैं, जो यह शिक्षा देते हैं । इनका कोर्स एक-वर्षीय होता है, तथा डिप्लोमा का सर्टीफिकेट संस्था या राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग से मिलता है । अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था नहीं है ।

३० जून १९५७ को केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर में लक्ष्मीनार्द शारीरिक महा-विद्यालय की स्थापना की है । भारत में यह सर्व प्रथम संस्था है, जिसने शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स आरम्भ किया है । आशा की जाती है कि भविष्य में यह कालिज अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा ।

† Ministry of Education. *The Five Year Plan : Schemes of Educational Developments*. pp. 4-5.

मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण

भूमिका.—प्रशिक्षण के दो रूप हैं : (१) 'पूर्व अध्यापन प्रशिक्षण' अर्थात् किसी प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से पूर्णकालिक ट्रेनिंग। हम इन कोर्सों की चर्चा इस अध्याय के द्वितीय शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में इस ट्रेनिंग का नामकरण 'पूर्व अध्यापन प्रशिक्षण' किया गया है। कारण, वहाँ पर पूर्व-कालिक प्रशिक्षण पाये बिना कोई भी व्यक्ति अध्यापन-कार्य आरम्भ नहीं कर सकता है। (२) 'मध्य अध्यापन प्रशिक्षण'—पूर्व अध्यापन प्रशिक्षण ने पश्चात् एक व्यक्ति शिक्षक बनता है। पर कुछ समय के बाद, उसके पूर्वार्जित ज्ञान में मोरचा लय जाता है। अध्यापन कार्य करते हुए, नवीन ज्ञान से सम्पर्क न रखने के कारण ही बहुधा ऐसा होता है। इस असम्पर्क के फल-स्वरूप अध्यापन कार्य ठीक ठीक नहीं चल सकता है। माध्यमिक आयोग ने कहा ही है।

चाहे कितना ही अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो, पर इससे उत्कृष्ट परिणाम नहीं निकलता है। इसके द्वारा शिक्षक को वह ज्ञान मिलता है, जो एक नौसिखिए को जरूरी रहता है। इससे उसका आत्म विश्वास बढ़ता है। कार्य क्षमता तभी बढ़ती है जब कि कुछ अनुभव के पश्चात् शिक्षक स्वतः या समुदाय में उन्नति की चेष्टा करे। अतएव शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों को मध्य अध्यापन प्रशिक्षण का समुचित आयोजन करना चाहिए।†

पूर्व चेष्टाएँ.—यह न सोचना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रशिक्षण की कुछ भी व्यवस्था न थी। समय-समय पर राज्यीय शिक्षा विभाग तथा कतिपय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ कई प्रकार की योजनाएँ चलाती थीं, जैसे . (१) पुनर्संजीवन कोर्स, (२) कर्म शालाएँ, (३) विशिष्ट विषयों के अल्प कालिक कोर्स तथा (४) प्रशिक्षित शिक्षकों की गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन। किन्तु इन कार्य कलापों की व्यवस्था समुचित न थी।

ट्रेनिंग कालिज प्रसारण केन्द्र.—माध्यमिक शिक्षा आयोग के निरीक्षण की ओर केन्द्रीय तथा फोर्ड फाउण्डेशन का ध्यान आकर्षित हुआ, और उनकी चेष्टाओं के कारण, हमारे कुछ ट्रेनिंग कालिजों में, प्रसारण केन्द्र स्थापित हुए — १९५५ में २४ केन्द्र, १९५६ में १७ और भी अधिक केन्द्र, एवं १९५७ में १२ अतिरिक्त केन्द्र। इस प्रकार की मध्य अध्यापन प्रशिक्षण की योजना विश्व के किसी भी देश में

† Secondary Education Commission's Report p 178

(बी० टी० या बी० एड० के पश्चात् एक या दो वर्षीय कोर्स), एवं (२) पी० एच० डी० (एम० ए० या एम० ईडी०) के बाद दो वर्ष का कोर्स ।

एम० ए० (शिक्षा) की व्यवस्था केवल कलकत्ता एवं गौहाटी विश्वविद्यालयों में है तथा एम० ईडी० की अन्य विश्वविद्यालयों — अलीगढ़, अलाहाबाद, बनारस, बड़ौदा, बम्बई, दिल्ली, मोरारपुर, गुजरात, जवल्पुर, कर्नाटक, केरल, लखनऊ, मद्रास, मैसूर, नागपुर, ओस्मानिया, पंजाब, पटना, पूना, राजस्थान, एस० एन० डी० टी०, सागर, उत्कल एवं विक्रम में है। दोनों परीक्षाओं के नामकरण में अवश्य भेद है, पर पाठ्यक्रम प्रायः एक-सा है। इन परीक्षाओं के लिए चार से छः पर्चे होते हैं। किसी-किसी विश्वविद्यालय में, इसके साथ-साथ या कुछ निश्चित पर्चों के बदले एक निबन्ध लिखना पड़ता है। बड़ौदा, गुजरात, पूना, बम्बई, कर्नाटक एवं सागर विश्वविद्यालय एक दूसरा एम० एडी० कोर्स भी चलाते हैं, जिसके लिए परीक्षार्थियों को केवल एक महा निबन्ध प्रस्तुत करना पड़ता है।

पी० एच० डी० या डाक्टरेट परीक्षा के लिए भी एक महा निबन्ध लिखना पड़ता है। इसका गवेषणात्मक तथा प्रयोगात्मक कार्य उच्च कोटि का होना चाहिए। पर बहुधा यह कार्य इस स्तर का नहीं होता है।

यह गैर-बुनियादी प्रशिक्षण की स्थिति हुई। उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी तक विशेष रूप से नहीं की गयी है। कतिपय बुनियादी अध्यापन महाविद्यालय अवश्य कुछ अनुसन्धान योजनाएँ चला रहे हैं। बुनियादी शिक्षा पर गवेषणा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बुनियादी अनुसन्धान-केन्द्र की स्थापना दिल्ली में की है।

सन् १९५३-५४ से भारत-सरकार ने शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षण-विभागों को अनुसन्धान योजनाएँ चलाने के लिए अनुदान देना आरम्भ किया है, ताकि अर्थाभाव के कारण शोध-कार्य बन्द न रखना पड़े। प्रत्येक योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से लेनी पड़ती है। संस्था के प्राध्यापकों के निरीक्षण में आवश्यकतानुसार कई शोध-शिष्य अनुसन्धान-कार्य करते हैं। साधन-उपकरणों के लिए भी अनुदान मिलता है। सन् १९५६-५७ के अन्त तक २९ शोध-योजनाएँ स्वीकृत हुई थीं, एवं कुल २,०५,००० रुपये व्यय हुए थे।†

† *Ten Years of Freedom*, p. 58.

सम्भवतः अभी तक चलाई नहीं गयी है। फोर्ड फाउण्डेशन इस योजना को आर्थिक साहाय्य—अनुदान—देता है, एवं अमेरिकी टेकनीकल कोआपरेशन मिशन शिक्षण साधन भेंट करती है।

प्रमाण-केन्द्रों के कार्य कलाओं की यह रूप रेखा है : (१) अल्प कालिक, दीर्घ कालिक तथा सप्ताहान्त कांस, (२) कर्म शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं समूह-चर्चा, (३) शैक्षणिक सप्ताह तथा प्रदर्शनी, (४) परामर्श तथा निर्देश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तकालयीय सुविधाएँ, (६) श्रव्य दृश्य माध्यमों की सहायता एवं (७) प्रकाशन।†

विशिष्ट गोष्ठियाँ—प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षण मन्त्रालय समय समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण प्रशासकों की गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशासकों को एकत्र करना, तथा शिक्षा के उन पेंचीदे—उलझन पूर्ण—प्रश्नों की चर्चा करना, जिससे अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके। अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं। विशेष विषयों की चर्चा के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी ग्यारह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विज्ञान, समाज शास्त्र, अंग्रेजी अध्यापन, प्रशासन इत्यादि विशद विषयों की चर्चा की गयी है। इनके अतिरिक्त परीक्षा सुधार के लिए सात कर्म शालाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ हुआ है।

शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ

भूमिका.—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में शिक्षक प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है, तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ साथ अध्यापन के नये पेंचीदे प्रश्न लगे हो रहे हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत दस प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की जायगी। हमें इस बात से दाढ़स होता है कि आज शिक्षा जगत् इन मामलों से सुपरिचित है।

नवीन विचार-धारा.—आजकल इस देश में शिक्षा की यथेष्ट प्रगति हो रही है, और सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि “यह नूतन शिक्षण केवल शिष्टाचारिक अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अपितु इसका सयोग मानवीय जीवन के दैनिक

† Second Seminar on Extension in Training Colleges Srinagar, June/July 1955



प्रशिक्षण महाविद्यालय

अल्पकालिक कोर्स

दीर्घकालिक कोर्स

कर्मशाखाएँ

गोष्ठियाँ

शैक्षणिक सप्ताह

प्रदर्शनी

परामर्श तथा निर्देश

पुस्तकालय सुभीते

श्रव्य-दृश्य उपकरण

प्रकाशन



माध्यमिक स्कूलें

अभ्यास की संकीर्णता की ओर आवर्तित हुआ था। इसी कारण समिति ने अभ्यापन-अभ्यास को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश की थी। इस ओर चेष्टा भी हो रही है, पर यह काम यथा-रीति नहीं हो सक रहा है। कारण, बी० एड० प्रशिक्षण का कार्य काल फेवल नौ महीने ही है। इस कठिनाई को समझते हुए, समिति ने सैद्धान्तिक फोर्स बहुत कुछ कम कर दिया है।

परन्तु अभ्यापन अभ्यास ठीक तौर से तभी दिया जा सकता है, जब कि ट्रेनिंग कालिज का प्रत्येक विद्यार्थी कुछ समय तक किसी स्कूल में पद-विद्यार्थी के रूप में काम करे, वह स्कूल-कार्य में भाग ले, विद्यार्थियों का गृह-कार्य-संशोधन करे, रजन कार्य-परिचालन करे, भव्य-दृश्य-उपकरण तैयार करे, स्थानिक समाज के सम्पर्क में आवे, इत्यादि। यह अभ्यास दो से चार सप्ताह तक किसी अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में दिया जाय। सब से अच्छा तो यह है कि इस कार्य के लिए ग्राम्य स्कूल-मुने जायें, ताकि शिक्षार्थी, देहात के सम्पर्क में आ सकें।

तीन-वर्षीय शिक्षा-स्नातक फोर्स.—बी० एड० फोर्स अल्प कालिक होने के कारण, थोड़े समय में शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में बहुत कुछ ठूसना पड़ता है। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने इस फोर्स की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का सुझाव दिया था, किन्तु शिक्षकों की कमी को देखते हुए आयोग को पीछे हटना पड़ा। उसने अंगीकार किया कि 'प्रशिक्षण के लिए हम शिक्षार्थियों को दो वर्ष रोक नहीं सकते हैं।'

एक और सुझाव दिया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् एक तीन-वर्षीय शिक्षा स्नातक फोर्स शुरू किया जावे। इसके अन्तर्गत सांस्कृतिक ज्ञान के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण का बी० एड० स्तरीय ज्ञान दिया जावे। जिस प्रकार कृषि या वाणिज्य की व्यवस्था बी० एजी० या बी० काम० फोर्स में की गयी है, उसी प्रकार 'शिक्षा' का अभ्यापन प्रस्तावित पाठ्यक्रम में किया जा सकता है। इस सुधार से दो मुख्य लाभों की सम्भावना है। प्रथमतः, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक ज्ञान का घना सम्बन्ध रहेगा। द्वितीयतः, शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि दीर्घतर होने के कारण, शिक्षा का ज्ञान एक विस्तृत समय में फैलाया जा सकेगा। इस विषय पर प्रथम अखिल भारतीय ट्रेनिंग कालिज सम्मेलन में विषय रूप से चर्चा हुई थी। कतिपय विश्वविद्यालय प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सोच-विचार कर रहे हैं। यह योजना कुछ नवीन

एकही प्रकार के उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें दोनों प्रणालियों के विशेष गुणों का समावेश हो। सम्मेलन ने फैसला किया कि यह एकीकरण दो उपायों से हो सकता है :

१. बी० एड० के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के बोझ को कुछ कम करना, तथा उसमें नियमित रूप से सुधार करना; एवं

२. अध्यापन-अभ्यास का प्रसार करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को क्राफ्ट, सामाजिक जीवन एवं समवाय-शिक्षा का ज्ञान मिले।†

परिवर्तित बी० ए० पाठ्यक्रम में इस ओर अवश्य लक्ष्य रखा गया है, पर पूर्ण रूप से नहीं। दो-एक ट्रेनिंग कालिज इस ओर चेष्टा कर रहे हैं। उदाहरण-स्वरूप, विश्व-भारती के विनय-भवन (ट्रेनिंग-कालिज) में एक पाठ्यक्रम प्रचलित है, जिसकी अवधि साधारण बी० एड० की अवधि से कुछ अधिक है। इस पाठ्यक्रम में बुनियादी और गैर-बुनियादी सिद्धान्तों का समावेश है। इसी प्रकार का एक प्रयोग विद्या-भवन, उदयपुर भी कर रहा है।

बी० एड० अध्यापन-अभ्यास में विस्तीर्णता.—अभी तक बी० टी० या बी० एड० अभ्यास के अन्तर्गत, प्रत्येक शिक्षार्थी को कुछ स्थिर पाठ पढ़ाना पड़ता है। आजकल इस पद्धति की काफी नुकता-चीनी हो रही है, क्योंकि इसका दृष्टि-कोण अति सकीर्ण है। आधुनिक शिक्षक का कर्तव्य केवल स्कूल पाठों तक ही मर्यादित नहीं होता है, बल्कि उसे स्कूल के खेल-कूद में भाग लेना पड़ता है, श्रव्य-दृश्य शिक्षा-साधनों का विशद रूप में उपयोग करना पड़ता है, आधुनिक वस्तुगत परीक्षाओं को समझना पड़ता है, विद्यार्थियों की उन्नति-विषयक रिकार्ड रखने पड़ते हैं तथा समाज के साथ मिल-जुल कर रहना पड़ता है। इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि शिक्षार्थियों को देहाती स्कूलों का कुछ भी अनुभव नहीं मिलता, जहाँ कि अधिकांश व्यक्तियों को अपने ट्रेनिंग के समाप्त होने पर काम करना है। इसी कारण, बुनियादी अध्यापन-अभ्यास (उत्तर-स्नातक डिप्लोमा) का क्षेत्र दृष्टि विस्तृत रखा गया है, तथा समाज एवं देहातों से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए 'सपन क्षेत्र' (काम्पैन्ट एरिया) में कुछ समय तक लगातार अध्यापन-अभ्यास का कन्शेवस्त रखा गया है। बी० एड० पाठ्यक्रम-सुधार-समिति का भी ध्यान प्रचलित अध्यापन-

† *Journal of Education and Psychology*. January, 1955. p. 234.

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा-क्षेत्र के उपयुक्त उच्च स्तर के शिक्षक, प्रशासक तथा ट्रेनिंग कालिजों के अध्यापक तैयार करना। इस परीक्षा के तीन मुख्य भाग हों : (१) अनिवार्य—(अ) शिक्षण तत्व ज्ञान, पाठ्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान, विभिन्न देशों के आधुनिक शिक्षण-विधि तथा शिक्षा-प्रशासन नियमों का तुलनात्मक ज्ञान, (आ) शैक्षणिक सांख्यिकी एवं अनुसन्धान विधि; (२) वैकल्पिक— किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान तथा उसीसे सम्बन्धित किसी प्रसंग पर एक निबन्ध; एवं (३) मौखिक परीक्षा।

अनिवार्य विभाग का उद्देश्य हो शिक्षार्थी को शिक्षा के समूचे क्षेत्रों का दिग्दर्शन कराना, पर वैकल्पिक विभाग का लक्ष्य रहे कि उसे एक चुने हुए विषय का विशेषज्ञ बनाना तथा अनुसन्धान करने के पश्चात् अपने विचारों को विधिबद्ध निबन्ध रूप में प्रकट करना। मौखिक परीक्षा का अभिप्राय है, शिक्षार्थी की समझ की जाँच करना, जो कि लिखित परीक्षा-द्वारा कमी नहीं हो सकती है। वैकल्पिक विभाग में कतिपय नये विषयों का समावेश हो, जैसे : पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा, प्रसारण-कार्य, शिक्षक प्रशिक्षण, निर्देश एवं परामर्श, किसी विशेष पाठ्य-विषय की शिक्षण-विधि, विश्वविद्यालय में सामान्य ज्ञान, इत्यादि।

कालिज अध्यापकों की तैयारी.—यह देखा गया है कि शिक्षण-विधि के ज्ञान के अभाव के कारण अनेक कालिज अध्यापकों का अध्यापन सफलीभूत नहीं हो पाता है। इस कारण, उनकी पढ़ाई नीरस हो जाती है। इस विषय की चर्चा, एक वार्ड्स-चान्सेलर के सम्मेलन में की गई थी। सम्मेलन ने अनुभव किया कि कालिज के नये अध्यापकों को शिक्षा-विधि के मूल तत्वों का दिग्दर्शन कराया जावे।† ये विषय हैं : (१) अपने विषय का यथोचित ज्ञान तथा इसे सुव्यवस्थित रूप में समझाना, (२) स्पष्ट भाषण, (३) सुचारुरूप से समझाने की शक्ति, (४) विद्यार्थियों में नवीन विचारों का प्रोत्साहन एवं (५) उनमें ज्ञान-पिपासा की वृद्धि।

इस विषय पर संयुक्त-राज्य अमेरिका में बहुत कुछ बहस हुई। अन्त में बहुमत से स्वीकार किया गया कि कालिज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी शिक्षा-पद्धति जानना आवश्यक है। इसके ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि रोचक बन जाती है। आज अमेरिका के कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में निम्न-लिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है : (१) वक्तृता-प्रणाली, (२) चर्चा विधि, (३) प्रायोगिक पद्धति, (४) श्रव्य और दृश्य साधनों का उपयोग, एवं

नहीं है। यह अमेरिका में प्रचलित है तथा कुछ अंग्रेजी विश्वविद्यालयों ने भी इसे आरम्भ किया है।

बहुद्देशीय स्कूलों के ट्रेण्ड शिक्षक.—हमारे नये बहुद्देशीय स्कूलों के लिए, कई विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है—प्राविधिक, कृषि, ललित कला, वाणिज्य एवं गृह-विज्ञान। प्रथमतः, इन क्षेत्रों के शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। द्वितीयतः, इनके प्रशिक्षण का कुछ भी बन्दोबस्त आज तक इस देश में नहीं है।

ट्रेनिंग की सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हमारे प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में इन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के केवल दो उपाय हैं : (१) इन विशिष्ट क्षेत्रों के कुछ कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हो, या (२) कुछ प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में एक/अधिक विशिष्ट विषय का/के विभाग खोले जायँ। दोनों प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा तथा विशिष्ट क्षेत्र के अध्यापकगण कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करेंगे—शिक्षा-शास्त्री अध्यापन-विधि की ओर ध्यान देगा एवं वैशिष्ट्यपूर्ण विशिष्ट विषय ज्ञान पर।

गत वर्ष, राज्यीय शिक्षा-मन्त्रियों के एक सम्मेलन में यह तय हुआ कि चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र इस कार्य के लिए स्थापित हों (२ जुलाई, १९५९)। पर ऐसे केन्द्र जल्दी खोले नहीं जा सकते। हमें उपर्युक्त किसी भी एक तरीके को अपनाना पड़ेगा—या, कुछ ट्रेनिंग कालिजों में विशिष्ट क्षेत्रों के विभाग खोले जाएँ; या, कतिपय व्यावसायिक कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हों।

माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल.—माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों का कोर्स कहीं एक वर्ष की अवधि का है और कहीं दो वर्ष का है। यह कोर्स सभी राज्यों में दो वर्ष का किया जाय, ताकि एक-रूपता आवे तथा ट्रेनिंग सुचारु रूप से दिया जा सके—प्रथम वर्ष में साधारण ज्ञान एवं द्वितीय वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा। अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त, प्रत्येक शिक्षार्थी कम-से-कम एक क्षेत्र में विशेषता लाने करे : (१) पूर्व प्राथमिक शिक्षा, (२) क्राफ्ट शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा-आयोग-द्वारा प्रस्तावित एक क्राफ्ट)† (३) शारीरिक शिक्षा एवं (४) कला तथा संगीत।

उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम.—एम० एड० पाठ्यक्रम के सुधार की भी विशेष जरूरत है। बहुधा देखा जाता है कि ये बी० एड० कोर्स के विस्तारित संस्करण हैं।

† देखिए पृष्ठ १२०।

हमारे शोध कार्य में भी एक सुगुणला की आवश्यकता है। कभी कभी एक ही प्रसंग पर कतिपय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान चलता रहता है, तथा प्रयोगात्मक कार्य होता रहता है। हमारे देश के लिए यह हितकर नहीं है। कारण, हमारा शोध कार्य पिछड़ा हुआ है। इसी कारण राधाकृष्णन् आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुसन्धान-कार्य की व्यवस्था अखिल भारतीय आधार पर हो।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रशासन में हम गड़बड़ी देखते हैं। किसी किसी राज्य में तो उत्तर स्नातक, स्नातक तथा उप स्नातक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशासन दो विभिन्न निकाय करते हैं, अर्थात्, विश्वविद्यालय एवं राज्यीय शिक्षा विभाग। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह प्रस्ताव किया था :

स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को स्वीकृति तथा मान्यता विश्वविद्यालय देवें और वे ही डिग्रियाँ प्रदान कर। उपस्नातक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुव्यवस्था तथा समुन्नति के लिए एक विशिष्ट मण्डल प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाय। †

शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ

शिक्षकों का स्थान.—किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षक का। शिक्षा की उन्नति के लिए, अत्यन्त उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षा साधन, शाला गृह की जरूरत है। पर उनसे ज्यादा जरूरत है पथारूप में उपयुक्त शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की। वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते हैं, वे ही पुस्तक, नक्शों, अव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग करते हैं और उन्हें छात्रों को समझाते हैं, वे ही शाला गृह में एक नवीन जीवन डाल देते हैं। देश के भावी नागरिकों का निर्माण वे ही करते हैं। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है।

अस्तु, अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जीव और निस्तेज हो जाती है। यही समझ कर, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षकों का एक विशिष्ट स्थान था। राजा और रक, नर और नारी, विद्वान् और निरक्षर भट्टाचार्य — सभी गुण को मान देते थे। समय ने आज पल्टा खाया है। आज, शिक्षक भारतीय समाज का दलित प्राणी है।

शिक्षकों की संख्या—आज, भारत में ११ लाख से अधिक शिक्षक तथा शिक्षिकाएँ क्रियाशील हैं। इनके विभिन्न स्तरों की संख्या का पता तालिका ३० से मिलेगा :

† *University Education Commission's Report* p 216

(५) गोष्ठियों तथा कर्मशालाओं का आयोजन । हमारे देश में भी, इस ओर सुधार की जरूरत है ।

अनुसन्धान-कार्य.—माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने लिखा है, “ट्रेनिंग कालिज केवल शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था ही नहीं है, वरन् यह विभिन्न संशैक्षिकी तत्त्वों का अनुसन्धान-कार्यालय भी है ।”† गवेषणा-कार्य प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के आचार्यों के तत्वावधान में हो । हों, वे माध्यमिक शिक्षकों से अवश्य सहायता ले सकते हैं । उनके निरीक्षण में कतिपय शोध-शिष्य भी काम कर सकते हैं । आज हमारे देश में निम्न लिखित शिक्षा-विषयों पर गवेषणा की अत्यधिक जरूरत है :

१. पाठ्य-क्रम निर्माण के लिए प्रायोगिक कार्य,
२. शिक्षा-प्रबन्ध तथा प्रशासन,
३. शिक्षकों का कार्य-बोझ,
४. शिक्षण-पद्धति की उन्नति,
५. भारतीय शिशु का मनोविज्ञान,
६. निर्देश एवं परामर्श,
७. परीक्षा,
८. बुद्धि-परीक्षण, एवं
९. शिक्षण समाज-शास्त्र ।

समन्वयता का अभाव.—अन्त में हम शिक्षक-प्रशिक्षण-प्रणाली में समन्वय का अभाव देखते हैं । उदाहरण-स्वरूप डिग्री-डिप्लोमाओं का नामकरण ही लीजिए — एम० इंजी०, एम० ए० (शिक्षा), एम० टी०, बी० टी०, बी० एड०, एल० टी०, सी० टी०, टी० टी० सी०, डिप० टी०, टी० डी० इत्यादि । फिर ट्रेनिंग की भवधि लीजिए । कहीं एम० इंजी० का कोर्स दो वर्ष है, और कहीं एक वर्ष । यही हाल स्नातक पाठ्य-क्रम का भी है । इसी प्रकार ‘कालिज’ शब्द का उपयोग विविध स्तर की संस्थाओं के लिए आता है । यहाँ तक कि किसी-किसी राज्य में प्राथमिक शिक्षण केन्द्रों के लिए भी यह शब्द प्रचलित है । इतना ही नहीं, कहीं ये संस्थाएँ ‘नार्मल स्कूल’ कही जाती हैं, और कहीं ‘ट्रेनिंग कालिज’ । इस अव्यवस्थित रूप को दूर करने की विशेष आवश्यकता है ।

† Secondary Education Commission's Report. p. 170.

हैं तो किसी किसी राज्य के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भोगी पाते हैं, जो अल्पतम हास्यास्पद जान पड़ता है — प्राथमिक शिक्षक ३०७, मैट्रिक पास शिक्षक ४५७, स्नातक शिक्षक ७०७ एवं हाई स्कूल के हेडमास्टर २००७। अनेक राज्यों में २५ वर्ष नौकरी के पश्चात् एक व्यक्ति १००७ मासिक वेतन पर प्राथमिक स्कूल का तथा २००७ माहवार पर हाई स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त होता है। इस प्रकार उनके जीवन की उच्चतम आकांक्षा पूर्ण होती है। अवश्य, सभी राज्यों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है।

कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों की स्थिति भी गिरी हुई है। इन अध्यापकों को हम पांच स्तरों में बाँट सकते हैं — डीन या प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, ट्यूटर या डिमान्स्ट्रेटर। विश्वविद्यालयों में तो यह वर्गीकरण निश्चित रूप से रहता है, पर सम्बद्ध कालिजों में इसका कोई ठीक हिसाब नहीं रहता है। बहुधा 'प्रोफेसर' नामकरण अविवेक रूप से व्यवहृत होता है। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के वेतन क्रम भी विभिन्न हैं — किसी विश्वविद्यालय में कुछ, और किसी में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो किसी में कुछ, सरकारी कालिज में कुछ, तो गैर-सरकारी कालिज में कुछ, साधारण कालिजों में कुछ, तो व्यावसायिक कालिजों में कुछ। इस समस्या की आलोचना करते हुए 'राधाकृष्णन आयोग' ने कहा ही है, "इस प्रकार समान कार्य करते हुए भी, वेतन असमान है।"† चित्र १६ से कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों के विभिन्न वेतन स्तर के अनुरूप विभाजन का पता चलेगा।

इस प्रकार २५ प्रति शत अध्यापकों को १५५७ से कम मासिक वेतन मिलता है, ५० प्रति शत को २२०७ से कम तथा ७५ प्रति शत को ३१५७ से कम। केवल १० प्रति शत अध्यापकों को ४७२७ से अधिक मासिक वेतन मिलता है एवं पाँच प्रति शत को ६१५७ से ज्यादा।‡

इस ओर शासकों की दृष्टि थोड़ी-बहुत आकर्षित हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालिज तथा विश्वविद्यालय के वेतन स्तर की उन्नति तथा उसमें शृंगार स्थापना की चेष्टा कर रहा है। शिक्षकों की वेतन वृद्धि के लिए, भारत सरकार राज्यसूचीय सरकारों को अनुदान भी दे रही है—सन् १९५७-५८ में, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम बढ़ाने के लिए ४३,७२,२५० रु० अनुदान देना स्वीकार किया। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन

† *University Education Commission's Report* p 73

‡ *Ministry of Education Education in Universities in India, 1954-56 Delhi: Manager of Publication 1959 p 29*

तालिका २६
भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७ †

संख्या	पुरुष	स्त्री	योग
विश्वविद्यालय तथा कालिज	३७,५५४	४,६१६	४२,१७०
माध्यमिक स्कूल :			
प्रशिक्षित	१,७५,७९७	५०,१२५	२,२५,८२२
अप्रशिक्षित... ..	१,२६,१४१	२०,११७	२,६७,९९२
प्राथमिक स्कूल :			
प्रशिक्षित	३,५१,०२८	९१,११९	४,४२,१४७
अप्रशिक्षित... ..	२,३७,८५०	३०,१४२	२,६७,९९२
पूर्व-प्राथमिक शाला :			
प्रशिक्षित	२२४	१,०३५	१,२५९
अप्रशिक्षित... ..	१२२	७५०	८७२
व्यावसायिक तथा तकनीकी स्कूल :	१४,४४२	३,०४९	१७,४९१
विशेष शिक्षावाले स्कूल :	२४,३०३	३,२०७	२६,५१०
योग... ..	९,६७,४६१	२,०३,१६०	११,७०,६२१

पन्द्रह प्रति शत शिक्षक महिलाएँ हैं, तथा पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में अधिकतर शिक्षक महिलाएँ हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या है— माध्यमिक स्तर में ५९.१ प्रति शत (पुरुष ५८.६ तथा स्त्री ७३.१) तथा प्राथमिक स्तर में ५६.६ (पुरुष ५६.६ तथा स्त्री ७१.१) इस प्रकार शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षिकाएँ अधिक प्रशिक्षित हैं।

शिक्षकों का वेतन-क्रम.—शिक्षकों का वेतनक्रम सन्तोपप्रद नहीं है, तथा विभिन्न राज्यों की पृथक् नीति है। हम वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए देखते

† *Education in the States, 1956-57. pp. 5-6.*

वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सन् १९५६-५७ में ७६,९५,५०० रु. और १९५७-५८ में १,८५,४६,००० रु. दिया था ।†

अन्य सुभीते.—वेतन के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य सुभीतों की भी जरूरत है ताकि वे अपना अध्यापन-कार्य ठीक रीति से कर सकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित सुभीतों के आयोजन की सिफारिश की है : (१) उचित प्राग्हीडेण्ट फण्ड तथा बीमा, (२) मुक्त चिकित्सा (३) बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं (४) सहायक प्रथा पर मकान । ‡ हर्ष की बात है कि प्रायः सभी राज्यों में गैर-सरकारी शिक्षकों के लिए प्राग्हीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की गई है—शिक्षक अपने वेतन का ६१/१०० प्रति शत अपने वेतन से देते हैं और उतना ही पैसा परिचालकगण अंशदान करते हैं ।

शिक्षकों के प्रति व्यवहार.—जीवन में केवल पैसा या वेतन ही सब कुछ नहीं है। सस्या के प्रति शिक्षकों के स्नेह की उत्पत्ति तथा वृद्धि परिचालकगण के व्यवहार पर निर्भर रहती है। पर गैर-सरकारी शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार के अनेक दृष्टान्त सुने जाते हैं—कहीं वृथा शिड़कियाँ सुननी पड़ती हैं, कहीं अकारण ही पदच्युत होना पड़ता है, कहीं वेतन काट लिया जाता है, तथा कहीं सिर पर कोई भी चढ़ा दिये जाते हैं। अवश्य कमी कमी, शिक्षकगण भी निर्दोष नहीं रहते। पर अधिकांश 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली बहावत चरितार्थ होती है। परिचालकगण की अधाबुन्धी चलती है।

शिक्षकों के बचाव के लिए, प्रत्येक राज्यीय शिक्षा विभाग ने कायदे कानून अध्ययन बनाये हैं। पर उनका यथोचित पालन नहीं होता। शिक्षक तथा परिचालकगण के झगड़ों के मिटाने के लिए न्याय-समिति (ट्रिब्यूनल की कहीं कहीं स्थापना हुई है। पर जब तक इसे कानूनी स्वीकृति न मिले, तब तक यह कठपुतली के समान है। इसका एक दृष्टान्त पिछले पन्नों में लिखा गया है ।*

उपसंहार

गत वर्ष के स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान द्वारा विभूषित किया। यह दिवस वर्तमान शिक्षा-

† भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१८ ।

‡ Secondary Education Commission's Report pp. 184-185

* देखिए, पृष्ठ १६१ ।

वेतन-वर्गों के अनुसार कालिज-अध्यापकों का वर्गीकरण (१९५५-५६)

मासिक वेतन	(प्रत्येक पूर्ण प्रतीक == १००)	संख्या	प्रतिशत
१०० रु. से कम	१००	२,९५४	९.८
१०१-१५० रु.	१००	४,०७५	१३.५
१५१-२०० रु.	१००	५,७१२	१८.९
२०१-२५० रु.	१००	५,६२८	१८.६
२५१-३०० रु.	१००	३,५९९	११.९
३०१-३५० रु.	१००	२,२२२	७.४
३५१-४०० रु.	१००	१,६२३	५.४
४०१-४५० रु.	१००	९८०	३.२
४५१-५०० रु.	१००	८७८	२.९
५०१-५५० रु.	१००	४५६	१.५
५५१-६०० रु.	१००	४४३	१.५
६०१-६५० रु.	१००	३२४	१.१
६५१-७०० रु.	१००	२०४	०.७
७०१-७५० रु.	१००	१६९	०.५
७५१-८०० रु.	१००	२०८	०.७
८०० रु. से अधिक	१००	७१९	२.४

दसवाँ अध्याय

विविध विषय

१. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

भूमिका.—जुछ बरों से लोगों का ध्यान पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ है। वे शैशवावस्था के गौरव को समझने लगे हैं। यह देखा गया है कि मानव-जीवन के प्रारम्भिक छः वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था में जो संस्कार बालक में डाल दिये जाते हैं, वे ही कालान्तर में सुदृढ हो जाते हैं और उसके चरित्र-गठन के आधार बनते हैं। ये संस्कार मनुष्य के आयु पर्यन्त रहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रवाह अन्तिम या स्थिर प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त यदि शिशु के प्रारम्भ से ही सवेग तथा स्थायी भाव सुचारु रूप से निर्मित हो जावें, तो उसका मविष्य निश्चित ही उज्ज्वलतर बन जाता है। अतएव शैशवावस्था से ही, हमें शिशु के जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का रूप.—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधि मनुष्य-जीवन के प्रथम छः वर्ष रहती है, अर्थात् शिशु के भूमिष्ठ होने से लेकर प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ होने तक। इसमें शामिल है माता पिता की शिक्षा, पूर्वजन्म विषयक तथा उत्तर जन्म विषयक सतर्कता, एव शैशवावस्था का प्रशिक्षण। यदि वास्तव में पूछा जाय तो इस प्रशिक्षण की सीमा स्कूल के निश्चित घण्टों की शिक्षा तक ही मर्यादित नहीं रहती है। गान्धीजी ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा मानव जीवन के गर्भाधान से ही आरम्भ होती है, क्योंकि इसी समय से माता बच्चे की जिम्मेवारी लेना आरम्भ करती है।” हमें महाभारत पढ़ने से मालूम होता है कि अभिमन्यु ने अस्त्र शिक्षा का ज्ञान सुभद्रा के गर्भ में अवस्थित रह कर ही अर्जन किया था।

पाश्चात्य देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति.—यह के बाहर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ करने का श्रेय सुप्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री श्री फ्रोबेल को मिलना चाहिए। उन्होंने सन् १८३७ में जर्मनी के ‘ब्लेकनबर्ग’ नामक नगर में

इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगा। कारण सरकार ने प्रकट रूप में, शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया है।

पर इने-गिने पत्र-वितरणों से काम न चलेगा। शिक्षकों को अपने पैरों पर खुद खड़े होना पड़ेगा, उन्हें मिल-गुलकर काम करना पड़ेगा, कटिबद्ध होकर शिक्षक-संघ स्थापित करने पड़ेंगे। ये संघ विविध स्तर में हों—जिला, राज्यीय, अखिल-भारतीय। इनका सम्बन्ध विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों के मुताबिक भी हो—प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयीय, प्राविधिक, चिकित्सा, शिक्षक-प्रशिक्षण इत्यादि। 'एकता से लाभ' का पाठ केवल कक्षा में ही नहीं, पर उन्हें अपने जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यान्वित करना पड़ेगा। उन्हें खुद को न भगवान् के भरोसे ही छोड़ना चाहिए, न दूसरों के भरोसे। स्वावलम्बी हुए बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। "वे अपनी समस्याओं पर," जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, "स्वतः विचार करें तथा उनको हल करने का प्रयत्न करें।"†

† जाकिर हुसैन : "उद्बोधन-भाषण", बिहार राज्यीय शिक्षण-गोष्ठी, १७ फरवरी, १९५८।

४. अच्छी आदतों का निर्माण किया जावे,
५. शिशु की कल्पना शक्ति के विकास का अवसर रहे,
६. बच्चों के सामाजिक जीवन का सगठन हो; तथा
७. गृह जीवन के साथ एकना स्थापित की जावे ।

इस प्रकार एक पूर्व प्राथमिक स्कूल छोटे बच्चों की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। यह स्कूल एक आदर्श वातावरण में हो, ताकि बच्चों को यथेष्ट हवा तथा धूप मिले। उनके स्वास्थ्य की जाँच नियमित समय पर होनी ही चाहिए, ताकि वे नीरोग नरें, और सहसा वे किसी बीमारा के शिकार न बन बैठें। उनके खाने पीने, उठाने बैठने तथा सोने का समय रखा हुआ—अनश्चित—होना चाहिए। उन्हें ठीक तरह मुँह धोना पड़ता है, दाँत तथा शरीर साफ करना पड़ता है तथा प्रत्येक वस्तु को यथोचित स्थान पर रखना सिखाया जाता है। इस प्रकार उनमें अच्छी आदतों की नींव डाली जाती है। उनको ठीक उच्चारण के साथ किस्से कहना तथा अभिनय करना पड़ता है। वे गाते हैं, नाचते हैं, खेलते तथा कूदते हैं, अपने हाथों से बालू का पहाड़ बना देते हैं एवं नाली के रूप में नदी बहा देते हैं, चित्र खींचते हैं या कागज़ काटते हैं। सार अर्थ यह है कि एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल शिशु के व्यक्तित्व के विकास की ओर सतर्कता पूर्ण ध्यान देता है। वहाँ शिशु पर कोई दबाव नहीं रहता, वह क्रीड़ा की स्वच्छन्द प्रवृत्ति से लाभ उठाता है। इस स्कूल में औपचारिक शिक्षा का नामनिशान नहीं रहता है, वरन् इसका ध्येय बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए अत्यावश्यक हैं—नीरोग शरीर, अच्छी आदतें, नियमित जीवन, विशुद्ध उच्चारण, एकाग्रता तथा समझने की शक्ति। एक सुव्यवस्थित पूर्व प्राथमिक स्कूल यह कार्य बहुत कुछ सम्पादित कर सकता है।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.—भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा शैक्षणा वस्था में है। सन् १९५१-५२ में सम्पूर्ण देश में केवल ३३० पूर्व प्राथमिक स्कूल थे और १९५६-५७ में ७७३। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग १०० स्कूल खुलते जा रहे हैं। इन स्कूलों में ३-६ वयवर्ग के बच्चे भरती किये जाते हैं। इनके विभिन्न नाम हैं— नर्सरी, किण्डरगार्टन, मोण्टेसरी, गाल मन्दिर, शिशु विहार, पूर्व प्राथमिक एवं पूर्व युनियादी। इनी-गिनी सस्थाओं को छोड़कर प्राय सभी स्कूलों में किण्डरगार्टन या मोण्टेसरी पद्धति या इनके साथ मिश्रित क्रीड़ा-पद्धति प्रचलित है।

प्रथम किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। श्री फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति तथा शिक्षा-उपकरणों में क्रीड़ा-पद्धति को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। किण्डरगार्टन पद्धति बालक की चार वर्ष की आयु से आरम्भ होती है।

किण्डरगार्टन के बाद नर्सरी (शिशु) स्कूल शुरू हुए। इनकी योजना उन बच्चों के लिए की गयी थी, जिनके मकान तंग मकानों तथा गन्दी गलियों में अवस्थित थे, और जिनकी माताओं को जीविकोपार्जन के लिए दिन भर बाहर इतस्ततः काम करना पड़ता था। ये स्कूल अति ही लोक-प्रिय हैं। कारण, ये संस्थाएँ छोटे बच्चों की खबरदारी रखती हैं। जैसा कि श्रीमती मार्ग्रेट मेकलिन नामक एक अंग्रेजी पूर्व प्राथमिक-शिक्षा-विद् ने कहा है, “नर्सरी स्कूलों की माँग है; कारण, छोटे-छोटे बच्चों को नर्सों की ज़रूरत है।”† नर्सरी स्कूल में दो से चार वर्ष वाले बच्चे भरती किये जाते हैं।

इन सब के पश्चात् प्रचलित हुए ‘मोण्टेसरी स्कूल’। इनकी प्रतिष्ठात्री डा० मेरिया मोण्टेसरी ने अपनी पद्धति तथा शिक्षा-साधनों का प्रयोग निर्धन एवं अस्वाभाविक बच्चों के बीच किया था। उनका पाठन-युक्ति-यन्त्र (डायडैक्टिक एपरेट्स) ऐन्ट्रिक ज्ञान के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा शिशु शीघ्रता शीघ्र शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और अपने ही प्रयास से वह पढ़ना-लिखना तथा गिनना सीख लेता है। इस प्रकार, यह पद्धति शिशु को ही अपनी शिक्षा का उत्तर-दायित्व देती है।

पूर्व-प्राथमिक स्कूल क्या है ?—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ अवश्य बच्चे के गर्भाधान-काल से ही होता है, तथा वह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भ तक चलती रहती है; पर एक पूर्व प्राथमिक स्कूल ही २-६ वयोवर्ग के बच्चों की देखरेख का भार उठाते हैं। ऐसे पूर्व-प्राथमिक स्कूल में उपयुक्त तीन पद्धतियों में से कोई भी एक प्रचलित रहती है। इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित हैं :

१. बच्चों के बाह्य वातावरण की ओर ध्यान दिया जाय, ताकि वे मुक्त वायु, धूप तथा प्रकाश का समुचित सेवन कर सकें;

२. स्वास्थ्यप्रद, आनन्दमय तथा नियमानुसार जीवन-यापन की व्यवस्था की जावे;

३. शृंखला-बद्ध डाक्टरी-निरीक्षण का प्रवन्ध हो;

† Margaret Mo Millan. *The Nursery School*. London, Dent, 1930. p 5.

आयु तक, (३) २½ वर्ष से ४ वर्ष की आयु तक और (४) ४ से छः वर्ष की आयु तक। प्रथम दो प्रक्रमों का सम्बन्ध केवल माता तथा बच्चे के साथ रहता है। इस कारण, पूर्व बुनियादी स्कूल के साथ एक मातृ-रक्ष्याग सदन का रहना आवश्यक है, ताकि माताओं को अपने तथा बच्चे के सम्बन्ध में यथोचित सलाह मिल सके।

अढ़ाई वर्ष की आयु में, बच्चा एक पूर्व-बुनियादी स्कूल में भरती होता है तथा वहीं सात वर्ष की आयु तक रहता है। शिशु के प्रशिक्षण में इन बातों की ओर ध्यान दिया जाता है : (१) पालन-पोषण, (२) डाक्टरों निरीक्षण, (३) आत्म-विश्वास, (४) सामाजिक प्रशिक्षण, (५) शिक्षणीय सूत्रनात्मक कार्य कलाप, (६) गीत, कहानी तथा अभिनय द्वारा उच्चारण विकास, (७) अंक-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि, (८) वैज्ञानिक इच्छा का विकास, (९) संगीत एवं लय और (१०) कला।† शिक्षा जीवन-स्थिति या शिशु के स्वाभाविक वातावरण की परिस्थितियों से सम्बन्धित रहती है।

समन्वय पद्धति.— आज, पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश की पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ तो किण्डरगार्टन पद्धति या मोण्टेसरी पद्धति का ही अनुकरण करना चाहते हैं, कुछ पूर्व-बुनियादी शिक्षा को अपना रहे हैं तथा कुछ मोण्टेसरी एवं पूर्व बुनियादी शिक्षा में एक समन्वय स्थापना की चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय वर्ग की समस्याओं में नूतन बाल शिक्षण सभ, भावनगर प्रधान है। इसके कार्य-कर्तागण मोण्टेसरी तथा पूर्व बुनियादी पद्धति के अच्छे गुणों के आधार पर एक नवीन प्रयोग चला रहे हैं। सम्भवतः यह पद्धति हमारे देश के पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के लिए अनुकूल तथा उपकृत सिद्ध होगी।

उपसंहार.— पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रसार आज सभी चाहते हैं, और इसका जितना अधिक प्रसार होगा, उतना ही वह राष्ट्र के लिए हितकर होगा। पर इसे दो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा : अर्थाभाव तथा शिक्षकों की कमी। आज देश के सामने सबसे कठिन प्रश्न अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का है। हम इसे ही हल नहीं कर पा रहे हैं। तब हम पूर्व-प्राथमिक शिक्षा विस्तार का बीड़ा किस बूते उठा सकते हैं? लेकिन हमें हतोत्साह नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश की निजी समस्याएँ हुआ करती हैं। हमें भारत की शिक्षा समस्याओं का समाधान विभिन्न रीतियों से करना पड़ेगा।

† Report of The Fifth All-India Basic Education Conference, 1950. pp 102-103

बहुधा ये संस्थाएँ फोरी कक्षाएँ होती हैं तथा किसी स्कूल से संलग्न होती हैं। प्रायः सभी संस्थाएँ शहरों में स्थित हैं। राजकीय स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार अवश्य स्वसञ्चालित स्कूलों को अनुदान देती है। अधिकांश स्कूलों की दशा बुरी है। न उनके शाला-गृह ही स्वास्थ्यकर स्थान में अवस्थित हैं, न उनमें यथोचित शिक्षा-उपकरण की व्यवस्था है और न प्रशिक्षित शिक्षकों की। आज पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को इन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है : शिक्षिकाओं की कमी, पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण की अव्यवस्था, इस देश के लिए उपयुक्त शिक्षु-साहित्य तथा शिक्षण-विधि का अभाव, अनुसन्धान तथा शाला-प्रयोग-शालाओं की अनुपस्थिति।

नये प्रयत्न : प्रारम्भिक चेष्टाएँ.—आज सभी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं। डॉ० मोण्टेसरी इस देश में सन् १९४०-४८ तक रहीं। उन्होंने सैकड़ों शिक्षकों को स्वतः प्रशिक्षित किया। इसके फल-स्वरूप हमारे देश की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हमारी कुछ आधुनिक सरकारों रिपोर्टों ने भी इस शिक्षा की अच्छी कदर की। उदाहरण-स्वरूप 'कैशिम' की द्वितीय बुनियादी समिति ने सुझाव दिया कि अनिवार्य शिक्षा की सहायता के लिए नर्सरी स्कूल तथा क्लबों की आवश्यकता है। सार्जेण्ट रिपोर्ट और भी आगे बढ़ी। उसने सिफारिश की, "सरकार को चाहिए कि अपने भावी नागरिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद नर्सरी स्कूल स्थापित करे। इनमें शिक्षिकाओं तथा शिक्षा-उपकरणों का यथोचित प्रबन्ध हो।"† इस रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि इस देश में दस लाख ३-६ बयोवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त नर्सरी स्कूल शिक्षा का प्रबंध किया जाय। हाल ही में अनुमान-समिति की चौथी रिपोर्ट को लोक-सभा में प्रस्तुत करते हुए श्री बलवन्तराय मेहता ने कहा, "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विषय में ऐसी अखिल भारतीय नीति नहीं है, जिससे राज्यों तथा व्यवस्थापकों को कुछ निर्देश मिल सके।"‡ समिति ने सुझाव दिया कि कुछ शिक्षा-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेकर शिक्षु-शिक्षा के प्रबन्ध एवं प्रसार के लिए कुछ नियम ठीक किये जावें।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.—पूर्व प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में कुछ नये प्रयोग हो रहे हैं। यह शिक्षा गर्भोधान से शुरू होकर सात वर्ष की आयु तक चलती रहती है। इसके मुख्य चार प्रक्रम हैं : (१) गर्भोधान से जन्म तक, (२) जन्म से २½ वर्ष की

† *Sargent Report*, p 18.

‡ *Estimates Committee, Elementary Education, 1957-58.*

अतएव, आज प्रौढ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। निरक्षरता देश की उन्नति में पग-पग पर बाधा डालती है। चाहे हम कोई भी जीवन-क्षेत्र लें, आर्थिक, राज-नैतिक या सामाजिक। इन सबमें प्रौढ जन ही समाज के मुखिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। परिवार की उन्नति भी उन्हीं पर निर्भर रहती है। अपठ मनुष्य शिक्षा का बहुधा कट्टर शत्रु होता है। वास्तव में वह शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाता है, फलतः वह अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देना चाहता। अशिक्षित प्रौढ ही बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं। अस्तु, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के यथोचित प्रसार के लिए प्रौढ शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है।

प्रौढ कौन है?—‘प्रौढ’ तथा ‘प्रौढ शिक्षा’ का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का होता है। इंग्लैण्ड के सन् १९४४ के शिक्षा कानून के अनुसार, पन्द्रह वर्ष के गालरू-बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का बन्दोबस्त किया गया है, तथा अठारह वर्ष की आयु तक उन्हें आंशिक सातत्य शिक्षा मिलनी है। अठारह वर्ष की उमर की आयु के व्यक्ति ही इंग्लैण्ड में प्रौढ गिने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और स्त्री वयस्क (प्रौढ) कहे जाते हैं। हमारे देश का लक्ष्य ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, अतएव १४ वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को हम प्रौढ कह सकते हैं।

प्रौढ शिक्षा के रूप —‘प्रौढ शिक्षा क्या है?’—इस विषय पर भी मतभेद है। प्रसिद्ध अमरीकी विद्वान् ब्राइसन का कथन है, “इस शिक्षा के अन्तर्गत हम मनुष्य के उन शैक्षणिक कार्य-कलापों को गिन सकते हैं, जिनका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में करता है और जिनमें उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है।” इसी प्रकार अमेरि-क विद्वान् भी अर्नेस्ट पार्कर का मत है, “अपने जीविकोपार्जन के साथ-साथ यह शिक्षा प्रौढ़ों को अंश-कालिक रूप में मिलती है। अतएव इस शिक्षा के अन्तर्गत वे सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक उपदेश आ सकते हैं, जिन्हें हम वयस्कों को दे सकते हैं।”

हमारे देश में इस शिक्षा के दो रूप हैं : (१) प्रौढ-साक्षरता, अर्थात् उन वयस्कों की शिक्षा, जो निरक्षर हैं, एवं (२) शिक्षित प्रौढ़ों की सातत्य शिक्षा।

प्रौढ साक्षरता से समाज शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका.—भारत में कभी ऐसा समय नहीं रहा है, जब कि जन-समाज को शिक्षित करके उसके जीवन को उष्ण करने के साधन नहीं अस्माये गये हों। वैदिक काल में प्रत्येक परिवारिक या संन्यासी का कर्तव्य था कि वह नगर नगर और

प्रथमतः, हमारे देश में इने-गिने शहर हैं, और समूचे देश में गाँवों का मानो जाल बिछा हुआ है। इन गाँवों में पहुँचने के लिए लम्बे मार्गों को तय करना पड़ता है। मार्गों की यह दूरी पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की स्थापना में बाधा पहुँचाती है। अतएव कुछ समय तक गाँवों को टहना पड़ेगा, और हमें अभी शहरों की ओर ही अधिक ध्यान देना उचित है। शहर में भी हमें अमीर, मध्यम वर्ग तथा गरीबों का ख्याल करना पड़ेगा। अमीर तो निस्सन्देह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अध्यापिकाएँ नियुक्त कर सकते हैं, या, सर्वोत्तम पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं। उन्हें पैसों के लिए पराया मुख ताकना नहीं पड़ता है। परन्तु यस्तुतः ऐसी संख्याओं की सर्वाधिक आवश्यकता है उन गरीब बच्चों के लिए, जिनके माँ-बापों को दिन भर काम करना पड़ता है, जिनके पेट में कठिनाई से दाना पड़ता है, और जो गन्दी गलियों में निवास करते हैं। ऐसे ही बालक-बालिकाओं के लिए मुक्त-वायु स्थित नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता है। जब तक इन असहाय बच्चों की ओर हम उचित ध्यान न देंगे, तब तक हम इस राष्ट्र को उन्नत मस्तक न कर सकेंगे।

मध्यम वर्ग के लिए, हमें माता-पिता सम्बन्धी एवं पारिवारिक शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। कारण, शिशु के सर्व प्रथम शिक्षक हैं उसके माता-पिता। अतएव उन्हें शिशुओं के पालन-पोषण का यथोचित ज्ञान होना चाहिए। यह शिक्षा उन्हें विवाह के पूर्व, स्कूल तथा कालिज में देना उचित है। प्रौढ़ों को भी उत्तर जन्म-विषयक तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हितकर सिद्ध होता है। अपढ़ प्रौढ़ों के साथ भी परिवार-योजना की चर्चा करनी चाहिए।

इस प्रकार हमें अपने घरों की स्थिति ठीक करनी चाहिए। कारण, देश की समृद्धि गृह-गृह की उन्नति पर निर्भर रहती है। मनुष्य जीवन की उन्नति का बीज घर में ही बोया जाता है। उचित वातावरण में वह पल्लवित होकर शाखाएँ प्रशाखाएँ फैलाने लगता है। यदि वातावरण अनुकूल न हुआ तो वह अङ्कुरित होने के पश्चात् ही कुम्हलाने लगता है।

१. प्रौढ (समाज) शिक्षा

प्रस्तावना

विशेषता.— सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार देश की कुल जन-संख्या ३५.७ करोड़ थी, अर्थात् पृथ्वी की संपूर्ण जन-संख्या की १५.१ प्रति शत जन-संख्या इस देश में वास करती थी। इस जन संख्या में १६.६ व्यक्ति साक्षर थे—२४.९ पुरुष एवं ७.९ स्त्री, अथवा ३४.६ प्रति शत शहरी लोग और १२.१ ग्राम-वासी।

सन् १९४२ ई० के राजनैतिक आन्दोलन और ब्रिटिश दमन नीति का विषमय प्रमात्र साक्षरता आन्दोलन पर भी पडा। इस नीति के फल स्वरूप सन् १९४२ से सन् १९४७ तक सभी प्रान्तों की प्रौढ शिक्षा प्रगति में शिथिलता आ गयी। भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने अपने आय-व्यय की एकम को घटाकर सीमित क्षेत्र में तथा सीमित ढग पर साक्षरता प्रसार के कार्य को जीवित रन्ने दिया।

प्रौढ शिक्षा को नया रूप.—सन् १९४७ तक प्रौढ शिक्षा का एक मात्र ध्येय केवल साक्षरता था, पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का अवतरण हुआ। 'केसशिप' क पन्द्रहवें अधिवेशन के समय (जनवरी, १९४४) शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने घोषणा की कि स्वाधीन भारत में प्रौढ शिक्षा का ध्येय केवल साक्षरता नहीं हो सकता है। इस शिक्षा को समाज शिक्षा का व्यापक रूप दिया जाय, जिसमें न केवल साक्षरता का स्थान हो बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, उन्नत कृषि तथा कला आदि सर्वोदय के सभी अंगों का समावेश हो।

समाज-शिक्षा का कार्यक्रम.—समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पञ्च सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके उद्देश्य ये हैं : (१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और (५) समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना। †

समाज शिक्षा आन्दोलन

भूमिका—मौलाना आजाद की घोषणा के पश्चात्, प्रौढ शिक्षा में एक नयी जान आयी। सन् १९४८-४९ के बाद समाज शिक्षा प्रसार के लिए यथेष्ट चेष्टाएँ की जा रही हैं। इन सबको हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं : (१) प्रशासन, (२) समाज शिक्षा संस्थाएँ, (३) समाज शिक्षा व्यवस्थापक और कार्य-कर्त्ताओं का प्रशिक्षण, (४) गोष्ठियाँ, और (५) उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध।

प्रशासन.—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय अखिल भारतीय स्तर पर समाज शिक्षा आयोजित करता है। यह कार्य योजना आयोग तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय के सहयोग से चलाया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कतिपय मन्त्रालय—श्रम, परिवहन एवं प्रतिरक्षा—स्वतः कुछ प्रोग्राम चलाते हैं।

† भारत १९५९, पृष्ठ ८४।

ग्राम-ग्राम घूम कर अध्यात्म-नीति तथा सदाचार का प्रचार करे। तत्पश्चात् हमारे सामाजिक जीवन के उन्नयन का प्रेरक एक और साधन था, वह था कथाओं, कीर्तनों, रामलीलाओं, नाटकों आदि की परम्परा। मध्य युग में हमारे भाट, चारण, जोगी और शकल द्वार-द्वार पर घूम-घूम कर भिक्षा का पात्र लिये, सारंगी अथवा अन्य वाद्य की सुमधुर ध्वनि के साथ उपदेशात्मक पद्य सुनाया करते थे। पर आजकल भिक्षा वृत्ति एक व्यवसाय-मात्र है।

ब्रिटिश युग.—ब्रिटिश युग में हम प्रौढ़ शिक्षा के विकास को दो मुख्य कालों में बाँट सकते हैं। प्रथम काल की अवधि सन् १८५७ से १९१९ ई० तक समझी जाती है, अर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी के पतन से सन् १९१९ ई० के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून तक। इस अवधि में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ छिट-पुट प्रयत्न अवश्य किये गये। इन सबका उद्देश्य निम्न-श्रेणी के बच्चों तथा बच्चों को साक्षर बनाना था। इसी उद्देश्य से, मिशनरी मण्डलों ने कुछ प्रौढ़ पाठशालाएँ खोलीं तथा औद्योगिक केन्द्रों में कतिपय रात्रि शालाएँ सञ्चालित हुईं। बड़ीदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का आरम्भ सन् १९१० में हुआ। इस अवधि के अन्त में कुछ रात्रि पाठशालाएँ मद्रास, मधुई, बंगाल, मैसूर तथा बड़ीदा में चल रही थीं, पर उनमें उचित व्यवस्था न थी।

प्रौढ़ शिक्षा विकास का द्वितीय युग सन् १९१९ से १९४७ तक माना गया है, अर्थात् गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून, १९१९ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक। इसी अवधि में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ होता है। माण्टफोर्ड गुधार तथा प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों में एक नवीन चेतना आरंभ कर दी। गुधार के कारण, मत-दान का क्षेत्र विस्तृत हो गया; इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जनता अपने हक को सोचे-समझे। प्रथम विश्व-युद्ध के कारण, अपढ़ सिपाही अन्य देशों के सम्पर्क में आये। वे हमारे देश में नये विचार लाये और उनमें ज्ञान की विषासा उत्पन्न हुई। इसके अनिरीक माण्टफोर्ड गुधार के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की बागडोर भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों के हाथ में आयी। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया।

इस प्रकार प्रौढ़-साक्षरता का आन्दोलन पूरे देश में आरम्भ हुआ। प्रौढ़ शालाएँ तथा रात्रि पाठशालाएँ गुली, कई प्रान्तों में ग्रामीण पुनःसंस्थापन तथा चरने-कृति पुनःसंस्थापन स्थापित हुए। साक्षरता-प्रचार के उद्देश्य में, अनेक न्यानों में, गैर-सरकारी संस्थाएँ भी खोली गयीं। सरकार ने उन्हें अनुदान अवरुध दिया। सन् १९३८ में भारतीय प्रौढ़-शिक्षा समिति दिल्ली में स्थापित हुई। यह संस्था क्रमशः भारत की केंद्रीय संस्था बनने की ओर धमगर होने लगी।

जनता क घनिष्ठ सम्पर्क में आना पड़ता है, समान सेवा के कार्य कलापों को चलाना पड़ता है, और यदि टेर फेर की आवश्यकता पड़े तो सरकार को सलाह देना पड़ता है।

संस्थाएँ—समाज सेवा के पंचमुखी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, विविध प्रकार का संस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तथा देश की आवश्यकताओं को समझ सके और समाज के निकटतम सम्बन्ध में आ सके। नीचे कतिपय मुख्य संस्थाओं का विवरण दिया जाता है।

साक्षरता-कक्षाएँ—प्रारम्भिक संस्थाओं का उद्देश्य व्यक्तियों की निरक्षरता का निवारण करना था। सन १९५३ तक इन संस्थाओं की संख्या ४०,००० थी। इसका लाभ प्रति वर्ष प्रायः चार लाख व्यक्ति उठाते थे। सामुदायिक विकास की कार्यवाही के कारण, इस कार्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस विकास क आरम्भ होने के प्रथम वर्ष ही ७,००० नयी कक्षाएँ खुलीं, जिनकी छात्र संख्या ९८,००० थी। सन १९५५ के अन्त तक सामुदायिक विकास खण्ड ७५,००० कक्षाएँ चला रहे थे, जिनमें छ लाख से अधिक प्रौढ़ समाज शिक्षा पा रहे थे। निरक्षरता निवारण योजना का यह बलन्त दृष्टांत है।

समाज सदन, कभी कभी साक्षरता कक्षाएँ विकसित होकर समाज सदन का रूप धारण करती हैं। इस संस्था में गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें आमोद प्रमोद एवं खेल का प्रबन्ध रहता है तथा लोग विविध विषयों की चर्चा भी करते हैं। किसी किसी सदन में तो व्यायाम-शाला, उद्योग-कक्षा, जलपान गृह, आदि की व्यवस्था रहती है।

तरुण सघ—खेल-कूद तरुणों को प्रिय होते हैं। इस कार्य के लिए, वे सघ स्थापित करते हैं। धीरे धीरे सघ अन्य कार्य भी आरम्भ करते हैं, जैसे : नाटकामिनय, निरुद्देश्य परिभ्रमण, स्काउटिंग, सेवा-समिति, सुरक्षा दल, हस्तोद्योग एवं प्रदर्शनी। गाँवों में कभी कभी तरुण-कृषक सघ की स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है ग्राम विकास एवं खेलों की उन्नति। अधिकतर ऐसे सघों की स्थापना पञ्जाब राज्य में हुई है।

महिला समिति—प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक व्यवस्थापिका रहती है। उसका काम ही महिला संस्थाओं की स्थापना करना होता है। इन समितियों में ये कार्य होते हैं : (१) भजन तथा गीत के लिए देहाती औरतों का सम्मेलन, (२) उत्सवों तथा त्योहारों का समारोह, (३) गृह उन्नति तथा शिशु-पालन, (४) सतिका-गृह सेवा, (५) पारु विशान और भोजन विशान, (६) बुनाई, सिलाई, दर्जीगिरी या

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के मुख्य कर्तव्य हैं : संयोजन, निर्देशन एवं आर्थिक सहायता । प्रथमतः, मन्त्रालय उन योजनाओं का विचार करता है, जिन्हें वह स्वतः मुझता है और जिन्हें विभिन्न राज्य-सरकारें चलाती हैं । द्वितीयः, 'केसशिम्' अथवा अन्य परिषदों की बैठकों में भारत के विभिन्न समाज शिक्षा विषयक कार्य-कलापों पर विचार विमर्श हुआ करता है । इन सामूहिक बैठकों का निर्णय देश के लिए हितकर सिद्ध होता है ।

समाज शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए कई समितियाँ हैं । प्रथम निकाय है 'केसशिम्' की समाज शिक्षा स्थायी समिति, जो सन् १९४८ में स्थापित हुई थी । यह समिति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को व्यक्तों की शिक्षा समस्याओं पर परामर्श देता है । द्वितीय निकाय है 'केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल' । इस स्वायत्त-शाली संस्था की स्थापना अगस्त, १९५३ में हुई थी । इसके द्वारा समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वेच्छिक समाज सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान दिये जाते हैं । समाज शिक्षा इस मण्डल का एक मुख्य काम है । तृतीय निकाय है 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र' । उच्च कर्मचारियों को समाज शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई समस्याओं पर उपयुक्त शोध-कार्य करने के लिए, इस संस्था की स्थापना हुई है ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है । शोध-कार्य तथा नव-साक्षरों के साहित्य के प्रकाशन के प्रोत्साहन के लिए भी वह आर्थिक सहायता देती है । इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा की कुछ गोष्ठियों को या तो वह स्वयं चलाती है, अथवा अन्य संस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है ।

सामाजिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व प्रधानतः राज्य-सरकारों पर ही है, पर इस विषय पर द्वैध शासन है । शिक्षा विभाग, अपना पुराना कार्य चलाते हैं; पर समाज शिक्षा के नवीन अंगों का परिचालन सामुदायिक विकास विभाग करता है । अनेक राज्यों ने इस द्वैध शासन का बहिष्कार किया है । उसका अधिकार एक ही निकाय की अधीनता में रहता है, चाहे सम्पूर्ण प्रशासन न हो ।

सम्पूर्ण राज्य का प्रशासन एक विधि अक्षम करते हैं, और उनके नीचे क्षेत्रीय और/या ज़िला-व्यवस्थापक रहते हैं । विभिन्न स्तर के अधिकारोगण सलाहकारी समितियों की सहायता से काम करते हैं : राज्य, क्षेत्र, ज़िला या नगर । राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समितियों का कर्तव्य केवल परामर्श देना ही रहता है, पर ज़िला या नगर समितियों को

२. सांस्कृतिक.—भ्रम्य दृश्य उपकरणों का उपयोग, नाटकाभिनय, लोक गीत, लोक-नृत्य, कवि सम्मेलन, मुशायरा, प्रीति भोज, इत्यादि ।

३. आमोद-प्रमोद.—कथा, भजन, खेल-कूद, प्रीति-यात्रा, तैरना, निरुद्देश्य परिभ्रमण, इत्यादि ।

४. कला और हस्तोद्योग.—युनाई, सिलाई, दर्जीगिरी, कशीदे का काम, आगवानी चढईगिरी, साबुनसाजी, पाक-क्रिया, कागज बनाना, इत्यादि ।

५. समाज सेवा.—प्रभात फेरा, नागरिक आन्दोलन, सफाई कार्य क्रम, गंदे मुहल्लों की सफाई, पापानो आदि का निर्माण, साक्षरता आ-दोलन, इत्यादि ।

समाज शिक्षा-कार्य-कर्त्ताओं का प्रशिक्षण.—समाज शिक्षा एक कला है, और इसकी विशेषता प्रशिक्षण के बिना सम्भव नहीं है । समाज शिक्षा कार्य करने वाले मुख्यतः तीन कोटियों में विभक्त हो सकते हैं : (१) व्यवस्थापक, (२) कार्य कर्त्ता शिक्षक तथा बहुमुल्य ग्राम स्तर कार्य कर्त्ता (ग्राम स्तर पर समाज शिक्षा का सगठन करने वाला, समाज सेवक, शिविर-व्यवस्थापक, समाज केन्द्रों का सचालक, ग्रामीण युवक कल्याण व्यवस्थापक) एव (३) सगठन कर्त्ता । ये वैतनिक और अवैतनिक—दोनों—हो सकते हैं ।

व्यवस्थापक तो उत्तर-रत्नानक प्रशिक्षित होते हैं । उन्हें व्यावसायिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा समाज सेवा महाविद्यालयों में मिलती है । कार्य-कर्त्तागण किसी समाज शिक्षा केन्द्र या जनता कालिज में प्रशिक्षित होते हैं । भारत में इन केन्द्रों की संख्या प्रायः बीस है । इन केन्द्रों में तीन से एक वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है । पाठ्यक्रम की रूप रेखा नीचे दी गयी है :

१. सैद्धान्तिक (सात पर्चे) : (१) समाज-शास्त्र के सिद्धान्त तथा समाज शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय, और समाज शिक्षा का इतिहास ; (२) शिक्षण मनोविज्ञान और समाज शिक्षा विधि, (३) समाज शिक्षा और समाज सेवा का सगठन तथा व्यवस्था एव स्वास्थ्य शिक्षा ; (४) कृषि एव गृह उद्योग एव ग्रामीण अर्थशास्त्र ; (५) भ्रम्य दृश्य शिक्षा और लोक साहित्य तथा लोक कला ; (६) ग्राम-पंचायत, सहाकार, सामुदायिक विकास योजना एव (७) सामान्य जानकारी ।

कोई अन्य हस्तोद्योग, (७) बाता, भाषण, प्रदर्शनी, ध्वनि, (८) खेल-कूद शिबिरो आदि का संघटन, (९) साग-सन्धी की बाटियों लगाना, (१०) साक्षरता, इत्यादि।

विस्तार.—गत कुछ वर्षों में समाज शिक्षा का कार्य विचार हो रहा है। विस्तार का अनुमान निम्नलिखित तालिका से दिया जा सकता है।

तालिका २७

समाज शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६

वर्ष	कक्षा, केन्द्र, स्कूल	छात्र-संख्या	साक्षरता प्रमाण-पत्र वितरण	खर्च (लाख रुपये)
१९५१-५२	४३,४६३	१०,६१,२८०	४,८९,१३५	७१-८३
१९५२-५३	४४,५९५	१०,८८,७८४	४,४२,७००	७३-७७
१९५३-५४	३९,९६५	९,४८,८४७	३,९२,४४०	६२-०५
१९५४-५५	४३,२२३	११,३१,४०५	४,६९,१०१	७७-४६
१९५५-५६	४६,०९१	१२,७८,८२७	५,४५,२२१	९६-८०

सन् १९५५-५६ में कुल संस्थाओं की संख्या ४६,०९१ थी। जिनमें १३,२७४ सरकारी, ४५८ जिला-मंडल की, २८२ नगर-पालिका की एवं ३२,०७७ स्वसंचालित थीं। खर्च का आवण्टन इस प्रकार था : सरकारी ९२-२ प्रति शत, स्थानीय मण्डल ३-० प्रति शत एवं अन्य स्रोत ४-८ प्रति शत।†

संस्थाओं के प्रोग्रामों में निम्नलिखित कार्य-क्रम शामिल थे :

१. शैक्षणिक.—साक्षरता-कक्षा, वाचनालय, समाचार-सूचना-पट, पुस्तक-आलोचना, प्रवचन, वाद-विवाद, गोष्ठी, प्रदर्शनी, भाषण, प्रारम्भिक तथा अत्यावश्यक चिकित्सा, इत्यादि।

† *Education in India*, 1955-56. Vol. I. p. 288.

की आयोजना करती है। इनमें लेखकों को इस नवीन साहित्य पर लिखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चतुर्थतः, सरकार स्वयं नव साक्षर साहित्य का प्रकाशन करती है, और कुछ नवीन सस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है। हाल ही में एक "राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट" की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आदर्श पुस्तकों का प्रकाशन है।

दिल्ली में 'केन्द्रीय अर्थ दृश्य शिक्षा संस्था' स्थापित हो चुकी है। यह संस्था भारत एवं राष्ट्रीय सरकारों को अर्थ दृश्य शिक्षा के विषय में परामर्श देती है। केन्द्रीय चल चित्र संग्रहालय में शिक्षा तथा सस्कृति-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७४ चलचित्र आदि हैं, जो संग्रहालय की 'सदस्य शिक्षा संस्थाओं' को निःशुल्क दिये जाते हैं। १,००५ शिक्षा संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'अर्थ-दृश्य शिक्षा' दीर्घक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। समय समय पर केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय सरकारें अर्थ दृश्य कार्य-कर्त्ताओं की प्रशिक्षण गोष्ठियों का भी आयोजन करती रहती हैं।

पुस्तकालय उत्तर-साक्षरता का प्रधान अङ्ग है पर हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। सम्पूर्ण देश में लगभग ३२,००० पुस्तकालय हैं। ये समाज शिक्षा केन्द्रों या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। औसतन प्रति व्यक्ति पीछे पचास पुस्तकें हैं और प्रति वर्ष शायद ही दस मनुष्य एक से अधिक पुस्तक पढ़ते हों !!

साक्षर शिक्षा

भूमिका.—खेद की बात है कि हमारे देश में एक शिक्षित व्यक्ति की शिक्षा स्कूल या कालिज की पढाई के साथ समाप्त हो जाती है। स्कूल शिक्षा की समाप्ति होने पर भी, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या की कुछ न-कुछ चर्चा करे। थार्नडाइक, बुडवर्थ इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि बचस्क भी मुस्तेदी के साथ सील सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र लिया जाय— सामाजिक, व्यावसायिक, नागरिक, कौटुम्बिक—सभी जगह कुछ न-कुछ सीखने की गुंजाइश रहती है। सतत परिवर्तन ससार का नियम है। जो व्यक्ति इस बदलते हुए ज्ञान के सम्पर्क में न रहेगा, वह सदा असन्तोषी तथा शिकायती रहेगा।

शिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरतों को देखते हुए साक्षर शिक्षा तीन स्तर में दी जा सकती है : (१) उच्च शिक्षित, (२) साधारण शिक्षित और (३) अव्य शिक्षित।

२. **व्यावहारिक :** सामूहिक जीवन का अभ्यास, गाँव का सर्वेक्षण, श्रव्य-दृश्य यन्त्रों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक संस्थाओं में भाग, प्रदर्शनी, उत्सव तथा त्योहारों का संगठन, आदि ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण-शिक्षा के अतिरिक्त ग्राम-सुधार कार्यकर्त्ताओं को सहायिता तथा कृषि-सुधार की शिक्षा दी जाती है । गाँवों की सर्वतोमुखी उन्नति और सुधार के लिए ग्राम-सेवकगण भी प्रायः इसी दृष्टि से प्रशिक्षित किये जाते हैं ।

गोष्ठियाँ.—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा-आन्दोलन एक महत्वपूर्ण अभियान है । विभिन्न एशियाई देशों की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी इस दिशा में एक उल्लेखनीय घटना है । यह गोष्ठी सन् १९४९ में मैसूर में भरी थी । उसमें अनेक एशियाई देशों ने भाग लिया था तथा वयस्क शिक्षा की अनेक समस्याओं पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे । तब से हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ ही करता है — अखिल भारतीय, राज्यीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय । गोष्ठियों में समाज शिक्षा के व्यवस्थापकगण, संगठन कार्य-कर्त्तागण तथा अन्य कार्य-कर्त्तागण एकत्र होते हैं, और सामूहिक रूप से इस शिक्षा विषयक तथ्यों की आलोचना करते हैं, जैसे : प्रशासन, अनुदान, पाठ्य क्रम, प्रशिक्षण, नवसाक्षर-साहित्य, श्रव्य-दृश्य-उपकरण, इत्यादि ।

उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध.—सामाजिक शिक्षा की जिम्मेवारी साक्षरता प्रमाण-पत्र विनरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, वरन् यह भी देखना पड़ता है कि नवशिक्षित वयस्क अपनी साक्षरता स्थिर रख सकें । अतएव उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि समाज शिक्षा-द्वारा जो कुछ एक प्रौढ़ ने सीखा हो, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा प्रौढ़ों में परस्पर हुआ करे । इसके लिए तीन विषयों की व्यवस्था चाहिए : (१) नव साक्षर-साहित्य प्रकाशन, (२) श्रव्य-दृश्य उपकरणों का निर्माण एवं (३) पुस्तकालयों का प्रबन्ध ।

राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार ने नव-साक्षर-साहित्य प्रकाशन की थोड़ी-बहुत व्यवस्था की है । प्रथमतः, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्तम वयस्क-उपयोगी पुस्तकों के लेखक को इनाम दिया जाता है तथा प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पुस्तकों की अनेक प्रतियाँ सरकार खरीदती है । द्वितीयतः, नव-साक्षरों के उपयोग की हिन्दी पुस्तकें भी सरकार खरीदती है, जिनका आधा खर्च भारत सरकार देती है और आधा राज्यीय सरकार । इसके अतिरिक्त पैकिंग और यातायात का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार स्वयं ही वहन करती है । तृतीयतः, समय-समय पर सरकार विशिष्ट कर्मशालाओं

जाये। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाय तथा चौदह वर्ष की आयु प्राप्त करते करते किशोर किशोरी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

हमारा तृतीय एव चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य इस सिफारिश को कार्यान्वित करना है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, यह सातत्य शिक्षा दिवस या रात्रि में दी जायगी। इनका ध्येय छात्रों को प्रज्ञा बुनियादी या मिडिल स्कूल शालान्त परीक्षा के लिए तैयार करना है।

हमारे देश में २०-३० वयवर्ग के अनेक वयस्क हैं, जिन्हें २-३ वर्ष की शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, और जो अब अध्ययन करना चाहते हैं। इनके लिए दो तीन वर्ष की अवधि के अर्ध-कालिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने इस वयवर्ग की महिलाओं के लिए कुछ कोर्स चलाये थे। जिनमें पढकर कुछ शिक्षार्थिनियाँ वनायकुलर फाइनल परीक्षा में घैठीं, और कुछ मैट्रिक परीक्षा में। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् जीविकोपार्जन के अनेक द्वार खुल जाते हैं, जैसे ग्राम सेविका, धानी, शिक्षिका, मुहर्रिर, इत्यादि। पुरुष तथा स्त्री, दोनों के लिए, ऐसे प्रयासों की आवश्यकता इस देश में इस समय अनुभव की जा रही है।

इस प्रकार हमारे देश में सातत्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है। यह शिक्षा उन वयस्कों की कमियों को दूर करती है, जिनकी शिक्षा अर्धाभास या अन्य कारणों से अधूरी ही रह गयी है। यह शिक्षा न केवल उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, वरन् उनके आर्थिक जीवन को उन्नततर करती है। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, लोगों को तैयार कर वह देश की जरूरतों को पूर्ण करती है तथा बेकारी समस्या के उन्मूलन में योग देती है। देखिए, चीन ने क्या कर दिखाया है

चीन के विश्वविद्यालय उन युवक युवतियों के लिए भी सदा खुले रहते हैं, जो अर्द्ध शिक्षित होते हैं, या, जिनकी शिक्षा मिडिल स्कूल तक ही रहती है। सन् १९५४ की प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थीगण बैठे, उनमें १६ प्रति शत ऐसे ही छात्र-वृन्द थे और उनका कार्य कोई असन्तोषप्रद न था।

यह सुभवसर अन्य विद्यार्थियों को भी दिया गया। वे थे ३,००० प्रायमरी शिक्षक एव विविध उद्योगों के ६,००० ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा नहीं मिली थी। इनका प्रवर्ण सरकार ने किया था।

उच्च शिक्षित.—उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए कालिज तथा विश्वविद्यालय प्रसारण वक्तृता का बन्दोबस्त करते हैं। भारत में यह आन्दोलन सन् १९१५ में आरम्भ हुआ था। कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रसारण केन्द्र शिक्षकों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पर यह यथेष्ट नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रसारण-विभाग की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य हो, उच्च शिक्षित व्यक्तियों में सुचारु रूप से प्रसारण-कार्य करना। इनकी चर्चा छोटे अध्याय में की गयी है।†

साधारण शिक्षित.—पैसे के अभाव के कारण, अनेक भारतवासियों की शिक्षा — सांस्कृतिक या औद्योगिक — पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों के हितार्थ सायङ्कालीन कक्षाएँ चलानी चाहिए। यह प्रथा अनेक सभ्य देशों में प्रचलित है। इंग्लैण्ड का उदाहरण लीजिए। यहाँ हजारों नैश-कक्षाएँ चलती हैं, जिनका लाभ लाखों वयस्क उठाते हैं। इन कक्षाओं में अनेक विषयों की अंश-कालिक शिक्षा दी जाती है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। पर ये कक्षाएँ निरक्षर शिक्षा-केन्द्र नहीं हैं। चरन् इनका वातावरण बहुत कुछ सामाजिक क्लबों के समान होता है, जहाँ कि वयस्कगण अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होते हैं।

उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करने के लिए तथा नौकरी में स्थित व्यक्तियों की सहायता के लिए, हमारे देश के केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय पत्र-व्यवहार द्वारा कतिपय विषयों के कोर्स का प्रबन्ध करनेवाले हैं। मन्त्रालय विश्वविद्यालयों को नैश-कक्षाएँ चलाने का भी सुझाव देनेवाले हैं, ताकि दिवा-कक्षाओं में भीड़ की कमी हो तथा नौकरी में स्थित व्यक्तियों को अध्ययन का सुअवसर मिले। शिक्षित वयस्कों के सातत्य शिक्षा का यह पहला कदम होगा।

अल्प शिक्षित.—माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है :

यद्यपि संविधान यह निर्देश देता है कि चौदह वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अंश-कालिक शिक्षा का आयोजन किया जाय, तित्त पर भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्देश कार्यान्वित करना, कुछ समय तक असम्भव प्रतीत होता है।‡

आयोग ने सिफ़ारिश की है कि ११-१४ वर्षीय (घण्टागं के) बच्चों के लिए मिडिल तथा हाई स्कूलों में निःशुल्क, अंश-कालिक सातत्य शिक्षा की व्यवस्था की

† देखिए पृष्ठ १७१।

‡ Secondary Education Commission's Report p. 66.

सामाजिक मजबूर अनाथ या निराश्रित बच्चे होते हैं। ये घर द्वार रहित होते हैं तथा इनके कोई अभिभावक नहीं रहते।

लक्षण सम्बन्धी वर्गीकरण.— जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक बच्चे की अनेक विषयों की जरूरतें रहती हैं—शारीरिक, दैहिक या सामाजिक। उसे भोजन, शारीरिक आराम, सामाजिक अभिस्वीकृति, प्यार एवं सुरक्षा चाहिए। परन्तु जीवन में ऐसी अनेक गाथाएँ आ जाती हैं, जिनके कारण, इन आकांक्षाओं की तृप्ति के साधन अनुपलब्ध रहते हैं। इन समस्या असामञ्जस्यों के कारण, मानसिक रोगों की सृष्टि होती है।

कुछ स्वाभाविक अभाव के कारण, मनुष्य अपने प्रकृत वातावरण एवं अवस्था में सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर पाता है—थोड़ी सी कठिनाई पड़ी और उसका असन्तोष जाग उठा। वातावरण का अभाव मुलभूत नहीं आ सकता है। वातावरण में मुख्य है—अशिक्षा, निर्धनता, आरोग्यस्थिति में माता-पिता का दुर्व्यवहार। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री एडलर के कथनानुसार समाज में निम्न स्थान, व्यवसाय में असफलता, वैवाहिक जीवन में अशान्ति—ये असामञ्जस्य के प्रमुख कारण हैं। परन्तु यह स्वाभाविक अभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता, तथापि कुछ इनके लक्ष्य बन ही बैठते हैं। ऐसे बदनसीब अपने जीवन को निष्फल गिनते हैं और अचेतना-वश उनमें कुछ न कुछ असामान्य आचार फैलते हैं। कोई हठीला उन बैठता है, तो कोई पिछड़ा हुआ होता है, कोई उदासीन तो कोई अपराधी। कई-कई तो अत्यधिक परावलम्बी या शिरा व्याधि ग्रस्त हो जाते हैं।

इन साधारण अवस्थाओं में से तीन मुख्य हैं—(१) अपराध, (२) शिरा व्याधि से होने वाले मानसिक रोग, एवं (३) स्कूली विषयों में पिछड़ना। बहुधा ये तीनों अवस्थाएँ आपस में मिली जुली रहती हैं, और तीनों की प्रतिक्रिया एक साथ करना उचित है।

मजबूरों का शैक्षणिक पाठ्यक्रम उद्देश्य.—मजबूरों के पाठ्यक्रम में उनके अवरोधन तथा आवश्यकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात् हमें देखना पड़ेगा कि उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति कहीं तक उसकी शिक्षा में बाधक सिद्ध होती है। इसीसे अनुकूल उसका पाठ्यक्रम भी होगा। जहाँ तक बच्चे, हमें रूढ़ियों को दूर करना चाहिए। प्रत्येक मजबूर व्यक्ति की निजी जरूरतें होती हैं और उन्हींके अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए।

तत्पश्चात् ये विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए थे। ये नियमित परीक्षा में नहीं बैठे। इनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था।†

३. मजबूरी की शिक्षा

मजबूरी का वर्गीकरण : भूमिका.—बीसवीं शताब्दी बच्चों का युग गिना जाता है। यद्यपि बच्चों की देख-भाल के विषय में भारत अन्य सम्य देशों से पिछड़ा हुआ है, तथापि इस देश में शिशु-पालन काल का उदय हुआ है। वर्तमान मशीन युग में मानव-कल्याण तथा बच्चों की भलाई की ओर ध्यान देना विशेष आवश्यक हो गया है। श्री नेहरू ने कहा ही है :

राष्ट्र की प्रगति में मनुष्य का प्रधान स्थान है। मानव विकास की भित्ति शैशवावस्था में कायम होती है। इस कारण, वयस्क की अपेक्षा शिशु अधिकतर महत्वपूर्ण है।

मजबूर बच्चे.—मजबूरी दो प्रकार की होती है — कारणात्मक तथा लक्षण-सम्बन्धी। वैयक्तिक या आत्मगत अवरोधन के कारण, प्रथम प्रकार की मजबूरी आ जाती है। क्योंकि ये शिशु के स्वाभाविक सामञ्जस्य में बाधक सिद्ध होते हैं। द्वितीय वर्गीकरण का लक्षण होता है कोई असामान्य या भद्दा आचार-व्यवहार। किसी आन्तरिक अवरोधन के कारण, ये लक्षण प्रकट होते हैं।

कारणात्मक वर्गीकरण.—इस मजबूरी की तीन श्रेणियाँ हैं : शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक।

शारीरिक मजबूर या विकलाङ्ग तीन प्रकार के होते हैं—अन्धे, बहरे और गूंगे, तथा लूले-लँगड़े।

जिन लोगों की बुद्धि औसत में कम होती है, वे द्वितीय श्रेणी में गिने जाते हैं। बुद्धि-परीक्षाओं के आधार पर, ये व्यक्ति दो भागों में बाँटे जा सकते हैं :

१. सीमा-रेखा स्थित अपूर्ण व्यक्ति... बोध-लब्धि : ७०-८०।

२. मानसिक दुर्बल

(१) मूर्ख बोध-लब्धि : ५०-७०।

(२) मूढ़ " : २५-५०।

(३) जड़ " : २५ से निम्न।

† Embassy of the People's Republic of China in India *Wide Horizons for Students in China*. Cultural and Information Office, 1955. p. 8.

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्रगति.—स्वाधीनता अर्जन के पश्चात् भी इस क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई। यह अवश्य है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा विभाग मजबूतों की शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं। सन् १९५२ में 'राष्ट्रीय शिक्षा मंगल परिषद' की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य है, बच्चों के मंगलार्थ कार्य का संयोजन एवं शोध, आर्थिक सहायता तथा समाचार प्रदान। सन् १९५५-५६ में एक अन्य राष्ट्र-परिषद स्थापित की गयी है। यह परिषद सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

शिक्षा संस्थाएँ.—निम्नांकित तालिका से मजबूतों की भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं तथा उनकी छात्र-संख्या का पता चलेगा :

तालिका २८

मजबूतों की शिक्षा-संस्थाएँ, १९५५-५६ †

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र संख्या
विकलाङ्ग :		
अन्धे	४९	२,२४५
मूक अधिर	३४	२,२९०
लूले लैंगडे	८	५५२
मानसिक मजबूत	३	२२७
योग	९४	५,३१४

† Education in India, 1955-56, Vol I, pp 98-99

रोग-निर्णय.—लक्षण-सम्बन्धी अवरोधित व्यक्तियों को समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इनका रोग-निर्णय प्रायः मजबूरी का आविष्कार कहा जा सकता है। इनकी डाक्टरी परीक्षा आवश्यक है। इन्हें निर्देश तथा परामर्श चाहिए। इनके रोग-निर्णय की जिम्मेवारी शिक्षु-निर्देश तथा उपचार-गृहों को सौंप देना उचित है।

शिक्षण-संस्थाएँ.—रोग-निर्णय के पदचात् बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है : (१) बच्चों को किसी उपचार-गृह या मानसिक अस्पताल में रखना, (२) बच्चे को एक साधारण स्कूल में भरती करना और उसके अनुरूप किञ्चित् परिवर्तित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, एव (३) उसे एक विशेष स्कूल या संस्था में दाखिल करना। विशेष संस्थाएँ सात प्रकार की हैं : (१) अन्ध-विद्यालय, (२) मूक-बधिर-विद्यालय, (३) लूले-लैंगड़ों के शिक्षालय, (४) मानसिक मजबूरी के संस्थान, (५) श्रमालय, (६) बाल-अपराधियों की संस्थाएँ एवं (७) उपचार-गृह तथा निर्देश-केन्द्र।

भारत में मजबूरों की शिक्षा-व्यवस्था : मजबूरों की संख्या.—खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जन-गणना में मजबूर बच्चों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया है यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विकलाङ्गों तक की संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूरों की संख्या प्रति हजार 'बीस' हैं। इसी गणना के आधार पर, भारत में मजबूरों की संख्या ७० लाख निर्धारित की गयी है। इस आनुमानिक गणना का हम कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं। सार अर्थ यह है कि मजबूरों के लिए कोई भी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करते समय इनकी भिन्न-भिन्न श्रेणियों की संख्या जानना आवश्यक है।

प्रारम्भिक चेष्टाएँ.—अंग्रेज सरकार मजबूरों की शिक्षा के प्रति निचेष्ट एवं उदासीन रही। प्रारम्भ में इस ओर ईसाई मण्डलियों ने कुछ ध्यान दिया। सन् १८८३ में कुमारी एनी शार्प नामक एक प्रोटेस्टेण्ट महिला ने अमृतसर में एक स्कूल अन्धी लड़कियों के लिए खोला। सन् १९०३ में यह संस्था देहरादून स्थानान्तरित की गयी। सन् १८९० में कुमारी एस्कविथ ने पाल्पम-कोट्टाय में एक दूसरा स्कूल अन्धों के लिए खोला। तत्पश्चात् बलकृष्ण अन्ध-विद्यालय का नम्बर आता है, जिसे सन् १८८७ में श्री लालबिहारी शाह नामक एक भारतीय ईसाई ने स्थापित किया था। सन् १९०० में कुमारी एन्ना मिलार्ड ने बम्बई में अन्धों के लिए एक स्कूल खोला, जिसका वर्तमान नाम 'दादर स्कूल फॉर ब्लाइण्ड गर्ल्स' है।

अन्ध विद्यालय — हमारे देश में बीस लाख से अधिक अन्धे हैं, पर इस सख्या के किञ्चित् अंश को ही शिक्षा मिलती है।† अधिकांश सस्थाएँ स्व-सञ्चालित हैं। इन्हें हम अनाथालय भी कह सकते हैं। उन्हें सरकार से थोड़ा बहुत अनुदान मिलता है, पर उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है। ब्रह्म पद्धति पर बच्चों को अपनी मातृ भाषा के पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा एक दस्तकारा भी सीखता है। मुख्य उद्योग हैं चेत की बुनाई, टोकरी बनाना, निवार या टाट बुनना, मोमबत्ती का काम, जिल्दसार्जा, बढईगिरा, बुनाई कताई, इत्यादि। अन्धे प्रायः सगीत पदु होते हैं। कई सस्थाओं में इन्हें सगीत भी सिखाया जाता है।

अन्धों की शिक्षा की विशेष जरूरतों की ओर भारत सरकार ध्यान दे रही है। हाल ही में 'भारतीय ब्रह्म' की सृष्टि हुई है। अक्टूबर, १९५० ई० में, देहरादून में 'केन्द्रीय ब्रह्म मुद्रणालय' स्थापित हुआ है, जिसके द्वारा भारतीय ब्रह्म-साहित्य प्रकाशित किया जाता है। सन् १९५० में केन्द्रीय सरकार ने देहरादून में 'अन्ध (मौढ) प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित किया है। इस सस्था के अन्तर्गत दो वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया है, तथा प्रशिक्षणार्थियों को वाद्य लिपि तथा टाइप राइटिंग में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सस्था का एक और भी महत्वपूर्ण अङ्ग है 'सगीत शिक्षा'। सन् १९५८ में इस सस्था के अन्तर्गत एक महिला विभाग भी खोला गया है।

देश में अभी तक नेत्र हीन बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है। लेकिन सन् १९५१ में अजमेर तथा बाण्य (कच्छ) में इन बालकों के लिए पाठशालाएँ स्थापित हो जाने का जोड़, यह कमी कुछ हद तक दूर हो गयी है। इससे अतिरिक्त भारत सरकार नेत्र हीन बालकों के लिए देहरादून में एक आदर्श पाठशाला स्थापित करनेवाली है। आशा है कि निरूप भविष्य में यह कार्य पूरा हो जायगा।

नेत्र हीनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास्य कार्य को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने १९४७ ई० में शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत एक विशेष युनिट (इकाई) स्थापित की है, जिसका संचालन एक उप शिक्षा-सलाहकार के अधीन है। भारत-सरकार के समस्त प्रशिक्षित नेत्र हीनों को नौकरी दिलाने की समस्या पर्याप्त विवेक रूप में विद्यमान थी। इस समस्या को हल करने के लिए १९५५ में सरकार ने मद्रास में एक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य ही विभिन्न उद्योग धर्मों में नेत्र हीनों के उचित समुचित कार्य की तलाश करना तथा उन्हें नौकरी दिलाना है।

† Planning Commission *Social Welfare in India*, Delhi Publications Division 1955 p 21



चित्र १७—गेल-पद्धति द्वारा शिक्षा

‘बाल-अधिनियम’। यह नियम आन्ध्र प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर राज्यों और दिल्ली के सघीय क्षेत्र में लागू है। इसके अनुसार बालापराधी न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ इनकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ बालापराधियों का न्याय साधारण अदालतों में होता है। अपराधीगण बालापराधी कैदखानों में निरीक्षित रखे जाते हैं। आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में ‘किशोर बन्दी’ (बोस्टल स्कूल) अधिनियम लागू है। सन् १८९७ का ‘सुधार-विद्यालय अधिनियम’ सभी बड़े राज्यों तथा कुछ सघीय क्षेत्रों में लागू है।

सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएँ शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा धन-सम्बन्धी सहायता भी देती हैं, जिससे वे सीखे हुए व्यवसाय में लग सकें। इन संस्थाओं में अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ साथ क्रीड़ा (खेल-कूद), नाटक, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने एक पालन पोषण (देग्न-भाल) कार्यक्रम लागू किया है, जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा त्रिपुरा में सुधार-विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

उपचार—गृह तथा निर्देश-केन्द्र.—इन केन्द्रों में बच्चों तथा वयस्कों की मानसिक चिकित्सा उच्च स्तर पर होती है। हमारे देश में ऐसे केन्द्र बहुत कम हैं। बहुधा ये मानसिक अस्पतालों एवं बाल रक्षा गृहों से सलग्न होते हैं। २ मार्च, १९५५ के दिन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक बाल-निर्देश केन्द्र दिल्ली नर्सिंग महाविद्यालय में स्थापित किया है। भारत में यह सर्व प्रथम सरकारी संस्था है, जिसमें बच्चों की मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है।

प्रशासन.—मजबूरों की शिक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य की निजी शासन व्यवस्था है। कहीं पर प्रधान अधिकारी को ‘चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ सर्टीफाइड स्कूल’ कहते हैं, और कहीं ‘प्रवेशन अफसर’। किसी-किसी राज्य में तो प्रवेशन अफसर को बैधा हुआ वेतन भी नहीं मिलता है। पर उसके सिपुर्द जितने बच्चे किये जाते हैं, उनकी संख्या के अनुसार उसे मेहनताना मिलता है।

मजबूरों की संस्थाओं के खर्च के लिए चार स्रोतों से आय आती है : (१) सरकार, (२) स्थानीय निकाय, (३) विद्यार्थियों से आय, अर्थात् उनकी फी तथा उनके

मूक-बधिर विद्यालय.—बहुधा बधिर, मूक-बधिर तथा अन्य विकलांगों की शिक्षा का आयोजन अन्धों के साथ-साथ होता है। इनका पाठ्यक्रम अन्धों की नाई होता है। इन्हें कोई-न-कोई दस्तकारी सिखायी जाती है। पढ़ना और बोलना, ओष्ठ-वाचन और उच्चारण पर निर्भर रहता है। संगीत के बदले इन्हें चित्रकारी तथा मिट्टी का काम सिखाया जाता है।

लूले-लँगडों की शिक्षा.—अन्धों तथा मूक-बधिरों के लिए तो विशेष शिक्षा-संस्थाओं की आवश्यकता रहती है, पर लूले-लँगड़े तो साधारण स्कूलों में शिक्षा पा सकते हैं। इनके प्रशिक्षण में सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता है कि ये किस प्रकार अग्रागाम-सम्बन्धी उपकरणों का ठीक रीति से उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक को अपने नामुओं का उपकरण के साथ इस प्रकार नियमित करना पड़ता है कि वह उनका यथा रीति व्यवहार कर सके। यह अभ्यास बुनना, बटुईगिरी, इत्यादि द्वारा कराया जाता है। यह काम केवल विशेषज्ञों की देख-रेख में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार, इन अपाहिजों को शिक्षा के अतिरिक्त इलाज की जरूरत रहती है। यह चन्द्रोबस्त अस्पतालों में ही करना पड़ता है, पर शिक्षा साधारण बच्चों के साथ ही दी जाती है।

मानसिक मजबूतों के संस्थान.—अधिकांश मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि बाह्य और अन्तर्गत में असामञ्जस्य ही मानसिक रोग का मूल कारण होता है। इस कारण, इन मानसिक मजबूतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहता है। इन रोगियों को अपनी रुचि तथा अपनी गति के अनुसार सीखने दिया जाता है। रोद की बात है कि हमारे देश में ऐसे बच्चों के लिए केवल तीन संस्थान ही हैं। कुछ मानसिक अस्पताल हैं, पर इनमें मानसिक रोगी बच्चों के इलाज की विशेष व्यवस्था नहीं रहती है।

बनायालय.—देश में हजारों अनायालय अनाथ तथा आबारा बच्चों के लिए स्थापित हैं। मुख्यतः ये गैरसरकारी संस्थाएँ हैं। रामकृष्ण मिशन, क्रिश्चियन ईसाई-मण्डल, कस्तूरबा अनुदान समिति, सेल्वेदान-आर्मी, इत्यादि कुछ आदर्श मण्डलियों ने बाल-कल्याणार्थ अनेक अनायाथनों की स्थापना की है। यह एक रोदनक बात है कि हमारे देश में स्थित कुछ ऐसी अनुमोदिन संस्थाएँ भी हैं जो कि निरगन्ध बाल-वाक्याओं का अनुचित उपयोग भी करती हैं।

बाल-अपराधियों की संस्थाएँ.—बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः गन्ध सरकारी के उत्तरदायि में आती है। इस दिग्ग में तीन प्रकार के बालदे हैं। मयन है

६ प्रशासन की कमजोरियों — बाल अधिनियम अभी पूरे देश में क्रियान्वित नहीं हुए हैं, और जहाँ हुए भी हैं, वहाँ भी उनका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ममी राज्यों में अफसरों की कमी है।

४. स्वास्थ्य एवं अनुशासन

भूमिका — किसी भी देश की शक्ति, जनता व विकास पर निर्भर रहती है, न कि ब्रह्म ज्ञान शक्ति पर। जनता का स्वास्थ्य व लिए सबसे अधिक आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा अनुशासन। इतिहास साक्षी है कि जो देश स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहना है तथा अन्य देशों से सहायता की अपेक्षा रखता है, उसकी स्वतन्त्रता कदापि स्थायी नहीं रही है।

यथेष्ट परिश्रम के पश्चात् हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है। हम फिर से पराधीनता की चेष्टियाँ नहीं पहनना चाहते हैं। पर यदि हममें वीरता की चिनगारी प्रज्वलित न रही, यदि हमारे देशवासी शारीरिक दौर्बल्य व लथ्थ रहें, यदि हममें उचित अनुशासन न रहा, तो चायद हम फिर से अपनी नगर्जित स्वाधीनता को ग्ने बैठे। अतएव हमारी प्रत्येक राष्ट्रीय योजना का एक अनिवार्य अंग होगा स्वास्थ्य एवं अनुशासन। स्कूल तथा कालिज व विद्यार्थियों की ओर विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। ये ही हमारे देश के भावी नागरिक हैं। इस विषय के अन्तर्गत आते हैं (१) शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद, (२) विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा (३) युवक कल्याण तथा (४) राष्ट्रीय अनुशासन योजना।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद भूमिका — स्कूल तथा कालिजों में कयायद तथा खेल-कूद की कुछ न कुछ व्यवस्था अंग्रेजों के शासन काल से ही थी। प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव के कारण, कयायद या ड्रिल निवृत्त सैनिकों, अफसरियों या पहलगानों द्वारा संचालयी जाती थी। पश्चात्त्य खेलों का प्रचलन अधिक था, एवं देशी खेलों की उपेक्षा की जाती थी।

नवीन जागृति — स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे स्कूलों तथा कालिजों में 'ड्रिल' के बदले 'शारीरिक शिक्षा' का उदय हुआ। प्राथमिक स्कूल के प्रथम वर्ग से लेकर स्नातक शिक्षा की समाप्ति पर्यन्त, शारीरिक शिक्षा हमारे स्कूल तथा कालिजों में एक अनिवार्य विषय है। प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा विभाग के निजी पाठ्यक्रम हैं, पर ये पाठ्यक्रम मुचारूप से चलाये नहीं जा रहे हैं। उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते, ७५ प्रति शत शिक्षा संस्थानों के खेल-कूद के निजी मैदान नहीं हैं, और ६० प्रति शत संस्थानों के स्कूल गृह अस्वास्थ्यकर हैं।

द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों से आय एवं (४) दान, चन्दा, आदि। सन् १९५५-५६ में इस शिक्षा पर २३-९६ लाख रुपये व्यय हुए थे।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने मद्रास तथा बम्बई में मजदूरों के लिए दो नौकरा-विनिमय केंद्र स्थापित किये हैं। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्वे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ दी जाती हैं।

कतिपय समस्याएँ.—इस प्रकार मजदूरों की शिक्षा का आयोजन इस देश में किया गया है। मजदूरों की मजदूरियों की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है, पर पैसे की मजदूरी के कारण, सभी मजदूर हैं। कतिपय ऐसी समस्याएँ हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :

१. **मजदूरों की संख्या का निर्णय.**—मजदूर विभिन्न प्रकार के हैं। कोई भी शिक्षा-योजना इन विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर रहेगी। पर हमारे देश की जन-गणना रिपोर्टों से इसका पता नहीं चलता है। हमारे देश की भावी जन-गणना रिपोर्ट इस ओर ध्यान दें।

२. **उत्तम तथा सुव्यस्थित संस्थाओं की आवश्यकता.**—हमारे देश में मजदूर बच्चों के लिए शिशु-शालाएँ, वृद्ध-वृद्धाओं के लिए कल्याण-गृह तथा मजदूरों के लिए पुस्तकालय, दस्तकारी-शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए।

३. **देहाती पाठ्य-क्रम की ओर झुकाव.**—बहु संख्यक मजदूर गाँवों में रहते हैं। इस कारण उनके पाठ्य-क्रम में देहाती एवं कृषि-शिक्षा की ओर अधिक ध्यान रहे, ताकि यह शिक्षा मजदूरों को उपयुक्त ग्राम-वासी बनावे।

४. **यथेष्ट अर्थ की आवश्यकता.**—अर्थाभाव के कारण, मजदूरों की शिक्षा की ओर, उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि हमारा पंचवर्षीय योजनाएँ इस ओर ध्यान देवेंगी। स्वसंचालित संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान-नीति निश्चित होनी चाहिए।

५. **प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत.**—सन् १९५५-५६ में केवल ६७५ शिक्षक मजदूर बच्चों के विद्यालयों में काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था।

राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल.—इस दल की स्थापना १५ जुलाई, १९४४ में हुई थी। इसमें स्कूल तथा कालिजों के १३-२६ वयोवर्ग के छात्र और छात्राएँ भरती हो सकती हैं। इसमें तीन दुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों दुकड़ियों की बल, स्थल तथा वायु शाखाएँ होती हैं। दल की प्रगति का पता अधो लिखित तालिका से चलेगा :

तालिका २८
राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की प्रगति†

तारीख	बालक		बालिकाएँ		योग
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	
१-१-१९४९	१४,९६०	२०,१६०	—	—	३५,१२०
१-१-१९५०	२२,१८४	३६,१८०	९३	—	५८,४५७
१-१-१९५१	२३,३४९	४५,१०५	२७९	—	६८,७३३
१-१-१९५२	२३,५७०	४७,६६३	२७९	—	६९,५१२
१-१-१९५३	२६,१०३	५३,५१५	५२७	—	८०,१४५
१-१-१९५४	२८,२१७	५४,४००	६२०	—	८३,२३७
१-१-१९५५	३९,०८५	५६,६१७	२,७२८	२,९१४	१,०१,३४४
१-१-१९५६	४६,६८०	६६,३०७	३,२५५	५,१४६	१,२१,३८८
१-१-१९५७	५२,१४७	७०,८२९	३,९९९	६,७२७	१,३३,७०२
१-१-१९५८	६४,४७५	७६,५३०	५,७३०	९,२७०	१,५६,००५
१-१-१९५९	७३,४०७	९२,२५८	९,२४६	१७,३४२	१,९२,२५३

केन्द्रीय सरकार की चेष्टाएँ.—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर सम्प्रति आकर्षित हुआ है। मन्त्रालय का एक संविभाग 'व्यायाम तथा मनोरंजन' की देखरेख करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में मण्डल ने 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-योजना' तैयार की है। शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कालिजों के विकास के लिए यह योजना तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य अखाड़ों एवं व्यायाम-शालाओं आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इस मण्डल ने अपनी १० नवम्बर, १९५९ की बैठक में ठहराव किया : (१) किशोरों की शारीरिक उन्नति के लिए एक शारीरिक मान-दण्ड स्थिर किया जाय, जिसमें पहुँचे बिना विद्यार्थियों को शालान्त परीक्षा पास न होने दिया जाय; (२) प्रत्येक शिक्षण-संस्था में प्रति २५० विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक हो; एवं (३) जिन संस्थाओं की छात्र संख्या ७५० से अधिक हो, वहाँ एक उत्तर-स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। वह संस्था की शारीरिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी गिना जावे।†

खेल-कूद का आयोजन.—खेल-कूद के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत-सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किये हैं :

१. अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद् की स्थापना;
२. विभिन्न राज्यों में राज्य खेल-कूद-परिषदों की स्थापना; एवं
३. 'राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा : भूमिका.—भारत के स्वतन्त्र होने पर हमें अपने सैनिक प्रबन्ध का कार्य अपने कंधों पर उठाना पड़ा है। सैनिक शिक्षा प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं गौरव की वस्तु है। जहाँ देश के नवयुवकों को पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है, वहाँ इसका होना भी आवश्यक है। इससे नवयुवकों में अनुशासन, आत्म-निर्भरता, स्वाभिमान, स्वदेश-प्रेम और आशाकारिता की भावना का उदय होता है। आज हमारे स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल (एन० सी० सी०) एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल (ए० सी० सी०) की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा-संस्थानों के ग्राह्य 'लोक-सहायक सेना' का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल.—इस दल की स्थापना १५ जुलाई, १९४४ में हुई थी। इसमें स्कूल तथा कालिजों के १३-२६ वयोवर्ग के छात्र और छात्राएँ भरती हो सकती हैं। इसमें तीन दुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों दुकड़ियों की जल, स्थल तथा वायु-शाखाएँ होती हैं। दल की प्रगति का पता अधो-लिखित तालिका से चलेगा :

तालिका २८
राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की प्रगति†

तारीख	बालक		बालिकाएँ		योग
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	
१-१-१९४९	१४,९६०	२०,१६०	—	—	३५,१२०
१-१-१९५०	२२,१८४	३६,१८०	९३	—	५८,४५७
१-१-१९५१	२३,३४९	४५,१०५	२७९	—	६८,७३३
१-१-१९५२	२३,५७०	४६,६६३	२७९	—	६९,५१२
१-१-१९५३	२६,१०३	५३,५१५	५२७	—	८०,१४५
१-१-१९५४	२८,२१७	५४,४००	६२०	—	८३,२३७
१-१-१९५५	३९,०८५	५६,६१७	२,७२८	२,९१४	१,०१,३४४
१-१-१९५६	४६,६८०	६६,३०७	३,२५५	५,१४६	१,२१,३८८
१-१-१९५७	५२,१४७	७०,८२९	३,९९९	६,७२७	१,३३,७०२
१-१-१९५८	६४,४७५	७६,५३०	५,७३०	९,२७०	१,५६,००५
१-१-१९५९	७३,४०७	९२,२५८	९,२४६	१७,३४२	१,९२,२५३

† India, 1959, p 106.

केन्द्रीय सरकार की चेष्टाएँ.—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर सम्प्रति आकर्षित हुआ है। मन्त्रालय का एक संविभाग 'व्यायाम तथा मनोरंजन' की देखरेख करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में मण्डल ने 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-योजना' तैयार की है। शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कालिजों के विकास के लिए यह योजना तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य अखाड़ों एवं व्यायाम-शालाओं आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इस मण्डल ने अपनी १० नवम्बर, १९५९ की बैठक में ठहराव किया : (१) किशोरों की शारीरिक उन्नति के लिए एक शारीरिक मान-दण्ड स्थिर किया जाय, जिसमें पहुँचे बिना विद्यार्थियों को शालान्त परीक्षा पास न होने दिया जाय; (२) प्रत्येक शिक्षण-संस्था में प्रति २५० विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक हो; एवं (३) जिन संस्थाओं की छात्र संख्या ७५० से अधिक हो, वहाँ एक उत्तर-स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। वह संस्था की शारीरिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी गिना जावे।†

खेल-कूद का आयोजन.—खेल-कूद के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत-सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किये हैं :

१. अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद् की स्थापना;
२. विभिन्न राज्यों में राज्य खेल-कूद-परिषदों की स्थापना; एवं
३. 'राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा : भूमिका.—भारत के स्वतन्त्र होने पर हमें अपने सैनिक प्रबन्ध का कार्य अपने कंधों पर उठाना पड़ा है। सैनिक शिक्षा प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं गौरव की वस्तु है। जहाँ देश के नवयुवकों को पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है, वहाँ इसका होना भी आवश्यक है। इससे नवयुवकों में अनुशासन, आत्म-निर्भरता, स्वाभिमान, स्वदेश-प्रेम और आशाकारिता की भावना का उदय होता है। आज हमारे स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी टल (एन० सी० सी०) एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी टल (ए० सी० सी०) की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा-संस्थानों के द्वारा 'लोक-सहायक सेना' का आयोजन किया जा रहा है।

१. सन् १९५४ से अन्तर्विदनविद्यालय समारोह का आयोजन तथा अन्तर्कालिज समारोहों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना;

२. युवक-नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाना;

३. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक यात्राओं के सम्बन्ध में किराये के सुभीते;

४ युवकों के लिए छात्रावासों का बन्दोबस्त;

५. विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारों को युवक कल्याण मण्डल स्थापित करने के लिए तथा यथोचित कार्यों के सम्पादन के निमित्त अनुदान;

६. कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन सहन का सर्वेक्षण;

७. छात्रेतर युवक-कल्याण मण्डलों की स्थापना;

८. विद्यार्थियों में शरीरश्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के लिए श्रम-दान तथा समाज-सेवा योजना का लागू किया जाना; तथा

९. अन्तर्कालिज समारोह योजना. - प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में व्यायाम-शाला, सन्तरण-जन्दाघराय, खुले रंगमंच, आदि की व्यवस्था ।

उपर्युक्त कार्यकलापों की बदौलत हमारे देश के युवकों में नवीन जागृति हुई है । हमारे विश्वविद्यालयों में ललित कला, संगीत, नाट्याभिनय का नवीन जन्म हो रहा है । विद्यार्थीगण समाज-सेवा में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको नेतृत्व का प्रशिक्षण मिल रहा है तथा उनमें शरीर श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा हो रही है । लेकिन विद्यार्थियों के श्रम-दान का ध्येय आर्थिक न हो । इसका उद्देश्य सदा शैक्षणिक रहे ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना : पूर्व-पृष्ठिका.—हाल ही में, इस देश में एक नवीन योजना आरम्भ हुई है । इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों की वर्तमान उद्वण्डता एवं उच्छ्वलता को रोकना तथा उन्हें अनुशासित करना । इस योजना की भावना श्री जवाहरलाल नेहरू के एक अभि-भाषण से शुरू होती है । सन् १९५४ में उन्होंने दिल्ली के एक राष्ट्रीय सैनिक टल को सकट काल में देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की चर्चा की । इसे

सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल.—स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जो राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं पाते, 'सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल' की स्थापना की गयी है। इसके सैनिक १२-२३ वयोवर्ग के होते हैं। प्रशिक्षण में सैनिक की अपेक्षा शैक्षणिक आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्कूलों से चुने जाते हैं, और इन्हें सेना तथा राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के कर्मचारीगण ट्रेनिंग देते हैं। सन् १९५२ में इस दल का आयोजन किया गया था, जब कि शिक्षार्थियों की संख्या ७०,००० थी। सन् १९५८ के अन्त में इनकी संख्या ८,५७,९४७ पहुँची।†

लोक-सहायक सेना.—सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में पुनर्संगठित हुई थी, अब 'लोक-सहायक-सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में लगभग पाँच लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है। इस सेना में, भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष भरती हो सकते हैं।

नये रँगल्टों को तीस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तथा शिविर की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको पन्द्रह रुपये दिये जाते हैं।

युवक-कल्याण.—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् युवक-कल्याण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्रायः प्रत्येक स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय में कम से कम एक 'युवक-कल्याण समिति' रहती है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पाठान्तर कार्यों का आयोजन एवं संयोजन है। संस्थानिक समितियों के अतिरिक्त अनेक जगह क्षेत्रीय कमिटियाँ भी होती हैं, जो विद्यार्थियों के खेल-कूद, समारोह, रहने की व्यवस्था, आदि की देख-भाल करती हैं।

सन् १९५१ में संयुक्त राष्ट्र-संघ ने शिमला में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस गोष्ठी ने युवक-कल्याण के प्रसार के लिए विविध योजनाओं पर विचार किया। मई, १९५५ में केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय में एक युवक कल्याण संविभाग स्थापित हुआ। युवक-कल्याण के क्षेत्र के मुख्य गति-विधियों का उद्देश्य इस प्रकार किया जा सकता है :

कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी तत्कालीन पुनर्वास उप मन्त्री श्री० जे० के० भोंसले को सौंपी गयी। जापान तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर, श्री भोंसले ने इस नवीन योजना की एक रूप रेखा तैयार की।

इसका श्रीगणेश दिल्ली के 'कस्तूरबा निवेदन' में हुआ। सन् १९५४ के अंत में श्री नेहरू ने इस संस्था के शिक्षार्थियों के कार्यमूलाप का परिदर्शन किया। वे इससे इतने सतुष्ट हुए कि उन्होंने इस योजना को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया।

विस्तार.— योजना का कार्यक्रम सम्पूर्ण दिल्ली, फरीदाबाद, राजपुरा, उड्डास-नगर, जलन्धर में विस्तारित हुआ। प्रथम वर्ष अर्थात् १९५४-५५ में इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक लाख रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष यह योजना १९ शिक्षा-संस्थानों में लागू हुई, तथा २४,८८१ विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये। सन् १९५६ के अंत में ६९,००० छात्र-छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए पाँच करोड़ रुपयों की माँग है।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का 'व्यायाम और मनोरंजन सविभाग' इस योजना का परिचालन करता है। इस योजना को १९५९-६० में लागू करने के लिए आय व्ययक्रम में बीस लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है। इस साल जिन नयी संस्थाओं में योजना चालू की गयी/या की जायगी, उनकी संख्या इस प्रकार है :

तालिका २९

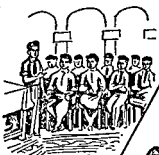
राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की व्यवस्था, १९५९-६०†

राज्य	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
दिल्ली	१६	६,५६१
पञ्जाब	८०	४८,२६८
मध्य प्रदेश	३	१,०००
उत्तर प्रदेश	८	२,४५०
बम्बई	२५	५,०२०
पश्चिम बंगाल	२६	५,१५०
कुल...	१५८	६८,४४९

† भारतीय समाचार, २५ सितम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९।



युवक
उत्सव



प्रशिक्षण
शिविर



अन्तर्कालिज
समारोह



यात्रा के
सुभीते

युवक कार्याण



श्रमदान तथा
समाजसेवा



छात्रावास



छात्रेतर युवक-
कल्याण मण्डल



छात्रों की रहन-सहन
का सर्वेक्षण



युवक-कल्याण
मण्डल

ग्यारहवाँ अध्याय

कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना

पिछले पन्नों में हमारे देश की मुख्य समस्याओं की आलोचना की गयी है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध काफी असन्तोष था। भारत के विभिन्न भागों में कुछ संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिनका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा देना। अधिकतर संस्थाएँ अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध खड़ी न रह सकीं, वे बिलीन हो गईं। पर कुछ अभी भी अपना सिर ऊँचा किए खड़ी हैं। इनमें से मुख्य हैं : गुरुकुल काँगड़ी, एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, विश्व-भारती, विद्यापीठ, दिल्ली जामिया मिलिया, एवं हिन्दुस्थानी नालीमी सघ, सेवाग्राम। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

गुरुकुल काँगड़ी

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, हिन्दू धर्म सुधार का आन्दोलन आरम्भ हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने घोषणा की, “हमें वेद का पुनरुद्धार करना है।” इससे अनुसार, गुरुकुल प्रणाली का प्रचार भी आवश्यक समझा गया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कई गुरुकुल स्थापित हुए। जिनमें गुरुकुल काँगड़ी मुख्य है। इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द ने सन् १९०३ में हरिद्वार के पास काँगड़ी में की।

संस्था का उद्देश्य है संस्कृत साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य का अध्ययन, प्राचीन राष्ट्रीय शिक्षण, भारत के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का अध्ययन। इसीलिए यहाँ सागोपाग वेद और अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी, रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भू विज्ञान, कृषि, पाश्चात्य दर्शन, अर्थ शास्त्र तथा आयुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।

शहर के कोलाहल से दूर, प्रकृति देवी की गोद में यह संस्था स्थित है। यहाँ सानास प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थी और शिक्षक साथ-साथ रहते हैं।

११ और १२ जुलाई, सन् १९५९ की एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना के बारे में निरीक्षकों की बैठक में यह सुझाव रखा गया कि या तो जिन स्थानों पर अनुशासन-योजना चल रही है, वहाँ उनका काम बढ़ाया जाय, अथवा कुछ और राज्यों में भी इसका काम शुरू किया जाय। एक सुझाव यह भी रखा गया कि सब राज्यों के कुछ स्कूलों में यह योजना चान्द की जाय। †

योजना के अङ्ग—योजना में शारीरिक शिक्षा, हिल तथा खेल-कूद-द्वारा की जाती है। नैतिक शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्म-निर्भरता, अभिमान, स्वदेश-प्रेम और आशाकारिता की भावना का उदय हो। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों की कम उम्र में ही दिया जाता है, ताकि इन भावनाओं की नींव पक्की हो।

शिक्षकों का प्रशिक्षण—शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाये जाते हैं, जिनमें त्रैमासिक ठोस कोर्सों की व्यवस्था रहती है। अभी तक एक हजार से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं। आशा की जाती है कि सन् १९६१ के पश्चात् यह कोर्स शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अङ्ग रहेगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय कुशल निरीक्षकों की एक केन्द्रीय सूची तैयार कर रहा है।

उपसंहार—२८ मई, १९५९ में केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने नौ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है। श्री हृदयनाथ कुंजरु इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को एक ऐसी योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मुख्यतः निम्न-लिखित बातों की जाँच करनी होगी :

१. देश में वर्तमान प्रचलित शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-गठन एवं अनुशासन विषयक विभिन्न योजनाओं की परीक्षा करना।

२. ऐसे सुझाव देना, जिनसे उपर्युक्त क्षेत्रों में दोहराव बन्द हो तथा एक समन्वय स्थापित हो।

३. उपर्युक्त क्षेत्रों के उत्तरोत्तर विकास तथा उन्नति के लिए एक उपर्युक्त योजना प्रस्तुत करना।

समिति इन विषयों की जाँच करेगी : बाल्चर तथा गर्लस गॉर्ड्स, राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल, अनुशासन एवं चरित्र संगठन योजना, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, तथा युवक-कल्याण की विविध योजनाएँ।

४. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, एवं

५. पराश्रयों में राह छात्राएँ भी बैठ सकती हैं। इसका लाभ अनेक महिलाएँ उठाती हैं, जो कि कालिजों में नियमित रूप से सदा अध्ययन नहीं कर सकतीं।

सन् १९३० में विश्वविद्यालय का सदर मुकाम बम्बई में स्थानान्तरित हुआ। क्योंकि बम्बई के एक करोड़पति ने अपनी माता, श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकुरसी, की पुण्य स्मृति में लाखों रुपये दान दिये। इसी कारण इस विश्वविद्यालय का वर्तमान नामकरण हुआ। सन् १९५१ में, इसे वैधानिक स्वीकृति दी गयी है। विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त कालाञ्च बम्बई, बौध्दा, पूना, सुरत, भावनगर तथा अहमदाबाद में स्थित हैं। गत चालीस वर्षों से यह संस्थान हमारे देश की महिलाओं की जाग्रति और सामाजिक क्रान्ति में बड़ा योग दे रहा है।

विश्व-भारती

सन् १८६३ में कवि स्वीड्रनाथ ठाकुर का पिता, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ने परमार्थ साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना कलकत्ते का पास बालपुर ग्राम में की थी। इसका नामकरण उन्होंने शान्ति निरन्तर किया। जिस स्थान में वे साधना किया करते थे, वहाँ एक सगममर गिला पर बँगला भाषा में खुदा हुआ है

तनि आमार प्राणेर आराम, मनेर आनन्द, आत्मार शान्ति ।†

सन् १९०१ में गुरुदेव ने इसी स्थान में बच्चा के लिए एक प्रायोगिक विद्यालय स्थापित किया, जिसका उद्देश्य एसी शिक्षा देना था जो प्राकृतिक हो जहाँ बच्चे परिवार का वातावरण का अनुभव करें और वे पारस्परिक विश्वास और उत्साह के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन करें। सन् १९२१ में यही विद्यालय विश्व भारती के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप में परिणत हुआ। कबिबर ने सरकारी स्वीकृति की परवाह न की। क्योंकि वे अपनी संस्था को सरकारी कायदों से शृंगलाबद्ध नहीं रखना चाहते थे। अथाभाव के कारण उन्हें भटकना पड़ा, पर उन्होंने अपने आदर्शों का बलिदान न करना चाहा। स्वाधीन भारत में ही इस विश्वविद्यालय को भारतीय संसद द्वारा सन् १९५१ में वैधानिक स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं

† अर्थात् वे मेरे प्राण के आराम मन के आनन्द एवं आत्मा की शान्ति हैं।

छः से आठ वर्ष की उम्र में, यहाँ बालक प्रविष्ट होता है; चौदह वर्ष के अध्ययन के बाद, यह स्नातक तथा दो वर्ष पश्चात् वाचस्पति होता है। गुरुकुल का आयुर्वेदिक विभाग विख्यात है। यहाँ विविध प्रकार की दवाइयाँ प्रस्तुत होती हैं। यहाँ का पाठ्य-क्रम पंच-वर्षीय होता है, और १५-१९ वयोवर्ग के विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं।

गुरुकुल में सहशिक्षा निषिद्ध है। बालकों को चौबीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उन्हें निरामिष भोजन करना पड़ता है। विद्यार्थियों की दिनचर्या प्राचीन गुरुकुलों की नाई होती है: प्रातःकाल उठना, शारीरिक परिश्रम, हवन, इत्यादि। आश्रम को साफ-सुथरा उन्हें ही रखना पड़ता है।

एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय का विकास पूना के एक सामान्य स्कूल से हुआ, जिसकी स्थापना सन् १८९६ में आचार्य कर्वे ने हिन्दू विधवाओं के लिए की थी। धीरे-धीरे इस छोटे से स्कूल में कई संस्थाएँ संलग्न हुईं, जैसे : एक छात्रावास, एक प्राथमरी स्कूल तथा एक प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र। संस्था इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक माता-पिता अपनी कुर्बानी कन्याओं को छात्रावास में रखने लगे।

इससे आचार्य कर्वे का उत्साह बढ़ा और उन्होंने भारतीय छात्राओं के लिए एक उच्च शिक्षा योजना आरम्भ की। उनका कथन है कि नर और नारियों का पाठ्य-क्रम समान नहीं हो सकता, कारण दोनों के जीवन-क्षेत्र ही विभिन्न हैं। इसीलिए उन्होंने महिलाओं की आवश्यकता के अनुकूल उच्च शिक्षा का एक पाठ्यक्रम तैयार किया। उन्होंने यह भी तय किया कि यह शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय। कारण, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास निज भाषा के द्वारा ही हो सकता है।

सन् १९१६ में आचार्य कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है। कारण, यहाँ भारत के कोने-कोने से छात्राएँ अध्ययन के लिए आती हैं। विश्वविद्यालय की अधोलिखित विशेषताएँ हैं, जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं पायी जाती :

१. विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए है;
२. इसके स्वीकृत कालिज देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं;
३. पाठ्य-क्रम में स्त्रियों के लिए उपयोगी अनेक विषयों का समावेश है, जैसे : संगीत, चित्रकला, नाट्य शास्त्र, यह विज्ञान, आदि;

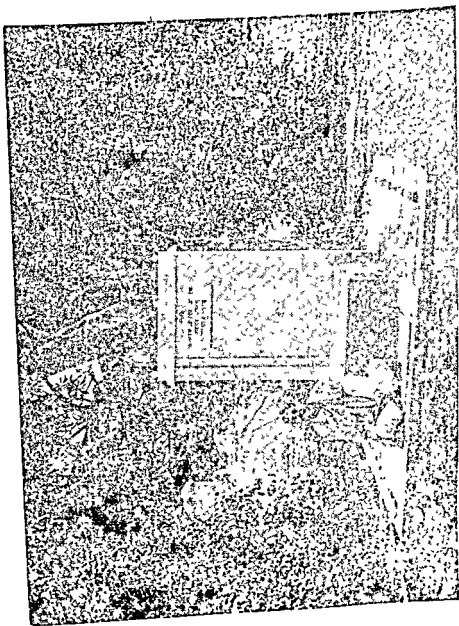
१. विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन का अध्ययन,
२. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनुसंधान,
३. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को उनकी मौलिक एकता व आधार पर पश्चिम के विद्वानों और संस्कृत के निष्कट पहुँचाना, एवं
४. सहबन्धुत्व का अनुभव करते हुए पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, जिससे विश्व-बन्धुत्व और विश्व एकता सम्भव हो सके ।†

विश्व भारती एक सादास विश्वविद्यालय है, जहाँ भारत व विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते हैं तथा प्राध्यापकगण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के छात्र तथा दर्शकगण यहाँ सदा आते जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहाँ नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के लिए विशेष उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे बंगला, हिंदी, संस्कृत, पार्सी, चीनी और तिब्बती भाषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इत्यादि। भारतीय कला तथा नृत्य की शिक्षा का भी यहाँ विशेष प्रबंध है। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में प्रिन्सिपल कुछ अतिरिक्त फी (ग्रन्ट) दिये कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स का अध्ययन नियमित या अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, यद्यपि कि वह उस विषय की ओर विशेष अभिरुचि दिखलावे।

विश्वविद्यालय में मुख्यतः नौ कालिजें हैं— विद्या भवन (उप-स्नातक एवं उत्तर-स्नातक कक्षाएँ तथा अनुसंधान), शिक्षा भवन (उच्चतर माध्यमिक स्कूल), कला भवन (ललित कला एवं क्राफ्ट), संगीत भवन (संगीत एवं नृत्य), प्रिन्सिपल भवन (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय), शिल्प-मंदिर (कुटीर शिल्प प्रशिक्षण केंद्र)। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विख्यात है जहाँ लगभग दो लाख पाण्डुलिपियों का संग्रह है।

दुनिया के रंगड़े झगड़े से दूर, शान्ति निकेतन में पूर्ण शान्ति विराजती है। नील गगन के नीचे आरक्षकतानुसार कक्षाएँ लगती हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा के अनुकूल विषय का चुनाव कर सके। चित्रकला, नाट्य, संगीत, काष्ठकला, खुदाई का काम, मास्कर्य मॉय, इत्यादि विषयों की शिक्षा भी यहाँ व्यवस्था है। यह व्यवस्था अनेक विश्वविद्यालयों में नहीं रहती है। विशेषतः इनका अध्यापन करते हैं।

विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना जाग्रत करना विश्व भारती का एक महान उद्देश्य है। लूले लैंगडे, अन्धे-बुंग तथा अन्य अपाहिजों की सेवा का गीटा इस विश्व



चित्र १९—सस-पण की छाया में गुरुदेव (शान्ति-निकेतन)

कतिपय विद्यापीठ कुछ न कुछ कार्य अश्वमेव चञ्चते रहे, जैसे : खादी प्रचार, बुनियादी शिक्षा, ग्राम सुधार आदि । स्वातन्त्र्योत्तर काल में इनका पुनरुद्धार हुआ । उदाहरण स्वरूप, आज गुजरातविद्यापीठ, अहमदाबाद, निम्न लिखित संस्थाएँ या कार्यक्रम चला रहा है :

१. बुनियादी प्रयोगिक हाईस्कूल—यह एक उत्तर-बुनियादी हाईस्कूल है ।
२. महादेव देसाई समाज सेवा महाविद्यालय—मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए तीनवर्षीय पाठ्यक्रम ।
३. बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय—प्राथमिक शिक्षकों के लिए ।
४. राष्ट्र भाषा प्रचार—तीन मुख्य कार्य :
(१) कथाएँ चलाना, (२) गुजरात में राष्ट्र-भाषा परीक्षाओं का संचालन, एवं (३) पुस्तक प्रकाशन ।
५. पुस्तकालय—जहाँ करीब एक लाख पुस्तकें हैं ।
६. बल्लभ विद्यालय, नोचासन सेवा-केन्द्र—अनुसूचित जातियों में काम करने के लिए ग्राम सेवकों को तैयार करना ।
७. अम्बेठी शुद्ध केन्द्र—आदिवासी बच्चों के लिए, एक आश्रम स्कूल तथा समाज शिक्षा केन्द्र ।†

जामिया मिलिया, दिल्ली

जामिया मिलिया की स्थापना असहयोग आन्दोलन के समय सन् १९२० में हुई थी । आरम्भ से ही यह विद्यापीठ अपना सिर ऊँचा किये हुए सेवा रत है । इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी, पर पाँच वर्ष पश्चात् यह सत्था दिल्ली में स्थानान्तरित हुई ।

जामिया मिलिया का ध्येय नौजवानों को सकारा नौकरी के लिए तैयार करना नहीं था । इसका उद्देश्य नवयुवकों को आदर्श नागरिक बनाना है — ऐसे नागरिक, जिनका अपनी राष्ट्रीय सस्कृति के प्रति प्रेम हो, जिनके हृदय में देश भक्ति भरी पड़ी हो और जो देशोन्नति के लिए सदा भरसक प्रयत्न किया करें । पाठ्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक विषय कूट-कूट कर भरे गये हैं, पर उसमें पाश्चात्य विषयों का भी समावेश है । यहाँ सभी कौम के विद्यार्थी—मुसलमान तथा गैर मुसलमान—अध्ययन करते हैं, पर उनकी शिक्षा में उनके व्यक्तित्व के विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाता है ।

विद्यालय ने उठाया है। विद्यार्थियों को आसपास के गाँवों में जाना पड़ता है तथा उन्हें ढालतों या पतितों की उन्नति की ओर लक्ष्य रखना पड़ता है, ताकि इन गरीबों का जीवन किञ्चित् सुव्यवस्थित हो।

शान्ति-निकेतन से एक मील दूरी पर पश्चिम की ओर 'श्रीनिकेतन' है। यह एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था है, और विश्वभारती का एक भाग है। श्रीनिकेतन की स्थापना गुरुदेव ने सन् १९२१ में की थी। तभी से यह ग्राम-सुधार तथा ग्राम-शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा है।

गुरुदेव के देहावसान को आज दस से अधिक वर्ष बीत गये हैं, पर विश्व-भारती के रोम-रोम में उनके व्यक्तित्व की छाप विद्यमान है। संस्था के वातावरण से कविवरु जैसे फूट उठता है — गाँव की सादगी, कोपई नदी का कल-कल रव, बाग-बगीचे की सुरम्य हरीतिमा, शुष्क पत्तों की मर्मर ध्वनि तथा पक्षियों का अजस्र कर्ण मधुर संगीत ! हम कह सकते हैं कि शान्ति-निकेतन को प्रकृति का वरदान है। विश्व-भारती भारतीय संस्कृति का केन्द्र है तथा अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान का विद्यापीठ है। इस संस्था के जन-हित तथा समाजसेवा-सम्बन्धी कार्य स्तुत्य एवं श्लाघ्य हैं।

विद्यापीठ

सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन के समय, कतिपय राष्ट्रीय विद्यापीठ भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित हुए, जैसे : पूना, अहमदाबाद, बनारस, लाहोर, पटना, अलीगढ़, (बाद में दिल्ली में स्थानान्तरित)। इनका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश के नौजवानों को ऐसी उच्च शिक्षा देना कि उनके हृदय में राष्ट्रीय भाव प्रस्फुटित हो उठे और वे देशोद्धार के संग्राम में जुट पड़े। अंग्रेजी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा यह शिक्षा सम्भव न थी।

इस उद्देश्य को सामने रखते हुए विद्यापीठों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसमें भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया गया, तथा हिन्दी एक अनिवार्य विषय रखा गया। इनमें शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जाती थी। विद्यापीठ निजी डिग्रियों तथा डिप्लोमा प्रदान करते थे। अनेक देश-भक्तों ने अल्प वेतन स्वीकार कर विद्यापीठों में अध्यापन का कार्य स्वीकार किया, पर असहयोग आन्दोलन की शिथिलता के साथ-साथ दिल्ली की जामिया-मिलिया के सिवा सभी विद्यापीठ बन्द हो गये। नौकरों के लिए इन विद्यापीठों के डिग्री डिप्लोमाओं का मान्यता नहीं दी गयी। तब फिर वहाँ विद्यार्थीगण कैसे अध्ययन कर सकते थे ! टाल-रोटी की समस्या जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है।

१३ समाज शिक्षा प्रकाशन-चन्द्र — यहाँ नवशिक्षित वयस्कों की शिक्षा के विषय में अनुसन्धान किया जाता है, तथा उनके उपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है।

आत्मत्याग व्रत लेनेवाले व्यक्तियों के द्वारा, इस संस्था का सञ्चालन होता है। ये केवल २००-५०० रु० मासिक वेतन लेते हैं तथा संस्था की तीस वर्ष तक सेवा करना अंगीकार करते हैं। ऐसे ही महानुभाव इस संस्था के सदस्य हो सकते हैं। यही सदस्य संस्था की देखभाल करते हैं तथा उसकी प्रवर्धकारिणी सभा के सदस्य होते हैं।

हिन्दुस्थानी तालीमी सघ, सेवाग्राम

भूमिका — बुनियादी शिक्षा की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में की गयी है। हिन्दुस्थानी तालीमी सघ, सेवाग्राम इस नयी शिक्षा का प्रधान चन्द्र है। इसकी स्थापना सन् १९३० में हुई थी।

इस कार्य के लिए सेवाग्राम सवात्तम स्थल गिना जा सकता है। इस केन्द्र के इर्द गिर्द लगभग तीस गाँव हैं। परन्तु कोई भी गाँव यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वर्षा होने पर स्टेशन यहाँ से केवल पाँच मील की दूरी पर स्थित है। सेवाग्राम ग्राम सुधार, रानी प्रचार तथा पशु पालन का एक प्रधान केन्द्र है।

शुरू शुरू में सघ ने एक पूर्ण बुनियादी स्कूल कायम किया। इनमें आठवर्षीय प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। नयी तालीम के अवसर के साथ साथ सघ को भी अपने कार्यमाला बढ़ाने पड़े। कारण, नयी तालीम के अन्तर्गत अने शामिल हैं (१) प्रौढ शिक्षा, (२) पूर्व बुनियादी शिक्षा। (३) बुनियादी शिक्षा एवं, (४) उत्तर बुनियादी शिक्षा

विभिन्न विभाग — आज यह सघ अधोलिखित विभागों का सञ्चालन कर रहा है

१ पूर्व प्राथमिक स्कूल या 'बालवाडी'।

२ बुनियादी स्कूल (७ १४ वयस्कों के बच्चों के लिए)। सघ स्वयं 'आनन्द निनेतन' नामक एक स्कूल चलाता है, और आसपास के गाँवों में स्थित लगभग बीस गाँवों के बुनियादी स्कूलों की देखरेख करता है।

३ उत्तर-बुनियादी स्कूल—इस संस्था में बुनियादी शिक्षा समाप्त किये विद्यार्थियों को ३-४ वर्ष अभ्यास करना पड़ता है। पाठ्यक्रम में इन विषयों का समावेश है (१) कृषि, (२) बागवानी, (३) पशु पालन, (४) तेल

औंधी-तृफ़ानों को शेलते हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता कायम रखी । इसने सरकारी मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं किया । इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकृत नहीं हुईं । पर भिन्नारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़नी है, इसके कारण जामिया ने सरकारी अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की । उसने सदा अपने आदर्शों को सामने रखा । दान और चन्दे पर ही यह संस्था चलती रही । लोगो ने इस संस्था के प्रति सहानुभूति भी दिखायायी । कारण, उन्होंने जामिया के आदर्शों को समझा ।

आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं को चला रही है :

१. एक सावास कालिज.—इसमें कला, विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है ।
२. एक सावास बहुद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक शाला ।
३. एक सावास प्राथमिक स्कूल.—यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा शिक्षा दी जाती है ।
४. प्रौढ़ शिक्षण-संस्था—जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन करती है ।
५. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.—इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं । अवर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाठ्यक्रम के लिए बी० एड० डिग्री मिलती है ।
६. मकतबा.—यहाँ से स्कूली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होती हैं ।
७. पुस्तकालय.—यहाँ बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं ।
८. कला-प्रशिक्षण-केन्द्र.—फ़ाफ़्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ।
९. ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाज-शास्त्र केन्द्र—यहाँ उत्तर-स्नातक स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है ।
१०. इतिहास एवं राजनीति शोध-संस्था.—यहाँ इन विषयों की शिक्षण-विधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है । तथा यहाँ से सहायक शिक्षण-सामग्री तैयार होती है ।
११. एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था ।
१२. एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल ।

हैं। इनके लिए अल्प कालिक (दो सप्ताह से लेकर कई महीने) प्रशिक्षण का विराप प्रबन्ध किया जाता है।

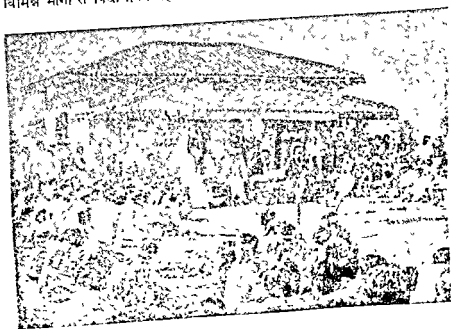
उपसहार—यह सघ बीस वष से भी अधिक काल से अपना कार्य सतत कर रहा है। इसे अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, पर इसने अपना काय प्रत्येक स्थिति में जारी रखा। सघ ने भारत क शिक्षा जगत म एक नयी क्रांति उत्पन्न की है। सघ का उद्देश्य एक ऐस समाज का सृष्टि करना है, जिसके जन समुदाय स्वावलम्बी हों, जो अपने हाथ स स्वयं श्रम कर स्वाश्रित हों, और उन्हें दूसरों की सहायता कदापि न लनी पड। अपन दृढ सकल्य को कार्यान्वित करने में सघ का बहुत कुछ सफलता भी मिली है। आश्रम म स्थित गांधीजी की कुटिया उसे ज्योति दिखाती रही है, और आग दिजानी ही रहेगी।

उत्पादन, ५) काष्ठ एवं धातु कार्य, (६) ग्राम इंजीनियरिंग एवं गृह-निर्माण, (६ बुनाई, (८) दर्जीगिरी, (९) गृह विज्ञान (लड़कियों के लिए)। नयी तालीम के सिद्धान्तों के अनुसार विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाया जाता है।

४. विश्वविद्यालयीय शिक्षा—कृषि, पशु-पालन. ग्राम इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का या तो प्रवर्धन किया जा रहा है या किया जानेवाला है।

५. प्रसार-कार्य—यह कार्य विश्वविद्यालय कार्य से सम्बन्धित है। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं: (१) सेवाग्राम से ७ मील के अर्धव्यास में स्थित सत्रन क्षेत्रों में प्रसार-कार्य, ताकि लोग सर्वोद्यम-समाज के हेतु को समझ सकें। (२) १९ वर्ष से ऊपर के युवक एवं युवतियों को नयी तालीम की ग्राम रचना पद्धति में प्रशिक्षित करना, ताकि वे भूदान आन्दोलन में भाग ले सकें। (३) नयी तालीम शिक्षा के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण-कार्य।

उत्तर-बुनियादी, विश्वविद्यालयीय तथा प्रसार-कार्य शिक्षा के लिए भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थीगण यहाँ आते हैं। थोड़े-बहुत अतिथि विदेशों से भी आते



चित्र २०—सेवाग्राम में गान्धीजी की कुटिया

बारहवाँ अध्याय

उपसंहार

स्वतन्त्रता-उपलब्धि के अनन्तर, शिक्षा की प्रगति एवं उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ इस देश में चलायी गयी हैं, और चलायी जा रही हैं। तिस पर भी अभी शिक्षा का विस्तार आशानुरूप नहीं हुआ है। सौ वर्षों से अधिक समय से वर्तमान शिक्षा-पद्धति ज्वली आ रही है। इस पद्धति की अकर्मण्यता का पता इसीसे चल सकता है कि आज ७० प्रति शत से अधिक स्त्री-पुरुष निरक्षर ही हैं। इतना ही नहीं, शिक्षित व्यक्तियों को उनके अनुकूल शिक्षा नहीं मिली। इस शिक्षा के द्वारा देश का यथोचित आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी न हुआ। इन खामियों की काफी नुकताचीनी हुई है, और हो भी रही है। पर इनका विशेष रूप से प्रतिकार नहीं किया गया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्वातन्त्र्योत्तर-काल में भी इस चुनौती का सामना विधिवत् नहीं किया गया।

हमारे शिक्षा-सम्मेलनों तथा परिषदों में, एवं विश्वविद्यालयीय दीक्षान्त भाषणों में, हमारे देश के गण्यमान्य महानुभाव लम्बी-चौड़ी हँकते हैं और शिक्षा के दोषों की टीका-टिप्पणी करते हैं। इन्हें सुनकर हताश हो जाना पड़ता है। जैसा कि स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा ही है, “वे नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी समालोचना के कारण, भलाई के बदले बुराई ही होती है। इस निन्दा के विपाक फल-स्वरूप शिक्षकगण ढीले पड़ जाते हैं, विद्यार्थीगण निरस्त हो जाते हैं एवं जनता शिक्षा का अनादर करने लगती है।” † हम इन उच्च-पदस्थ दिग्गज महारथियों से प्रार्थना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने स्वयं शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए क्या किया ?

भारतीय शिक्षा को अनेक समस्याओं का सामना करना है। इनकी चर्चा पिछले अध्यायों में की गयी है। फिर भी हम तीन समस्याओं के सम्बन्ध में, इस अध्याय में, थोड़ा-बहुत कहना चाहेंगे। ये समस्याएँ ये हैं : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा का निरता हुआ मान-दण्ड एवं (३) विद्यार्थीवर्ग की अनुशासन-हीनता।

हमारी शिक्षा-योजनाओं को लोगों की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना होगा। शिक्षा के द्वारा ही जनता की गरीबी दूर हो सकती है, जैसा कि श्री सैयदन ने कहा है, "उचित शिक्षा के अभाव में यह निर्धनता चिरस्थायी रहगी।"

आज हम ऐसे गगन-तारिक समाज के सृजन में सलग्न हैं जो कि न्याय, भ्रमन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व पर आधारित है। पर इस भावना का अभाव हम अपनी शिक्षा योजनाओं में अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अर्थाभाव के कारण, हमारे जितने ही नवयुवकों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि पिता या अभिभावक के पास सम्पत्ति हुई तो बच्चों को शिक्षा मिल सके, अन्यथा योग्यता एवं पिपासा रहते हुए भी उसे सरस्वती देवी से नमस्कार कर लेना पड़ता है। हम यह अवश्य मानते हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वृत्ति दान तथा मुफ्त शिक्षा का थाड़ा बहुत क्रदोवस्त अवश्यमेव किया है, पर यह यथेष्ट नहीं है। इस ओर उम्ई राज्य का प्रयास सराहनीय है। गत वर्ष से इस राज्य में, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय नव सौ रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा को लोक-तन्त्रीय बनाने का इस देश में यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी इस आदर्श का अनुसरण कर शिक्षा को लोक तन्त्रीयता प्रदान करने में सहायक होंगे।

जिसी भी शिक्षा पुनर्योजना में सबसे अधिक आवश्यकता रहती है सशक्त शासकीय प्रबन्ध की। खेद के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद 'केन्द्रीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय' दो भागों में विभक्त हुआ। मौलाना साहब की मृत्यु पर्यन्त, शिक्षा-मन्त्रालय की चागडोर एक मन्त्री मण्डल के सदस्य के हाथ में थी। पर इस विभाजन के कारण, दो राज्य मन्त्री दो भिन्न विभागों के लिए नियुक्त हुए। यदि काम बढ जाने के कारण, इन दो पृथक् मन्त्रालयों की सृष्टि हुई हो तो हमें कुछ कहना नहीं है; पर यदि इस विभाजन का कोई वैयक्तिक कारण हो, तो यह निस्सन्देह खेद का विषय है। इस नीति का प्रत्यक्ष फल होता है, कतिपय कार्यकलापों का टोहरावा, अर्थ तथा श्रम की कुछ-न कुछ बरबादी।

शिक्षा प्रशासन में अभी यथेष्ट अलगाव है।[†] राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग पर शिक्षा की अधिकतर जिम्मेवारी रहती है, और शिक्षा मन्त्रालय ही अधिकांश शिक्षा सस्थाओं को चलाता है। पर कुछ विशेष स्कूलों तथा कालिजों को अन्य मन्त्रालय (केन्द्रीय तथा

[†] *Times of India* July 18 1959

[‡] देखिए पृष्ठ १३०।

हमारी शिक्षा योजनाओं को लोगों की आर्थिक उन्नति की आर ध्यान देना होगा। शिक्षा के द्वारा ही जनता की गरीबी दूर हो सकती है, जैसा कि श्री सैयदन ने कहा है, “उचित शिक्षा के अभाव में यह निर्धनता चिरस्थायी रहेगी।”

आज हम ऐसे गण-तांत्रिक समाज के सृजन में सलग्न हैं जो कि न्याय, भ्रतन्त्रता, समता तथा ऋतुत्व पर आधारित है। पर इस भावना का अभाव हम अपनी शिक्षा योजनाओं में अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अर्थाभाव के कारण, हमारे कितने ही नययुवकों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि पिता या अभिभावक के पास सम्पति हुड ता ँच्चे को शिक्षा मिल सकी, अन्यथा योग्यता एव पिपामा ग्हेतीं हुए भी उसे सरस्वती देवी से नमस्कार कर लेना पड़ता है। हम यं अयस्य मानते हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वृत्ति ढान तथा मुफ्त शिक्षा का थोड़ा ग्हुत ँदोस्त् अवश्यमेव किया है, पर यह यथेष्ट नहीं है। इस ओर ँग्ई राज्य का प्रयास मराहनीय है। गत वर्ष से इस राज्य में, उन ँच्चों का नि शुल्क शिक्षा मिल रही है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय नव सौ रूपय से अधिक नहीं है। शिक्षा को लोक-तन्त्रीय बनाने का इस देश में यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा की जाती है कि अन्य राज् भी इस आदर्श का अनुसरण कर शिक्षा का लोक तन्त्रीयता प्रदान करने में सहायक हगि।

किसी भी शिक्षा पुनर्योजना में सबसे अधिक आवश्यकता ग्हेती है मशत् शासकीय ँक्वध की। खेद के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना अतुल कलाम आजाद ँ ँद ‘केन्द्रीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय’ दो भागों में विभक्त हुआ। मौलाना साहब की मृत्यु पर्यन्त, शिक्षा मन्त्रालय की ँगडोर एके मन्त्री मण्डल के सदस्य के हाथ में थी। पर हम विभाजन के कारण, दो राज्य मन्त्री दो भिन्न विभागों के लिए नियुक्त हुए। यदि काम बढ जाने के कारण, इन दो पृथक् मन्त्रालयों की सृष्टि हुई हो तो हम कुछ कहना नहीं है, पर यदि इस विभाजन का कोई ँैत्तिक कारण हो, तो यह निस्सन्देह खेद का विषय है। इस नीति का प्रत्यक्ष फल होता है, कतिपय कायकराणों का ढाहरावा, अर्थ तथा श्रम की कुछ न कुछ ँरजादी।

शिक्षा प्रशासन में अभी यथेष्ट अलगाय है। ई राष्ट्रीय शिक्षा विभाग पर शिक्षा की अधिकतर जिम्मेवारा ग्हेती है, और शिक्षा मन्त्रालय ही अधिकतर शिक्षा सन्धाओं को चलाता है। पर कुछ रिटोर स्कूलों तथा कालिजों का अन्य मन्त्रालय (केन्द्रीय तथा

† *Times of India* July 18 1959

‡ दोसिए पृष्ठ १३०।

का है। पर हम इतने धक्के खा चुके हैं कि हमारा विश्वास किसी भी योजना पर नहीं रहा। भगवान् कम-से-कम इस योजना को तो सफल बनायें !

यह मानना ही पड़ेगा कि गणकार शिक्षा के लिए पर्याप्त अर्थ की व्यवस्था नहीं कर रही है। तिस पर भी गत दस वर्षों में हमारे देश का शिक्षा-विभागीय व्यय तिगुना हो गया है। पर यह शिक्षा-व्यय यथोचित नहीं हो रहा है। इस समय तो केन्द्रीय मन्त्रालय की हालत उस गधेवाले बूढ़े के समान है, जो कि सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टाओं में असफल हुआ। मन्त्रालय आज इधर दाय मार रहा है तो कल उधर। — आज 'जनता कालिज', तो कल 'संस्कृत-विश्वविद्यालय', तो परसों 'ग्रामीण उच्चतर संस्था'। हाल ही, उक्त मन्त्रालय एक नवीन योजना की परिकल्पना कर रहा है, जिसके अनुसार स्नातक होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष ग्राम-सेवा करनी पड़ेगी। इस अनिवार्य भर्ती पर वार्षिक व्यय पांच करोड़ रुपये होगा, अर्थात् प्रति व्यक्ति पर एक हजार रुपये। न कभी बलात् कोई कार्य सफल हो सकता है, और न डण्डे की मार से समाज-सेवा का भाव ही उदित हो सकता है। यह तो 'धर-बांध सती करना' रहा। हमें पैसे की बरबादी को भी रोकना चाहिए। कभी-कभी हम अन्धा-धुन्ध अर्थ-नाश देखते हैं। फरवरी या मार्च में थड़ाथड़ नवीन योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है; सोच-विचार किये बिना ही, अल्प काल में द्रव्य का व्यय कर दिया जाता है और यह ख्याल भी नहीं किया जाता कि पैसे का उचित उपयोग हुआ भी है या नहीं!! इस विषय में हम हार्टग समिति की अधो लिखित चेतावनी कभी विस्मृत नहीं कर सकते :

लोगों का ख्याल है कि शिक्षा-विस्तार केवल पैसे का सवाल है। यह ठीक नहीं है। हम यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि सर्वदा पैसे की आवश्यकता होती है; पर इससे भी अधिक आवश्यकता एक दृढ़ एवं स्थिर संकल्प की होती है, जिसके अनुसार शिक्षा-नीति को कार्यान्वित करने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय और उसीके अनुरूप अर्थव्यय हो। †

आज हमारे देश की सबसे अधिक आवश्यकता है जन-शिक्षा, और उसी ओर हमें अपने प्रयत्नों को केन्द्रीभूत करने की भी आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि भारत की ५ प्रति शत जनता, याने, दो करोड़ व्यक्तियों की मासिक आय ३.२ रुपये है, १० प्रति शत याने ३८ करोड़ जनता की आय ६.२ रुपये है तथा ५० प्रति शत अर्थात् बीस करोड़ लोगों की आमदनी १४.६ रुपये है। भारत की एक चतुर्थांश जनता को चार आने के खर्च पर दैनिक जीवन गुजारना पड़ता है।

† Hartog Report, p 290.

राज्यीय) भी चलते हैं, जैसे : कृषि, रेल, धर्म, परिवहन, स्वास्थ्य, उद्योग, सामुदायिक विकास, आदि । ये मन्त्रालय अपनी-अपनी डाफ्टरी, अपना अपना राग धलापा करते हैं तथा ये बहुत ही कम एक दूसरे के संस्पर्श में आते हैं । इनके कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने की विशेष आवश्यकता है ।

हमारे शिक्षा-कार्यालयों की फाइलों की संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है । किसी भी सामान्य विषय पर आदेश निकलने के लिए महीनों लग जाते हैं । इस प्रकार शिक्षा-प्रसार में लकवा लग जाता है । इस शोचनीय स्थिति के दो कारण हो सकते हैं : (१) निरर्थक पत्र-व्यवहार तथा टफ्तरी परिपाटी और (२) अफसरों की शिथिलता या अकर्मण्यता । शिक्षा-विभागों को प्रथम कारण की तहकीकात करनी चाहिए । जो प्रथाएं अनावश्यक मालूम पड़े, उन्हें तत्काल उठा देना चाहिए । पर शिथिलता या अकर्मण्यता तो सख्ती से ही रोकी जा सकती है । इसे दूर करने के लिए पञ्जाब सरकार ने एक विवेक-पूर्ण मार्ग निकाला है । इसके अनुसार सरकारी अफसरों की एक टोली किसी भी टफ्तर की एकाएक तलाशी लेनी है और जाँच करती है कि अफसरगण अपना काम कहाँ तक सुचारु रूप से करते हैं । हाल ही में एक ऐसी जाँच शिक्षा-विभाग की हुई थी; और देखा गया है कि २,६०० अनिर्णीत कागजात पड़े हुए थे । एक यह दृष्टान्त ही हमारे टफ्तरों की वर्तमान स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश डालता है ।

अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-नीति शिक्षा-विदों द्वारा निर्धारित हो, न कि राजनीतियों या अधिकारी-दल-द्वारा । खेद के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी-दल के नियमों के आधार पर अनेक राज्यीय सरकारें अपनी शिक्षा-नीति स्थिर करती हैं । शिक्षा एक अत्यन्त तकनीकी विषय है, जिसका प्रबन्ध सुचारु रूपेण शिक्षा-शास्त्री ही कर सकते हैं । शिक्षा को सबसे अधिक क्षति पहुँचती है 'प्रयास और भूल पड़ति' द्वारा । हम राजनीतियों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया शिक्षा-क्षेत्र में अपना पैर पसारने की अनाधिकार चेष्टा न किया करें ।

हमारी शिक्षा की दूसरी जटिल समस्या है शिक्षा का गिरता हुआ मान-दण्ड— शिक्षा-स्तर का क्रमागत हास । इस विषय पर दो भिन्न मत नहीं हैं । लेकिन हमें इतना नहीं होना चाहिए । हमें समझना होगा कि शिक्षा के विस्तार के कारण, अब सभी प्रकार के विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । पच्चीस या पचास वर्ष पहले ज्यादातर उच्च स्तर के छात्रगण स्कूल या कॉलेज में प्रविष्ट होते थे । पर अब तो समस्त शिक्षा-संस्थाएँ छात्र-समूह से खचाखच भर रही हैं । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आजकल के श्रेष्ठतम विद्यार्थीगण, भूतपूर्व श्रेष्ठतम छात्रों से अच्छा काम कर दिखा रहे हैं ।

अपनी सन् १९५७-५८ की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता का मुख्य कारण है सामाजिक जीवन में अनुशासन का अभाव एवं बाहरी कारणा का प्रभाव। इसे रोकने के मुख्य तीन उपाय हैं। प्रथमतः, कायदे कानूनों के द्वारा चर्चों एवं विद्यार्थियों का उपयोग चुनाव या किसी भी राजनैतिक प्रचार के लिए बन्द कर लिया जावे। इसने साथ हमारे नेतागण यह घोषणा करें कि वे विद्यार्थियों का उपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करेंगे। हमारे देश में पुरातन काल से धर्म युद्ध का ही महत्व था। क्या चुनाव जीतने के लिए यह आवश्यक है कि हम बालकों की एक पूरी पीढ़ी की नैतिकता और शिष्टता का अल्पदान कर दें? द्वितीयत, शिक्षा संस्थानों को भी सतर्क रहना चाहिए कि संस्था में विद्यार्थी सघ क्षेत्रीय या राजनैतिक आधार पर समूहित न हों। विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। उनका यह उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब वे उत्तम चित्त होकर विद्या प्राप्ति में ही संलग्न रहें। राजनीति व कार्यों में भाग लेने से, जीवन में संघर्ष, क्रान्ति और विप्लवों व बीजों का अङ्कुरण होता है, जिससे उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और शिक्षा व कार्यों में एक प्रकार का आन्दोलन मचता है। तृतीयत, छात्रों को अपने अवकाश व समय का सदुपयोग करना सिखाया जाय। विद्यार्थी कल्याण कार्यों के प्रसार की सख्त जरूरत है।

वस्तुतः छात्रों की अनुशासन हीनता की चर्चा जितने बड़े पैमाने पर हम सुना या पढ़ा करते हैं, उतने पैमाने पर वह होती नहीं है। यह तो परकारिता का प्रसार है कि एक छोटी सी घटना को मिर्च मसाला लगाकर विस्तृतरूप दे दिया जाता है। हमें यह भी निस्मृत नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों की यह अनुशासन हीनता वल हमारे देश की ही बीमारा नहीं है, वरन् यह एक विश्व व्यापी व्याधि है। दो विश्व युद्धों के कारण, सत्तार व अनेक देशों का नैतिक पतन हुआ है, जैसा कि श्री हुमायूँ कबीर कहते हैं

इन युद्धों के समय में, पृथ्वी से 'सत्य का सबसे पहले लोप हुआ। लड़ाइयों के फल स्वरूप एक ऐसे व्यक्तित्वगर्ग का उन्मत्त हुआ, जिमने अस्तु उपायों के द्वारा धन जोड़ा था। नैतिक पतन, काला-बाजार, उ कोच, रिदयत या घूसगोरो का प्रभाव युवक-समुदाय पर पड़े बिना न रहा।†

अनुशासन हीनता का एक और कारण है, और वह है भविष्य जीवन की अन्धकारिता। विद्यार्थियों का हृदय दहल उठता है, जब व सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन

अपनी सन् १९५७-५८ की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता का मुख्य कारण है सामाजिक जीवन में अनुशासन का अभाव एवं बाहरी कारणों का प्रभाव। इसे रोकने के मुख्य तीन उपाय हैं। प्रथमतः, कायदे-कानूनों के द्वारा बच्चों एवं विद्यार्थियों का उपयोग चुनाव या किसी भी राजनैतिक प्रचार के लिए बन्द कर दिया जावे। इसके साथ हमारे नेतागण यह घोषणा करे कि वे विद्यार्थियों का उपयोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं करेंगे। हमारे देश में पुरातन काल से धर्म युद्ध का ही महत्व था। क्या चुनाव जीतने के लिए यह आवश्यक है कि हम बालकों की एक पूरी पीढ़ी की नैतिकता और शिष्टता का बलिदान कर दें? द्वितीयतः, शिक्षा संस्थानों को भी सतर्क रहना चाहिए कि सस्था में विद्यार्थी-सघ क्षेत्रीय या राजनैतिक आधार पर संगठित न हों। विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। उनका यह उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब वे दत्तचित्त होकर विद्या-प्राप्ति में ही सलग रहें। राजनीति के कार्यों में भाग लेने से, जीवन में सर्वप, क्रान्ति और विप्लवों के बीजों का अंकुरण होता है, जिससे उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और शिक्षा के कार्यों में एक प्रकार का आन्दोलन मचता है। तृतीयतः, छात्रों को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाया जाय। विद्यार्थी कल्याण-कार्यों के प्रसार की सख्त जरूरत है।

वस्तुतः छात्रों की अनुशासन-हीनता की चर्चा जितने बड़े पैमाने पर हम सुना या पढ़ा करते हैं, उतने पैमाने पर वह होती नहीं है। यह तो पत्रकारिता का प्रसाद है कि एक छोटी सी घटना को मिर्च मसाला लगाकर विस्तृतरूप दे दिया जाता है। हमें यह भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों की यह अनुशासन-हीनता केवल हमारे देश की ही बीमारी नहीं है, वरन् यह एक विश्व व्यापी व्याधि है। दो विश्व-युद्धों के कारण, ससार के अनेक देशों का नैतिक पतन हुआ है, जैसा कि श्री हुमायूँ फरीर कहते हैं :

इन युद्धों के समय में, पृथ्वी से 'सत्य' का सबसे पहला लोप हुआ। लड़ाइयों के फल-स्वरूप एक ऐसे व्यक्तिवर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने असत् उपायों के द्वारा धन जोड़ा था।... नैतिक पतन, काल-बाजार, उन्कोच, रिश्तत या घूसगोरी का प्रभाव युवक-समुदाय पर पड़े बिना न रहा।†

अनुशासन हीनता का एक और कारण है, और वह है भविष्य जीवन की अंधकारिता। विद्यार्थियों का हृदय टहल उठता है, जब वे सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन

† Humayun Kabir Student Indiscipline Delhi, Publications Division, 1955 p 6.

देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति कुछ-कुछ विद्यार्थियों में अनुशामन-हीनता के लिए जिम्मेवार है। हमारे नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन चलाने के लिए विद्यार्थियों का उपयोग किया, और अगहयोग तथा सत्याग्रह के आन्दोलनों में विद्यार्थियों ने अच्छा हाथ बटाया। नवयुवकों के भोज के कारण, अंग्रेजों के उत्पीड़न, अत्याचार आदि का वेग उनके आवेदानय ज्वार में तिनके की भाँति बढ़ गया। फल-स्वरूप वे आज उन्हीं अस्त्रों का उपयोग करते हैं, जिनके कारण, अंग्रेजों को यह देश छोड़ना पड़ा। रात ही रात में स्टूडेंट का तांता लगा ही रहता है, स्कूल-कालिजों पर धावा बोल दिया जाता है, असबाब इत्यादि तोड़-फोड़ डाले जाते हैं। इस तरह कभी कभी राजनैतिक दलों की भाँति विद्यार्थी-सघों की सृष्टि होती है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है, जब कि शालकों का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। उत्तर भारत के कुछ नगरों के चुनाव का एक दृष्टान्त नीचे दिया जाता है :

चुनावों के कई दिन पहले से ही छोटे-छोटे बच्चों (जिनकी अवस्था मात-धात वर्ष से लेकर चौदह-पन्द्रह वर्ष की थी) की टोलियों गलियों में तरह-तरह के नारे लगाती हुई घूमती थीं। ये नारे बड़े विचित्र थे। उदाहरण के लिये—एक लड़का कहता—“कौन जीतेगा ?” इसके उत्तर में पूरी टोली समवेत स्वर में कहती—“अमुक जीतेगा।” किन्तु ऐसे भी नारे थे; और दुर्भाग्य से वे ही अधिक थे, जो आपत्ति-जनक थे, जैसे :

गलीगली में जोर है—क्षत्रज्ञ चोर है।

गली-गली में जोर है—क्षत्रज्ञ डाकू है।

क्षत्रज्ञ गुंडे की यही पहचान—

हाथ में लकड़ी, मुँह में पान ॥ †

क्षत्रज्ञ के स्थान पर विरोधी उम्मेदवार का नाम लिया जाता था। इन बालकों की टोलियों ने बड़े-बड़े नेताओं, प्रोफेसरो, जन-सेवकों आदि को गली-गली उच्च स्वर से चोर और डाकू घोषित करके जनता को सचेत करने का उद्योग किया।—शालकों को आचरण, शिष्टता और नैतिकता से अग्र करना राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यन्त आपत्तिजनक है। सभी दल के नेताओं को ठण्डे दिल से विचार करना चाहिए कि छोटे बच्चों का इस प्रकार उपयोग करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है ! व्यावहारिक राजनीति में विद्यार्थियों का उपयोग करना स्वभावतः अनुपयुक्त है, तिस पर छोटे-छोटे बच्चों को इस प्रकार गली-गलीज सिखाना हमें कहाँ ले जायगा ?

† सरस्वती, अप्रेल, १९५७, पृष्ठ २३३।

उपदेश देते हैं — बड़े बड़े उपदेश — सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न चुराओ, आदि । पर जब वह नवयुवक उसी पूज्य उपदेशक को असत्यगामी, उच्छृण्वल और काम चोर पाता है तब वह ध्वरा उठता है, उसका मन सत्य से डिग जाता है और वह आत्म विश्वास रखे बैठता है । हमारे नवयुवकों के सामने केवल आदर्श की आवश्यकता नहीं है, बरन् आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर्श समाज की आवश्यकता है । पर श्रावकल तो भारत का दिनां दिन नेतिक पतन होता जा रहा है !

आज हम पच वर्षीय योजनाएँ चला रहे हैं । हम फेक्टरी तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाएँ खोल रहे हैं, कल कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बाँध बांध प्रपि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएँ चला रहे हैं । इन सब कार्य उद्देश्य है देश की समृद्धि, लोगों की आर्थिक उन्नति तथा देश से गरीबी का निष्कासन । पर किसी भी देश की उन्नति उमरी धन राशि के द्वारा है । देश की उन्नति जनता की वैयक्तिक उन्नति पर निर्भर है ।
 प्रत्येक व्यक्ति के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा । कारण, फलित होता है । इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के जिनका हृदय देश प्रेम से भरा हो, एव जो कर्तव्य ही है ।

ॐ प्रती, पवित्र —

भारत का अभ्युदय;
 विमल चरित्र
 सबको ऐसा हृदय ! !

देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति कुछ-कुछ विचारा जिम्मेवार है। हमारे नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध धियों का उपयोग किया, और अमहयोग तथा सत्य अर्थात् हाथ बटाया। नवयुवकों के ओज के कारण आदि का वेग उनके आवेशमय ज्वार में तिनके आज उन्ही अस्त्रों का उपयोग करते हैं, जिमने पड़ा। बात ही बात में स्ट्राइक का तांता लगा बोल दिया जाता है, असवाध दत्त्यादि तोड़-फोड़ राजनैतिक दलों की भाँति विचारार्थ-सधों की : यह है, जब कि बालकों का उपयोग चुनाव के नगरों के चुनाव का एक दृष्टान्त नीचे दिया

चुनावों के कई दिन पहले
मात-भाठ वर्ष से लेकर चौदा
तरह-तरह के नारे लगाती हुई
के लिये - एक लड़का कहता-
टोली समवेत स्वर में कहती-
और दुर्भाग्य से वे ही अधिन

गलीगली में शोर है-
गली-गली में जोर है
क्षत्रज्ञ गुंडे की यही
हाथ में लकड़ी, मुँह

क्षत्रज्ञ के स्थान पर विरोधी उर्ध्व की टोन्त्रियों ने बड़े-बड़े नेताओं, प्रफिसन चोर और डाकू घोषित करके जनता को भ्रान्त, शिष्टता और नैतिकता से भ्रष्ट सभी दल के नेताओं को ठण्डे दिल से विप्रकार उपयोग करना कहीं तक औचित्यपूर्ण उपयोग करना सम्भावितः अनुपयुक्त है, निम्न गत्यौत निम्नाना हमें कहीं ले जायगा ?

उपदेश देते हैं — बड़े बड़े उपदेश — सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न चुराओ, आदि । पर जब वह नजयुक्त उसी पूज्य उपदेशक को असत्यवादी, उच्छृंखल और काम-चोर पाता है तब वह धरसा उठता है, उसका मन मत्स्य से डिग जाता है और वह आत्म विश्वास रगो घंटता है । हमारे नजयुक्तों के सामने नेत्रल आदर्श की आवश्यकता नहीं है, शरन् आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर्श समाज की आवश्यकता है । पर आजकल तो भारत का दिनों दिन नैतिक पतन होता जा रहा है ।

आज हम पंच वर्षीय योजनाएँ चला रहे हैं । हम फेक्टरों तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाएँ गोल रहे हैं, कुछ कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बांध बांध रहे हैं, कृषि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएँ चला रहे हैं । इन सब कार्य-कारणों का उद्देश्य है देश की समृद्धि, लोगो की आर्थिक उन्नति तथा देश से गरीबी और बेकारी का निष्कासन । पर किसी भी देश की उन्नति उसकी धन राशि के द्वारा मापी नहीं जा सकती है । देश की उन्नति जनता की वैयक्तिक उन्नति पर निर्भर है । जनतन्त्र भारत में हमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास का ओर ध्यान देना पड़ेगा । कारण, जनतन्त्र जनो द्वारा ही संगठित होता है । इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के लिए हमें ऐसे नर नारी चाहिए, जिनका हृदय देश प्रेम में भरा हो, एव जो कर्तव्य निष्ठ तथा चरित्रवान् हों । वहा ही है ।

जने कर्मठ, दृढ़ व्रती, पवित्र —

कर सके भारत का अभ्युदय,

लक्ष्य हो जिसका विमल चरित्र

मिले हम सबको ऐसा हृदय ! !



की समाप्ति के बाद क्या होगा ! बेकारी की समस्या को सोचकर उनका हृदय भयाकुल हो जाता है । आज जो पढ़े-लिखे लोग बेकार हो रहे हैं, और उनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है; वह कितनी चिन्ताजनक है !! आज से अस्सी वर्ष पूर्व भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने एक व्यंग्य लिखा था :

तीन बुलावे, तेरह धावे;
निज-निज विपदा रोइ सुनावे ।
आँखें फूटी, भरा न पेट;
क्यों सखि साजन ? नाईं 'मैनुएट' ! !

हमारे देश में प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है । पर कभी-कभी प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या हम आवश्यकता से अधिक प्राविधिकों की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे हैं ? साधारण शिक्षित की बेकारी की अपेक्षा उच्च एवं महँगी शिक्षा पाये हुए प्राविधिक व्यक्तियों की बेकारी से अधिक जटिल समस्याएँ, असन्तोष और कुण्ठा उत्पन्न होती है ।

काउन्सिल ऑफ़ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिसर्च की उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी, १९५७ में १,३४८ उच्च शिक्षा-प्राप्त वैज्ञानिक और प्राविधिक बेकार घंटे हुए थे । ये आँकड़े सम्पूर्ण न थे । अभी जब हमारी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा योजनाएँ पूरी तरह से चालू नहीं हो पायी हैं और उनसे अपेक्षित संख्या में स्नातक नहीं निकल रहे हैं तब उनकी बेकारी की यह स्थिति है !! तो यह स्थिति उस समय किस रूप में होगी जब देश और विदेश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर देश में स्नातकों का मेला लगेगा ? निरश्चय ही यह एक जटिल समस्या है, जिसके हल न होने से देश की आर्थिक क्षति तो होवेगी ही, साथ ही हम उच्च शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की बेकारी से उत्पन्न खतरों का सामना करने को भी बाध्य हो जावेंगे । जब देश में नियोजन का योलबाला है, तब अवश्य ही यह धारा की जा सकती है कि देश के कर्णधार अभी से इस खतरे को रोकने का प्रयत्न करेंगे ।

पर सबसे भीषण समस्या है दैनिक जीवन में आदर्श की अवनति की । हम जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, वहाँ ही आदर्श का पतन देखते हैं । घूस-रिश्त का प्रचार बढ़ रहा है, कर्तव्य-निष्ठा उठी जा रही है, आत्मीयों या रिश्तेदारों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिलती हैं, कार्य-दक्षता या ठोस योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं है । ऊपरी दिखावा ही उन्नति का मूल माना जाता है, न कि वास्तविक कार्य । जवाबदार लोग नवयुवकों को

उपदेश देते हैं — बड़े-बड़े उपदेश — सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न चुराओ, आदि । पर जब वह नवयुवक उसी पूज्य उपदेशक को असत्यवादी, उच्छृंगल और काम-चोर पाता है तो वह घमसा उठता है, उसका मन सत्य से टिग जाता है और वह आत्म-विश्वास ग्वा घेड़ता है । हमारे नवयुवकों के सामने केवल आदर्श की आवश्यकता नहीं है, रसन् आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर्श समाज की आवश्यकता है । पर आज तो भारत का दिनों दिन नैतिक पतन होता जा रहा है !

आज हम पंच वर्षीय योजनाएँ चला रहे हैं । हम फेक्टरी तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाएँ ग्वाल रहे हैं, कल-कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बाँध बांध रहे हैं, कृषि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएँ चला रहे हैं । इन सब कार्य कल्याण का उद्देश्य है देश की समृद्धि, लोग की आर्थिक उन्नति तथा देश से गरिबी और बेकारी का निष्कासन । पर किसी भी देश की उन्नति उसकी धन राशि के द्वारा मापी नहीं जा सकती है । देश की उन्नति जनता की वैयक्तिक उन्नति पर निर्भर है । जनतन्त्र भारत में हमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा । कारण, जन तन्त्र जनो द्वारा ही संगठित होता है । इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के लिए हमें ऐसे नर-नारी चाहिए, जिनका हृदय देश प्रेम से भरा हो, एव जो कर्तव्य निष्ठ तथा चरित्रवान् हों । कहा ही है :

यने कर्मठ, दृढ व्रती, पवित्र —

कर सके भारत का अभ्युदय ;

लक्ष्य हो जिसका विमल चरित्र

मिले हम सबको ऐसा हृदय !!



की समाप्ति के बाद क्या होगा ! बेकारी की समस्या को सोचकर उनका हृदय भयाकुल हो जाता है । आज जो पढ़े लिखे लोग बेकार हो गये हैं, और उनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है; वह कितनी चिन्ताजनक है !! आज से अस्सी वर्ष पूर्व भारतेन्दु बाबू हरिदचन्द्र ने एक व्यंग्य लिखा था :

तीन युवावे, तेरह धावे;
निज-निज विपदा रोइ सुनावे ।
आँखें फूटी, भरा न पेट;
क्यों सखि साजन ? नहीं 'प्रेणुएट' !!

हमारे देश में प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है । पर कभी-कभी प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या हम आवश्यकता से अधिक प्राविधिकों की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे हैं ? साधारण शिक्षित की बेकारी की अपेक्षा उच्च एवं महँगी शिक्षा पाये हुए प्राविधिक व्यक्तियों की बेकारी से अधिक जटिल समस्याएँ, असन्तोष और कुण्ठा उत्पन्न होती है ।

काउन्सिल ऑफ़ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिसर्च की उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी, १९५७ में १,३४८ उच्च शिक्षा-प्राप्त वैज्ञानिक और प्राविधिक बेकार बठे हुए थे । ये आँकड़े सम्पूर्ण न थे । अभी जब हमारी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा योजनाएँ पूरी तरह से चालू नहीं हो पायी हैं और उनसे अपेक्षित संख्या में स्नातक नहीं निकल रहे हैं तब उनकी बेकारी की यह स्थिति है !! तो यह स्थिति उस समय किस रूप में होगी जब देश और विदेश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर देश में स्नातकों का मेला लगेगा ? निश्चय ही यह एक जटिल समस्या है, जिसके हल न होने से देश की आर्थिक शक्ति तो होवेगी ही, साथ ही हम उच्च शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की बेकारी से उत्पन्न खतरों का सामना करने को भी बाध्य हो जावेंगे । जब देश में नियोजन का बोलबाला है, तब अवश्य ही यह आशा की जा सकती है कि देश के कर्णधार अभी से इस खतरे को रोकने का प्रयत्न करेंगे ।

पर सबसे भीषण समस्या है दैनिक जीवन में आदर्श की अवनति की । हम जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, वहाँ ही आदर्श का पतन देखते हैं । घूँस-रिश्वत का प्रचार बढ़ रहा है, कर्तव्य-निष्ठा उठी जा रही है, आत्मीयों या रिश्तेदारों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिलती हैं, कार्य-दक्षता या ठोस योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं है । ऊपरी दिखावा ही उन्नति का मूल माना जाता है, न कि वास्तविक कार्य । जवाबदार लोग नवयुवकों को

मंस्था	सस्था सख्या	छात्र-संख्या
साधारण शिक्षा के स्कूल		
उच्च/उच्चतर एव उत्तर पुनियादी	११,८१५	२२,५४,९१२
मिडिल ...	२४,४८६	५१,५८,६८५
प्राथमिक ...	२,८७,२९८	२,५९,६४,८०८
पूर्व प्राथमिक	७६९	९९,३१३

व्यावसायिक एवं तकनीकी स्कूल

कृषि	९४	६,२४४
क्ला एव फ़ास्ट	२०४	१४,७४७
घागिज्य ..	८२९	८०,५९१
इजीनियरिंग .	६८	२९,०२६
घन विद्या ...	४	१३४
उद्योग .	५३३	३६,८२०
मेडिकल ...	१०९	७,५६१
शारारिक शिक्षा ..	३६	३,५०५
शिक्षक प्रशिक्षण ..	९१६	९५,४७४
टेकनीलॉजी ...	१११	१७,४६६
पशु विद्या ..	७	१,०६६
अन्य विषय ...	११	१,७७७

विशेष शिक्षा सम्बन्धी स्कूल

मजबूतों के लिए .	९८	५,०२८
समाज कार्यकर्ताओं के लिए ...	४४	४,०१०
संगीत, नृत्य एव अन्य ललित कलाएँ	१८४	१५,६९३
प्राच्य विद्या ...	३,३२२	१,२९,३५६
ग़ाल अपराधियों के स्कूल ..	३७	७,२७३
समाज (प्रौढ़) शिक्षा	४४,०५८	१२,०४,९८५
अन्य विषय .	१,३२७	६८,८७८

कुल योग.. २,७७,८३० ३,६०,०५,६२७

परिशिष्ट एक
शिक्षा संस्थाएँ एवं छात्र-संख्या
भारत (१९५६-५७)

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र-संख्या
विश्वविद्यालय ...	३३	
माध्यमिक एवं इण्डरमीडिएट शिक्षा-मण्डल	१२	
अनुसन्धान-संस्थाएँ ...	४१	६,२७,७३४
कला एवं विज्ञान कालिज ...	८४९	
व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा-सम्बन्धी कालिज		
कृषि ...	२५	७,०५१
वाणिज्य ..	२८	६१,३६३
शिक्षक-प्रशिक्षण ...	१३३	१५,१६६
इंजीनियरिंग ...	४७	१९,२०४
वन-विद्या ...	३	४२७
कानून ...	२९	२०,८१७
मेडिकल ...	९९	२७,२८९
शारीरिक शिक्षा ...	१०	४७८
टेकनोलॉजी ...	७	२,७०१
पशु-विद्या ...	१४	४,६५९
अन्य क्षेत्र ...	४	८७८
विशेष शिक्षा-सम्बन्धी कालिज		
संगीत, नृत्य, एवं अन्य ललित कलाएँ	२७	३,७३८
प्राच्य विद्या ..	७९	५५३
समाज-शास्त्र ...	६	४७६
अन्य क्षेत्र	१०	३,१८२

परिशिष्ट दो

भारत के विश्वविद्यालय, १९५८

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिन्न संख्या	छात्र संख्या
१	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (१९२७)	शैक्षणिक एवं संघट्तीय	६०	३७,३१५
२	अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (१९२०)	सावास एवं शैक्षणिक	२	४,३७०
३	अलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलाहाबाद, (१८८७)	सावास एवं शैक्षणिक	४	८,१६९
४	आम्ब्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (१९२६)	संघट्तीय एवं शैक्षणिक	४९	२९,८४०
५	अन्नामलय विश्वविद्यालय, अन्नामलयनगर (१९२९)	सावास एवं शैक्षणिक	—	२,७६५
६	अनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९१६)	सावास एवं शैक्षणिक	२१	१०,२१०
७	बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (१९४९)	सावास एवं शैक्षणिक	३	४,८५१
८	बिहार विश्वविद्यालय, पटना (१९५२)	संघट्तीय एवं शैक्षणिक	७६	४८,०३१
९	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (१८५७)	संघात्मक एवं शैक्षणिक	४२	३९,४५६
१०	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१८५७)	संघट्तीय एवं शैक्षणिक	१४८	१,१३,७५१
११	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (१९२२)	संघट्तीय एवं शैक्षणिक	२२	१३,०२८
१२	गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी (१९४८)	संघट्तीय एवं शैक्षणिक	२६	१५,५८१

परिशिष्ट तिन

परिभाषिक शब्दावली

A
 Ability-योग्यता
 Aboriginal-आदिवासी
 Academic-शास्त्रीय
 Accommodation-वास-स्थान
 Account-हिसाब, लेखा
 Achievement-निष्पत्ति
 Act-कानून
 Activity -क्रियाशीलता
 — Method-क्रियात्मक प्रणाली
 Administrator-प्रशासक
 Adolescent-निशोर
 Adviser-परामर्शदाता
 Affiliating-सम्बन्धीय
 Agenda-कार्यसूची
 Aid-अनुदान
 Aided-सहायता-प्राप्त
 All-India Council for
 Elementary Education
 -अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा
 परिषद
 All-India Council for
 Secondary Education-
 अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-
 परिषद
 All-India Council for
 Technical Education-
 अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा
 परिषद

Astronomy-ज्योतिष
 Audio-visual aids-श्रव्य-दृश्य
 उपकरण
 Autonomy-स्वायत्तता
 ACC-सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल
B
 Basic Education-बुनियादी
 शिक्षा
 Bill-विधेयक
 Biology-जीव विज्ञान
 Board-मण्डल
 Body-निकाय
 Book-binding-जिल्दसाजी
 Borstal school-निशोर-बन्दी
 स्कूल
 Botany-वनस्पति शास्त्र
 Budget-आय-व्ययक
 Bureau-कार्यालय
C
 Cabinet-मन्त्रि मण्डल
 Camp-शिविर
 Card-board work-दफ्तरीगिरी
 Carpentry-बढ़ईगिरी
 Census-जनगणना
 Central Advisory Board
 of Education-केन्द्रीय मलाह-
 कारी शिक्षा-मण्डल
 Centralisation-केन्द्रीकरण
 Certificate-प्रमाण पत्र
 CER-उपकर

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिज संख्या	छात्र-संख्या
२६	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३४	१७,५१४
२७	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	११६	५१,११५
२८	पटना विश्वविद्यालय, पटना (१९१७)	सावास एवं शैक्षणिक	१०	९,४७७
२९	पूना विश्वविद्यालय, पूना (१९४९)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३९	१९,८४६
३०	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४१	१७,७२४
३१	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (१९४८)	सावास एवं शैक्षणिक	—	६७३
३२	सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभविद्यानगर, आनन्द (१९५५)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४	२,६३७
३३	सागर विश्वविद्यालय, सागर (१९४६)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२३	९,४५८
३४	एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९५१)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	६	१,९९४
३५	श्री व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९४८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१७	२०,००२
३६	उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१९४३)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२१	७,१३०
३७	विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन (१९५१)	सावास एवं शैक्षणिक	६	६५९
३८	विक्रम-विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२६	—

F

Family Planning-परिवार
नियोजन

Federal-सघात्मक

Fee-शुल्क

Finance-वित्त

Fund निधि

Furniture-असबाब

G

Gardening-सागबानी

General Education-सामान्य
शिक्षा

Geology-भूगर्भ विज्ञान

Geometry-रेखा गणित

Gift-उपहार

Graduate स्नातक

Grant in aid-आर्थिक अनुदान

Guidance-निर्देश

———— Bureau-निर्देश केंद्र

H

Handicapped-मजबूर

Handicraft-दस्तकारी

Hostel-छात्रावास

Humanities-मानवीय विषय

I

Idiot-जड़

Indirect-परोक्ष, अप्रत्यक्ष

Individual वैयक्तिक, व्यक्तिगत

Industry-उद्योग

Infancy-शैशव

Inspection-निरीक्षण

Inspector-निराक्षक, इन्स्पेक्टर

Inservice Education-मध्य
अध्यापन शिक्षा

Institution-संस्था

Integration-एकीकरण

Intelligence-बुद्धि

Intelligence Quotient-बोध
लक्षि

———— Pest-बुद्धि पराक्षा
माप

International-अंतर्राष्ट्रीय

J

Juvenile-बाल अपराधी

———— Court-बालापराधी
न्यायालय

L

Laboratory-प्रयोगशाला

Labourer-श्रमिक

Leather work-चर्मकाय

Life long-आजीवन

M

Maladjusted-असामञ्जस्य

Management-प्रबंध

Manual-शारीरिक

Mechanistic-यांत्रिक

Medium-माध्यम

Meeting- बैठक, अधिवेशन

Mental Testing-बुद्धि परीक्षा

Military Training-सैनिक
प्रशिक्षण

Ministry-मंत्रालय

Minute-छेत्त पत्र

Chancellor—कुलपति
 Charter—अधिकार-पत्र
 Chemistry—रसायन-शास्त्र
 Citizenship—नागरिकता
 Classification—वर्गीकरण
 Clinic—उपचार गृह
 Co-curricular—पाठ्य-विषयान्तर
 College—कालिज, महाविद्यालय
 Commerce—वाणिज्य
 Commission—आयोग
 Committee—समिति
 Compact—टोस, सघन
 Cumulative Record Card—
 उन्नति-विषयक लेखा
 Concurrent—समवर्ती-सूची
 Co-education—सह-शिक्षा
 Continuation Education
 सातत्य शिक्षा
 Constitution—संविधान
 Co-ordination—समन्वय, एकसूत्री-
 करण
 Correlation—समन्वय, समन्वय
 Council—परिषद
 Curricular—पाठ्यक्रमान्त, पाठ्य-
 विषयक

D

Data Sheet—विषय-सूची
 Democracy—जन-तन्त्र
 Despatch—घोरना-पत्र
 Didactic Apparatus—पाठन
 युक्ति-सम्प
 Direct—प्रत्यक्ष

Director of Education—शिक्षा
 संचालक
 Discipline—अनुशासन
 Drawing—चित्र-कला
 Dying—रंगरेजी

E

Education—शिक्षा
 Education Department—
 शिक्षा विभाग
 Educationist—शिक्षाविद, शिक्षा
 विज्ञ
 Efficiency—कार्यकुशलता
 Embroidery—कशीदे का काम
 Engineer—इंजीनियर
 English—अंग्रेजी
 Entertainment—आमोद-प्रमोद,
 मनोरंजन कार्य
 Examination—परीक्षा
 Examination (External)
 —बाह्य-परीक्षा
 ————— (Internal)—
 आन्तरिक परीक्षा
 ————— (Periodical)
 —सावधिक-परीक्षा
 Ex-officio—पदेन
 Experiment—प्रयोग
 Experimental Method—
 प्रयोगात्मक पद्धति
 Extension—प्रमाण
 Extracurricular Activity—
 पाठ्योत्तर कार्य

Resolution-प्रस्ताव
Moral-प्राम्य

S

Salary-वेतन
Scholarship-वृत्ति
Secretary-सचिव
Self activity-आत्मक्रियाशीलता
— Government-स्वायत्त शासन
— Supporting-स्वायत्तगामी, सहाय्यी
Senior-गोष्ठी
Sense training-ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा
Social Efficiency-सामाजिक कुशलता
Socialization-समाजीकरण
Socialization-विशिष्टीकरण
Socialist-विशेषज्ञ
Sponsoring-कताई
Sacrificial-आध्यात्मिक
Sustenance-अवरोधन
Standard-स्तर, मान
Stage-प्रक्रम
State-राज्य
Statistics-सांख्यिकी
Survey-सर्वेक्षण
T
Table-तालिका
Technical Education-तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा
Text-book-पाठ्य-पुस्तक
Theoretical-सैद्धान्तिक

Thesis-महा निबन्ध

Time-table-समय सारिणी

Training-प्रशिक्षण

Trial-and-error Method
प्रयास और त्रुटि-प्रणाली

Tribunal-न्याय-सभा

U

Unaided-स्वाश्रित

Undergraduate-उप स्नातक

Union-संघ

Unit-अन्विति

UNESCO-विज्ञान एवं संस्कृति
संगठन

UNO-संयुक्त राष्ट्र संघ

Uniformity-एकरूपता

Universal-सार्वभौमिक

UGC-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

V

Value-मान्यता, मूल्य

Virtue-गुण

Vocational-व्यावसायिक

W

Wastage-व्यर्थता

Weaving-बुनाई

Work-कार्य

———— load-कार्यभोझ

———— shop-कर्मशाला

Y

Youth-युवक

———— welfare-युवक-कल्याण

Monitorial System-
छात्राध्यापक प्रणाली
Moron-मूर्ख
Mother-tongue-मातृ-भाषा
Multipurpose-बहुद्देश्यीय
Municipality-नगरपालिका
Ministry of Education-
शिक्षा मन्त्रालय
**Ministry of Scientific
Research and Cultural
Affair-**वैज्ञानिक अनुसन्धान
और संस्कृति मन्त्रालय

N

NCC-राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थीदल
**National Council of
Rural Edu.-** राष्ट्रीय ग्रामीण
उच्चतर शिक्षा परिषद
**National Council for
Women's Edn -**राष्ट्रीय
स्त्री-शिक्षा परिषद
Needle-work-सूत्रि-कार्य
Nurse-धात्री

O

Objective Test-वस्तुगत परीक्षा
Observation-अवलोकन
Occupation-धन्धा, रोजगार
Optional-वैकल्पिक
Oral-मौखिक
Overseer-कार्य-निरीक्षक

P

Physically Handicapped
-बिह्वलाङ्ग

Physiology-शरीर विज्ञान
Planning-योजना
Post-graduate-उत्तर-स्नातक
Post-war-युद्धोत्तर
Poultry-कुकुट-पालन
Practice Teaching-अध्यापन
अभ्यास
Preparatory-प्रारंभिक
Pre-service Education-
पूर्व-अध्यापन शिक्षा
President-अध्यक्ष
Principal-भाचार्य
Private-निजी, स्वसंचालित
Productive-उत्पादनशील
Psychology-मनोविज्ञान

Q

Qualification-योग्यता
Qualitative-गुणात्मक
Quantitative-संख्यात्मक
Quarterly-त्रैमासिक
Quinquennial-पंच-वर्षीय

R

Rambling-परिभ्रमण
Recognition-मान्यता, प्रस्वीकृति
Reconstruction-पुनर्रचना
Re-education-पुनः शिक्षा
Reformatory-सुधार विद्यालय
Refresher-पुनर्संजीवन
Report-प्रतिवेदन
Repression-दमन
Research-शोध, गवेषणा, अनु-
सन्धान

Mukerji, S. N. *An Introduction to Indian Education*. Baroda, Acharya Book Depot. 1956. Ch. II.

—, *Secondary School Administration* Baroda, Acharya Book Depot, 1959. Ch. III.

The Indian Institute of Public Administration. *The Organisation of Government of India*. Bombay, Asia Publishing House, 1958. Ch. XVI.

तीसरा अध्याय : बुनियादी शिक्षा

अन्नारी, सैयद एवं शर्मा, मोहनलाल : बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त. दिल्ली, अक्षरचन्द्र कपूर एण्ड सन्स, १९५८. पृष्ठ १६० ।

Aryanayakam, E. W. *The Story of Twelve Years*. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh. n. d. pp. 16

Avinashlingam, T. S. *Understanding Basic Education*. Delhi, Manager of Publications, 1954. pp. 61.

Government of India. *Handbook of Teachers for Basic Schools*. 1956. pp. 325.

Hindustani Talimi Sangh, Sevagram. *Basic National Education* n. d. pp. 96.

—, *Educational Reconstruction*. 1950. pp. 183.

—, *One Step Forward*. 1940. pp. 292.

समग्र नई तालीम. १९४६. पृष्ठ २२५.

कश्यप, सन्तोषराज एव गुप्त, अमृतलाल : नई तालीम के सिद्धान्त एव शिक्षाविधि. पंजाब, किताबघर, १९५७. पृष्ठ २८६ ।

Kripalani, J. B. *The Latest Fad*. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1938. pp. 102.

Patel, M. S. *Educational Philosophy of Gandhiji* Ahmedabad, Navjivan Press, 1953. pp. 238.

Shrimali, K. L. *The Wardha Scheme*. Udaipur, Vidya Bhawan, 1949. pp. 303.

Solanki, A. B. *Technique of Correlation in Basic Education*. Baroda, Faculty of Education & Psychology, 1956. pp. 43.

ग्रन्थ-सूची

पहला अध्याय : भारतीय शिक्षा की रूपरेखा

- Apte, D. G. *Universities in Ancient India*. Baroda, Faculty of Education and Psychology, n. d. pp. 56.
- Basu, A. N. *Education in Modern India*. Calcutta, Orient Book Co., 1947. pp. 184
- Bhagwan Dayal. *Development of Modern Indian Education*. Bombay, Orient Longmans, 1955. pp. 558.
- Government of India. *India, 1959*. Delhi, Ministry of Information & Broadcasting, 1959. pp. 263.
- James, H. R. *Education and Statesmanship in India*. Bombay, Longmans, 1917 pp. 143.
- Mayhew. A. *The Education of India*. London, Faber & Gwyer, 1928 pp. 306.
- Mookerji, R. K. *Ancient Indian Education*. Bombay, Macmillan, 1947. pp. 658.
- Mukerji, S. N. *History of Education in India (Modern Period)*. Baroda, Acharya Book Depot, 1957. pp. 341.
- Nurullah S., and Naik J. P. *A History of Education in India*. Bombay, Macmillan, 1951. pp 953.
- प्रसाद, मुनेश्वर : भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रथम भाग. पटना, अजन्ता प्रेस, १९५५, पृष्ठ २८८ ।

दूसरा अध्याय : शिक्षा-व्यवस्था

- भारत सरकार के पब्लिकेशन्स डिवीजन-द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित प्रतिवेदन :
- Annual Reviews on Education: *Education in India*, 1947-48; 1948-49; 1949-50; 1950-51; 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56.
- भारत, १९५९, पृष्ठ ३८९ ।
- Education—A Graphic Representation in India*. 1957. Ch. VI.
- Progress of Education in India, 1947-52*. 1953 pp. 279.

पाँचवा अध्याय : माध्यमिक शिक्षा

- A Report on Secondary Education Extension Course.* Madras, South India Teacher, Nos. 7 & 8. 1954.
- Estimates Committee. *Secondary Education.* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. pp 90.
- Government of India *Head Masters on Secondary Education.* Delhi, Publications Division, 1954. pp. 40
- . *Report of the Secondary Education Commission.* Delhi, Publications Division, 1953. pp. 319
- Hampton, H. V. "Secondary Education", *The Educational System* Bombay, O U P n d pp 64
- Mukerji, S N., ed. *Secondary Education in Other Lands.* Baroda. Faculty of Education and Psychology. 1956. pp 65
- Report of a Study by an International Team *Teachers and Curricula in Secondary Schools.* Delhi, Ford Foundation 1954. pp. 142.
- "Report on Baroda Workshop," *Journal of Education & Psychology.* April, 1955
- सिंह, राधामप्रसाद: भारतवर्ष तथा उत्तरप्रदेश में प्रजातन्त्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका. लखनऊ, हिन्दी साहित्य मंडार, १९५९. पृष्ठ २०८ ।
- Siqueira T. N. "The Aim of Secondary Education", *South India Teacher.* November, 1954.

छठा अध्याय : विश्वविद्यालयीय शिक्षा

- Basu, A N. *University Education in India.* Calcutta, Book Emporium. 1944. pp. 166.
- Dongerkerly, S. R. *Thoughts on University Education* Bombay, Popular Book Depot, 1955. pp. 170.
- *Universities and National Life.* Bombay, Hind Kitabs. 1950, pp. 115.

Varkey, C. J. *Wardha Scheme of Education*. Bombay, O.U.P. 1940. pp. 176.

चौथा अध्याय : प्राथमिक शिक्षा

Basu, A. N. *Primary Education in India*. Calcutta, Indian Associated Publishing Co. 1946. pp 64.

भटनागर, रामप्रसाद. भारतीय शिक्षा का आधुनिक इतिहास मुरादाबाद, कालिज स्टोर्स, १९५९. पृष्ठ २४० ।

Desai, D. M. *Universal Compulsory and Free Primary Education in India*. Bombay, Indian Institute of Education, 1953. pp. 392.

Desai, Dinker. *Primary Education in India*. Bombay, Servants of India Society, 1948 pp. 128.

दुवे लक्ष्मीकान्त एवं सूर रमणीकान्त. भारतीय शिक्षा का इतिहास, अलाहाबाद, किताबघर, १९५७, पृष्ठ ५९८ ।

Estimates Committee. *Elementary Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. pp. 89.

Ministry of Education. *Report of the First Meeting of the All-India Council for Elementary Education*. Delhi, Manager of Publications, 1958. pp 121.

Parulekar, R. V. *Literacy in India*. Bombay, Macmillan, 1939. pp. 181.

Saiyadain, K. G., Naik, J. P., and Husain S. Abid. *Compulsory Education in India*. Paris, UNESCO, 1952. pp. 191.

Sen, J. M. *History of Elementary Education in India*. Calcutta, Book Co., 1943. pp. 313.

सिंह, वैशीधर एवं शास्त्री, भूदेव. भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास. आगरा, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, १९५७. पृष्ठ २२९ ।

- Dasgupta, Jyoti Probha *Girls' Education in India in the Secondary and Collegiate Levels* Calcutta, University of Calcutta, 1938 pp 269
- Gandhi, M K *Women and Social Injustice* Ahmedabad, Navivan Press, 1942 pp 276
- Government of India *Report of the National Committee on Women's Education* Delhi Manager of Publications 1959 pp 335
- Indra *Status of Women in Ancient India* Lahore Minerva Book Shop 1949 pp 324
- Joshi, K L, and Shukla P D *Women and Education in India, Women and Education, Paris, UNSECO, 1953 pp. 264.*
- सिंह गणेशप्रसाद : हमारी शिक्षा वाराणसी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५८. पृष्ठ ३०९.

आठवाँ अध्याय : प्राविधिक शिक्षा

- C A B E *Report of the Technical Education Committee, 1943* Delhi, Manager of Publications, 1956 pp 37
- Chandiramani, G K *Technological Education in India* Delhi, Publications Division 1956 pp 20
- Estimates Committee *Technical Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p 127
- Government of India *Report on Vocational Education in India (Abbott Wood Report)*. Delhi Manager of Publications, 1937 pp 138
- *Scientific Research* Delhi, Manager of Publications 1957 pp 88
- National Planning Committee *General Education and Technical Education, and Developmental Research* Bombay, Vora & Co, 1938 pp 209
- प्रसाद, मुनेश्वर • भारतीय शिक्षा का इतिहास. (द्वितीय विभाग). पटना, श्री अजन्ता प्रेस, १९५७. पृष्ठ ५१७.

- . *Universities and Their Problems*. Bombay, Hind Kitabs, 1948. pp. 191.
- Education Committee. *Report of the Three-year Degree Course*. Delhi, Ministry of Education, 1958. pp. 23.
- Estimates Committee. *University and Rural Higher Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. p. 112.
- Ghosh, J. *Higher Education in Bengal*. Calcutta, Book Company, 1929. pp. 242.
- Government of India. *Directory of Institutions of Higher Education*. 1958. Delhi, Manager of Publications, 1958. pp. 245.
- . *Indian University Administration*. Delhi, Manager of Publications, 1958. pp. 149.
- . *Rural Institutes*. Delhi, Manager of Publications, 1955. pp. 77.
- . *The Report of the University Education Commission*. Vol. I. Delhi, Manager of Publications. 1949. pp. 747.
- Iyenger, K. R. S. *A New Deal for Our Universities*. Calcutta. Orient Longmans, 1951. pp. 134.
- शिमरन, वशैगोपाल एवं शर्मा, वेदराम : हमारे शिक्षा प्रतिवेदन. अलीगढ़, विश्व-प्रकाशन, १९५९. पृष्ठ ५५८.
- Mukerji, S. N. *Higher Education and Rural India*. Baroda, Acharya Book Depot, 1956. pp. 342.
- Sheshadri, P. *The Universities of India*. Bombay, Oxford University Press, pp. 58.

सातवाँ अध्याय : स्त्री-शिक्षा

- All-India Women's Conference. *Education of Women in Modern India*. Aundh Publishing Trust, 1946. pp. 87.
- Baig, Tara Ali, ed. *Women of India*. Delhi; The Publications Division, 1958. pp. 276.
- Cousins, M. E. *Indian Womenhood Today*. Allahabad, Kitabistan, 1941. pp. 207.

रावत, प्यारेलाल. भारतीय शिक्षा का इतिहास. आगरा, भारत पब्लिकेशन्स, १९५८.
पृष्ठ ६०८।

Venkatraman, K. "Technical Education", *The Educational System*. Bombay, O. U. P., 1943. pp. 64.

नवौं अध्याय : शिक्षक प्रशिक्षण

A.A.C.T.E. *School and Community Laboratory Experiences in Teacher Education*. Oneonta, N. Y. 1948. pp. 340.

Association of Training Colleges in India. *Report of the First, Second and Third Conferences*. Baroda, Faculty of Education and Psychology.

Commission on Teacher Education. *The Improvement of Teacher Education*. Washington, American Council on Education. 1946. pp. 283.

Divekar, S. M. "A Plea for Bridging Gulf Between the Basic and Non-Basic Graduate Teacher Education Programmes", *Journal of Education & Psychology*, October, 1956,

Filho, M. B. L. et al. *The Training of Rural School Teachers* Paris, UNESCO, 1953. pp. 164.

Hindustani Talimi Sangh. *Revised Syllabus for the Training of Teachers*. Sevagram, 1952. pp. 81.

Kaul, G. N. and Menon T, K. N. *Experiments in Teacher Training*. Delhi, Publications Division, 1954. pp. 73.

Mukerji, S. N. "Practical Work of Teachers' Colleges." *Journal of Education & Psychology*, January, 1955.

National Teachers' Association. *Education for Teaching*. Washington, WCOTP. 1954. pp. 57.

Report of the First Seminar on Extension Services in Training Colleges. Hyderabad, 1954. pp. 55.

Richardson, C. A. et al. *The Education of Teachers in England, France and U.S.A.* Paris, UNESCO. 1953. pp. 339.

Thacore C. N. "Some Aspects of the Educational Thought of India", *Educational Studies and Investigations*, Vol. I. Bombay, Asia Publishing House, 1951. pp 262.

Vidyavachaspati Indra. "Gurukulas' Contributions to the Present Educational System", *Educational India*. December, 1955.

Visva Bharati. *Prospectus*. Santiniketan Press, n. d pp. 15.

वारह्वो अध्याय : उपसंहार

Chakraverty, A. *Thoughts on Indian Education* Delhi, Manager of Publications, 1958. pp 101

Government of India. *Future of Education in India*. Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, 1956 pp 126.

—, *The Field of Education*. Delhi, Ministry of Education & Scientific Research, 1957. pp 72.

Kabir, Humayun *Education in New India*. London, George Allen & Unwin. 1955. pp 212

—, *Student Indiscipline*. Delhi, Ministry of Education. 1955. pp 23.

Sondhi, G. D. *A Plan for Youth Welfare*. Delhi, Ministry of Education. 1956. pp. 67.

Priestly, K. E., and Wright B. P. *Mentāl Health and Education*. Hong Kong, University Press, 1956. pp. 97.

Sent, M. "Problems of Handicapped Children in India", *Indian Journal of Child Health*. November 1952. pp. 597-607.

४. स्वास्थ्य एवं अनुशासन

C. A. B. E. *A National Plan of Physical Education*. Delhi, Publications Division, 1959. pp. 61.

Desai, C. R. *History and Progress of Physical Education in India*. Baroda, Faculty of Education & Psychology, Unpublished Dissertation for M. Ed., 1956. pp. 521.

Estimates Committee. *Cultural and International Activities*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat. 1958. p. 116.

Planning Commission. *Social Welfare in India*. Delhi, Publications Division, 1955. pp. 53-119.

ग्यारहवाँ अध्याय : कृत्तिय राष्ट्रिय संस्थान

Fleming, D. J. *Schools With a Message for India*. Madras, O.U.P., 1948. pp. 192.

Government of India. *Experiments in Primary and Basic Education*. Delhi, Ministry of Education. 1956. pp. 33.

Gujarat Vidyapitha. *Annual Report, 1954-55* (in Gujarati). Ahmedabad, Navjivan Press, 1955. pp. 21.

Hindustani Talimi Sangh, Wardha. *Basic Education At Sevagram*. 1951. pp. 26.

—, *Nai Talim at Sevagram*. 1955. pp. 8.

Jamia Millia Islamia, *Review of Aims, History and Scope of Work*. Report 1954-55. pp. 54.

Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. *Sri Aurobindo International University Centre*. 1958. pp. 16.

इ

एम्प्रीडियेट, ३६, १०२, ११७,
११८, १८६, १९९, २०४, २०९।
इण्डियन नेशनल काँग्रेस, ४१, ४३, ६७,
७१, १९६।
इन्स्पेक्टर, ३४, ३५, ८०, १०९,
१३१, १८३, २६९।

ई

साई धर्म प्रचारक मण्डल, १७, ६३,
९८, १३७, १७९, २१६, २६४,
२६८।
ईण्डिया कम्पनी, १६ २१, ६२,
६४, ६५, ९७, १७८, १७९,
१९७, १९६।

उ

उत्तर माध्यमिक स्कूल, २४, ३६,
११२, ११७-२५, १३५।
उ, १५, ४३।
उत्पति, १३८, १४६, १५५, १५६।
उपनिषद, २, ७।
उपनिषद, १३६।
उत्पदा, ७, ९।
उत्पति विषयक लेखा, १३४, १६९, १

ए

एडेमिक काउन्सिल, १४६, १७६, १
शिक्षक स्कूल, ६३, ७६, ७७, ८२,
९४।

क

कानून - आशा पत्र (१८१३), १७,
इंग्लैण्ड का शिक्षा कानून (१९४४).
८३, पटेल एक्ट, ७०, प्राथमिक

शिक्षा, ६८, ७०, बनारस हिन्दू
विश्वविद्यालय, १७६, बाल अधि
नियम, २६९, भारत सङ्कार
(१९१९), २१, २२, २८, ६९,
२५२; भारत सरकार (१९३५),
६९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
१४७, विश्वविद्यालय कानून
(१९०४), ९६, ९९, १३९, १४०,
सुधार विद्यालय, २६९, स्थानीय
निकाय, ३४।

कुमान, १३, ३७।

कुल्पति, १३८, १४६, १५५।

क्रिण्डर गार्टन, २४६, २४७।

केन्द्रीय (भारत) सरकार, २१, २२,
२७, २८, ३३, ८५, ८७, ८८,
९३, १११, १५३, १५४, २४१,
२५४, २६७, २७२, २९३।

कृषि, ३८, ४२, ४५, ४६, १०२,
१२०, १२२, १२७, १७२, १५३,
१९४, २२३, २३६, २८७।

ख

खेल क्लब, १०६, १११, १२०, १३४,
१४६, २७१, २७२।

ग

गुरुकुल, २, ३, ५, ६, २७९, २९०।

ग्रह विज्ञान, ४६, १२२, १२६, १६६,
१८६, १९१, २२६।

गोष्ठी, १३१, १७३, २२९-३१,
२४४, २५६, २५८, २९१।

ग्राम सेविका, १८६, १८७, १९१।

ग्रामीण शिक्षा, २३, ४१, ४५-४८,

अनुक्रमिका

(विषयानुसार)

अ

अग्रहार, ६ ।
 अजायबघर, १३९ ।
 अमरिकी टेकनिकल कोअपरेशन, २३१ ।
 अनाथालय, २६४, २६८ ।
 अनुदान: केन्द्रीय, २८, ३३, ८६, ९३,
 १५९; प्राथमिक, ६४, ६९, ७८,
 ८६, ९३; प्राविधिक, २-४; प्रौढ
 (समाज), २५२, २५४; माध्यमिक,
 ९२, ९९, १११, १३१, १३२;
 विश्वविद्यालय, १४०, १५९, १६०;
 शिक्षक, २४१, २४२; शिक्षक-
 प्रशिक्षण, १११; स्त्री-शिक्षा १८० ।
 अनुशासन, २७१, २७५, २७७, २७८,
 २९०, २९५, २९६ ।
 अनुसन्धान; अनुदान, १४८, १५९,
 १६०, १७५; प्रयोगशालाएं, ३३,
 १७५, २०५; प्रवासन, १३१;
 प्राथमिक शिक्षा, ७२, ९५, ९६;
 प्राविधिक शिक्षा, ३३, २०४, २०५,
 २१२; बुनियादी शिक्षा, ५०, ५१;
 माध्यमिक-शिक्षा, ११२, १३१;
 विश्वविद्यालयीय शिक्षा, १४२,
 १५९, १६०, १६९, १७४, १७५;
 वृत्ति, १५९, १७४, १७५, २०४,
 २०५; वैज्ञानिक, ३३; शिक्षक-
 प्रशिक्षण, २१९, २२९, २३७, २३८;

समाज शिक्षा, २५४; संस्थाएं, ३३,
 ३६, २२० ।
 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम
 जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग, ७३,
 ८२, ८९, ९०, ९२, ९९ ।
 अवरोधन, ७७, ७८, ९६ ।
 अस्वास्थ्य, १११, १४४, १५९, १६० ।
 अहिंसा, ४०-४२, ४४, ४७ ।
 अंग्रेजी, १८-२०, ४२, ४५, ९७, ९८,
 १००, १०१, १२०, १२१, १२३,
 १७१, १७२, २१० ।

आ

आयुर्वेद, १२, ३५ ।
 आयोग : अमरिकी उच्च शिक्षा, २०८,
 २०९; माध्यमिक शिक्षा, १०५,
 ११६-२२, १३०, १३२, १३३,
 २३६, २३९, २४३; योजना, ८५,
 २०६; विश्वविद्यालय (१९०२),
 २१, १३९, १७३; विश्वविद्यालय
 अनुदान, ३१, ३३, ११२, १४७,
 १४८, १५४, १५९, १७१, २४१,
 २९७; विश्वविद्यालयीय (राष्ट्राध्ययन)
 शिक्षा, १०५, ११८, १३५, १४२,
 १५२, १५४, १७२, १७४, १७७,
 १८९, २३९, २४१; सैडलर, २१
 १००-०२, १४१, २१९; हण्टर,
 २१, ९८, १७९, २१७ ।
 आश्रम, ३, ५ ।

१२; बाह्य, ४९, ११३, ११४,
१३४, २८१; मौखिक, २३७; वस्तु-
गत, १३४, २३८; विश्वविद्यालयीय,
१३५, १७३; शालान्त, १०२,
११४; सुधार, ११२, १३३, १३४,
१७३, २३१।

पंच वर्षीय योजनाएँ : २३, २१३;
तृतीय, २५, ८५, १७७, १९०,
१९१, २०२, २६१; द्वितीय, २३,
२४, ८३, १२५, १९०, २००,
२०७; प्रथम, २३, ८३, १११।

पाठ्यक्रम : गुरुकुल, २७९, २८०;
टोल, १५; पूर्व प्राथमिक, २४७;
प्राथमिक, ६३, ७२, ७६, ७७,
८२; प्राविधिक, १९९, २००,
२०३, २०४, २०८, २०९;
प्रौढ (ममाज), २५३; बुनियादी,
४२, ४५, ४६, ४९; मकतब,
१३, १४; मजबूर, २६७-२६९;
मदरसा, १४; माध्यमिक, ११३,
११९-२५, १२८; विश्वविद्यालयीय,
१५२, १५३, १६५-६८; शिक्षक-
प्रशिक्षण, २२८-३२, २३५-३७;
स्त्री शिक्षा, १७८, १८७, १८९,
१९१।

पाठ्य पुस्तक, १४, ३५, ६३, २५८,
२५९, २८७।

पाठशाला, १५, ६२।

पारिभाषिक शब्द, १७२, २८५।

पार्लियामेण्ट, १७, २७।

पार्लियामेण्ट, २००, २०२।

पुस्तकालय, १२, १४, १६, ३२, १११,

१३९, १४६, १५९, १६९,
२५८, २५९, २८३, २८५, २८६।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा : कार्यक्रम,
२४७, २४९; प्रकार, २४८, २४९;
प्रगति, २४७; प्रयोग, २४८, २४९;
प्रौढ शिक्षा, ४४, बुनियादी शिक्षा,
४५, २४६; रूप, २४४; शिक्षक,
२४९, सुधार; २४८।

पेन्शन, १५९।

प्रकाशन, २८, ३२, १७५, २३०,
२३१, २५४, २५९, २८७।

प्रदर्शनी, १७६ २३०, २३१, २५६।

प्रशासन : केन्द्रीय सरकार, २२,

२७-३३, ४८, ५०, ८५, १११,

११५, १२५, १३०, १५४, १५५,

२४१, २५४, २६७, २७२, २९३;

पूर्व प्राथमिक, २४५; प्राथमिक,

७०, ७२, ८५ ८६; प्राविधिक;

३३, १९८; मजबूरों की शिक्षा,

२६९, २७०; माध्यमिक, ९९,

१०१, १०८, १०९, १११, ११२,

१२५, १३०; राज्य सरकार, २१,

२२, ३३, ३४, ६४, ७१, ८६,

१११, १२५, १५४, १६०, २४१,

२५४, २९२; विश्वविद्यालयीय, ९९,

१०१, १३८-४०, १४३, १४७,

१४८, १५३-५७; समाज शिक्षा,

२५३, २५४; स्थानीय निमाय, ३४,

३५, ६८, ८०; स्त्री शिक्षा, १८३,

१८४।

प्रसारण कार्य, ११२, १६०, १६२,

१७६, १८७, २११, २६०, २८८।

५४, ५९, ६२, ६५, ८१, ९०-९२,
१२०, १२७, १२८, १५२, १५३,
१८७, १९१, २०४, २९२।

घ

घोषणा-पत्र : बुड, २० २१, २७,
१३८, २१६; स्टैनले, ६४, २१६।

च

चन्द्रा, १६०, २७०।
चम्पारण सत्याग्रह, ४०।
चिकित्सा, ६, ४६, २४३, २४७।
चित्र-कला, ७, ३८।

छ

छात्रावास, ४, १२, ३८, १११, १४४,
१४६, १५९।
छात्र-संख्या : कुल, २५; प्राथमिक, ७८,
८८, ९२, ९४, ९५; प्राविधिक,
२००, २०१; मजदूर, २६५; माध्य-
मिक, ९९, १०४, १०६-०८,
११६; विश्वविद्यालयीय, १४२,
१४४, १७०; समाज शिक्षा, २५६;
स्त्री-शिक्षा, १८०-८३।

ज

जनता कालिदास, २५७, २९२।
जन संख्या, २७, ७६, ९०, २५०।

ट

टोल, १५, ६२।
टिप्पणियाँ, १६१, २४३।

ड

दण्ड, ६३।
दल, ११०, १५८, १६०।

देशी शिक्षा, १६, १८, ६२-६५।
द्वैत-शिक्षा-पद्धति, ९४, ९५।

ध

धर्म, ५, ६, १३।

न

नर्सरी स्कूल, २४६-४८।
नसिग, १९१।
निर्देश तथा परामर्श, ११५, १२८,
१२९, १६८, २३८।
नृत्य, ६, ३५।

प

पञ्चव्रजा, ७, ९।
परिपत्र : अखिल भाग्रीय खेलकूद,
२७२; अखिल भारतीय प्रारम्भिक
शिक्षा, ३१, ७२, ७३, ८५, १११;
अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा,
३१, ३३, ११२, १९७-२००,
२०३, २०८, २०९; अखिल भारतीय
माध्यमिक शिक्षा, ३१, १११, ११२,
१२१-२३; मन्त्रि, ३३; राष्ट्रीय प्रामाणिक
उच्चतर शिक्षा, ३१, १५२; राष्ट्रीय
शिक्षा-मंडल, २६५; राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा,
३१, १८३, १९१; विद्यय स्त्री, १८१;
पैशनल तथा औद्योगिक शोध,
१९७, २०२।
पब्लिक स्कूल, ३२।
परीक्षा तथा योग्यता निर्धारण : आन्तरिक
११३, १३४; उद्देश्य, १३३; गोठी,
२३१; प्रशासन, १०२, १०९;
प्रशिक्षण, ३५; प्राथमिक प्रमाणी, ५,

मण्डल : अन्तर्विद्ययालय ३१ १४६,
१४७, १९९; केन्द्रीय समाज
कल्याण, ३५४ केन्द्रीय समाज सेवा,
३१; केन्द्रीय सलाहकारा शिक्षा,
२८, ३१, ३२, ४९, ११८, १२३,
१६५।

मजदूरों की शिक्षा : इतिहास, २६४;
पाठ्यक्रम, २६३; प्रशासन, २६९,
२७०; वर्गीकरण, २६२, २६३;
संस्थाएँ, २६४-६९।

मदरसा, १४, १७, ६२, १३६।

मनोरञ्जन कार्य १०४, १७६, ५७,
२६९।

मन्त्रालय कृषि, १३०, १९२;
परिवहन एवं प्रतिरक्षा, २५३,
२९३; वाणिज्य तथा उद्योग, १३०,
वित्त, २१४; वैज्ञानिक शोध एवं
संस्कृति, २९, ३३, १९८, २००,
शिक्षा, २९ ३२, ७३, १११,
११२, १५६, १७७, १८३, २५४,
२६४, २७२, ७४, २७७, २७८,
२९१, २९३; श्रम, १३०, १८३,
२५३; सामुदायिक विकास तथा
सहकार; १३० १८३, २९३;
सूचना तथा प्रसारण, २९३; स्वास्थ्य
१८३, २६९।

माध्यमिक शिक्षा : अनुसंधान, ११२,
११३, इतिहास ९७-१०५,
उद्देश्य, ११५, ११६, ग्राण्ट-इन एड
९८, निरीक्षण १३१; परीक्षा, ९८,
९९, ११२-११५, १३३; पाठ्य-
क्रम ९८, ९९, १०३, १०४,

११३-११४, ११९-२४; प्रशासन,
१०१ १०६, १०८, १३०-३४;
माध्यम, ९७, १०१; वित्त, ११०,
१११; विशेष स्कूल, १२४-२८;
शाला गृह ११३; शिक्षा मण्डल,
१०९; शिक्षक, १२५, २४०,
२४१।

मैट्रिक परीक्षा, ३८, ४२, ९३, ९८,
९९, १०१, १०४, १०९, ११४,
११६, १५१, १८५ २६१।

य

यज्ञोपवीत, २, ५, १।

युवक कल्याण, १४६, २७४, २७५।

व्यर्थता, ७७, ७८, ९६, १६३।

व्यवसाय निर्देशक, १२८।

व्यायाम, ३, ४, २९, ३०, १०६,
२७२।

र

रामकृष्ण मिशन, २६८।

राज्य (प्रान्तीय) सरकार, २१, २२, २८,

२९ ३२ ३४, ६४, ७१, ७५,

८६-८८, ९३, १११, ११५, १५४

१६०, २४१, २५४, २९२।

राष्ट्रीय प्रयोग शालाएँ २५, ३३, १५४,
२०५।

रात्रि पाठशाला, २५२, २५५ २६०।

रिपोर्ट : एडम, ६२; एक्ट बुड, १०१,

१०३, २०७; जाकिर हुसैन ४२,

५२, ५३; माण्टेग्यु चेम्सफोर्ड,

३५; साजेंट, ४९, ५१, ८६,

१०१, १०३, १०४, २४८ २९१।

प्राथमिक शिक्षा : अनुसन्धान, ९५, ९६; अनिवार्य, ६६-७१, ७६, ८७, ८८, २९१; इतिहास, ६४-७१; देहात, ९०, ९१; पाठ्य-क्रम, ७६, ७७, ८२, ९२; प्रशासन, ७२, ७८, ८०, ८५; वित्त, ७३, ७४, ८०, ८१, ८७; शाला-गृह, ७७; शिक्षक, ७६, ९३; सर्वेक्षण, ८७।

प्राविधिक शिक्षा : अनुसन्धान, २०३, २०५, २१२; इतिहास, १९५-९८; उच्चतर प्राविधिक संस्था, २०३, २०४; कर्मशाला अभ्यास, २१०, २११; पंचवर्षीय योजनाएँ, २४, २५, २००-०३; पाठ्यक्रम, २०३, २०४, २०८, २०९; प्रशासन, ३३, १९८, १९९, २०७; रूप, १९५, १९९, २००; विस्तार, २००-०२; वृत्ति, २०४; शिक्षा का माध्यम, २१०; शिक्षक, २०९, २१०।

प्रावीडेन्ड फण्ड, १५९, १६९, २४३।
प्रौढ (समाज) शिक्षा : इतिहास, २५२, २५३, २५६; कार्यक्रम, २५३, २५६, २५७; प्रशासन, २५३, २५४; प्रशिक्षण, २५७; बुनियादी, ४४, ४५; रूप, २५१, २५३; विश्वविद्यालयीय, १७६, १७७, २५९; संस्थाएँ, २५५, २५६; मातृशिक्षा, २५९-२६२; स्त्री, १८७, २५५, २५६।

फ

फारसी, १८, १९, ३५।
फॉटो काउन्सेशन, २२९, २३१।

व

बहुद्देशीय स्कूल २४, १०५, १११-१३३, १२५, १२६, २३६, २८६, २९१।

बुनियादी शिक्षा : अनुसन्धान ५१; अहिंसा : ४१, ४२; आक्षेप, ५२ ५४; उत्तर-बुनियादी, ४६, ४७, १०६, १०८, २००; केन्द्रीय दस्तावेजी, ४२, ४५, ५२-५४; गुण, ५६-५७, ६०, ६१; धार्मिक शिक्षा, ५४; ध्येय, ४०, ४३, ४५, ५७; नियम-निष्ठा, ५८, ५९; पाठ्यक्रम, ४२, ४५, ४६, ४९; पूर्व-बुनियादी ४५; प्रक्रम, ४४, ४९; प्रगति, ४३, ५७; प्रौढ शिक्षा ४४, ४५; भूदान, ४७, ४८; शिक्षक-प्रशिक्षण, २२४, २२५, २३२-३४; समवाय ५३, ५४।
वेकार, ९३, २९, ८।

बोस्टल संस्था, २६८, २६८।
ब्रेल पद्धति २६६, २६७।

भ

भारतीय संविधान, २७, ३३, ७९, ८३ ८५, १२० २५३, २८८, २६०।

भाषा, ७, १४, २५ ४५, ८२, ११३, १२०-२४ १४१, १७१, २१०।

भूदान ४७, ४८, २८८।
भूमीक्षण, ३३।

म

महायुव, १३, ६२, २८६।

२२८, २६९, २७७, २९१।

शिक्षा-साधन, ६३, ८७, १११; ११३,
१४४, १५८, १६०, २३३, २५७।

शिक्षा-संचालक, २७, २८, ३४, १८४।

शिक्षा सूचना-कार्यालय, २८, ३२।

शिक्षक ४८, ६३, ७६, ८१, ८२,
९३, २०६, २०९; २१०, २३९-

४४, २७८।

शिक्षक-प्रशिक्षण : अनुदान, १११; अनु

शासन, २७७, २७८; अनुसन्धान,

१११, २१९, २२७, २२८, २३८;

इतिहास, २१४-१९; उत्तर-स्नातक,

२२५, २२६, २३३, २३४; कालिज

अध्यापन, १६९, २३७; पाठ्यक्रम,

२३४, २३५; पूर्व-प्राथमिक, २००,

२२१; प्राथमिक, २०१-२८; बुनि-

यादी, २२३, २२५, २२६, २३३,

२३४; मध्य-अध्यापन, ९४, ११२,

२२९, २३०; न्यय, २१७; वृत्ति,

१११; शिक्षिका, १८६, १८७,

१९१, २२०, २२७; सुधार, २३१-

३९; स्नातक, २१९, २२०।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा, ६३, २३०, २३१,
२३३, २३७, २३८, २५७, २५८।

स

समाज कल्याण, ८९, ९१, २०४।

समाज सेवा, १७६, १७७, २५५,
२८४।

समिति : अखिल भारतीय प्रौढ शिक्षा,

२५२; उच्च प्राविधिक-प्राप्त, १९९,

२००; कस्तूरबा अनुदान, १६८;

केन्द्रीय बुनियादी, ४९; कुजल :

(शारीरिक शिक्षा) २७८, (शिक्षा

माध्यम) १७१, १७२; खेर, ४८,

४९, २९१; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा,

३१, १५२; बुनियादी अनुमान

निर्धारण शिक्षा, ४५, ५०; ताराचन्द्र,

१०५; भारतीय शिशु शिक्षा, २०१;

राष्ट्रीय नारी शिक्षा, १८३, १९०;

वैज्ञानिक एवं मानवीय शक्ति, १९७;

सरकार, १९७, २०३; हार्टिंग, २८,

७१, १०१, १०२, २९२।

सम्मेलन : अखिल भारतीय ट्रेनिंग कालिज,

२३३, २३४; अखिल भारतीय

राष्ट्रीय शिक्षा, ४०, ४३, ४४;

अखिल भारतीय स्त्री परिषद, १८९;

माध्यमिक शिक्षा-मण्डल सचिव,

१३४; राज्यीय शिक्षा-मन्त्री, ८५,

२३६; विश्वविद्यालय उपकुलपति,

१६९, २३७।

सर्वेक्षण, ७२, ७७, ८०, ८७, १३२,
२९२।

सह-शिक्षा, ५, १८७, १९१, २८०।

सच : अखिल भारत महिला, १८१;

अखिल भारतीय शिक्षण, ११२;

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रसार,

१९६; हिन्दुस्थानी तालीमी, ४७,

२२३, २७९, २८७, २८८; संयुक्त

राष्ट्र, ३२, २७५।

संधाराम, ९, १३६।

सघीय क्षेत्र, २७, ३२।

घ

वाणिज्य, ६, ३८. ४६ ।
वित्त : पंच-वर्षीय योजनाएँ, २३-२५,

८७, १२५, १९८; प्राथमिक शिक्षा
६४, ७३, ७४, ८७; प्राविधिक
शिक्षा, १९८; मजदूरों की शिक्षा,
२७०; मध्य-अध्यापन शिक्षा
२२९, २३१; माध्यमिक शिक्षा,
११०, विश्वविद्यालयीय शिक्षा,
१५७, १६०; शिक्षा, ३८; समाज
शिक्षा, २५६ ।

विद्यापीठ, २७९, २८४, २८५ ।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा : अध्यापन
१६८-७०; अनुदान, १५९;

अनुसन्धान, १३९, १६९. १७४,
१७५; अंग्रेजी, १७१; इतिहास,
१३६-४२; कालिज, १४३, १४८-

५०, १६०, १६१; ग्रामीण,
१५२, १५३; छात्र, १४८. १७४,
१७५; परीक्षा, १३८, १६३,

१७३; पाठ्यक्रम, १६५-६८;
पुस्तकालय, १३९, १४५; प्रकार,
१४४, १४५; प्रशासन, १४६,

१५३-५७, १६०, १६१; माध्यम,
१७१, १७२; माध्यमिक शिक्षा
१००-१०२; वित्त, १४५. १५७,

१६० ।

विहार, ९, १३६ ।

विज्ञान मन्दिर, २५, २०४ ।

वृत्ति, १५, ३०, ३१, १११, १५९,
२०४ ।

वेतन, ४१, १३३, १३५, १९२, २४६-
४३ ।

श

शहर-ग्राम कल्याण, २०३, २०४ ।

शान्ति सेना, ४८ ।

शारीरिक शिक्षा, २९, १०४, १२०,
१३४, १४१, १४६, २२६ ।

शाला-गृह, ६३, ८७, ९०, १११,
११३, १३२, १५९, १६०, २१४ ।

शिक्षा का माध्यम : १४, १८, १९, २५;

प्राथमिक, ६३; प्राविधिक, २११;

बुनियादी, ४१; माध्यमिक, ९६,
२००, १०१, १२०; विश्वविद्या-

लयीय, १७१, १७२ ।

शिक्षा का ढाँचा, ३६-३८, १०६, १९९ ।

शिक्षा छनाई सिद्धान्त, ६५, ६६, ७९ ।

शिक्षा-नीति : वैदिक (१८३५), ९६;

हाडिगज (१८४४), ९६; सरकारी
प्रस्ताव (१९०४), २१, ६४, ८९,

१०१, २१७; सरकारी प्रस्ताव
(१९१३), २१, ६९, १४० २१८,

२१९ ।

शिक्षा परामर्शदाता, २९, ३१, ७३ ।

शिक्षा-मन्त्री, २२, २९, ३२, ३३, ३४,
४८, ७१, ८५, ८७, ९३, १३०,

१५६ ।

शिक्षा-व्यय, १२, १७, २३, ३९, ४०-

४२, ४६, ६४-६६, ७३, ७४,
८१, ८७, ११०, १५७-६०, १६६,

१८१, २९८, १०४, २१७ २२०,

- सयुक्तराष्ट्र संघ, २९, ३२।
 संस्कृत, १८, १९, ३५।
 सातत्य शिक्षा, ८५, १७६, १९२।
 सामान्य शिक्षा, १६६, १६७, २०९।
 सामुदायिक विकास योजनाएँ, १५३।
 साक्षरता, २७, ६२, ९६, १७८, २५०,
 २५५, २९०।
 सिनेट, १३८-४०, १४६, १५६।
 सिण्डिकेट, १३५, १३९, १४६।
 सैनिक शिक्षा, २७२-७५।
 सैन्य शिक्षार्थीदल: राष्ट्रीय, ११३, २७४,
 २७५, २७८; सहायक, २५, २७२,
 २७४, २७८।
 स्वायत्त शासन, २९-३४।

- स्त्री-शिक्षा: आदर्श, १८९, १९०-९२;
 इतिहास, १७८-१८१; उच्च शिक्षा,
 १८५, १८६, १९३; पाठ्यक्रम,
 १७८, १८५, १८६, प्रशासन,
 १८३; प्राथमिक शिक्षा, १८४,
 १९०; प्रौढ़-शिक्षा, १८२; माध्यमिक
 शिक्षा, १८४, १८५, १९५, १९२;
 व्यावसायिक शिक्षा, १८७; वाधायें,
 १७८; विश्वविद्यालयीय, १८५,
 १८६, १९१; शिक्षा-संस्थाएँ, १९०;
 शिक्षिका प्रशिक्षण, १९१।

ह

- हाजरी निरीक्षक, ८०, ८९, १
 हिन्दी; २९, ३०, ४३, ४३, १२०
 १२१, १२३, १७१।
 हेड मास्टर, २४१।

जाजे, पंचम, ६९ ।
जादवपुर, १००, १४२, १४५, १९६,
३०३ ।

जापान, ८८, ९६, २६१ ।

जामियानगर, १५२ ।

ट

टर्की, ९४, ९६ ।

ठ

ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, २८१ ।

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १००, २८१,
२८२, २८४ ।

ठाकरसी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर,
२८१ ।

ड

डन्कन, जानाथन, १७ ।

डेनमार्क, ९४ ।

ढ

दाका, १०९, १४१ ।

त

तधशिला, ६ ।

तंजौर, ६ ।

थ

थामस, जान, १३६ ।

थेम्बर, एम० एस०, २०० ।

द

दयानन्द सरस्वती, २७८ ।

दिल्ली, १३, २७, ६९, १०९, १३६,
१४१, १४५, १५४, २०२, २२८,
२६९, २७७, ३०२ ।

दुर्गापुर, २०२ ।

दुर्वासा, १३६ ।

देशमुख, चिन्तामन, १५७, १६५ ।

देसाई, महादेव, २८५ ।

देसाई, मोरारजी, २१४ ।

देवधानी, ५ ।

देहरादून, २६४, २६७ ।

न

नवद्वीप, १३६ ।

नागपुर, २७, १०९, १४०, १४१,
१४५, १६६, २०२, २२५, ३०३ ।

नायडु, सरोजिनी, १८१ ।

नालन्ड, १२ ।

नाशिक, ६ ।

नेहरु, जवाहरलाल, २१०, २६२, २७५ ।

नेरोबी, ३२ ।

न्यूजीलेण्ड, ९४ ।

प

पण्डित, विजयालक्ष्मी, १८९ ।

पन्त, सुमित्रानन्द, १९३ ।

पटना, १०९, १४०, १४१, १४५,
२०५, २८४, ३०४ ।

पटेल, बह्मभाई, २४२, ३०४ ।

पटेल, विठ्ठलभाई, ७०, ८८, १४२ ।

पर्सा, युस्टेस, २१३ ।

पजात्र, १०, २६, १३८, १४५, १५३,
२०२, २६९, २७७, ३०४ ।

पाटलीपुत्र, ६ ।

पूना, १०९, १३६, १४१, १४२,
१४५, १६६, १९५, २२४, २८०,
२८४, ३०४ ।

ओ

ओदन्तपुरी, १०, १२।
ओस्मानिया, १४५, १६६, २२५,
२२८, ३०४।

क

कज्जिन, लार्ड, २१, १००, १३९, १४०।
कटक, १०९।

कनौज, ६।

कबीर, हुँमायुन, २०४, २९७।

कस्तबा, १३।

कलकत्ता, २१, ३३, ९८, १३७,
१३९, १४५, १९५, २१६, २२४,
२२५, २२८, २८१, ३०२।

कर्ने, डी० के०, २८०।

कानपुर, ३३, १९७, २०३।

कारे, २१६।

काशी, ६।

काश्मीर, १०, ४३, १४२, १४५,
१४६, ३०३।

कौची, ६।

किलपेन्ड्रू, विलियम, २१९।

कुरुक्षेत्र, १४२, १५५, ३०३।

कुसैयोंग, २१८।

कुँजरू, हरयनाथ, १७१, २७८।

केरल, २६, १४५, १६६, २०२,
२२२, २६९, ३०३।

ख

खडगपुर, २०३।

खगरीजग, १३।

खिलजी, अलाउद्दीन, १५।

ग

गर्गी, ५।

गगौटी, १५३।

गान्धीजी, ३८, ४०, ४१, ४३, ४४,
४८, १८१, २४६, २९९।

गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव, ६७।

ग्वालियर, १०९।

गुजरात, १०, ६६, १४२, २२४,
२२८, ३०३।

गोखले गोपालकृष्ण, २१, ६८-७०,
८८।

गोरखपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,
२२८, ३०३।

गौहाटी, १४२, १४५, १९५, २२४,
२२८, ३०३।

घ

घोषा, ५।

घोष रायबिहारी, १००।

च

चीन, ८८, ९६, २६१।

चेम्सफोर्ड, लार्ड, २१, ६९।

ज

जगदल, १०, १२।

जबलपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,
२२४, २२८, ३०३।

जमशेदपुर, २०२।

जर्मनी ९४, ९५, २१४।

जयपुर, १०९, ३०४।

जाकिर हुसैन, ४१, ४३, ५२, ५३,
२४४।

मार्गरेट, कसिन्स, १९१ ।
 मार्गरेट, मैकमिलन, २४६ ।
 माण्टेग्यू, २१, ६९ ।
 मिथिला, ६, १३६ ।
 मिनिकाय तथा धमीन द्वीप, २७ ।
 मिलाड, एन्ना, २६४ ।
 मुदालियर, लक्ष्मणस्वामी, १०५, १५६ ।
 मर्शिदाबाद, १३६ ।
 मेस्सिको, ९०, ९१, ९३ ।
 मेयो, लार्ड, ६४ ।
 मेरठ, १५० २१६ ।
 मैक्लारे, लार्ड, १८-२० ।
 मैसूर, २६, १४०, १४१, १४५, १६६,
 २०२, २२८, २५२, २५८, २६९,
 ३०३ ।
 मैत्रेयी, ५ ।
 मोण्टेसरी, २४६ ।
 मोयसेज, सेएज, ९१ ।

य

यशोवर्मा, ७ ।
 याशगल्कच, ५ ।
 न्यूमेन, १९५ ।

र

रजिया, १५ ।
 रहेमतुल्ला, इब्राहीम, ६७ ।
 रंगून, १०९, १४०, १४१ ।
 राजपुताना (राजस्थान), २६, १४२,
 १४५, १६६, २०२, २२८, ३०४ ।
 राजपुरा, १५३ ।
 राजमहेन्द्री, २१८ ।

राजेन्द्रप्रसाद, २४३ ।
 राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली, ७, ४७, १४
 रामपुर, १४, १३६ ।
 रायननिन्गर, एस०, १०१ ।
 रावलपिण्डी, ६ ।
 रिपन, लार्ड, ३४ ।
 रुडकी, १३७, १४२, १४५, १९०
 ३०४ ।
 रूस, ९६, १५२, १९४ ।

ल

लखनऊ, १४, १३६, १४१, २२८
 २२८, ३०३ ।
 लका, २७, १३८ ।
 लडन, १३२, १३८ ।
 लाहोर, १४, २१७, २१८, २८४ ।
 लोधी, इब्राहीम १५ ।

च

चलमी, १०, १२ ।
 चशिष्ट, १३६ ।
 चाल्मीकि, १३६ ।
 चारंगल, २०२ ।
 चाशिगटन, ३२ ।
 विक्रम विश्वविद्यालय, १४२, १४५
 १६६ ।
 विक्रमशिला, १०, १२ ।
 विन्नेट, ६६ ।
 विवेकानन्द, ६७ ।
 वुड, चार्ल्स, २१ ।

श

शार्प, एनी, २६४ ।
 शाह, लालबिहारी, २६४ ।

पेरिस, १७७।
 पोर्तुगाल, ९४।
 प्रसाद, जयशंकर, १९३।
 प्लासी, १३।

फ

फिलिपाईन द्वीपसंज, ९६।
 फीरोजशाह, १५।
 फोवेल, २४४।

व

वगदाद, १३।
 वडोदा, ६७, १४२, १४५, १६६,
 २२४, २२५, २२८, २५३, २८१,
 ३०२।

वनारस, १३६, १४०, १४५, १५४,
 १५६, १५७, २१६, २२५, २२८,
 २८४, ३०३।

वरनी, १३।

वलवन, १३, १५।

वक्ख, १३।

वगलोर, १०९, १४२, २०२।

वंगाल, १०, २६, ६२, ६४, १०९,
 ११०, २०२, २१६, २५२, २६९,
 २७७।

वंगई, २१, २६, ३३, ४३, ६२, ६७,
 ९८, १३९, १४५, १५५, १९६,
 २०३, २१६, २२४, २२८, २५२,
 २६९, ३०२।

वार्कर, अर्नेस्ट, २५१।

वान, ३२।

वायर, १५।

विहार, १०, ४३, ६२, १०९, १४२,
 १४५, १५२, २०२, ३०२।

वीदर, १३६।

वीसेण्ट, एनी, १८१।

बुखारा, १३।

बुद्ध, ७।

बेथून, ट्रिक्वाटर, १७९।

बेल, एन्ड्रू, २१५।

बैटिक, लार्डे, ९७।

बोलपुर, २८१।

भ

भैंडोच, ६७।

भावनगर, २८१।

भाघे, विनोबा, ४७, ४८।

भोपाल, २०२।

भोसले, जे० के०, २७७।

म

मथाई, जान, १५७।

मद्रास, २१, २६, ३३, ९८, १०९,
 १३७, १३९, १४५, १६६, १९५,
 २०२, २०५, २१६, २१७, २२८,
 ३०३।

महुरा, १५०, १५२।

मध्य प्रदेश, २६, ४३, ११०, २०२,
 २६९, २७७।

मनरो, ६२।

मराठावाड़ा, १४२, १४५, ३०३।

महमूद, गजनवी, १३।

महेंद्रोदारो, १९४।

मंगलोर, २०२।

स

- समरकन्द, १३ ।
 मरकार, नलिनीरजन, १९७ ।
 सागर, १४२, १४५, १६६, २२४,
 २२८, ३०४ ।
 सिक दर, १९४ ।
 सिंध, १४२ ।
 सीतलगाड, चिमनलाल, ६७ ।
 सीलोन, ९४ ।
 सुरेन्द्रनगर, १५२ ।
 सूत, २८१ ।
 सेगान, ४१ ।
 सेराग्राम, ४१, २७९, २८७, २८८ ।
 सैडलर, माइकेल, १०१ ।

- सैयदैन, १६६, २३२, २९३ ।
 सीराष्ट्र, १५३ ।

ह

- हरिद्वार, २७८ ।
 हरिपुरा, ४१ ।
 हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु, २८७ ।
 हिमाचल प्रदेश, २७ ।
 हेस्टिंग्ज घारन, १७ ।
 हैदराबाद, १४०, १४१ ।
 होप, टी० सी० ६६ ।

ज

- जावशकोर, १४२ ।
 जिपुरा, २७, २६९ ।
 जिवेद्रम, १०९ ।

५५९४

शिमला, २७३।

शिला संस्थाएँ : अर्थ-शास्त्र स्कूल, दिल्ली, २०४; अर्थ-शास्त्र तथा समाज विज्ञान स्कूल, बम्बई २०४; अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, २६७; अन्ध विद्यालय, कलकत्ता, २६४; आर्य कन्या महाविद्यालय, बडौदा, १८६; इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स, घानघाट, ३३, १९७; कलकत्तामदरसा, १७, १३७; कलाक्षेत्र, अड्यार, २२७; कस्तूरबा निकेतन, दिल्ली, २७७; क्रिश्चियन कालिज, मद्रास, १३७; गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; ४३, २८४, २८५; गुरुकुल, काँगड़ी, २७९, २८०; जामिया मिलिया, दिल्ली, ४३, २२७, २७८, २८१, २८५-८७; धार्मिक इंजीनियरिंग कालिज, रुड़की, १३७; दिल्ली पोलि-टेकनिक, ३३, १९७; नवभारत विद्यालय, वर्धा, ४०; नर्सिंग महा-विद्यालय, दिल्ली, २६९; नेशनल इन्सट्यूट ऑफ वेसिक एज्युकेशन, दिल्ली, ३२, ५१; पद्वैपा कालिज, मद्रास, १३७; प्रयाग महिला विद्या-पीठ, अलाहाबाद, १८६; भारतीय औद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, ३३, २०३; भारतीय विज्ञान संस्था, बेंगलूर, २०३, २०४; राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र, दिल्ली, २५४; लक्ष्मी-बाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर, २२७; ललित कला फेकल्टी,

बडौदा, २२७; लेडी हरविन कालिज, दिल्ली, १८६; लेडी हाइंग्र मेडी-कल कालिज, दिल्ली, १८०; विक्टो-रिया जुविली टैकनीकल इन्सट्यूट, बम्बई, १९६, विद्याभवन, उदयपुर, २३४; विलसन कालिज, बम्बई, १३७; विन्च-मार्ती, (शान्ति-निकेतन), १४२, १४५, १५४, २२७, २३४, २७९, २८१-८४; श्रीमती नार्थीबाई टामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई, १४१, १४२, १४५, १८६, २२९, २७८-८१; श्रीनिकेतन, १५२, २८४; समाज, कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता, २७४; सर जे० जे० रूड ऑफ आर्ट्स, बम्बई, २२७; संस्कृत कालिज, बनारस, १७; सेण्ट जॉन्स कालिज आगरा, १३७; सेण्ट्रल इन्सट्यूट ऑफ एज्युकेशन, दिल्ली, ३२, १३२; सेण्ट्रल ट्रेल प्रेस, देहरादून, ३२, २६७; सेण्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय, बनारस, १८०; हारकोर्ट बटलर टैकनीकल इन्स-ट्यूट, कानपुर, १९७; हिन्दू कालिज, कलकत्ता, १३७; होम साईन्स फेकल्टी, बडौदा, १८६, २२१।

श्री अरविन्द, १००।

श्रीनगर, २०२, ३०३।

श्रीमाली, कादलाल, ८७, १६१, २९१।

श्रीव्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय, १४२,

१४५, १६६, ३०४।

SOME BOOKS by Dean S. N. MUKERJI

Higher Education and Rural India: The book examines the educational problems of rural India and offers a scheme of rural institutes, universities and higher secondary schools to improve Indian villages

First Edition (1956) pp. 342 Rs. 10-00

History of Education in India (Modern Period). A historical survey of Indian education from the downfall of the great Moghuls to the independence of the country, and description of the existing educational system

Third Edition (1960) pp. 341 Rs. 8-00

भारतीय शिक्षा का इतिहास छप रही है)

This is a Hindi version of the above book.

Education in India—Today and Tomorrow: A comprehensive inquiry into the current problems of Indian education with schemes for reconstruction

Fourth Edition (1960) pp. 435 Rs. 10-00

भारत में शिक्षा : A Hindi version of the above book.

First Edition (1960) pp. 335 Rs. 9 00

राष्ट्र-भाषा की शिक्षा : The book discusses modern methods of teaching Hindi as the national language of India.

First Edition (1957) pp. 264 Rs. 6-00

An Introduction to Indian Education: Gives a bird's eye-view of the existing educational system of the country.

First Edition (1958) pp. 117 Rs. 4-00

Secondary School Administration: The book presents a detailed discussion of the development, principles and functions of secondary school administration in India.

First Edition (1959) pp. 348 Rs. 10-00

ACHARYA BOOK DEPOT—BARODA

